{ संपादकीय }

नई दिल्ली, मंगलवार 11 जून 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

अब इंडिया की राह क्या हो ?

रविवार को नरेन्द्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद सम्हाल लिया है और उनकी सरकार ने एक तरह से कामकाज शुरू भी कर दिया है। 2014 और 2019 के मुकाबले एक बड़ी चुनौती को पार करने के बाद मोदी अपनी सरकार फिर से बनाने में कामयाब तो हो गये हैं लेकिन उनके सामने खड़े कांग्रेस एवं संयुक्त प्रतिपक्षी गठबन्धन इंडिया ने उससे कहीं बड़ी बाधाओं को पार करते हुए खुद को ऐसी मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है जहां भाजपा का मुकाबला संसद के भीतर व बाहर दोनों जगहों पर दमदारी से किया जा सकता है। मोदी के तीसरी बार सरकार बनने के पहले से ही, सच कहा जाये तो 4 जून की रात से ही साफ हो गया था कि यह अपने पैरों पर नहीं खड़ी है। इसलिए अनुमान जताये जा रहे हैं कि यह सरकार बहुत लम्बा चलने से रही। विवादास्पद मुद्दों को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों- खासकर तेलुगु देसम पार्टी (टीडीपी) एवं जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से टकराव बढ़ेगा तो इस सरकार के गिरने के अनुमान जाहिर किये जा रहे हैं।

तो क्या इंडिया को इन अंतर्विरोधों के बढ़ने और भाजपा प्रणीत नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (एनडीए) के अपने आप गिरने का इंतज़ार करना चाहिये ? इसका जवाब ढूंढने के लिये कई आयामों पर गौर करना होगा। पहली बात, यह तो सच है कि परस्पर टकरावों के कारण इस सरकार के गिरने का अंदेशा कई राजनीतिक विश्लेषक व्यक्त कर रहे हैं। कई तो इसकी समयावधि तक निर्धारित करने से नहीं चूक रहे हैं। यह अवधि कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक की है। इस तरह के कयासों के कई आधार हैं। इनमें प्रमुख है विभागों का वितरण। अनुमान जतलाये जा रहे हैं कि गठबंधन के जिन सहयोगी दलों को प्रभावशाली मंत्रालय, जिन्हें 'मलाईदार विभाग' भी कहा जाता है, न मिलें तो खींचतान होगी। माना जा रहा था कि सबसे रौबदार विभाग यानी गृह, रेल, विदेश और रक्षा मंत्रालयों के लिये भी कहा-सुनी सम्भावित है। इसे सभी सहयोगी दल, खासकर बड़े घटक अपने पास रखना चाहेंगे। इनमें टीडीपी एवं जेडीयू शामिल हैं जिनके क्रमशः 16 व 12 सदस्य हैं और जिन पर सरकार काफी-कुछ निर्भर करती है। किसी भी एक के हाथ खींचने की देर है और मोदी सरकार का पतन हो जायेगा। दूसरा अहम मुद्दा होगा लोकसभा के अध्यक्ष पद का। आने वाली राजनीतिक परिस्थितियों में इस पद का बहुत महत्व होगा। खासकर, टकराव की स्थिति में आसंदी पर बैठे व्यक्ति का आदेश व उसकी प्रतिबद्धता मोदी सरकार के लिये निर्णायक होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय टीडीपी ने ही अपने सांसद जीएमसी बालयोगी को इस पद पर बिठाने में सफलता पायी थी। बड़ी बात नहीं कि वह फिर इसकी कोशिश करे। देखना यह होगा कि क्या इस बार जेडीयू यह पद पाना चाहेगी। वैसे अनुमान लगाये जा रहे थे कि दोनों दल ज्यादा मंत्री पद चाहेंगे पर इनके एक-एक सदस्य को ही केबिनेट मंत्री बनाया गया है। फिलहाल तो कोई विवाद होता नहीं दिख रहा है। राकांपा ज़रूर नाराज़ है जिसे केवल एक राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था। इसलिये उसका कोई प्रतिनिधि रविवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ।

इंडिया के लिये असली संदेश तो यही है कि वह एनडीए में विवादों के पनपने और उनके इस कदर बड़ा होने का इंतज़ार न करे जिससे सरकार गिरे। अगर यह होना है तो वह अपने समय व कारणों से होता रहेगा लेकिन विपक्ष को अपने तईं प्रयासों को जारी रखना होगा। क्या हैं वे प्रयास ? उसे वही करना है जो वह पिछले दो वर्षों से करती आई है। 2014 व 2019 के मुकाबले कांग्रेस को बड़ा जनादेश मिला है और दस वर्षों में उसके सदस्यों का आंकड़ा दहाई को छूने जा रहा है। राहुल गांधी द्वारा वायनाड या रायबरेली की एक सीट छोड़ने पर वहां से जो भी कांग्रेस प्रत्याशी लड़े, जीतेगा। इस तरह कांग्रेस 100 तक पहुंच जायेगी। दो राष्ट्रव्यापी यात्राओं के बाद राहुल का कद तो बढ़ा ही है, एक सर्वे में उन्हें पीएम के रूप में देखने वाले मोदी के मुकाबले 4 प्रतिशत ज्यादा पाये गये- यूपी में पीएम की पहली पसंद के तौर पर 36 फीसदी लोगों ने राहुल गांधी और 32 फीसदी लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना। यह उनकी लोकप्रियता के साथ स्वीकार्यता को भी दर्शाता है। एक उत्तर व दूसरी दक्षिण भारत की सीट जीतकर राहुल विपक्ष के नेता के सहज ही दावेदार बन जाते हैं। उनकी इसी बढ़ी ताकत से कांग्रेस पुनर्जीवित हुई है और अन्य दलों ने उसका नेतृत्व स्वीकार किया है।

ऐसे में कांग्रेस लोकसभा में वैसे ही मोदी सरकार के कारनामों का पर्दाफाश करती रहे, जैसी वह राहुल के नेतृत्व में 17वीं लोकसभा की आखिरी बैठक तक करती रही थी। मोदी द्वारा अपने मित्र कारोबारियों- गौतम अदानी व मुकेश अंबानी की होती सहायता, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ईवीएम के जरिये होने वाली हेराफेरी, कोरोना वैक्सीन, अग्निवीर योजना आदि ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो कांग्रेस व इंडिया संसद के भीतर व बाहर उठाती रही है। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, चुनाव प्रचार आदि में भी विपक्ष ने ये मुद्दे जोर-शोर से उठाये थे। इनका असर भी पड़ा। महिलाओं, युवाओं, किसानों, मजदूरों, आदिवासियों आदि के लिये जो वादे कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में किये थे, उन्हें आधार मानकर पूरे इंडिया ब्लॉक को एक मजबूत आवाज दोनों सदनों में उठानी होगी। सामाजिक न्याय के लिये जातिगत जनगणना की वह मांग कर सरकार की घेराबन्दी करे। इंडिया के घटक दलों पर मोदी सरकार के आक्रमण और भी होंगे, तो भी वह अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाये।

मजबूरी का नाम एनडीए

राजेंद्र शर्मा

यह किसी से छुपा हुआ नहीं था कि यह चुनाव, भारत का अब तक का सबसे नाबराबरी का चुनाव था। यह एक ऐसा चुनाव था जिसमें बराबरी के मुकाबले की यह न्यूनतम से न्यूनतम शर्त भी पूरी नहीं हो रही थी कि चुनाव आयोग, जिस पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व था, कम से कम निष्पक्ष दिखाई देने की कोशिश करेगा।

बेशक, 9 जून की शाम को राष्ट्रपति भवन के कोर्टयार्ड में पूरे बहत्तर सदस्यों के जंबो मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के साथ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की तीसरी पारी शुरू हो गयी है। लेकिन, यह तीसरी पारी कितनी असामान्य होने जा रही है, इसका अंदाजा एक इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इस चुनाव में कौन जीता है और कौन हारा है, इसके विवाद पर सरकार के शपथग्रहण के बावजूद, संतोषजनक तरीके से विराम नहीं लग पाया है। इसमें शक नहीं कि 4 जून को देर शाम 18वीं लोकसभा के चुनाव की मतगणना लगभग पूरी होने तक, जब इंडिया गठबंधन की गिनती 240 पर रुक गयी और दूसरी ओर भाजपा और उसके 2024 के चुनाव के सहयोगियों की गिनती बहुमत के 272 के आंकड़े को पार कर 290 पर पहुंच गयी, तभी इतना तो सभी यथार्थवादी प्रेक्षकों के सामने साफ हो गया था कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ जरूर लेंगे। यह इसके बावजूद था कि कुल मिलाकर इस चुनाव में जिस तरह का जनादेश आया है, उसे देखते हुए खुद संघ-भाजपा के समर्थकों के भी एक हिस्से को यह मानने में हिचक थी कि इस चुनाव का फैसला, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के जारी रहने के पक्ष में है। 2024 के चुनाव से निकली लोकसभा सदस्यों की गिनती बेशक, भाजपा और उसके सहयोगियों के मिलकर सरकार बनाने का रास्ता बनाती थी, लेकिन इस चुनाव का जनादेश कुछ और ही कह रहा था।

यह किसी से छुपा हुआ नहीं था कि यह चुनाव, भारत का अब तक का सबसे नाबराबरी का चुनाव था। यह एक ऐसा चुनाव था जिसमें बराबरी के मुकाबले की यह न्यूनतम से न्यूनतम शर्त भी पूरी नहीं हो रही थी कि चुनाव आयोग, जिस पर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व था, कम से कम निष्पक्ष दिखाई देने की कोशिश करेगा। इसका नतीजा यह हुआ कि एक ओर सत्ताधारी पार्टी, चुनावी मुकाबले में विपक्ष को पंगु करने के लिए, शासन के सभी दमनकारी साधनों का खुलेआम इस्तेमाल करते हुए, जिसमें विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने से लेकर विपक्षी पार्टियों के खाते जाम करना तक शामिल था, निष्पक्षता की धज्जियां उड़ा रही थी। तो दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी को अपने शीर्ष नेताओं से लेकर नीचे तक, विपक्ष के खिलाफ सरासर झूठे और सांप्रदायिक प्रचार को हथियार बनाने के जरिए, जनता के जानकारी पर आधारित चुनाव करने के अधिकार की जड़ें ही काटने की खुली छूट मिली हुई थी। इसके ऊपर से सत्ताधारी पार्टी को मुख्यधारा के मीडिया को न सिर्फ पैसे तथा मीडिया धन्नासेठों के समर्थन के बल पर अपने लिए छेक लेने का बल्कि तरह-तरह के सर्वेक्षणों के जरिए उसे मारक हथियार बनाने का और कुल मिलाकर बेशुमार पैसा बहाने तथा विपक्ष के संसाधनों के सारे स्रोत सुखाने का भी, मौका मिला हुआ था। इसके बावजूद, इस चुनाव में जनता ने जो फैसला सुनाया था, साफ तौर पर भाजपा के खिलाफ था।

बेशक, चार सौ पार के जो दावे सत्तापक्ष और उसके मीडिया में छाए प्रचारकों द्वारा विधिवत चुनाव प्रचार शुरू होने से महीनों पहले से शुरू कर, एक्जिट पोलों तक के जरिए किए जा रहे थे, उन सबके सामने, सत्ताधारी भाजपा का 240 के आंकड़े पर और सहयोगियों को भी जोड़कर, 292 के आंकड़े पर अटक जाना भी, किसी हार से कम नहीं था। लेकिन, बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इससे बड़ी बात यह थी कि जहां अकेले भाजपा के 370 पार और संगियों के साथ मिलकर चार सौ पार जाने का दम भरा जा रहा था, जब नतीजे आए भाजपा खुद 240 सीटों पर सिमट गयी और सहयोगियों के साथ मिलकर मुश्किल से बहुमत का आंकड़ा पार कर पायी। इतना ही नहीं, 2019 के चुनाव में भाजपा को जो 303 सीटें हासिल हुई थीं, उनमें पूरे 20 फीसद यानी 63 सीटों की कमी इस चुनाव में जनता ने कर दी और उसके गठजोड़ की सीटों में से भी करीब इतनी ही कमी। साफ है कि जनता ने पिछले चुनाव के मुकाबले, सत्ताधारी दल और उसके गठजोड़ को ठुकराया ही है, उसे अपनी करनियों और अकरनियों के लिए राजनीतिक सजा ही दी है।

इसी का एक और साक्ष्य, पिछले चुनाव के मुकाबले भाजपा और उसके गठजोड़ के मत प्रतिशत में भी बहुत ज्यादा न सही, फिर भी कुछ न कुछ गिरावट का ही होना है। खुद भाजपा के मत फीसद में यह गिरावट इसलिए और भी उल्लेखनीय हो जाती है कि 2024 में उसने तमिलनाडु, पंजाब जैसे राज्यों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हुए, पिछले चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर भी, पिछली बार के मुकाबले करीब 1 फीसद कम वोट हासिल किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2019 में भाजपा को 37.36 फीसद वोट मिला था, जो इस चुनाव में घटकर 36.56 फीसद ही रह गया है। इस चुनाव में सहयोगियों के साथ मिलकर भी सत्तापक्ष का मत फीसद 42.5 फीसद से ज्यादा नहीं बैठता है।

बेशक, यह कहा जा सकता है कि लोकसभा सदस्यों की गिनती के हिसाब जनादेश भाजपा के खिलाफ होने के बावजूद, गठबंधन के हिस्से के तौर पर तो भाजपा जनादेश का दावा कर ही सकती है। वास्तव में खुद नरेंद्र मोदी ने भी गठबंधन की आड़ लेकर ही, जनादेश का दावा करने की कोशिश की है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में अपने भाषण में नरेंद्र मोदी ने गठबंधन का ही सहारा लेकर यह दावा किया था कि ''न हम हारे थे, न हम हारे हैं!'' इसके लिए हाथ की सफाई का सहारा लेते हुए, मोदी ने यह दावा किया था कि 'किसी से पूछो कि पहले क्या था, एनडीए था, अब क्या है, एनडीए है', वही तब भी जीता था, वही अब भी जीता है, आदि। इसमें हाथ की सफाई अन्य बातों के अलावा इसमें थी कि 2024 के चुनाव के बाद, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम की जिन 16 और जनता दल यूनाइटेड की 12 सीटों के समर्थन के बल पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बहुमत का दावा किया जा रहा है, ये दोनों ही पार्टियां इस चुनाव के दौरान ही भाजपा द्वारा विशेष ऑपरेशन चलाकर, जिसमें विभिन्न रूपों में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल भी शामिल है, एनडीए में शामिल की गयी थीं। याद रहे कि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम् ने 2019 का चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ा था, जबकि जनता दल यूनाइटेड के सुप्रीमो नीतीश कुमार, 2024 के चुनाव के लिए ही बने इंडिया एलाइंस के सूत्रधारों में रहने के बाद, अचानक पल्टी खिलाकर भाजपा के पाले में ले आए गए थे। जाहिर है कि उनके समर्थन के बल पर 'एनडीए जीता था, एनडीए जीता है' का दावा करना, अर्द्धसत्य का ही सहारा लेना है।

एनडीए के संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी ने भले ही एनडीए के 30 साल की दुहाई दी हो, सच्चाई यह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद गुजरे दस साल में, एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में एनडीए कॉमा की अवस्था में ही पड़ा रहा है, जिसका होना न होने के बराबर ही रहा है। हां! विशेष मौकों पर नुमाइश के लिए जरूर पांच-पांच साल पर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। दूसरी ओर, सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी के राज में सभी स्तरों पर जिस तरह के सारी सत्ता का केंद्रीयकरण किया गया है, खुद सत्ताधारी भाजपा भी उससे बच नहीं पायी है, फिर उसके नेतृत्व में बने किसी बहुदलीय गठबंधन के बचे रह जाने का तो सवाल ही कहां उठता है। इसीलिए, हैरानी की बात नहीं है कि इन दस वर्षों में न तो मोदी की भाजपा ने एनडीए के किसी साझा कार्यक्रम की जरूरत समझी और न ही एनडीए की तालमेल समिति जैसे किसी निकाय की ही गुंजाइश छोड़ी है। हां! सत्ता के लाभों में थोड़ी-बहुत हिस्सेदारी की गाजर और केंद्रीय एजेंसियों का डंडा दिखाने के जरिए जरूर, उसने सहयोगी पार्टियों को साथ लगाए रखने की कोशिश की है।

इसीलिए, हैरानी की बात नहीं है कि इन दस वर्षों में शिव सेना, अकाली दल, तेलुगू देशम, जदयू, अन्नाद्रमुक आदि अनेक पार्टियां विभिन्न मुद्दों पर मोदी की भाजपा का साथ छोड़कर छिटक गयी हैं। वास्तव में मोदी के दूसरे कार्यकाल में तो, एनडीए का शायद ही कभी नाम भी लिया गया होगा। गठबंधन की किसी भी प्रकार की सामूहिकता के बजाए, इन पांच वर्षों में तो ''मोदी-मोदी'' और ''एक अकेला सब पर भारी '' की ही हवा बनायी जा रही थी। वह तो जब इंडिया गठबंधन से वास्तविक खतरा नजर आने लगा, तब इस गठबंधन के जवाब में अचानक मोदी की भाजपा को अपने गठबंधन की याद आ गयी और कॉमा में पड़े एनडीए को बाहर निकाल लाया गया। लेकिन, चूंकि इस एनडीए में सिर्फ गिनती के लिए गिनाए जा रहे संगठनों का कोई असर नहीं था, चुनाव की तैयारियों के बीच विशेष अभियान चलाकर जदयू, तेलुगू देशम् जैसी पार्टियों को दोबारा भाजपा के पाले में लाया गया।

इसलिए, एनडीए के नाम पर इन पार्टियों को जोड़-बटोर कर, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जरूरी गिनती तो जुटायी जा सकती है, लेकिन सत्ता की मलाई के लालच की गाजर और केंद्रीय एजेंसियों के डंडे के सहारे खड़ी की गयी यह एकता, ज्यादा दिन चल पाएगी इसमें संदेह की ही पूरी गुंजाइश है। इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी की भाजपा के तानाशाहाना मिजाज का, विभिन्न मुद्दों पर अपने से भिन्न नजरिया रखने वाली राजनीतिक पार्टियों के साथ सहमति तथा आम राय बनाकर चलने के मिजाज से मेल बैठ ही नहीं सकता है। ऐसे में मोदी की भाजपा, दूसरी पार्टियों को वास्तव में साथ लेकर चलने का लचीलापन दिखाने के बजाए, इन पार्टियों में तोड़-फोड़ कर के और खरीद-फरोख्त के जरिए, अपने अल्पमत को बहुमत में तब्दील करने की ही कोशिश करेगी, जिससे दूसरी पार्टियों के समर्थन पर निर्भरता की मजबूरी से मुक्त होकर अपनी मनमर्जी चला सके। और ठीक यही चीज तेलुगू देशम्, जदयू जैसी पार्टियों को, जिनके अपने राजनीतिक-समर्थन आधार कई मामलों में उन्हें मोदीशाही के खिलाफ भी करते हैं, जाहिर है कि खुद अपने ही राजनीतिक हितों के लिए, मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के खोखल को छोड़कर बाहर निकलने के लिए भी मजबूर कर सकती है। एनसीपी-अजित पवार के फिलहाल मंत्रिमंडल से बाहर ही बैठने से, शपथग्रहण के साथ ही कसमसाहट की।

(लेखक साप्ताहिक पत्रिका लोक लहर के संपादक हैं।)

नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक समय

■ जेम्स एम डोर्सी

नेतन्याहू की समस्या यह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री और उनके अति-राष्ट्रवादी और अति-रूढ़िवादी साझेदारों के साथ बाइडेन की हताशा का इजरायल के लिए अमेरिकी समर्थन की कीमत से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि संभवतः यह संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के बीच एक 'विशेष संबंध' में उभरते ऐतिहासिक बदलाव से अधिक है।

आने वाले एक या दो सप्ताह प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं और इज़रायल के गाजा युद्ध के लिए बाइडेन प्रशासन के समर्थन को नया आकार दे सकते हैं। यानी, अगर नेतन्याहू युद्ध कैबिनेट के सदस्य बेनी गैंट्ज़ की इस मांग को पूरा करने में विफल रहते हैं कि प्रधानमंत्री युद्ध के बाद के प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करें, तो उनके साथ युद्ध कैबिनेट के सदस्य और इज़राइल रक्षा बलों (आईडीएफ) के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ़गैबीईसेनकोट भी शामिल हो सकते हैं।

गैंट्ज़ के पास अपनी चेतावनी पर अड़े रहने के अच्छे कारण हैं। हाल ही में हुए एक इजरायली जनमत सर्वेक्षण से पता चलता है कि भले ही वह चुनाव जीत जायेंगे, लेकिन सरकार में उनकी मौजूदगी उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। सर्वेक्षण में गैंट्ज़ को 38प्रतिशत वोट मिले, जो जनवरी में उनके 46प्रतिशत के उच्चतम स्तर से कम है, जबकि नेतन्याहू के वोटों की संख्या छह महीने पहले के 24प्रतिशत से बढ़कर 30प्रतिशत हो गयी। हालांकि नेतन्याहू फिर भी चुनाव हार जायेंगे, लेकिन सर्वेक्षण से पता चलता है कि गैंट्ज़ अपनी लोकप्रियता को और जोखिम में डालने का जोखिम नहीं उठा सकते।

गैंट्ज़ क्या निर्णय लेते हैं, इस पर निर्भर करते हुए चार परिदृश्यों में से एक के सामने आने की संभावना है और संभवतः यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हमास और इजरायल दोनों पर दबाव बनाने के लिए कतर और मिस्र समर्थित युद्धविराम योजना की आधिकारिक घोषणा करने के निर्णय का हिस्सा था।

नेतन्याहू 24 जुलाई को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने तक युद्धविराम टाल सकते हैं। वह अपने सबसे उग्रवादी अति-राष्ट्रवादी और अति-रूढ़िवादी गठबंधन सहयोगियों को छोड़ सकते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमारबेनग्वीर और वित्त मंत्री बेज़ेलस्मोट्रिच करते हैं, जो युद्धविराम समझौते का विरोध करते हैं, जिससे हमास द्वारा बंधक बनाये गये लोगों की रिहाई होगी। इसके बजाय, नेतन्याहू गैंट्ज़, विपक्षी नेता यायरलैपिड और दो धार्मिक गठबंधन सहयोगियों, शास और यूनाइटेड टोरा यहूदी धर्मावलम्बी, जो युद्ध विराम और बंधक समझौते के पक्षधर हैं, के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं।

एक और संभावना यह है कि नेतन्याहू पासा पलट सकते हैं और गैंट्ज़ और ईसेनकोट के इस्तीफ़ा देने पर तुरंत चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। अंत में, गैंट्ज़ और ईसेनकोट इस्तीफ़ा दे सकते हैं, जिससे नेतन्याहू और भी ज़्यादा ज़िम्मेदार बन सकते हैं। बेनग्वीर और स्मोट्रिच ने युद्ध विराम वार्ता में नेतन्याहू के स्थान को सीमित करने की कोशिश की, क्योंकि उनके हज़ारों समर्थक 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में पूर्वी यरुशलम पर इज़राइल की विजय का जश्न मनाने के लिए यरुशलम के मुस्लिम क्वार्टर से यरुशलम ध्वज दिवस पर मार्च कर रहे थे।

मार्च में भाग लेते हुए, बेनग्वीर ने कहा कि इसने हमास को संदेश दिया कि 'यरूशलम हमारा है।' पुराने शहर के एक गेट का जिक्र करते हुए, जिसका मुस्लिम चार्टर हिस्सा है, और मंदिर पर्वत जो इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल अलअक्सा मस्जिद की मेज़बानी करता है, बेनग्वीर ने जोर देकर कहा कि 'दमिश्कगेट हमारा है। मंदिर पर्वत हमारा है, और, ईश्वर की इच्छा से, पूरी जीत हमारी है।'

उग्रवादी बेनग्वीर अनुयायियों ने फ़िलिस्तीनी निवासियों और पत्रकारों पर हमला किया, 'अरबों की मौत', 'तुम्हारा गांव जल जाये,' और 'शुआफ़त आग की लपटों में है' के नारे लगाये, जो पूर्वी यरुशलम के फ़िलिस्तीनी इलाके का संदर्भ था। गैंट्ज़-ईसेनकोटवॉक-आउट जो नेतन्याहू को बेनग्वीर और स्मोट्रिच पर और भी अधिक निर्भर बना देगा, रक्षा मंत्री गैलेंट पर दबाव बढ़ायेगा, ताकि वे भी ऐसा ही करें और इज़राइल के लिए बाइडेन के समर्थन को जटिल बना दें।

'मुझे पता है कि इज़राइल में ऐसे लोग हैं जो इस योजना से सहमत नहीं होंगे और युद्ध को अनिश्चित काल तक जारी रखने का आह्वान करेंगे' कुछ तो सरकारी गठबंधन में भी हैं। और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है: वे गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं, वे वर्षों तक लड़ते रहना चाहते हैं, और बंधक उनके लिए प्राथमिकता नहीं हैं... मैंने इजरायल के नेतृत्व से इस सौदे के पीछे खड़े होने का आग्रह किया है, चाहे जो भी दबाव आये,' बाइडेन ने अपने प्रस्तावित युद्धविराम सौदे को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो नेतन्याहू द्वारा समर्थित एक मसौदे पर आधारित प्रतीत होता है। वास्तव में, बाइडेन नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे थे कि वे ऐसी स्थिति की अनुमति न दें जिसमें वे बेनग्वीर और स्मोट्रिच पर अपनी निर्भरता कम करने के बजाय उसे बढ़ायें।

साथ ही, इजरायली विश्लेषकों का सुझाव है कि नेतन्याहू के दिमाग में, प्रधानमंत्री और गैलेंट के युद्ध अपराध के आरोपों पर गिरफ्तारी के लिए संभावित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) वारंट गाजा युद्ध की निरंतरता को एक परिसंपत्ति के बजाय एक दायित्व में बदल रहा है जो सुनिश्चित करेगा कि वह पद पर बने रहें।

संयुक्त राज्य अमेरिका और 16 अन्य देश जिनके नागरिकों को 7अक्टूबर को हमास द्वारा बंधक बनाया गया था, ने नेतन्याहू पर दबाव बढ़ा दिया और एक संयुक्त बयान जारी किया जिसमें इजरायल और हमास से युद्धविराम समझौता करने का आह्वान किया गया। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसमें नेतन्याहू संभावित रूप से एक चौराहे पर हैं, ने बाइडेन की युद्धविराम योजना का समर्थन करने वाले प्रस्ताव पर चर्चा करने में देरी की है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरू में योजना के समर्थन में एक मसौदा प्रस्ताव प्रसारित किया था, जिसे वीटो किये जाने की संभावना थी क्योंकि इसने स्वीकृति का भार हमास पर डाल दिया था। ऐसा करना अधिक कठिन होगा क्योंकि इजरायल सरकार में अधिकांश 'वयस्क' नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल के प्रति अपने अड़ियल समर्थन के कारण कम असुरक्षित है, जैसा कि कई लोग मानते हैं। नेतन्याहू को लग सकता है कि वह अपने कांग्रेस के भाषण का उपयोग करके गैंट्ज़ और ईसेनकोट के जाने से होने वाले किसी भी परिणाम से बच सकते हैं।

नेतन्याहू शायद सही हों कि संयुक्त राज्य अमेरिका को शब्दों के बजाय कामों से इज़राइल पर शिकंजा कसने के लिए कम दबाव महसूस होता है। निश्चित रूप से, यूक्रेन और गाजा युद्धों के प्रति अपने दृष्टिकोण में कथित दोहरे मानकों के कारण अमेरिका ने नैतिक स्थिति खो दी है। मानवाधिकारों और कानून के शासन का प्रचार करने वाले अमेरिकी राजनयिकों को शायद ही हंसी में उड़ाया जायेगा।

फिर भी, खाड़ी के देश और कई एशियाई देश अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका को शहर में एकमात्र सुरक्षा खेल के रूप में देखते हैं। इसके अलावा, इज़राइल के समर्थन से संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्थिक रूप से बहुत कम नुकसान हुआ है, सिवाय स्टारबक्स जैसी खाद्य फ्रेंचाइज़ी के, जिन्हें कई मध्य पूर्वी देशों में बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है।

बाइडेन प्रशासन, इज़राइली रक्षा मंत्री योवगैलेंट और वरिष्ठ इज़राइली सैन्य कमांडर गैंट्ज़ की निराशा को साझा करते हैं। फिर भी, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित प्रौद्योगिकी पर चीन की तुलना में अमेरिका के साथ सहयोग करना पसंद करते हैं। इसने खाड़ी देशों को चीनी प्रौद्योगिकी में निवेश करने से नहीं रोका है।

यूनाइटेड अरब अमीरात की जी 42 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होल्डिंग कंपनी ने अप्रैल में माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की थी, जिसके बाद उसने अमेरिकी वाणिज्य विभाग के उद्योग और सुरक्षा ब्यूरो के साथ सहमति जताई थी कि वह चीन में अपनी उपस्थिति कम करेगी या फिर उसे दंडात्मक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।

नेतन्याहू की समस्या यह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री और उनके अति-राष्ट्रवादी और अति-रूढ़िवादी साझेदारों के साथ बाइडेन की हताशा का इजरायल के लिए अमेरिकी समर्थन की कीमत से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि संभवतः यह संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के बीच एक 'विशेष संबंध' में उभरते ऐतिहासिक बदलाव से अधिक है।

पावन प्रसंग

संस्कृत भाषा की उपादेयता

संस्कृत दिव्य समृद्ध भाषा है। ऐतिहासिकता की दृष्टि से यह संसार को सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत संसार की प्राचीनतम एवं प्रथम भाषा है। भारतीय आर्प ग्रंथ का समस्त ज्ञान इसी भाषा में लिपिबद्ध है। संस्कृत ज्ञान की अभिव्यक्ति की भाषा है। भारत की आत्मा संस्कृत है। यदि आज के पाठ्यक्रम के साथ संस्कृत का संबंध स्थापित कर लिया जाए तो संस्कृत परिवर्द्धित होगी। संस्कृत में जोड़ने की शक्ति है, इसीलिए इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सन् 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संस्कृत शिक्षा का एक अविभाज्य भाग होना चाहिए।

सृष्टि के आदिकाल में हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, वह ज्ञान आज भी विश्व में स्वीकृत प्राचीनतम ज्ञानग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ गृहस्थ जीवन और समस्त संस्कारों का आधार है। दर्शन शास्त्र सत्यासत्य का निर्णायक है। जबकि व्याकरण शास्त्र कुंजी है। रामायण भारतीय मर्यादा का प्रतीक है। गीता कर्ममय ज्ञान का उपदेश देती है तो मनुस्मृति व्यवस्थित शासन व आत्मानुशासन की संस्थापक है। आयुर्वेद समस्त प्राणियों को आरोग्य प्रदान करने वाला है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजसत्ता को विधिसम्मत बनाता है। भारत का यह सारा अमृततुल्य ज्ञान जिस भाषा में व्यक्त हुआ वह संस्कृत है। जहां विश्व के दूसरे देश भारत के इस अमरत्व को जानने के लिए संस्कृत भाषा और साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं वहीं विडम्बना यह है कि अपने देश में संस्कृत को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।

20वीं सदी से संस्कृत के अध्ययन में कमी आई है। 2011 जनगणना के अनुसार 14,135 व्यक्तियों ने संस्कृत भाषा को अपनी मातृभाषा माना है। 1991 में 49,736 लोग संस्कृत को अपने मातृभाषा मानते थे। 1991 से 2001 के बीच ऐसे लोगों की संख्या में 71,58 फीसदी की कमी आई है। उत्तर प्रदेश में संस्कृत बोलने और समझने वालों की संख्या सर्वाधिक है। आज कोई संस्कृत पढ़ना नहीं चाहता। इसे केवल कर्मकांड और पूजा-पाठ की भाषा माना जा रहा है। वर्तमान समय में संस्कृत की उपयोगिता हमारे देश में कम और विदेशों में ज्यादा है। अमेरिका के लगभग हर विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। अमेरिका में बच्चों को बचपन से ही संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। हम अंगरेजी को सर्वाधिक महत्व देते हैं। यह हमारे पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण का परिणाम है अन्यथा जो स्थान संस्कृत का था, वह अंगरेजी का कैसे हो गया ?

जब दुनिया का हर देश अपनी भाषा में बात करता है तो क्यों हम अपनी भाषा को समाप्त करने पर तुले हुए हैं। हम बड़ा बनने की बात करते हैं, पर श्रेष्ठ मानव बनना भूलते जा रहे हैं। हमारे नीति-निर्माताओं की दृष्टि और सोच इस विषय की ओर जाना चाहिए।

अखंड ज्योति

आपके पत्र

एआई संचालित प्रयोगशाला की बड़ी उपलब्धि

एक हालिया उपलब्धि में कृत्रिम बुद्धि (एआई) द्वारा प्रबंधित स्वचालित प्रयोगशालाओं की एक टीम ने ऐसे पदार्थ की खोज करने में सफलता प्राप्त की है जो अत्यंत कार्य-कुशलता से लेज़र उत्पन्न करता है। साइंस जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस विशिष्ट उपलब्धि से लगता है कि एआई संचालित प्रयोगशालाएं अनुसंधान के कुछ क्षेत्रों में मानव वैज्ञानिकों को पछाड़ सकती हैं, खासकर वे ऐसी खोज कर सकती हैं जो मनुष्यों की नज़रों से चूक गई हों।

दरअसल, नए अणु और सामग्री बनाने के पारंपरिक तरीके अक्सर धीमे और श्रम-साध्य होते हैं। शोधकर्ताओं को कई विधियों से और अभिक्रिया की कई स्थितियों में प्रयोग करना पड़ता है, प्रत्येक चरण में नए यौगिकों के साथ वही परीक्षण दोहराना पड़ता है और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उनकी क्षमता का मूल्यांकन करना होता है।

पिछले दशक से इनमें से कई तरह की अभिक्रियाओं को दोहराने का काम रोबोट्स ने संभाल लिया है। मसलन 2015 में, इलिनॉय युनिवर्सिटी के रसायनज्ञ मार्टिन बर्क द्वारा छोटे अणुओं के संश्लेषण के लिए एक स्वचालित प्रणाली शुरू की गई थी। इस प्रणाली में एआई को शामिल करने से फीडबैक लूप तैयार किया जा सका जिससे नई विशेषता वाले यौगिकों का डैटा भविष्य के संश्लेषण प्रयासों का मार्गदर्शन कर सकता है। इस आधार पर, बर्क और टोरंटो विश्वविद्यालय के रसायनज्ञ एलन असपुरु-गुज़िक ने समन्वित रूप से काम करने वाली स्व-चालित प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की कल्पना की। उन्होंने कई प्रयोगशालाओं - दक्षिण कोरिया के इंस्टीट्यूट फॉर बेसिक साइंस, ग्लासगो विश्वविद्यालय, ब्रिटिश कोलंबिया युनिवर्सिटी (यूबीसी) और जापान की क्यूशू युनिवर्सिटी की प्रयोगशाला - को जोड़ा। प्रत्येक प्रयोगशाला की संश्लेषण की प्रक्रिया में अपनी विशेषज्ञता थी। लक्ष्य था अत्यधिक शुद्ध लेज़र प्रकाश उत्सर्जित करने में सक्षम कार्बनिक यौगिकों की खोज करना। इससे उन्नत किस्म के डिस्प्ले और दूरसंचार तंत्र स्थापित करने में मदद मिलेगी।

सबसे पहले ग्लासगो और यूबीसी प्रयोगशालाओं ने थोड़ी मात्रा में आधारभूत सामग्री का निर्माण किया। फिर इन्हें बर्क और असपुरु-गुज़िक की टीमों को भेजा गया, जहां रोबोट ने इन पदार्थों से विभिन्न संयोजन (मिश्रण) बनाए। इन संभावित उत्सर्जकों को टोरंटो प्रयोगशाला भेजा गया, जहां अन्य रोबोट ने उनके प्रकाश उत्सर्जक गुणों का मूल्यांकन किया। सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले उत्सर्जकों को यूबीसी भेजा गया, जहां यह पता किया गया कि बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए इन पदार्थों का संश्लेषण और शोधन कैसे किया जाएगा, और फिर इन्हें व्यावहारिक लेज़रों में परिवर्तित करने और उसके परीक्षण के लिए क्यूशू विश्वविद्यालय भेजा गया।

इस पूरी प्रक्रिया को क्लाउड-आधारित एआई प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया गया था, जिसे मुख्य रूप से टोरंटो और दक्षिण कोरिया की टीमों द्वारा विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म ने प्रत्येक प्रयोग से सीखा और अगली पुनरावृत्तियों में फीडबैक को शामिल किया, जिससे एक कुशल और फुर्तीली शोध प्रक्रिया विकसित हुई।

इस सहयोगी प्रयास से 621 नए यौगिक तैयार हुए, जिनमें 21 ऐसे थे जो अत्याधुनिक लेज़र उत्सर्जकों से मेल खाते थे और एक तो ऐसा था जो किसी भी अन्य ज्ञात कार्बनिक पदार्थ की तुलना में अधिक कुशलता से नीले रंग की लेज़र रोशनी उत्सर्जित करता था।

गौरतलब है कि हाल ही में मिली सफलता एआई-संचालित प्रयोगशाला अनुसंधान में एकमात्र सफलता नहीं है। पिछले साल, मिलाद अबुलहसानी की प्रयोगशाला ने रिकॉर्ड-सेटिंग फोटोल्यूमिनेसेंस के साथ नैनोकणों का निर्माण किया था।

एआई के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए बर्क को उम्मीद है कि स्वचालन और एआई में प्रगति वैश्विक स्तर पर अधिक प्रयोगशालाओं को सहयोग करने में सक्षम बनाएगी। इस तरह की साझेदारी वैज्ञानिकों को ढर्रा कार्यों से मुक्त करेगी, ताकि वे अनुसंधान के अधिक जटिल और रचनात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। **(स्त्रोतफीचर्स)**

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बाल-श्रम की अंधी गलियों में बेहाल बचपन कब तक?

-ललित गर्ग

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस- 12 जून, 2024

पूरी दुनिया में बाल श्रम एक ज्वलंत समस्या है, कैसा विरोधाभास है कि हमारा समाज, सरकार और राजनीतिज्ञ बच्चों को देश का भविष्य बताते हुए नहीं थकते लेकिन क्या इस उम्र के लगभग 25 से 30 करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी के जरिए उनका बचपन और उनसे पढने का अधिकार छीनने का यह सुनियोजित षड्यंत्र नहीं लगता? बचपन इतना डरावना एवं भयावह हो जायेगा, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर क्या कारण है कि बचपन अपराध एवं बाल श्रम की अंधी गलियों में जा रहा है? बचपन इतना उपेक्षित क्यों हो रहा है? बचपन के प्रति न केवल अभिभावक, बल्कि समाज और सरकार इतनी बेपरवाह कैसे हो गयी है? यह प्रश्न विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हुए हमें झकझोर रहे हैं। पूरी दुनिया में प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की पहल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने की थी, जिसका मकसद बाल श्रम को रोकना था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2024 की आधिकारिक थीम है- ह्यआइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें- बाल श्रम समाप्त करें!ह्व यह दिन जागरूकता बढ़ाने, परिवर्तन की वकालत करने तथा बाल श्रम से मुक्त भविष्य की दिशा में योगदान देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

मालूम हो कि इसको मनाने के पीछे एक खास वजह यह थी कि बच्चों को मजदूरी न कराकर उनको स्कूलों की ओर शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके। मालूम हो कि बाल श्रम लगातार एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिसके कारण बच्चों का बचपन गर्त में जा रहा है और उनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उनका यह बचपन रूपी भविष्य आज बाल श्रम के कारण नशे, अपराध एवं जटिलताओं की दुनिया में धंसता चला जा रहा है। जब हम किसी गली, चौराहे, बाजार, सड़क और हाईवे से गुजरते हैं और किसी दुकान, कारखाने, रैस्टोरैंट या ढाबे पर 12-14 साल के बच्चे को टायर में हवा भरते, पंक्चर लगाते, चिमनी में मुंह से या नली में हवा फूंकते, जूठे बर्तन साफ करते, गारा उठाते, या खाना परोसते देखते हैं और जरा-सी भी कमी होने पर उसके मालिक से लेकर ग्राहक द्वारा गाली देने से लेकर, धकियाने, मारने-पीटने और दुर्व्यवहार होते देखते हैं तो अक्सर ह्यहमें क्या लेना हैह्व या ज्यादा से ज्यादा मालिक से दबे शब्दों में उस मासूम पर थोड़ा रहम करने के लिए कहकर अपने रास्ते हो लेते हैं। लेकिन कब तक हम बचपन को इस तरह प्रताड़ित एवं उपेक्षा का शिकार होने देंगे।

बचपन से जुड़ी इस त्रासद एवं दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों पर नियंत्रण के लिये, बाल श्रम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन एवं सरकारी संगठनों को प्रेरित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, पिछले दो दशकों से पूरी दुनिया में बाल श्रम को कम करने के लिए लगातार पहल की जा रही है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों के दौरान संघर्षों, संकटों और कोरोना महामारी ने विश्व में कई परिवारों को गरीबी में धकेल दिया है, जिसके कारण लाखों बच्चों को बाल श्रम के लिए मजबूर होना पड़ा है। आज का बालक ही कल के समाज का सृजनहार बनेगा। बालक का नैतिक रूझान व अभिरूचि जैसी होगी निश्चित तौर पर भावी समाज भी वैसा ही बनेगा। आज दुनिया में 160 मिलियन बच्चे अभी भी बाल श्रम में लगे हुए हैं। यह दुनिया भर में लगभग दस में से एक बच्चा है। बाल श्रम के मामले में अफ्रीका सभी क्षेत्रों में सबसे ऊपर है। अफ्रीका और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में दुनिया भर में बाल श्रम में लगे हर दस बच्चों में से लगभग नौ बच्चे बाल-श्रमिक हैं। शेष बाल श्रमिक आबादी अमेरिका (11 मिलियन), यूरोप और मध्य एशिया (6 मिलियन) और अरब राज्यों (1 मिलियन) में विभाजित है। जबकि बाल श्रम में बच्चों का प्रतिशत निम्न आय वाले देशों में सबसे अधिक है, वास्तव में उनकी संख्या मध्यम आय वाले देशों में अधिक है। निम्न-मध्यम आय वाले देशों में 9 प्रतिशत बच्चे और उच्च-मध्यम आय वाले देशों में 7 प्रतिशत बच्चे बाल श्रम में हैं।

पिछले कुछ वर्षों में बाल श्रम को कम करने में बहुत प्रगति हुई है, हाल के वर्षों में वैश्विक रुझान उलट गए हैं और अब पहले से कहीं अधिक यह महत्वपूर्ण है कि सभी रूपों में बाल श्रम को समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए मिलकर काम किया जाए। 2022 में बाल श्रम के उन्मूलन पर 5वें वैश्विक सम्मेलन के बाद प्रतिनिधियों द्वारा अपनाई गई डरबन कॉल टू एक्शन रास्ता दिखाती है। अब बाल श्रम के उन्मूलन को वास्तविकता बनाने का समय आ गया है। मालूम हो कि बाल श्रम का प्रमुख कारण गरीबी है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई छोड़कर मजबूरी में मजदूरी का रास्ता चुनना पड़ता है। हालांकि, कई बच्चों को अपराध रैकेट द्वारा बाल श्रम के लिए मजबूर किया जाता है। भारत की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार तो लगभग 5 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। इन बाल श्रमिकों में से 19 प्रतिशत के लगभग घरेलू नौकर हैं, ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों में तथा कृषि क्षेत्र से लगभग 80 प्रतिशत जुड़े हुए हैं। शेष अन्य क्षेत्रों में, बच्चों के अभिभावक ही बहुत थोड़े पैसों में उनको ऐसे ठेकेदारों के हाथ बेच देते हैं जो अपनी व्यवस्था के अनुसार उनको होटलों, कोठियों तथा अन्य कारखानों आदि में काम पर लगा देते हैं। उनके नियोक्ता बच्चों को थोड़ा सा खाना देकर मनमाना काम कराते हैं। 18 घंटे या उससे भी अधिक काम करना, आधे पेट भोजन और मनमाफिक काम न होने पर पिटाई यही उनका जीवन बन जाता है। केवल घर का काम नहीं इन बालश्रमिकों को पटाखे बनाना, कालीन बुनना, वेल्डिंग करना, ताले बनाना, पीतल उद्योग में काम करना, कांच उद्योग, हीरा उद्योग, माचिस, बीड़ी बनाना, खेतों में काम करना (बैल की तरह), कोयले की खानों में, पत्थर खदानों में, सीमेंट उद्योग, दवा उद्योग में तथा होटलों व ढाबों में झूठे बर्तन धोना आदि सभी काम मालिक की मर्जी के अनुसार करने होते हैं। इन समस्त कार्यों के अतिरिक्त कूड़ा बीनना, पोलीथिन की गंदी थैलियाँ चुनना, आदि अनेक कार्य हैं जहाँ ये बच्चे अपने बचपन को नहीं जीते, नरक भुगतते हैं परिवार का पेट पालते हैं। इनके बचपन के लिए न माँ की लोरियां हैं न पिता का दुलार, न खिलौने हैं, न स्कूल न बालदिवस। इनकी दुनिया सीमित है तो बस काम काम और काम, धीरे धीरे बीड़ी के अधजले टुकड़े उठाकर धुआं उडाना, यौन शोषण को खेल मानना इनकी नियति बन जाती है। इन कमजोर नींवों पर हम कैसे एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर हकीकत में हम उन्हें पैसा कमाकर लाने की मशीन बनाकर अंधकार में धकेल रहे हैं। बचपन बचाओ आंदोलन, चाइल्ड फंड, केयर इंडिया, तलाश एसोसिएशन, चाइल्ड राइट्स और ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर आदि संस्थाओं ने बाल श्रम खत्म करने की दिशा में सार्थक पहल की है।

बाल मजदूरी से बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता ही है, देश भी इससे अछूता नहीं रहता क्योंकि जो बच्चे काम करते हैं वे पढ़ाई-लिखाई से कोसों दूर हो जाते हैं और जब ये बच्चे शिक्षा ही नहीं लेंगे तो देश की बागडोर क्या खाक संभालेंगे? इस तरह एक स्वस्थ बाल मस्तिष्क विकृति की अंधेरी और संकरी गली में पहुँच जाता है और बाल-श्रमिक एवं अपराधी की श्रेणी में उसकी गिनती शुरू हो जाती हैं। ऐसा न हो इसके लिए आवश्यक है कि अभिभावकों और बच्चों के बीच बर्फ-सी जमी संवादहीनता एवं संवेदनशीलता को फिर से पिघलाया जाये। फिर से उनके बीच स्नेह, आत्मीयता और विश्वास का भरा-पूरा वातावरण पैदा किया जाए। सरकार को बच्चों से जुड़े कानूनों पर पुनर्विचार करना चाहिए एवं बच्चों के समुचित विकास के लिये योजनाएं बनानी चाहिए। ताकि इस बिगड़ते बचपन और भटकते राष्ट्र के नव पीढ़ी के कर्णधारों का भाग्य और भविष्य उज्ज्वल हो सकता है।

सावधान! जरा संभलिए, मोबाइल देकर बच्चों के दुश्मन बन रहे हैं आप

अशोक भाटिया

छोटे बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन थमाना इन दिनों आम बात हो गई है। बच्चों की जरा-सी शैतानी और रोने पर अभिभावक उनके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। गेम लगाकर या फिर यूट्यूब पर वीडियो चलाकर बच्चों को दे देते हैं ताकि वे मोबाइल पर रमे रहें। लेकिन इस बीच अभिभावक यह भूल जाते हैं कि छोटे बच्चों के लिए मोबाइल जितना मनोरंजन का साधन है, उससे कई ज्यादा खतरनाक भी है। स्मार्टफोन से निकलने वाली खतरनाक रेडिएशन बच्चों की परवरिश पर असर डालती हैं। ये खतरनाक किरणें, बच्चों को कई तरह की बीमारियां भी दे सकती हैं। कई बच्चें वीडियो गेम खेलने के आदि हो जाते हैं जिससे मानसिक तनाव पैदा हो जाता है।

बच्चों में इसकी बढ़ती सहज उपलब्धता समय के साथ भयानक रूप लेती जा रही है। इतनी भयानक कि जिस उम्र के बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है वह हैवान और कातिल तक बनते जा रहे हैं।कुछ ऐसा ही घटना कुछ समय पूर्व छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में ,जहां मोबाइल फोन छीने जाने से नाराज बच्चे ने फांसी लगा ली । दिल्ली में कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई कर रही थी. घटना के दौरान माता-पिता व दूसरा भाई हिमांशु शादी में यूपी के गोरखपुर गए थे. घर पर बहन-भाई प्रयांशु और अनन्या थे. बड़ी बहन अनन्या ने प्रियांशु को फोन छोड़कर पढ़ाई करने के लिए कहा तो उसको गुस्सा आ गया और उसने गला दबाकर अपनी बहन की हत्या कर दी. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोबाइल गेम खेलने से रोकने के कारण 16 साल के बच्चे ने अपनी मां की ही हत्या कर दी। न सिर्फ हत्या की बल्कि शव को दो दिनों तक घर में छिपाकर भी रखा। इस तरह की आपराधिक मानसिकता किसी बच्चे में कैसे विकसित हो सकती है, यह निश्चित ही गंभीर और चिंताजनक बात है। ये कोई अकेली घटनाए भी नहीं है, कई अन्य देशों की रिपोर्ट उठा कर देख लीजिए तो इसी तरह के दर्जन भर से अधिक मामले देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इस तरह की मानसिकता के पीछे का कारण क्या है? क्या खुद के लिए थोड़ा समय निकालने के चक्कर में हम बच्चों के हाथ में उनके ही विनाश की चाभी थमा रहे है?

इन घटनाओं के पीछे के कारणों के बारे में पता चलता है कि बच्चा मोबाइल गेम का लती हो चुका थे । इससे पहले भी कई गेम्स के कारण भी कई जानलेवा मामले सामने आ चुके हैं। सारा ठीकरा इन्हीं पर क्यों फोड़ना, इंटरनेट-मोबाइल में इसी तरह के और भी कई गेम्स हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से आक्रामक प्रवृत्ति विकसित करने वाला माना जाता है, इतना आक्रामक कि बच्चा किसी की जान तक ले ले।

मोबाइल गेम्स की लत ने बच्चों के स्वभाव को आपराधिक और गुस्सैल बना दिया है। वैश्विक स्तर पर गेम के कारण जानलेवा प्रवृत्ति के कई मामले देखने के मिले हैं। इसी साल जनवरी में मोबाइल गेम की लत वाले एक बच्चे ने अपनी मां सहित 3 भाई-बहनों की हत्या कर दी थी। वाशिंगटन में भी इसी तरह के मामले देखे गए। भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे मामले अक्सर रिपोर्ट किए जाते रहे हैं। सितंबर 2019 में कर्नाटक में 21 साल के नवयुवक ने अपने पिता की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उन्होंने मोबाइल गेम खेलते समय मोबाइल छीन लिया था। जुलाई 2021 में इसी तरह बंगाल में मोबाइल गेम को लेकर हुई बहस में एडिक्टेड युवक ने अपने भाई की हत्या कर दी थी। ऐसे कइयों मामले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बच्चों में मोबाइल फोन्स की बढ़ती सहज उपलब्धता और आक्रामक गेम्स की लत काफी गंभीर रूप लेती जा रही है। पीएमसी जर्नल में में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि मोबाइल गेम की लत, हत्या और आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि किशोरों और वयस्कों में मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह की स्थिति हो सकती है। इस तरह के वीडियोगेम्स पर दिन में कई घंटे बिताना मस्तिष्क की प्रवृत्ति को इस खेल के रूप में परिवर्तित करती जाती है। ऐसे गेम्स आक्रामकता को बढ़ावा देते हैं ऐसे में इसकी लत गंभीर हो सकती है। मोबाइल गेम्स के कारण बढ़ते आक्रामक व्यवहार के बारे में मनोचिकित्सकों का कहना है कि बालपन-युवावस्था में हम जिस तरह की चीजों का अधिक देखते, सुनते और पढ़ते हैं, उसका दिमाग पर सीधा असर होता है। मोबाइल गेम्स के साथ भी यही मामला है। ये लत का कारण बन जाते हैं और एडिक्शन के कोर में व्यावहारिक परिवर्तन प्रमुख होता है। अगर घरवाले इसे अचानक से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो यहां विड्रॉल की स्थिति में आ जाती है, उसी तरह जैसे अल्कोहल विड्रॉल होता है जिसमें अगर किसी शराबी से अचानक शराब छुड़वाई जाए तो उसके व्यवहार में आक्रामक परिवर्तन हो सकता है। मनोचिकित्सक कहते हैं, बच्चे में 'ऑब्जर्वेशन लर्निंग' की क्षमता अधिक होती है। बच्चे स्वाभाविक रूप से किसी चीज को समझने से ज्यादा चीजों को देखकर सीखने में अधिक निपुड़ता वाले होते हैं। ऐसे में अगर बच्चे का समय मोबाइल फोन्स पर अधिक बीत रहा है, साथ ही वह हिंसक गेम्स पर अधिक समय बिता रहे हैं तो इसका सीधा असर मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मोबाइल-वीडियो गेम्स का नेचर बच्चों को और प्रभावित करता है क्योंकि गेम खेलते समय आपका पूरा ध्यान टास्क पर होता है। ऐसे में अगर इसकी प्रवृत्ति हिंसात्मक, मार-पीट, गोली-बारी वाली है तो यह बच्चे के दिमाग को उसी के अनुरूप परिवर्तित करने लगती है।

रोज घंटों मोबाइल में इस तरह के गेम्स पर समय बिताने से बच्चों में इसकी लत लग जाती है। लत का मतलब, उस गेम के बिना वह रह नहीं पाते, इस दौरान जो भी उन्हें उस गेम से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है, वह बच्चों का दुश्मन बन जाता है। इस तरह के विकारों से बच्चों को मुक्त रखने के लिए माता-पिता को बच्चों की मॉनिटरिंग करते रहना जरूरी हो जाता है। आप देखिए कि बच्चे कि तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह के गेम्स खेल रहे हैं, उनका दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है? मोबाइल फोन्स से बच्चों की बढ़ती दोस्ती को स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बेहद अस्वास्थ्यकर मानते हैं। यह न सिर्फ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक आदत है साथ ही इससे शारीरिक समस्याओं का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। बच्चों के मोबाइल फोन्स पर अधिक समय बिताने की आदत को स्वास्थ्य विशेषज्ञ कई प्रकार से हानिकारक मानते हैं। मोबाइल फोन पर बहुत अधिक समय बिताने के कारण बच्चों में शारीरिक निष्क्रियता बढ़ती जाती है, जो मोटापा और अन्य आंतरिक स्वास्थ्य जटिलताओं के जोखिम को बढ़ाती है। इसके अलावा अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल के अनुसार, मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। मोबाइल फोन्स की लत को अध्ययनों में विशेषज्ञ कैंसर, मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव, ट्यूमर जैसी समस्याओं को बढ़ावा देने वाला मानते हैं।

इसके अलावा मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने वाले बच्चों में नींद की कमी और नींद की गुणवत्ता में गिरावट जैसी दिक्कतें अधिक देखने को मिली हैं। शोध से पता चलता है कि सेल फोन की नीली रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन में बाधा डालती है। मेलाटोनिन वह हार्मोन है जो नींद-जागने के चक्र को नियंत्रित करता है (जिसे सर्केडियन रिदम भी कहा जाता है)। जब यह हार्मोन असंतुलित हो जाता है, तो इसके कारण नींद संबंधित विकारों की शिकायत बढ़ जाती है। नींद की कमी को अध्ययनों में कई प्रकार के गंभीर रोगों का कारक माना जाता है। बच्चों सहित सभी आयुवर्ग के लोगों में बढ़ते मोबाइल के इस्तेमाल को विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफी हानिकारक मानते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पहले के समय में बच्चे बाहर खेलते थे, प्रकृति के साथ जुड़ाव था, एक दूसरे से मिलते थे। वहीं अब मोबाइल ने इन सभी आदतों को सीमित कर दिया है लिहाजा बच्चों में कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं विकसित होने लगी हैं।

किसी भी चीज की लत मस्तिष्क के रसायनों को प्रभावित करती है, इसी तरह मोबाइल की लत के कारण बच्चों में डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर से संबंधित विकार बढ़ रहे हैं। डोपामाइन एक न्यूरोकेमिकल संदेशवाहक है, यह आपको रिवार्ड फील कराने वाले अनुभव देने में मददगार है। मोबाइल ने इस संदेशवाहक की गतिविधि को प्रभावित कर दिया है। यही कारण है कि एक दशक के पहले के बच्चों की तुलना में अब के बच्चे ज्यादा आक्रामक, झगड़ालू, सुस्त और बात-बात पर परेशान और चिड़चिड़े प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर बताते हैं, माता-पिता थोड़ा आराम करने, बच्चों को कुछ खिलाने या बच्चों को व्यस्त रखने के चक्कर में मोबाइल थमा देते हैं। यह बच्चों की धीरे-धीरे लत बनती जाती है, ऐसी लत जिसके बिना बच्चे रह ही नहीं पाते। आपको पता भी नहीं चलता कि आपने थोड़ा आराम पाने के चक्कर में बच्चों के हाथ में विनाश की चाभी थमा दी है। मोबाइल ने बच्चों की सहज प्रकृति को जैसे खत्म सा कर दिया है। बच्चे, बच्चे कम प्रौढ़ ज्यादा होते जा रहे हैं। मसलन हमने अपने थोड़े से आराम के चक्कर में बच्चों से उनके बचपन को छीन लिया है, इसके नतीजे आए दिन सामने आते रहते हैं। प्रकृति ने हर उम्र के आधार पर सजह कार्य निर्धारित किए हैं। बच्चों का स्वभाव बाहरी वातावरण से जुड़ना, अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना-दोस्त बनाने वाला होता है। मोबाइल ने इन सब को खत्म कर दिया है। आज के बच्चों के लिए लोगों के बीच खुद को ढालना कठिन हो गया है, वह दूसरों से बात नहीं कर पाते, प्रकृति और मिट्टी से दूर हो गए हैं, यह भविष्य के लिए जरा भी सुखद नहीं है। समय के साथ इसके दुष्परिणाम बढ़ते जाएंगे।

बाल श्रम पर लगे लगाम

-रमेश सर्राफ धमोरा

12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर विशेष

किसी देश के बच्चे अगर शिक्षित और स्वस्थ्य होंगे तो वह देश उन्नति और प्रगति करेगा और देश में खुशहाली आयेगी। लेकिन अगर बच्चे बचपन से ही किताबों को छोड़कर कल-कारखनों में काम करने लगेंगे तो देश समाज का भविष्य उज्ज्वल नहीं होगा। इसीलिये बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। देश में आज भी करोड़ों बच्चे स्कूलों की बजाए कल-कारखानों, ढाबों और खतरनाक कहे जाने वाले उद्योगों में कार्य कर रहे हैं. जहां दो पेट के भोजन की शर्त पर उनका बचपन और भविष्य तबाह हो रहा है।

बाल श्रम लगातार एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। जिसके कारण बच्चों का बचपन गर्त में जा रहा है और उनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है। यह दिवस बाल श्रम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन एवं सरकारी संगठनों को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। इस साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का थीम आइए अपनी मांगों पर कार्य करें बाल श्रम समाप्त करें! इस दिन जागरूकता बढ़ाने, बदलाव की पहल करने और बाल श्रम से मुक्त भविष्य की दिशा में योगदान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।

संयुक्त राष्ट्र ने बाल श्रम पर कहा है कि पिछले तीन दशकों के इस समस्या से निपटने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, अगर मूल कारणों को दूर कर दिया जाए तो बाल श्रम को खत्म किया जा सकता है। बाल मजदूरी उन्मूलन के लिए दुनिया भर में 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जा रहा है। बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस काम से निकालकर उन्हें शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से साल 2002 में द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन की ओर से इस दिवस की शुरूआत की गई थी। बाल श्रम के खात्मे के लिए आज के दिन श्रमिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन और सरकारें तमाम आयोजन करती हैं। इन सबके बावजूद बाल मजदूरी पर लगाम नहीं लग पा रही है।

भारत में आदिकाल से ही बच्चों को ईश्वर का रूप माना जाता रहा है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य इस सोच से काफी भिन्न है। बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। गरीब बच्चे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की पहल इस दिशा में सराहनीय है। उनके द्वारा बच्चों के उत्थान के लिये अनेक योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिससे बच्चों के जीवन व उनकी शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव दिखे। शिक्षा का अधिकार भी इस दिशा में एक सराहनीय कार्य है। इसके बावजूद बाल श्रम की समस्या अभी भी एक विकट समस्या के रूप में विराजमान है।

वर्तमान में देश के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे स्तर पर होटल, घरों व फैक्ट्री में काम कर या अलग अलग व्यवसाय में मजदूरी कर लाखों बाल श्रमिक अपने बचपन को तिलांजलि दे रहें हैं, जिन्हें न तो किसी कानून की जानकारी है, और ना ही पेट पालने का कोई और तरीका पता है। भारत में ये बाल श्रमिक कालीन, दियासलाई, रत्न पॉलिश व जवाहरात, पीतल व कांच, बीड़ी उघोग, हस्तशिल्प, सूती होजरी, नारियल रेशा, सिल्क, हथकरघा, कढ़ाई, बुनाई, रेशम, लकड़ी की नक्काशी, फिश फीजिंग, पत्थर की खुदाई, स्लेट पेंसिल, चाय के बागान में कार्य करते देखे जा सकते हैं। लेकिन कम उम्र में इस तरह के कार्यों को असावधानी से करने पर इन्हें कई तरह की बीमारियां होने का खतरा होता है। एक अध्ययन में पता चला है कि जितने भी बच्चे बालश्रम में लिप्त हैं, वे या तो निरक्षर थे या पढ़ाई छोड़ दी थी। इनमें अधिकांश बच्चे बीमार पाए गए और कई बच्चे नशे के आदि भी थे।

बाल श्रम की समस्या का मुख्य कारण है निर्धनता और अशिक्षा है। जब तक देश में भुखमरी रहेगी तथा देश के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे तब तक इस प्रकार की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। देश में बाल श्रमिक की समस्या के समाधान के लिये प्रशासनिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सभी स्तरों पर प्रयास किया जाना आवश्यक हैं। यह आवश्यक है कि देश में कुछ विशिष्ट योजनाएं बनाई जाएं तथा उन्हें कार्यान्वित किया जाए जिससे लोगों का आर्थिक स्तर मजबूत हो सके और उन्हें अपने बच्चों को श्रम के लिये विवश न करना पड़े। प्रशासनिक स्तर पर सख्त-से-सख्त निदेशों की आवश्यकता है जिससे बाल-श्रम को रोका जा सके। व्यक्तिगत स्तर पर बाल श्रमिक की समस्या का निदान हम सभी का नैतिक दायित्व है। इसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिये तथा इसके विरोध में सदैव आगे आना चाहिये। पूरी दुनिया के लिये बाल श्रम की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। विभिन्न देशों द्वारा बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाने के लिये समय समय पर विभिन्न प्रकार के कदम उठाए गए हैं। बाल श्रम को काबू में लाने के लिये विभिन्न देशों द्वारा प्रयास किये जाने के बाद भी इस स्थिति में सुधार न होना चिंतनीय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि बाल श्रम को दूर करने में हम अभी बहुत पीछे हैं। दुनिया भर में 73 मिलियन बच्चे खतरनाक काम करते हैं। खतरनाक श्रम में मैनुअल सफाई, निर्माण, कृषि, खदानों, कारखानों तथा फेरी वाला एवं घरेलू सहायक इत्यादि के रूप में काम करना शामिल है।

बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक घटना है। यूनीसेफ के अनुसार बच्चों का नियोजन इसलिये किया जाता है, क्योंकि उनका आसानी से शोषण किया जा सकता है। बच्चे अपनी उम्र के अनुरूप कठिन काम जिन कारणों से करते हैं, उनमें आमतौर पर गरीबी पहला कारण है। इसके अलावा, जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों का लागू नहीं होना, बच्चों को स्कूल भेजने के प्रति अनिच्छुक माता-पिता जैसे अन्य कारण भी हैं। बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के जरिए बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया है ताकि किसी काम में बच्चों को नियुक्त करने वाले व्यक्ति पर जुमार्ना के अलावा सजा भी बढ़ाई जा सके। संशोधित कानून सरकार को ऐसे स्थानों पर और जोखिम भरे कार्यों वाले स्थानों पर समय समय पर निरीक्षण करने का अधिकार देता है जहां बच्चों के रोजगार पर पाबंदी है।

संशोधित कानून के जरिए इसका उल्लंघन करने वालों के लिए सजा को बढ़ाया गया है। बच्चों को रोजगार देने वालों को अब छह महीने से दो साल की जेल की सजा होगी या 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुमार्ना या दोनों लग सकेगा। पहले तीन महीने से एक साल तक की सजा और 10,000 से 20,000 रुपये तक का जुमार्ना या दोनों का प्रावधान था। दूसरी बार अपराध में संलिप्त पाए जाने पर नियोक्ता को एक साल से लेकर तीन साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून के मुताबिक किसी भी बच्चे को किसी भी रोजगार या व्यवसाय में नहीं लगाया जाएगा। हालांकि स्कूल के समय के बाद या अवकाश के दौरान उसे अपने परिवार की मदद करने की छूट दी गई है। समाज के प्रमुख लोगों को बाल श्रम को रोकने की दिशा में एक नई पहल करनी चाहिये। लोगों को बाल श्रम को रोकने के लिये समाज में जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिये व बच्चो से काम करवाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनन कार्यवाही करवानी चाहिये तभी बाल श्रम पर रोक लग पायेगी। कानूनन कार्यवाही के डर से मालिक बाल श्रमिको को अपने यहां काम पर रखने से डरने लगेगें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

देवनगरी मथुरा दर्शन

सोलह कलाओं से सुसज्जित भगवान श्री कृष्ण विष्णु अवतार वासुदेव देवकी नंदन मथुरा में प्रगट हुए. गोकुल में नंद यसोदा के आंगन में बाल लीलायें की. कंस द्वारा भेजे गये सभी राक्षसों का संहार एवम् कंस के सभी षडयंत्रों को निःसफल करने वाले प्रभु श्रीकृष्ण अंत में कंश का अंत कर अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को आजाद कर निहाल करते हैं. गोकुल में बाल लीलायें करते करते गोप और गोपियों के साथ वृंदावन व्रज में अलौकिक लीलायें आलोकित कर देवताओं को भी वशीभूत करते हैं.

द्रोपदी की चीरहरण और पांडवों को अपमानित होते देख, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दुखी होते हैं. कौरवों का दिनोंदिन बढ़ता अत्याचार पृथ्वी पर बोझ के जैसा बढ़ता देख श्रीकृष्ण पींडवों का साथ देते हैं. कौरव और पांडव द्वारा घोषित युद्ध को रोकने का प्रयास समझौते द्वारा न होते हुए अंत में दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार होते हैं. दोनों अपने हैं. इसलिए स्वयं को अलग रखने का प्रयास कर लेते हैं और युद्ध में हथियार नही उठाते हैं और अर्जुन के रथ के सारथी बन जाते हैं. पांडव विजयी होते हैं. कौरवों का अंत होता है. युद्ध शुरू होने से पहले जो ज्ञान प्रभु श्रीकृष्ण अर्जुन को दिया वह गीता का ज्ञान कहलाया. जिसे महाभागवत पुराण कहा जाता है. महाभागवत पुराण अकाट्य है. महाभागवत पुराण के जैसा कोई पुराण नही है. और भविष्य में भी नही होगा. महा भागवत पुराण की महिमा अनंत है. भगवान श्रीकृष्ण को विश्व गुरु भी कहा जाता है. यदुवंशियों की समाप्ति तक भगवान श्रीकृष्ण धरती पर रहते हैं बाद में वह कृष्ण लोक चले जाते हैं.

श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे

हे नाथ नारायण वासुदेवा..

देवनगरी मथुरा दर्शन करने की जिज्ञासा हुई. रेलवे सेवा से मथुरा आये और मथुरा से पहले वृंदावन के लिए निकल पड़े. बडा ही मनोहर द्दष्य द्दष्टिगत होने लगा. शांत वातावरण देख, मन को सकून मिलने लगा. मन में बड़ी बड़ी अभिलाषायें जगी थी हम बड़े लालायित भी थे. एक जगह विश्राम के लिए रुके और नहाने धोने के बाद प्रभु दर्शन के लिए निकल पड़े.

सुना है बांके विहारी के दर्शन करने से मनोकामनायें पूर्ण होती हैं. ठाकुर बांके विहारी मंदिर में प्रवेश करते ही कृष्ण कृष्ण राधे राधे के मंत्रोच्चारण से ही सारे असफल कार्य सफल होने लगते हैं. मंदिर के दर्शनार्थियों ने बताया कि श्री बांके विहारी मंदिर में हरपल भक्तों को दर्शन देने के लिए सदा ही ठाकुर बांके विहारीजी विराजमान रहते है. बात हकीकत की है किसी किसी को बांकेविहारीजी के दर्शन करने में गंभीर भीड़ की वजह से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. मगर मुझे बड़े ही सरल ढ़ंग से प्रभु के दर्शन हुए. मैं दर्शन करके धन्य होगया. स्नेह विहारी मंदिर दर्शन करने के बाद कालीदह, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर, निधिवन, पं हरीदास समाधि, राधा रमन मंदिर, गोपेश्वर महादेव मंदिर, गोविंद देव मंदिर,रंग नाथ मंदिर, केसी घाट, पागलबाबा मंदिर, इस्कान मंदिर,वंशीवट, देखते हुए प्रेम मंदिर पहुँचे.

प्रेम मंदिर का नजारा अध्यात्मिक और दिलको सुकून देनेवाला है. सुंदर कारीगरी से सजाया हुआ आपस में बातें करती हुई अनेक सजीव कलाकृतियाँ. श्रीकृष्ण भगवान के बचपन से लेकर महाभारतकाल तक के मनहर अलौकिक द्दष्य सुख प्रदान करने वाला देखने को मिला. प्रेम नंदिर का भव्य और रमणीक द्दष्य देखकर मन भक्ति के सागर में डूबने लगता है. परमसुख देने वाला द्दष्य आँखों में समाने लगता है. एकबार प्रेम मंदिर में जाने के बाद पुनः वापस आने का मन नही करता है. नैनाभिराम श्रीकृष्ण की प्रेम गाथायें धीरे धीरे यमुनाजी के जल से निकलती हुई प्रेम के सागर में समाने लगती हैं. तदुपरांत वहाँ से मथुरा के लिए निकल पड़े. श्रीकृष्ण जन्म भूमि मथुरा दर्शन, द्वारकाधीश मंदिर, विश्रामघाट, कंसकिला, कुसुम सरोवर, तिलकद्वार, गोकुल, चौरासीखंभा, रमन रेती, चिंताहरण महादेव मंदिर, ब्राम्हणघाट, बलदेव मंदिर, गोवर्धन, राधामंदिर, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, बरसाना, राधाकुंड, श्यामकुंड, मानसरोवर, कीर्तिमंदिर,पुराना रंगजी मंदिर, कांचका मंदिर, गिरिराजमंदिर, कात्यायनी मंदिर, वैष्णोंमाता मंदिर, बरसाना में राधा जन्मस्थान गये. पहाड़ों पर मातारानी राधारानी का भव्य मंदिर रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठे हुए देखा. देखते ही राधारानी राधारानी की आवाज सभी श्रद्धालुओं के मुखसे एक स्वर में गूँजने लगी. राधारानी का जयकारा आसमान की बुलंदियों पर गूँजने लगा. राधारानी का दर्शन कर परमसुख, परम आनंद प्राप्त हुआ. देवनगरी मथुरा, व्रज, बरसाना, गोकुल भ्रमण कर हृदय राधेकृष्णमय होकर आनंदित हो गया.

संपादकीय

जब दो देशों के बीच कूटनीति खत्म हो जाती है, तो युद्ध की शुरुआत होती है।
-एडोल्फ हिटलर

जब देश की राजधानी में नई सरकार शपथ लेने जा रही हो, ठीक तभी जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर गोलियां बरसाना आतंकियों के दुस्साहस को ही दर्शाता है। जम्मू-कश्मीर में आतंकी जिस तरह से नए रास्ते खोज रहे हैं, उसे देखते हुए सतर्कता और रणनीतियों पर पुनर्विचार बेहद जरूरी है।

दुस्साहस

जम्मू के रियासी में रविवार की शाम को आतंकियों ने जिस तरह श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया, वह दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, ऐसे वक्त में जब देश की राजधानी में नई सरकार शपथ ले रही हो, ठीक उससे पहले इस वारदात को अंजाम देना, आतंकियों के दुस्साहस को भी दर्शाता है। दरअसल, श्रद्धालुओं से भरी बस शिवखोरी से कटरा लौट रही थी, तभी घात लगाकर बैठे आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दीं, जिससे बस संतुलन खोकर खाई में गिर गई और करीब दस लोगों की मौत भी हो गई। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन दशकों में यह दूसरी बार था, जब आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया। इससे पहले, जुलाई, 2017 में अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें सात तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। दरअसल, राजोरी, पुंछ और रियासी जिले 1990 के दशक के अंत से 2000 के दशक की शुरुआत तक आतंकवाद का केंद्र जरूर रहे, लेकिन उसके बाद से यहां शांति स्थापित हुई। वर्ष 2021 से राजोरी और पुंछ में आतंकी वारदात फिर से शुरू हुई हैं, लेकिन रियासी अब तक आतंकवाद से अपेक्षया अछूता ही रहा था। ताजा हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से संचालित लश्कर-ए तैयबा के एक आतंकी गुट टीआरएफ ने ली है, जो जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से दर्जनों आतंकी हमलों में शामिल रहा है। टीआरएफ इस क्षेत्र में किस तरह सक्रिय है, उसका पता जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक रिपोर्ट से भी होता है, जिसके अनुसार, कश्मीर में 2022 में आतंकी गुटों के साथ सुरक्षा बलों की 90 मुठभेड़ों में 172 आतंकी मारे गए, जिसमें करीब 108 टीआरएफ से जुड़े थे। चिंता की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा पार आतंकवाद का पैटर्न जिस तरह बदलता दिख रहा है, उसके अनुरूप जवाबी रणनीति अब तक नहीं बन सकी है। पहले आतंकी घाटी पर हमला करते थे, अब वे जम्मू के पुंछ, राजोरी और

रियासी को निशाना बना रहे हैं। दरअसल, घाटी में आतंकियों की कमर टूट चुकी है, इसलिए वे कश्मीर के दुर्गम इलाकों के बजाय कम ऊंचाई वाले पीर पंजाल के दक्षिणी इलाके चुन रहे हैं, जहां से वारदात को अंजाम देकर घने जंगलों में भागने में सहूलियत होती है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर में जो बदलाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी यहां रिकॉर्ड मतदान हुआ, उससे उपजी हताशा ही इन आतंकी हमलों के रूप में दिख रही है। 29 जून से चूंकि अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। जम्मू-कश्मीर में आतंकी जिस तरह से नए रास्ते खोज रहे हैं, उसे देखते हुए सतर्कता और रणनीतियों पर पुनर्विचार बेहद जरूरी है।

चीन को उसी की भाषा में

अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के चीनी कदम का जवाब देने के लिए भारत ने 'जैसे को तैसा' अभियान चलाया है। भारतीय सेना का सूचना युद्ध प्रभाग इसका नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने तिब्बत के 30 स्थानों की एक सूची को अंतिम रुप भी दे दिया है।

सुबीर भौमिक
(वरिष्ठ पत्रकार)
साथ में प्रत्यूष मुखर्जी

भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के चीनी कदम का जवाब देने के लिए 'जैसे को तैसा' अभियान चलाया है, यानी भारत भी तिब्बत के 30 स्थानों के नाम बदलेगा। चीन द्वारा भारतीय क्षेत्रों के नाम बदलने को लेकर नई दिल्ली को संदेह है कि बीजिंग ने पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश पर अपनी मजबूत दावेदारी दिखाने के लिए ऐसा किया है।

भारतीय सेना का सूचना युद्ध प्रभाग इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है, जिसे कोलकाता स्थित ब्रिटिशकालीन एशियाटिक सोसाइटी जैसे प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों का समर्थन प्राप्त है। सेना ने अपने लोगो के साथ प्रसारित विस्तृत ट्वीट में अरुणाचल प्रदेश के सात स्थानों के नाम बदलने को चुनौती दी है और चीन द्वारा जिन 30 स्थानों के नाम बदले गए, उनके विरोध का प्रयास कर रही है। अब उन्होंने तिब्बत के 30 स्थानों की एक सूची को भी अंतिम रूप दे दिया है, तथा ऐतिहासिक अभिलेखों से भारतीय भाषाओं में उनके प्राचीन नामों को पुनः प्राप्त किया है। इन पंक्तियों के लेखक के पास यह सूची उपलब्ध है, जो मीडिया के जरिये सार्वजनिक की जाएगी। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और विवादित सीमा के अन्य हिस्सों पर चीनी दावों के खिलाफ एक मजबूत जवाबी आख्यान प्रस्तुत करने के वैश्विक अभियान का हिस्सा है।

अब चूंकि केंद्र में नई सरकार का गठन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसलिए चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के स्थानों का नाम बदलने का इस्तेमाल अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावे को खत्म करने के लिए बदले के तौर पर किया जाएगा। सैन्य अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि नए नाम व्यापक ऐतिहासिक शोध के आधार पर रखे जाएंगे।

पूर्व खुफिया ब्यूरो के अधिकारी बेनु घोष, जिन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्षों काम किया है और जिन्हें पर्वतारोहण में भी दिलचस्पी है,

कहते हैं, 'जब भी ऐसा होगा, यह भारत द्वारा तिब्बत के प्रश्न को फिर से उठाने की तरह होगा। जब से बीजिंग ने तिब्बत पर जबरन कब्जा किया है, तब से भारत ने इसे चीनी हिस्सा माना है, लेकिन अब मोदी सरकार चीनी मानचित्रण और नामकरण संबंधी आक्रामकता को कम करने के लिए अपना रुख बदलने को तैयार है।'

भारतीय सेना ने हाल के हफ्तों में इन विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में मीडिया के कई दौरे आयोजित करवाए हैं तथा मीडिया को उन स्थानीय लोगों से बात करने का मौका दिया है, जो चीनी दावों का कड़ा विरोध करते हुए कहते हैं कि वे हमेशा से भारत का हिस्सा थे। नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर इस अभियान से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि भारत का 'अंतिम लक्ष्य क्षेत्रीय और वैश्विक मीडिया के माध्यम से विवादित सीमा पर भारत के जवाबी आख्यान को आगे बढ़ाना है, जो ठोस ऐतिहासिक शोध और स्थानीय निवासियों के जनमत पर आधारित है। गौरतलब है कि इसी वर्ष कुछ समय पूर्व अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने के लिए चीन ने इस राज्य में एलएसी के पास के 30 स्थानों का नाम बदल दिया। हांगकांग स्थित एक दैनिक के अनुसार, प्रशासनिक प्रभागों की स्थापना और नामकरण के लिए जिम्मेदार चीनी असैन्य मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 'मानकीकृत' भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की है, जिसे बीजिंग जंगनान कहता है। यह चौथी बार है, जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का एकतरफा नामकरण किया है। इससे पहले उसने ऐसा वर्ष 2017, 2021 और 2023 में किया था। चीन द्वारा नाम बदले गए स्थानों की सूची में 11 आवासीय क्षेत्र, 12 पर्वतीय, चार नदियां, एक झील, एक पहाड़ी दर्रा और एक भूखंड है। इन नामों में चीनी, तिब्बती और पिनयिन अक्षर हैं, जो मंदारिन चीनी का रोमन वर्णमाला संस्करण है। *साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट* ने मंत्रालय के बयान को उद्धृत किया है, जो कहता है कि 'भौगोलिक नामों के प्रबंधन पर राज्य परिषद (चीनी मंत्रिमंडल) के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, हमने संबंधित विभागों के साथ मिलकर चीन के जांगनान में कुछ भौगोलिक नामों को मानकीकृत किया है।' बीजिंग ने वर्ष 2017 में अरुणाचल प्रदेश के छह स्थानों के कथित मानकीकृत नामों की पहली सूची जारी की थी, फिर वर्ष 2021 में 15 स्थानों की दूसरी सूची जारी की और उसके बाद वर्ष 2023 में 11 स्थानों के नामों की एक और सूची जारी की। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीनी कदम को बार-बार खारिज करते हुए कहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और 'मनगढ़ंत' नाम रखने से यह वास्तविकता नहीं बदल जाती। वर्ष 2023 में तत्कालीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, 'हमने ऐसी रिपोर्टें देखी हैं। यह पहली बार नहीं है, जब चीन ने ऐसा प्रयास किया हो। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं।' उन्होंने आगे कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। मनगढ़ंत नाम रखने की कोशिशें इस सच्चाई को नहीं बदल पाएंगी।'

अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को पुष्ट करने के लिए चीनी बयानों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर भारत के समक्ष कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने से हुई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फुट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 मार्च को अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बार-बार के दावे को 'हास्यास्पद' बताते हुए कहा कि यह सीमावर्ती राज्य 'भारत का स्वाभाविक हिस्सा' है। उन्होंने सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान में व्याख्यान देने के बाद अरुणाचल मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, 'यह कोई नया मुद्दा नहीं है। चीन के ये दावे शुरू से ही हास्यास्पद रहे हैं और आज भी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में हम हमेशा से बहुत स्पष्ट और तार्किक रहे हैं। यह सीमा पर चल रही चर्चाओं का हिस्सा बनेगा।' कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है और जैसे को तैसा की रणनीति अपनाते हुए नाम बदलने के अभियान में शामिल हो गया है।

जीवन धारा

कार्लोस अल्कारेज

जरूरी नहीं है कि आप हर बार सफल या विफल रहें, लेकिन प्रयास छूटने नहीं चाहिए। मैं हमेशा एक अच्छा इन्सान और अच्छा खिलाड़ी बनने की कोशिश करता हूं।

सूरज हर सुबह नई उम्मीदों के साथ निकलता है

मैं हमेशा खुद पर विश्वास करता हूं और सभी से ऐसा ही करने के लिए भी कहता हूं। मुश्किलें आती हैं। कई बार तो लगता है कि अब सब कुछ हाथ से निकल गया। मन संशय से भर जाता है। लेकिन ऐसे कमजोर क्षणों से भी बाहर निकला जा सकता है। आप खुद पर फोकस करें। मुश्किल वक्त में भी सकारात्मक बने रहें। मैच के दौरान कई बार मुश्किल क्षण आते हैं, लेकिन मैं खुद पर केंद्रित होकर मुस्कराता रहता हूं, लोगों से हंसी-मजाक करता रहता हूं, ताकि दबाव मुझ पर हावी न हो सके और मैं खुद को संतुलित रख सकूं। आपके ऊपर जब दबाव होता है, तो उससे बाहर आने का रास्ता भी खुद ही ढूंढना पड़ता है। कई बार परिस्थितियों के अनुकूल ढलना पड़ता है। अनेक बार ऐसे पल आते हैं, जब मन और शरीर दोनों ही धैर्य खो बैठते हैं, तब कुछ समय के लिए शांतचित्त हो जाएं और आपके ऊपर जो दुख या कष्ट आया है, उसमें खुशी ढूंढें। कष्ट का भी एक अपना आनंद है, जब सफलता हाथ लगती है, तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मेरी खुद की कोई सीमा नहीं है और उसे निर्धारित भी नहीं करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि आपको कोई चीज उपहार में नहीं मिलती और अंगुलियां चटकाने से भी दुनिया आपके कदमों में नहीं होगी। ठोस उपलब्धियां पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने प्रतिद्वंद्वियों को बताना होता है कि आप क्या हैं। मेरा लक्ष्य और सपना दोनों स्पष्ट हैं कि मुझे दुनिया में नंबर एक बनना है। मुझे पता है कि मैं टेनिस खेलता हूं और उससे प्यार भी करता हूं। जब आप आने काम में आनंद नहीं ले रहे हैं, तो समझो आप हार गए हैं।

स्पेन के 21 वर्षीय कार्लोस अल्कारेज फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर टेनिस के तीनों कोर्ट (हार्ड, ग्रास और क्ले) पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। आइए जानें, वह जीवन के बारे में क्या सोचते हैं?

आपका लक्ष्य और सपना पवित्र होना चाहिए और सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहें। प्रतिदिन कठिन मेहनत करें। मुझे चिढ़ होती है, जब कोई मुझे स्पेशल कहता है, क्योंकि ऐसा कहकर वह मेरी मेहनत को अनदेखा कर रहा होता है। बड़ा लक्ष्य बनाएं और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। सफल या असफल होना अलग बात है। दोनों ही सूरतों में सुधार के लिए कोशिश करते रहें। आप जब कठिन परिश्रम करते हैं, तो उसका नतीजा अवश्य मिलता है। अच्छा बनने की कोशिश में आप जब कार्यक्षेत्र में जाते हैं, तो दिमाग में जीतने के बजाय अपना ध्यान सर्वश्रेष्ठ करने पर दें। जरूरी नहीं है कि आप हर बार सफल या विफल रहें, लेकिन प्रयास छूटने नहीं चाहिए। मैं हमेशा एक अच्छा इन्सान और अच्छा खिलाड़ी बनने की कोशिश करता हूं। हर दिन नया सूरज नई उम्मीदों के साथ निकलता है। *(विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित)*

थकने का समय नहीं

सूत्र

लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि थकने का समय नहीं है। मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए कई कष्टों से गुजरना पड़ा है। मुझे कोई फूलों की सेज नहीं मिली। कई बुरे दौर देखे हैं। मेरे आदर्श और सार्वकालिक महान खिलाड़ी राफेल नडाल से मैंने काफी कुछ सीखा है कि अच्छे वक्त में भी सौम्य कैसे बना रहा जा सकता है। दरअसल सबसे बेहतर को पाने के लिए आपको प्रयास भी सर्वश्रेष्ठ करने पड़ते हैं।

दूसरा पहलू

ओपन एआई के नए चैटबॉट का डेमो एक तरह से धोखा साबित हुआ। इसके नए चैटजीपीटी में कोई सुधार नहीं हुआ।

चैटजीपीटी : नाम बड़े और दर्शन छोटे

ओपन एआई ने अपने बेहद लोकप्रिय चैटजीपीटी चैटबॉट के नवीनतम संस्करण का अनावरण किया, तो इसमें एक नई आवाज थी, जिसमें मनुष्यों की तरह उतार-चढ़ाव एवं भावनाएं थीं। डेमो अनिवार्य रूप से एक प्रलोभन और धोखा साबित हुआ, क्योंकि नए चैटजीपीटी को इसकी अधिकांश नई सुविधाओं के बगैर जारी किया गया था। अभी नए चैटजीपीटी में जो कुछ पेश किया गया है, वह बॉट के विश्लेषण के लिए फोटो अपलोड करने की क्षमता है। बॉट वास्तविक समय में भाषा अनुवाद कर सकता है, पर चैटजीपीटी अपनी पुरानी, मशीन जैसी आवाज में जवाब देगा। फिर भी यह अग्रणी चैटबॉट है, जिसने टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। दो हफ्ते तक इस चैटबॉट को आजमाने के बाद मेरे मन में मिली-जुली भावनाएं थीं। भाषा का अनुवाद तो यह उत्कृष्ट करता है, लेकिन गणित एवं भौतिकी की समस्याओं को हल करने में इसे जूझना पड़ता है। कुल मिलाकर, मुझे पिछले संस्करण चैटजीपीटी-4 से इसमें कोई सार्थक सुधार नहीं लगा। यह रणनीति, जिसमें एआई कंपनी नए-नए फीचर्स का वादा करती हैं, लेकिन आधे-अधूरे उत्पाद बनाकर पेश करती हैं, लोगों को भ्रमित एवं निराश करती है। ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी सैम अल्टमैन द्वारा वित्त पोषित स्टार्ट-अप ह्यूमैन का 700 डॉलर का पिन, जो एक बोलने वाला लैपल पिन है, की सार्वभौमिक रूप से आलोचना की गई, क्योंकि यह बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। मेटा ने भी हाल में अपने एप में एक एआई चैटबॉट जोड़ा है, जो अधिकांश कार्यों में खराब प्रदर्शन करता है, जैसे कि हवाई जहाज के टिकट के लिए वेब सर्च करना। कंपनियां पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही एआई उत्पाद जारी कर रही हैं। अतीत में जब कंपनियां फोन जैसे नए तकनीकी उत्पाद जारी करती थीं, तो हमें जो दिखाया जाता था, वही मिलता था। एआई के साथ कंपनियां ऐसी तकनीकों का प्रदर्शन कर रही हैं, जो केवल सीमित, नियंत्रित परिस्थितियों में ही काम कर रही हैं। एक परिपक्व, विश्वसनीय उत्पाद आ भी सकता है-या नहीं भी। सीखने वाली बात यह है कि एक उपभोक्ता के रूप में हमें प्रचार का विरोध करना चाहिए और एआई के प्रति सजग दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमें किसी भी कमजोर तकनीक पर तब तक ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, जब तक कि इसका सबूत न मिले कि उपकरण विज्ञापन के अनुसार काम करते हैं। चैटजीपीटी का नया संस्करण (जीपीटी-4 ओमनी) अब ओपन एआई वेबसाइट और एप पर मुफ्त में आजमाया जा सकता है।

ब्रायन एक्स चेन

चैटबॉट को आजमाने के बाद मेरे मन में मिली-जुली भावनाएं थीं। भाषा का अनुवाद तो यह अच्छा करता है, पर गणित एवं भौतिकी की समस्याओं को हल करने में उलझ जाता है।

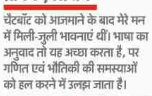

ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी सैम अल्टमैन द्वारा वित्त पोषित स्टार्ट-अप ह्यूमैन का 700 डॉलर का पिन, जो एक बोलने वाला लैपल पिन है, की सार्वभौमिक रूप से आलोचना की गई, क्योंकि यह जल्द ही गर्म हो जाता है।

आंकड़े

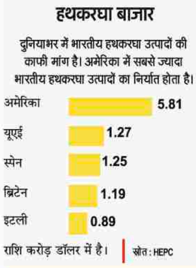

जनक ने कहा कि राजा होने के बाद भी मुझे राज्य का मोह नहीं। मान और अपमान पर ध्यान नहीं देता। सुलभा ने कहा-अभी आप पूरे ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं।

सुलभा ने दिया जनक को ज्ञान

अंतर्यात्रा
संकलित

महाभारत के शांति पर्व में जनक और सुलभा के संवाद का जिक्र है। सुलभा परम विदुषी थीं। वह प्रधान नाम के राजर्षि के कुल में पैदा हुईं। उनके पूर्वजों ने कई बड़े यज्ञ संपन्न कराए। वह इतनी ज्ञानी थीं कि उनके योग्य कोई वर नहीं मिला और आजन्म ब्रह्मचारिणी रहीं।

महाराज जनक का ब्रह्मज्ञानियों में बड़ा ही नाम था। सुलभा ने सोचा कि देखना चाहिए कि जनक कितने ज्ञानी हैं। वह संन्यासिनी का वेश त्याग कर अपने योग के बल से सुंदर युवती का रूप धारण कर भिक्षा मांगने के बहाने महाराज जनक के दरबार में पहुंचीं। महाराज जनक ने उनका आदर किया और भोजन करवाया। इसी दौरान सुलभा ने ब्रह्म ज्ञान की बात शुरू कर दी। महाराज जनक ने कहा कि शासन करते हुए मुझे राज्य का मोह नहीं। अग्नि और चंदन को समान समझता हूं। मुझे मान-अपमान का ध्यान नहीं। इत्यादि कई बातें बताईं।

इसके बाद सुलभा ने कहा, महाराज आप जो कह रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन जिन लोगों को ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वे मौन हो जाते हैं। सब कामों से उदासीन होकर एकदम शांत रहते हैं। आपको अब भी वादी-प्रतिवादी, जय-पराजय, स्वपक्ष-परपक्ष का ध्यान है। शास्त्रार्थ भी करते हैं। अतः कुछ कमी है। सुलभा की बात सुनकर महाराज जनक ने कहा कि जो भी त्रुटि है, उसे दूर करेंगे। जनक को ज्ञान देने के बाद सुलभा अपने आश्रम लौट गईं।

आज का इतिहास

पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म

भारत के इतिहास में 11 जून की बात करें, तो इसी दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की इच्छा के अनुरूप उनकी अस्थियों (राख) को देश भर में बिखेरा गया था। 1770 : कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की। 1776 : अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए समिति बनाई गई। 1866: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। 1897: भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी पण्डित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ। 1921: ब्राजील में महिलाओं को चुनाव में मतदान का अधिकार मिला। 1935: एडविन आर्मस्ट्रांग ने पहली बार एफएम का प्रसारण किया। 1940: यूरोपीय देश इटली ने मित्र देशों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की 1955: पहले मैग्निशियम जेट हवाई जहाज ने उड़ान भरी। 1987: 160 वर्षों में पहली बार मारग्रेट थैचर लगातार तीसरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनीं। 2001: अमेरिका के ओकलाहोमा शहर में 1995 में एक संघीय इमारत पर बम फेंकने वाले टिमोथी मैग्वेग को मौत की सजा दी गई।

बढ़त को बरकरार रखने की चुनौती

लोकसभा चुनाव की सफलता अखिलेश के लिए अवसर लेकर आई है, तो चुनौतियां भी हैं, क्योंकि देश में फिर से गठबंधन का दौर लौट आया है।

अजय बोस
सियासत

देश के सबसे अधिक आबादी वाले और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी (सपा) ने अविश्वसनीय छलांग लगाई है। पिछली बार पांच सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार पांच गुना से ज्यादा 37 तक पहुंच गई है। यह इस पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सपा ने 2004 में अनुभवी नेता मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 35 सीटें जीती थीं।

अपने पिता के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना अखिलेश के लिए व्यक्तिगत बड़ी सफलता है, जिनकी अक्सर राजनीतिक सूझबूझ और संगठनात्मक कौशल की कमी के लिए आलोचना की जाती रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में लगभग खत्म हो चुकी

कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अपना मतदान प्रतिशत 33.59 तक पहुंचा दिया और 2019 के चुनाव में 62 सीटें हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी (33 सीट) को दूसरे स्थान पर खिसका दिया। हालांकि अतीत में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन करने का समाजवादी पार्टी का अनुभव अच्छा नहीं रहा था, फिर भी अखिलेश ने राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन के साथ जाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। अखिलेश शुरुआत में हिचकिचा रहे थे, लेकिन जमीन स्तर पर चर्चा करने के बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का मन बनाया। अखिलेश का पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) मुद्दा, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर गया। जहां गैर-यादव पिछड़ी जातियां, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का महत्वपूर्ण गठजोड़ बनता है। यादव मतदाताओं की निष्ठा के प्रति आश्वस्त और यह जानते हुए कि मुसलमानों के पास समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन को वोट देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, उन्होंने गैर-यादव पिछड़ी और दलित जातियों के लिए अपना रास्ता ही बदल लिया। यद्यपि यादवों और मुस्लिमों की पार्टी का ठप्पा लगा होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने सिर्फ चार मुस्लिम और पांच यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया, जबकि अन्य पिछड़ी जातियों, जैसे कि निषाद और कुर्मियों के साथ-साथ दलितों को 27 टिकट दिए। महत्वपूर्ण तो यह है कि दलितों को न केवल आरक्षित सीटों पर, बल्कि फैजाबाद जैसी सामान्य श्रेणी की सीट पर टिकट दिया, जहां अयोध्या में राममंदिर है, वहां समाजवादी पार्टी के अनुभवी दलित नेता अवधेश प्रसाद ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीबी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल होने से अखिलेश को तगड़ा झटका लगा था, लेकिन वह इससे घबराए नहीं, इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। इस चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का उत्थान हुआ है, तो यह मायावती और बहुजन समाज पार्टी का शायद अंतिम राजनीतिक पतन है, जिन्होंने डेढ़ दशक पहले भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का वादा किया था। बहनजी की पार्टी का वोट प्रतिशत एकल अंक (9.39 फीसदी) में आ गया है, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन से भी ज्यादा निराशाजनक है। 2014 में भी बसपा कोई सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन उसे 20 फीसदी वोट मिले थे। बहनजी के लिए सबसे अधिक अपमानजनक तो नगीना लोकसभा क्षेत्र से उनके प्रतिद्वंद्वी दलित नेता और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद की जीत रही। चंद्रशेखर ने आश्चर्यजनक रूप से डेढ़ लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। हालांकि, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती और बसपा द्वारा रिक्त किए गए राजनीतिक स्थान पर चंद्रशेखर आजाद कब्जा कर पाते हैं या नहीं।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 116 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

सम्पादकीय

लोकसभा चुनाव परिणाम जनहित में, होंगे त्वरित फैसले

देश में मोदी सरकार ने तीसरी पारी का काम शुरू कर दिया है। दस साल तक एकछत्र राज करने के बाद इस बार मिलीजुली सरकार है। गठबंधन की सरकारें हो सकता है कि कुछ दिक्कत सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए खड़ा करती हो लेकिन इस बार भाजपा के सत्ता में बैठे लोगों को भी लगने लगा है कि जनता ने उनको कमजोरी के साथ मौका दिया है तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। यही कारण है कि आचार संहिता हटने के बाद अब राज्यों में त्वरित गति से निर्णय शुरू हो गए हैं जिससे जनता को सीधे फायदा होगा। प्रदेश में किसान निधि बढ़ाने का फैसला और उसके तत्काल बाद केन्द्रीय किसान निधि का पैसा मिलना इसी कड़ी में है। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता सदैव कृषक कल्याण की रही है। मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला कार्य 'पीएम किसान सम्मान निधि' के अंतर्गत देशभर के किसानों को 17वीं किस्त जारी करने का किया है। राजस्थान में भी लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा। दरअसल प्रदेश के किसानों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रति कुछ नाराजगी दिखाई थी। इसके चलते सबसे पहले किसान हित देखा गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 6 हजार रुपए की वार्षिक आर्थिक सहायता बड़ी योजना है। मोदी ने प्रधानमंत्री पद संभालते ही इस योजना की 17वीं किस्त जारी कर 20 हजार करोड़ रुपए वितरित किए हैं। तय है कि यह निर्णय किसानों के जीवन में आशा जगाने में सहायक सिद्ध होगा। इस निर्णय से देशभर में लगभग 9.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। अब तक इस योजना के तहत 16 किस्तों में 12 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) से वितरित किये गए हैं। राज्य सरकार ने भी पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए प्रतिवर्ष किया है। साथ ही, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देकर इसे 2400 रुपए किया गया है।

देखना है गठबंधन के कितने दबाव में काम करते हैं मोदी?

चुनाव से पूर्व ही नरेंद्र मोदी अपना अजेंडा बताते रहे हैं किंतु इस बार उनके सामने कई और भी चुनौतियां होगी। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के समय जम्मू में आंतकियों ने श्रद्धालुओं की बस हमला कर मोदी की नई सरकार के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है।सरकार पहले ही आंतकवाद से मजबूती से जूझ रही है। उसे आंतकवाद की जड़े खत्म करने के लिए इस कार्यकाल में काम करना होगा। पाक अधिकृत कश्मीर में बैठे आंतकियों के आकाओं के खात्मे के लिए भी उसे लगना होगा।हालाकि पाकिस्तान में ये काम चल रहा है। काफी समस ये वहां रह रहे भारत विरोधी आंतकियों को चुन- चुन कर कत्ल किया जा रहा है।

अशोक मधुप

रविवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल की शपथ ली।उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ने देश की सत्ता संभाल ली। प्रधानमंत्री के साथ ही 72 मंत्रियों ने भी मंत्रीपद की शपथ ली। हालांकि अभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना बाकी है, किंतु टीम में पुराने साथियों को जगह मिलना बताता है कि सब नरेंद्र मोदी की योजना के अनुसार हो रहा है। उन्हें अपनी टीम पर पूरा भरोसा और विश्वास है। हालाकि 2024 के इस आम चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिला है और उसे सत्ता में बने रहने के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टियों के समर्थन की जरूरत होगी। अब तक ठसक से सत्ता चलाने वाले नरेंद्र मोदी को गठबंधन के घटक दलों की सुननी और माननी होगी।वैसे शपथ ग्रहण की रात में भारत ने टी20 विश्व कप 2024 में इतिहास रच दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ ही टीम इंडिया ने कई रिकॉर्ड बना दिए। यह जीत एक तरह से नई सरकार का स्वागत ही मानी जाएगी।

लोकसभा चुनाव के पहले ही भाजपा ने यह साफ कर दिया था कि मोदी सरकार 3.0 में यूनिफॉर्म सिविल कोड कोर एजेंडे में शामिल होगा। उत्तराखंड में भाजपा सरकार पहले ही इसे लागू कर चुकी है। ऐसे में माना जा रहा था कि केंद्र की सत्ता वापस में लौटने के बाद भाजपा प्राथमिकता के साथ इसे आगे बढ़ाएगी। लेकिन अब सहयोगी दल भाजपा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भाजपा पर इस निर्णय को वापस लेने पर दबाव बना सकते है। भाजपा के एजेंडे में वन नेशन, वन इलेक्शन भी शामिल हैं। इस संबंध में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी हैं। 47 राजनीतिक दलों में से 32 दल तैयार हैं। एनडीए गठबंधन में इस बार जदयू और टीडीपी की भूमिका अहम है। ऐसे में वे भाजपा के इस एजेंडे पर भी रोड़ा बन सकते हैं।

तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का विस्तार भी शामिल है।। नरेंद्र मोदी चुनावी कार्यक्रमों में यह कहते रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसलों के लिए मोदी की गारंटी पूरी की जाएगी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने भविष्य के लिए अपने विजन को रेखांकित किया था। मोदी ने आयुष्मान भारत के तहत प्रदान की जाने वाली मुफ्त स्वास्थ्य सेवा तक अभूतपूर्व पहुंच पर जोर दिया। भाजपा के 2024 के घोषणापत्र में आयुष्मान भारत के कवरेज को 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने के लिए आगे बढ़ाने का भी वादा किया गया है।इस एजेंडे को लागू करने में गठबधंन को कोई आपत्ति नही होगा और यह सरलता से लागू हो जाएगा। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिपहसालार कहते घूमते रहे हैं कि सरकार बनी तो पाक अधिकृत कश्मीर पर भारत का कब्जा होगा। शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता हरियाणा के रोहतक में व्यापारियों द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में कहा कि कि आने वाले दो-तीन साल में किसी भी क्षण पाक अधिकृत

कश्मीर भारत में शामिल हो सकता है। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी एक बयान में पीओके को लेकर भारत के दावे को दोहराया था। सेरामपुर पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का है और हम उसे लेकर रहेंगे ।योगी आदित्यनाथ तो सबसे आगे बढ़ गए। चुनाव के बाद के मोदी जी को तीसरे कार्यकाल पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को निशाने पर लेते हुए कहा कि आज पाकिस्तान के लिए पीओके को भी बचाना मुश्किल हो रहा है. उन्होंने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले छह महीने के अंदर पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि पीओके ले सकें। भाजपा के सिपहसालार की पाक अधिकृत कश्मीर पर चुनाव प्रचार के दौरान कब्जे की बात करते रहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चुप्पी साधे रखी।किंतु कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, और जम्मू -कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला के ये कहा कि भाजपायी पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जे की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने चूड़ी नही पहन रखी। पाकिस्तान के पास एटम बम है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप्पी साधे थे।किंतु पाकिस्तान ने चूडी नही पहन रखीं, पर उन्होंने जरूर कहा कि कांग्रेसी और कुछ विपक्षी नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ी नही पहन रखीं तो उसे पहना दी जाएंगी। प्रधानमंत्री के इस कथन से साफ होता है कि उनके सिपहसालारों के पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जे की घोषणा उनकी अपनी नही है। यह कहीं केंद्रीय नेतृत्व में पक रहा है और नई सरकार बनने पर वह इस पर कार्रवाई कर सकता है। इतना सब होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोदी सरकार पर देशभर में जातिगत जनगणना कराने को लेकर दबाव बना सकते है। क्योंकि बिहार में पिछड़ी जातियों के अलावा दलित और मुस्लिम मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है। नीतीश अपने राज्य बिहार में इस जनगणना को करवा चुके है। वे लंबे समय से देश में इसे करवाने की डिमांड कर रहे है। क्योंकि अन्य विपक्षी दल चाहे वह कांग्रेस हो या फिर आरजेडी दोनों ही इस जातिगत जनगणना की मांग कर रही है।हालाकि भाजपा इसके विरूद्ध है।नीतीश कुमार वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे है। भाजपा में शामिल होने के पहले भी नीतीश ने केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी।

उन्होंने इस मांग को लेकर बिहार में अभियान चलाने की बात भी कही थी। इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर सकते है। ये दोनों नेता अब अपनी इन मांगों को लेकर मोदी सरकार पर दबाव रहेगा। वैसे मोदी ऐसे दबाव से निपटना बखूबी जानते हैं। महाराष्ट्र की शिवसेना को गठबंधन में लेकर ये दबाव कम किया जा सकता। चुनाव से पूर्व विपक्षी गठबंधन से जैसे नितीश कुमार पल्टी मार कर भाजपा के साथ आ गए, ऐसे ही विपक्ष में बैठे कई दल भाग सकतें हैं। बस इशारे की जरूरत है। मोदी पुराने राजनयिक हैं। कब किस हालात से कैसे जूझना है, वह जानते हैं। उम्मीद है कि वह अपनी सूझबूझ से सरकार को सरलता से पांच साल चलाते रहेंगे।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, अपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताए और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
नौकरी पेशावालों को लाभ का अवसर मिलेगा। वैवाहिक जीवन में सुख-संतोष की अनुभूति होगी। पत्नी, पुत्र और बुजुर्गों की ओर से लाभ होगा। मित्रों के साथ रमणीय पर्यटन होगा। मित्र विशेष लाभकारी साबित होंगे।

वृष
विदेश में बसने वाले निकटस्थ संबंधियों के समाचार मिलेंगे। संतान के संबंध में चिंता होगी। आज आपको वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा अन्यथा अनर्थ हो सकता है। सर्दी और कफ के कारण आपका स्वास्थ्य खराब होगा।

मिथुन
आज सभी विषय के नकारात्मक पहलुओं का अनुभव होगा। थकान और आलस के कारण स्फूर्ति का अभाव रहेगा। नौकरी-व्यवसाय में अवरोध खड़े होंगे। उच्च पदाधिकारियों के साथ वाद-विवाद में न पड़ें।

कर्क
विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम कहा जा सकता है। आपका स्वाभिमान भंग होगा। ऑफिस या व्यवसाय में विरोधियों से सावधान रहें। आप तन और मन से स्वस्थ और प्रफुल्लित रहेंगे। परिजनों के साथ घर के संबंध में चर्चा करेंगे। संतान के शुभ समाचार मिलेंगे।

सिंह
दांपत्यजीवन में घनिष्ठता अनुभव करेंगे। आप अत्यधिक चिंता और भावनाओं के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से व्यग्र और अस्वस्थता अनुभव करेंगे। गलत दलीलबाजी और वाद-विवाद और संघर्ष खड़ा हो सकता है।

कन्या
कोर्ट-कचहरी के मामले में सावधानी रखें। वाणी और व्यवहार में संयम रखना आवश्यक है। आय की अपेक्षा खर्च अधिक होगा। गलतफहमी पैदा न हो इसका ध्यान रखें। व्यापार-धंधे में विकास के साथ-साथ आय भी बढ़ेगी। धन लाभ होगा।

तुला
आर्थिक मामलों पर अधिक ध्यान देंगे। आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। भाग्यवृद्धि के योग हैं। भाई-बंधुओं का सहयोग मिलेगा। प्रिय व्यक्ति का साथ और सार्वजनिक सम्मान मिलेगा। विरोधियों को परास्त कर सकेंगे।

वृश्चिक
आज आप बहुत भावनाशील रहेंगे, इसलिए किसी के ज्यादा बोलने से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। मां के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। स्थायी संपत्ति के मामले में निर्णय लेना उचित नहीं है।

धनु
धन खर्च में वृद्धि होगी। नियम विरोधी काम तथा अनैतिक काम से आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है, इसका ध्यान रखें। विचार, व्यवहार में भावुकता रहेगी। फिर भी आप परिजनों और मित्रों के साथ खुशी से अपना दिन व्यतीत करेंगे।

मकर
आज भावनाओं के प्रवाह में सराबोर रहेंगे। परिजन, मित्र तथा सगे-संबंधी उसमें सहभागी बनेंगे। स्वादिष्ट भोजन करने और बाहर घूमने जाने का आयोजन होगा। मांगलिक अवसरों पर जाना हो सकता है।

कुंभ
परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण रहेगा। ऑफिस और नौकरी में आय वृद्धि, पदोन्नति के लिए योग बनेंगे। ऑफिस में उच्च पदाधिकारियों द्वारा काम की सराहना होगी और वे आपके प्रेरणा स्रोत बनेंगे।

मीन
थोड़ा विलंब या अवरोध के बाद निर्धारित रूप से काम पूरा कर सकेंगे। आर्थिक आयोजन सफल कर सकेंगे। स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए मध्यम दिन है। स्नेहीजनों और मित्रों के साथ की मुलाकात होगी। मानसिक चिंता और शारीरिक अस्वस्थता रहेगी।

आज का इतिहास

11 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- कैप्टन जेम्स कूक ने 1770 में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की।
- अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए 1776 में समिति बनाई गई।
- इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। इसे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था।
- न्यूजीलैंड ने 1901 में क्रुक द्वीप पर कब्जा किया।
- ब्राजील में महिलाओं को 1921 में चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया।
- एडविन आर्मस्ट्रांग ने 1935 में पहली बार एफएम का प्रसारण किया।
- इटली के जेनेवा तोरन पर 1940 में ब्रिटेन ने बमबारी की।
- यूरोपीय देश इटली ने 1940 में मित्र देशों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में इटली की वायु सेना ने पहली बार माल्टा द्वीप पर हमला किया।
- अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लैंड-लीज समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- ब्रिटिश सेना ने 1943 को भूमध्यसागर में स्थित सिसली द्वीप के दक्षिण में स्थित एक छोटे से द्वीप पैंटेलेरिया पर हमला किया।
- अमेरिका के 15 लड़ाकू विमानों ने 1944 में मारियाना द्वीप समूह में स्थित जापान के आधार शिविर पर हमला किया।
- अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1947 में पूर्ण रूप से चीनी की रसद खत्म हुई।
- पहले मैग्निशियम जैट हवाई जहाज ने 1955 में उड़ान भरी।
- प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छानुसार 1964 में उनकी अस्थियों की भस्म पूरे देश में विखेरी गई।
- पहली बार अश्वेत समुदाय के एबट, पॉल बोटेग और बर्नी को 1987 को ब्रिटेन में संसद सदस्य चुना गया।
- वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सकलेन मुश्ताक ने 1999 में जिम्बाब्वे के खिलाफ हैट्रिक लगाई थी।
- कोर्निकोवा महिला 2003 में टेनिस की सबसे सुन्दर खिलाड़ी घोषित कि।
- नेपाली संसद ने 2006 में आम राय से नरेश के वीटो अधिकार को समाप्त किया।
- फिजी के अपदस्थ प्रधानमंत्री लाडसेनिया करासे को 2007 में राजधानी सुवा में प्रवेश की इजाजत मिली।
- भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बन्द बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख़ हसीना वाजेद 2008 में रिहा हुईं।
- अफगानिस्तान में 2012 में भूकंप के झटके के बाद हुए भूस्खलन में 80 लोगों की मौत।

11 जून को जन्मे व्यक्ति

- अमेरिका की पहली संसद सदस्य रैफिन का जन्म 1880 में हुआ।
- महान् स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में हुआ।
- भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के. एस. हेगड़े का जन्म 1909 में हुआ।
- ब्रिटिश गिटार वादक ग्रेम रसेल का जन्म 1911 में हुआ।
- भारतीय राजनितिज एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का जन्म 1948 में हुआ।

भारत की 'साइक्लोन' पूजा तोमर ने यूएफसी जीतकर रच दिया इतिहास

रामस्वरूप रावतसरे

उत्तर प्रदेश की पूजा तोमर ने अल्टीमेट फाइटिंग चौंपियनशिप (यूएफसी) में फाइट जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। पूजा ने यूएफसी लुइसविले 2024 में ब्राज़ील की रेयान डॉस सैंटोस को हराकर यह खिताब जीता लहै। पूजा तोमर ने पिछले साल यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर नई कीर्तिमान स्थापित किया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली पूजा तोमर ने महिलाओं के स्ट्रॉवेट डिवीजन में अपनी पहली फाइट में 30-27, 27-30 और 29-28 के स्कोर के साथ विभाजित निर्णय से जीत हासिल की। यह मुकाबला काँटे का था, जिसमें दोनों फाइटर्स ने अपनी-अपनी ताकत दिखाई। पूजा ने पहले राउंड में शक्तिशाली बॉडी किक्स के साथ दबदबा बनाया और आखिरकार जीत में तब्दील हो गई। 'साइक्लोन' के नाम से मशहूर 28 वर्षीया पूजा तोमर को भारतीय सर्किट की सबसे बेहतरीन महिला फाइटर्स में से एक माना जाता है। पूजा ने इस पल को भारतीय फाइटर्स और डड। प्रशंसकों को समर्पित किया। पूजा की जीत से पहले हर कोई सोचता था कि भारतीय फाइटर्स को न्थ्ब् जैसे मंच पर होने का अधिकार नहीं है। पूजा ने कहा कि वह दुनिया को दिखाना चाहती थीं। भारत बेहतरीन मिक्स्ड मार्शल आर्ट (एमएमए) फाइटर पूजा ने कहा, फ्मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि भारतीय फाइटर्स हारे हुए नहीं हैं। हम पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं! हम रुकने वाले नहीं हैं! हम जल्द ही न्थ्ब् चौंपियन बनेंगे! यह जीत मेरी नहीं है, यह सभी भारतीय प्रशंसकों और सभी भारतीय फाइटर्स की जीत है। मैं भारतीय ध्वज के साथ भारतीय गीत पर बाहर निकली और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। पूजा ने आगे कहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर (ऑक्टागन) कोई दबाव नहीं था, मैंने बस यही सोचा कि मुझे जीतना है। मैंने दो या तीन मुक्के खाए, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं खुद को बेहतर बनाने जा रही हूँ और मैं पूरी तरह से आगे बढ़ रही हूँ। पूजा भारत कंडारे और अंशुल जुबली के पदचिन्हों पर चलती हैं, जिन्होंने यूएफसी में मुकाबला किया था, लेकिन वे अपना पहला मैच जीत नहीं पाए थे। पूजा तोमर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढाना गाँव में हुआ है। वह 28 साल की हैं। घर में उनकी दो बहन और माँ हैं। जब वह सिर्फ छह साल की थीं तो उनके पिता का देहांत हो गया। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें कठोर बना दिया। पूजा मानती हैं कि कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के कारण उन्होंने मैट्रिक्स फाइट नाइट (एमएफएन) को चुना, न कि खेल के प्रति जिज्ञासा, रुचि या प्यार के कारण। उनका मानना था कि एमएफएन में टॉप फाइटर में से एक बनने के लिए उनकी मानसिक दृढ़ता काम आई। उन्होंने इसके लिए न केवल खेल की प्रकृति को जिम्मेदार ठहराया, बल्कि जीवन में होने वाले झगड़ों को भी जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से बात करते हुए पिछले साल पूजा ने कहा था, हम तीन बहनें हैं। मेरी एक बहन के पैर में समस्या थी और जब कोई उसे इसके लिए परेशान करता था या चिढ़ाता था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने कहा, मैंने इसके लिए लड़कों को पीटना शुरू कर दिया था। बड़े होकर मैं जैकी चेन अभिनीत फिल्में देखती थी और मुझे लगता था कि मैं उनके स्टंट से कुछ चीजें सीख सकता हूँ और उन्हें इन लड़कों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूँ।

विशेष आलेख

एमबीबीएस नहीं तो और क्या?

विजय गर्ग

डॉक्टर बनना कम उम्र से ही कई बच्चों का सपना होता है। बीमारों को ठीक करने और साथ ही लोगों से कृतज्ञता और सम्मान पाने से बेहतर जीवन बिताने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? और पहले के वर्षों के विपरीत, आज सक्षम डॉक्टर भी अच्छी आय अर्जित करते हैं। दुर्भाग्य से भारत में, 2 साल की एमबीबीएस (बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी) डिग्री के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या पूरे भारत में लगभग 100,000 तक सीमित है, जो 1000 से अधिक कॉलेजों में फैली हुई है। इसलिए, कई उम्मीदवारों को अपने सपनों का कोर्स करने का मौका नहीं मिलता है। साथ ही, चिकित्सा अध्ययन बहुत अधिक विस्तृत होते हैं, जिसके लिए बड़े हिस्से को कवर करने, नैदानिक कार्य और अंत में, इंटर्नशिप के एक कठोर वर्ष की आवश्यकता होती है। इसलिए, कई अच्छे इरादे वाले छात्र जो अपने स्कूल के दिनों में डॉक्टर बनने का सपना देखते थे, वे चिकित्सा पेशे में आने की उम्मीद छोड़ देते हैं और किसी ऐसी चीज़ की ओर बढ़ जाते हैं जिसके बारे में वे बहुत भावुक नहीं होते हैं। वैकल्पिक लेकिन बहुत से लोग इस बात से अवगत नहीं हैं कि एमबीबीएस की पढ़ाई स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर बनने का एकमात्र तरीका नहीं है। ऐसे कई अन्य विकल्प भी हैं जो आशाजनक और फायदेमंद हैं और ये क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रौद्योगिकी विकास के साथ, स्वास्थ्य देखभाल अधिक स्वचालित होती जा रही है, जिसके लिए उच्च योग्य पैरामेडिकल पेशेवरों की आवश्यकता होती है। एमबीबीएस किए बिना एक योग्य डॉक्टर बनने के लिए, कोई भी आयुष (आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) पाठ्यक्रमों में से किसी एक में प्रवेश ले सकता है, जिसे अब सरकार द्वारा नियमित कर दिया गया है और पूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के रूप में पेश किया जाता है। यदि कोई इन प्रणालियों में विश्वास करता है तो वह बीएचएमएस (बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी), बीएएमएस (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एम एंड एस), बीयूएमएस (बैचलर ऑफ यूनानी एम एंड एस) या बीएनवाईएस (बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज) का विकल्प चुन सकता है। इनमें से प्रत्येक एमबीबीएस के समान अवधि के लिए है, और उसके बाद इंटर्नशिप होती है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर एमडी पाठ्यक्रम भी हैं। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश तुलनात्मक रूप से आसान है और ट्यूशन फीस भी कम है। हालाँकि, एक उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे वास्तव में चुनी गई वैकल्पिक चिकित्सा धारा में विश्वास है, उसने उस पद्धति के माध्यम से उपचार का प्रयास किया है और संतुष्ट है – क्योंकि तभी वह व्यक्ति उस धारा का अभ्यास करने के लिए प्रेरित होगा और रोगियों को ठीक करने में सफल होगा। जो लोग एलोपैथिक साइंस में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, उनके लिए पांच वर्षीय बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) जैसे विकल्प हैं, जिसके बाद वे ओरल, ऑर्थोडॉन्टिक, पेरियोडॉन्टिक में तीन साल के एमडीएस कोर्स में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। कृत्रिम या मैक्सिलो-चेहरे की सर्जरी। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम ये वे डिग्रियां हैं जो पीसीबी के साथ 10+2 पूरा करने वाले छात्रों को सीधे प्रवेश प्रदान करती हैं, और कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं है। वे हैं- फिजियोथेरेपी (बीपीटी) और व्यावसायिक थेरेपी (बीओटी) – साढ़े चार साल बैचलर ऑफ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एंड ऑडियोलॉजी (बीएसएलपीए) – चार साल रेडियोग्राफी, ऑप्टोमेट्री, मेडिकल लैब, ऑपरेशन थिएटर टेक, कार्डियक, डायलिसिस टेक, पब्लिक हेल्थ, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स, स्पोर्ट्स साइंस आदि में बीएससी – तीन साल अधिकांश पैरामेडिकल स्ट्रीम में डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं, ज्यादातर पीयूसी के बाद, लेकिन कुछ कक्षा 10 के बाद भी

पेश किए जाते हैं। अवधि दो से तीन वर्ष है। पहले के विपरीत, अब पैरामेडिकल पेशेवरों के पास अच्छे पारिश्रमिक के साथ हाई-टेक काम करने के अच्छे अवसर हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान इसमें चार साल की बीवीएससी और फिर पशु चिकित्सक, पालतू जानवरों की देखभाल पेशेवर के रूप में अभ्यास करना या पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सा में करियर बनाना शामिल है।व्यवहार, प्रबंधन, सैन्य सेवा, आदि। सरकारी पशु चिकित्सा कॉलेज काफी कम शुल्क पर पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, और नौकरी के अवसर सरकारी सेवा से आगे बढ़कर पशु पोषण और स्वास्थ्य, पशु उत्पाद, सौंदर्य और विभिन्न पशु फार्मों से संबंधित निजी क्षेत्र में पहुंच गए हैं। अस्पताल या स्वास्थ्य सेवा इन्हें अस्पताल प्रशासन (एमएचए), या एमबीए (हेल्थकेयर) आदि में दो वर्षीय मास्टर्स के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर पेश किया जाता है। कुछ कॉलेज केवल डॉक्टरों को लेते हैं, लेकिन कई अन्य किसी भी स्ट्रीम से स्नातकों के लिए सीटें प्रदान करते हैं। हालांकि ऐसे पेशेवर वास्तव में उपचार में भाग नहीं लेते हैं, वे अपनी दक्षता सुनिश्चित करने और दर्जनों विभिन्न विभागों और सलाहकारों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बड़े हाई-टेक और कॉर्पोरेट अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया की निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। ऑपरेशन थिएटर, बाल चिकित्सा, मनोरोग नर्सिंग आदि में चार वर्षीय बीएससी (नर्सिंग) और एमएससी इस श्रेणी में आते हैं। कुछ अन्य विकल्प... कोई फार्मेसी में चार साल की बी फार्म डिग्री देख सकता है, और एम फार्म के माध्यम से आगे विशेषज्ञता हासिल कर सकता है। साथ ही, छह साल के पीएचएआरएमडी पाठ्यक्रम को अब एक बहुत ही पेशेवर और व्यावहारिक पाठ्यक्रम (सीईटी में पीसीबी या पीसीएम अंकों के आधार पर) के रूप में मान्यता दी जा रही है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में चार साल के इंजीनियरिंग कोर्स पर भी विचार किया जा सकता है। और जो लोग रुचि रखते हैं, उनके लिए मनोविज्ञान में बीए/एमए/एमएससी एक अच्छा विकल्प है। एनआईएमएचएएनएस, एम्स आदि में क्लिनिकल साइकोलॉजी में दो साल का एमफिल कोर्स करके कोई भी क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकता है। भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना 12वीं कक्षा के बाद व्यक्तियों को नर्सिंग या चिकित्सा सहायक के रूप में भर्ती करती है, और वजीफे के साथ नौकरी पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कई विदेशी विश्वविद्यालय भी भारतीय छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए लेते हैं और उनकी ट्यूशन फीस भी काफी प्रतिस्पर्धी है। हालाँकि, ऐसे छात्रों को हमारे देश में अभ्यास करने से पहले भारत वापस आना होगा और एक योग्यता परीक्षा देनी होगी। विदेशी डिग्रियों की समकक्षता का विवरण www.mohfw.nic और www.mciindia.org से प्राप्त किया जा सकता है। तनाव प्रबंधन, जीवनशैली प्रबंधन, खेल प्रबंधन, स्कूलों में बच्चों की भलाई और वृद्धावस्था देखभाल जैसे क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य देखभाल का महत्व बढ़ रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेज गति से बढ़ते रहेंगे और उन लोगों के लिए उत्कृष्ट दीर्घकालिक कैरियर के अवसर प्रदान करेंगे जो अभी इसमें शामिल हो रहे हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

गठबंधन धर्म संग मंत्रिमंडल में संतुलन

भले ही 18वीं लोकसभा में भाजपा बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई हो, लेकिन चुनाव पूर्व गठबंधन के बूते बहुमत हासिल करके और पार्टी व गठबंधन के नेता चुनने के बाद मंत्रिमंडल गठन के मुद्दे को भी राजग ने बेहद जल्दी सुलझा लिया है। रविवार की सायं राष्ट्रपति भवन परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राजग नेताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, गठबंधन के साथियों को संतुष्ट करने तथा तमाम सामाजिक समीकरण साधने के लिए प्रधानमंत्री के साथ जम्बो मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। जिसमें तीस कैबिनेट मंत्री बताए जाते हैं। जिन राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां ज्यादा मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कैबिनेट व राज्य मंत्री बनाने में ऐसा नजर नहीं आया कि भाजपा गठबंधन सहयोगियों के किसी तरह के दबाव में हो। पिछली सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालने वाले भाजपा के सांसद वरिष्ठता क्रम में शपथ लेते नजर आए। मंत्रिमंडल के गठन में गठबंधन के हितों के साथ ही जातीय संतुलन और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया। हरियाणा में भले भी पांच सांसद इस बार चुने गए हों, लेकिन इस साल राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कैबिनेट व राव इंद्रजीत सिंह तथा कृष्णपाल सिंह को राज्यमंत्री बनाया गया। वहीं पंजाब से कोई भाजपा सांसद नहीं चुना गया लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते रवनीत बिट्टू को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। झारखंड में इस साल चुनाव होने हैं तो राज्य को तीन मंत्री दिये गए हैं। बहरहाल, राजग सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल में भाजपा ने पार्टी, सहयोगी दलों तथा जातीय व क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का भरसक प्रयास किया है। जैसे कि महत्वपूर्ण मंत्रालयों को लेकर गठबंधन के साथियों की दावेदारी को लेकर सवाल उठाये जा रहे, उस तरह का कोई टकराव नजर नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार के सामने महत्वपूर्ण फैसलों में सर्वसम्मति से निर्णय करने की चुनौती जरूर रहेगी। हालांकि, नेता चुने जाने से पहले नरेंद्र मोदी ने राजग को जैविक गठबंधन के रूप में वर्णित करते हुए अब तक सबसे मजबूत सत्तारूढ़ गठबंधन बताया है। बहरहाल, नरेंद्र मोदी पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे। उनके सामने मुख्य सहयोगी गठबंधन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी और नीतीश कुमार के जनता दल (यू) के साथ तालमेल बनाने की जरूरत होगी। यही वजह है कि 72 सदस्यीय मंत्रिमंडल में गठबंधन दलों के बारह मंत्री बनाये गए हैं। वहीं जातीय समीकरण साधने के लिए 27 ओबीसी, पांच एस.टी व अल्पसंख्यक वर्ग से पांच सांसदों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कहा जा रहा है कि भाजपा अपने सहयोगियों के प्रति उदार रवैये अपनाएगी। राजग की कोशिश है कि गठबंधन को मजबूत करके इस बार सशक्त होकर उभरे विपक्ष का मुकाबला किया जा सके। इतना तय है कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष अग्निपथ, समान नागरिक संहिता, बेरोजगारी व महंगाई जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजग सरकार के लिये कड़ी चुनौती पेश करता रहेगा। वहीं सवाल उठाया जा रहा कि क्या नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार सहयोगी दलों की आकांक्षाओं के बीच पिछले दो कार्यकाल की गति से काम कर पाएगी?

भाजपा जानती है गठबंधन सरकार का धर्म

आर.के. सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

बहरहाल, जनता पार्टी की उस चुनाव में जीत के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार दो साल तक चली। उसके बाद वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी बिखर गई। मोरारजी देसाई सरकार में गृह मंत्री चरण सिंह को कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। संयोग देखिए कि अब चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी उस एनडीए सरकार का हिस्सा हैं जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बहरहाल, चरण सिंह 1979 में जनता पार्टी के बिखरे हुए समूहों के समर्थन और कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बने। लेकिन चरण सिंह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल 23 दिनों तक चला क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे चरण सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रविवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपना कामकाज संभाल लिया है। यह पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेगी। वास्तव में, भाजपा की पहली सरकार, जो 1996 में गठित हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक गठबंधन की सफल प्रयोग वाली सरकार थी। भले ही वह केवल 13 दिनों तक चली। अटल जी 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः वापस आए थे। इसलिए यह कहना सरासर गलत होगा कि भाजपा को गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने का अनुभव नहीं है। भाजपा को 2014 में 283 और 2019 में 303 सीटें मिली थीं। उन जीतों में मोदी जी की सबसे अहम भूमिका रही थी। लेकिन , पूर्ण बहुमत के बाद भी मोदी जी ने गठबंधन का धर्म निभाया ।

हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 240 सीटें जीतीं - बहुमत से 32 कम। यह तय मानिए कि जो विकास का पहिया 2014 में घूमना शुरू हुआ था वह अब गठबंधन सरकार के दौर में भी आगे बढ़ता ही रहेगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में 14 पार्टियां शामिल हैं। उसमें भाजपा को 240 सीटों पर विजय मिली और शेष 53 सीटें हासिल कीं , उसकी सहयोगी दलों ने।

अगर हम गुजरे दौर के पन्नों को खंगाले तो पता चलेगा कि कि भारत में सबसे पहले 1977-1979 गठबंधन सरकार बनी थी। कांग्रेस के 1977 में चुनाव हारने के बाद जनता पार्टी की सरकार देश में बनी थी। 1977 के चुनाव प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल की स्थिति लागू करने के लगभग दो साल बाद हुए थे। श्रीमती गांधी ने आपातकाल हटा दिया और जनवरी 1977 में अचानक चुनावों की घोषणा की। श्रीमती गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी को जनता पार्टी नामक कई पार्टियों के एक गठबंधन द्वारा हराया गया था, जिसमें भाजपा की पूर्ववर्ती, भारतीय जनसंघ शामिल थी। जनता पार्टी को देश की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला था। उस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री थे। उस सरकार में बाबू जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे जननेता भी शामिल थे।

बहरहाल, जनता पार्टी की उस चुनाव में जीत के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार दो साल तक चली। उसके बाद वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी बिखर गई। मोरारजी देसाई सरकार में गृह मंत्री चरण सिंह को कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। संयोग देखिए कि अब चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी उस एनडीए सरकार का हिस्सा हैं जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बहरहाल, चरण सिंह 1979 में जनता पार्टी के बिखरे हुए समूहों के समर्थन और कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बने। लेकिन चरण सिंह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल 23 दिनों तक चला क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे चरण सिंह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस स्थिति के कारण देश में लोकसभा भंग करने के बाद 1980 में फिर चुनाव हुआ। इस बार इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ गईं, जब कांग्रेस ने 353 सीटें जीतीं।

लोकसभा के 1989 के चुनाव परिणाम भारत के लिए एक नये दौर को लेकर आए। यह पहली बार था जब राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा 529 सीटों में से 197 जीतने के बाद किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं किया था। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में भाजपा के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार 1990 में गिर गई जब भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया , जब उस समय के सबसे बड़े नेता, लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए आयोजित उनकी यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया गया था।1989 से 2004 तक, छह आम चुनावों में एक भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इनमें से कुछ गठबंधन विशेष रूप से अराजक रहे : 1989 और 1999 के बीच, आठ गठबंधन बनाए गए और कई जल्दी ही ढह गए। इस बीच, ये मानना होगा कि भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकारों के समय ही आए।

अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक रहे, जिन्होंने 1998 से 2004 तक एक सफल बहु-पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत में विदेशी निवेश बढ़ा, एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज हुआ, व्यापार बाधाओं को कम किया गया, और देश में आईटी क्रांति का जन्म हुआ। उनके ही दौर में देश ने पोखरण का परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान के साथ तनाव को कम किया और अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए।

और अतीत में, सफल अल्पसंख्यक सरकारें और भी कम सीटों के साथ चलाई गई हैं। कांग्रेस 1991 में 232 सीटों के साथ और 2004 और 2009 में केवल 145 और 206 सीटों के साथ एक सफल अल्पसंख्यक सरकार चलाने में सक्षम कोशिश की थी ।

मैं मानता हूं कि मोदी जी जनता दल के नेता नीतीश कुमार और तेलुगू देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू जैसे तपे हुए नेताओं के सहयोग से देश को एक मेहनती और ईमानदार गठबंधन सरकार देने में सफल रहेंगे। उन्हें अपनी पार्टी के अनेक अनुभवी नेताओं का समर्थन और सहयोग तो मिलेगा ही।

अब लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सरकार गठित हो गई है। अब इंडिया गठबंधन को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। उन्हें हर बात पर सरकार को कोसना छोड़ना होगा। रोज विधवा विलाप करने की आदत छोड़नी होगी ।आप चुनाव प्रचार के समय तो कुछ भी बोलते हैं। पर चुनाव नतीजों के आने के बाद आपको अपनी बयानबाजी सोच-समझकर करनी होती है। हां, विपक्ष को सरकार को राष्ट्र हित के मसलों पर सजग करते रहना होगा। लोकतंत्र में वाद, विवाद, संवाद लगातार जारी रहना चाहिए। इसके बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिल कर देश को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में बढ़ना होगा। संसद के दोनों सदनों में भी स्वस्थ और सार्थक बहस हो, यह देश देखना चाहता है। संसद में हंगामा और वॉक आउट ही नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के पुराण पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी को गठबंधन सरकारों को चलाते हुए देखा है। बेशक, वे गठबंधन सरकार को चलाते हुए अटल जी के फैसलों से प्रेरित होंगे।

पहली अग्नि परीक्षा में मोदी पास

महेश खरे

मोदी का करिश्मा तो गठबंधन के नेताओं को एकजुट रखेगा लेकिन यह ध्यान भी रखना होगा कि बेलगाम बयानबाजी गठबंधन की एकता में असमंजस और दरार डालती है। ऐसे बयानों पर लगाम लगाने की हिदायतों का ही यह असर है कि एनडीए के नेताओं के बयानों जोड़ने वाले स्वर ही बाहर आ रहे हैं। गठबंधन धर्म निभाने में कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ती है। मंत्रियों के ढ़ांचे को देखकर कहा जा सकता है कि मोदी ने राजनीतिक चतुराई के साथ अपनी टीम में अधिकतम राज्यों के प्रतिनिधित्व, जातीय समीकरण साधने के अलावा भविष्य पर पैनी नजर रखी है। गुजरात से मोदी के करीबी पुरुषोत्तम रुपाला को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी है... लेकिन प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटिल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। नवसारी से गुजरात में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले सीआर पाटिल भाजपा की पन्ना प्रमुख योजना के पुरोधा होने के साथ साथ मोदी के विश्वस्तों में से एक हैं। संभवतः राजपूतों को लेकर विवादित बयान देकर पार्टी को परेशानी में डालने वाले रुपाला स्वयं तो राजकोट से जीत गए लेकिन मंत्रिमंडल में अपनी सीट गंवा बैठे। रुपाला बहुत ही वरिष्ठ और लोकप्रिय नेता हैं। इसलिए उन्हें कोई अन्य जिम्मेदारी मिलने की संभावना है।

अपनी तीसरी पारी की अग्नि परीक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अव्वल नंबरों से पास हो गए। भाजपा की बहुमत वाली सरकारें चलाने के अनुभवी मोदी के लिए अल्पमत वाली भाजपा के दौर में 16 दलों की एनडीए सरकार के मंत्रियों का चयन किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था। सियासत के सर्वमान्य गुरु नरेन्द्र मोदी ने ना केवल तयशुदा अवधि में भारी-भरकम मंत्रिमंडल का गठन कर लिया अपितु एनडीए के मंत्रियों को शपथ लेने से पहले सरकारी कामकाज का पाठ भी पढ़ाया।

मोदी ने शपथ ग्रहण से पहले मंत्रियों को चाय पर बुलाया था। चाय पर चर्चा मोदी के लिए दही चीनी की तरह शुभ है। चाय के बहाने मोदी मंत्र ना मिले यह हो कैसे सकता है? 9 जून का सूरज नए मंत्रियों के लिए ज्ञान प्राप्ति का संदेश लेकर उदय हुआ। मोदी की कक्षा में केवल भाजपा के ही नहीं गठबंधन के वे चेहरे भी शिष्य भाव से उपस्थित थे जिन्हें शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंत्री पद की शपथ दिलाने वाली थीं। क्लास चली। 'मास्टर' मोदी ने 3.0 सरकार की नई राह दिखाई। मंत्री के रूप में क्या प्राथमिकताएं हैं? कामकाज कैसे चलाना है? नए मंत्रियों को मोदी ने जो प्राथमिकताएं बताईं उनमें ईमानदारी के साथ गरीब और मजदूरों की सेवा...100 दिन का रोड मैप बनाकर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना और कम-से-कम सप्ताह में चार दिन कार्यालय में उपस्थित रहना प्रमुख हैं।

मंत्रियों के लिए समय का कितना मूल्य है...यह समझने के लिए एक घटना पर्याप्त है। सुबह की चाय पर अमित शाह के बंगले पर 9 बजे पहुंचने का न्यौता पंजाब के रवनीत बिट्टू को भी मिला था। रास्ते में बिट्टू जिस कार से आ रहे थे वह खराब हो गई। समय गुजर रहा था। बिट्टू ने कार को छोड़कर गंतव्य की ओर दौड़ लगा दी और समय पर पहुंच गए। जिस सरकार में ऐसा अनुशासन हो उसे कामयाब होने से कौन रोक सकता है?

चाय पर चर्चा ने एक और बात साबित कर दी। वह यह कि एनडीए 3.0 सरकार के कामकाज में अनुशासन के साथ समय का पालन सबसे बड़ी प्राथमिकता है। जिस मनोयोग से क्लास में सहयोगी दलों के नेता भी मोदी को सुन रहे थे उससे यह संदेश भी जग जाहिर हुआ है कि मोदी का नेतृत्व सभी सहयोगियों ने दिल से स्वीकार किया है। फिलहाल यह भरोसा किया जा सकता है कि सत्ता और पद की होड़ सरकार चलाने में कोई समस्या बन कर नहीं उभरेगी। मोदी भाजपा के नेता तो हैं ही अब वह 16 दलों वाले एनडीए के सर्वसम्मत नेता भी हैं। मोदी का नेतृत्व और व्यक्तित्व है ही ऐसा जिसके पीछे सियासत चल देती है। इस भरोसे के साथ कि मोदी का नेतृत्व देश के विकास की पक्की गारंटी है।

गारंटी से याद आया। मोदी ने चुनाव प्रचार के समय मतदाताओं के समक्ष 24 गारंटियों का ऐलान किया था। तब यह गारंटी मोदी की थीं। अब यह एनडीए की 72 मंत्रियों वाली सरकार की जिम्मेदारी है। इसके लिए भी समय सीमा तय होगी। मोदी की क्लास में नई टीम को यह संदेश मिल चुका है। समय गंवाना मोदी को मंजूर नहीं। बिना समय गंवाए बड़े फैसलों के साथ कामकाज भी शुरू हो चुका है। पीएम मोदी ने जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए...उसने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। किसान सम्मान निधि की सत्रहवीं किस्त के रूप में 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की राशि जारी हो गई।

लेकिन, मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के भविष्य को लेकर देश में शंकाएं कुशंकाएं (पुराने अनुभवों को देखते हुए) जाहिर की जा रहीं हैं। सरकार की कार्यशैली और मंशा को देखते हुए निर्दलीय और विपक्ष के कुछ सांसद मोदी के नेतृत्व से आकर्षित होकर अगर पाला बदल लें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तीन राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव तक एनडीए का संख्या बल बढ़ने के संकेत तो मिलने लगे हैं। चुनाव नतीजों के तत्काल बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने एनडीए का संख्या बल 303 होने का दावा किया है।

महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनावों की बेला करीब आती जा रही है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव भी होंगे। बिहार का अगला चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नीतीश यही चाहते थे। उनकी यह मुराद पूरी होने तक जदयू मोदी के साथ ही रहेगा। लोकसभा चुनाव से निपटकर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। इसके साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में उम्मीद के अनुरूप चुनाव नतीजे नहीं आने के कारणों की भी समीक्षा शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ही हैं। अमित शाह से उनकी मुलाकात को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है।

मोदी का करिश्मा तो गठबंधन के नेताओं को एकजुट रखेगा लेकिन यह ध्यान भी रखना होगा कि बेलगाम बयानबाजी गठबंधन की एकता में असमंजस और दरार डालती है। ऐसे बयानों पर लगाम लगाने की हिदायतों का ही यह असर है कि एनडीए के नेताओं के बयानों जोड़ने वाले स्वर ही बाहर आ रहे हैं।

गठबंधन धर्म निभाने में कुछ तो कुर्बानियां देनी पड़ती है। मंत्रियों के ढ़ांचे को देखकर कहा जा सकता है कि मोदी ने राजनीतिक चतुराई के साथ अपनी टीम में अधिकतम राज्यों के प्रतिनिधित्व, जातीय समीकरण साधने के अलावा भविष्य पर पैनी नजर रखी है। गुजरात से मोदी के करीबी पुरुषोत्तम रुपाला को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल सकी है... लेकिन प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटिल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। नवसारी से गुजरात में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाने वाले सीआर पाटिल भाजपा की पन्ना प्रमुख योजना के पुरोधा होने के साथ साथ मोदी के विश्वस्तों में से एक हैं। संभवतः राजपूतों को लेकर विवादित बयान देकर पार्टी को परेशानी में डालने वाले रुपाला स्वयं तो राजकोट से जीत गए लेकिन मंत्रिमंडल में अपनी सीट गंवा बैठे। रुपाला बहुत ही वरिष्ठ और लोकप्रिय नेता हैं। इसलिए उन्हें कोई अन्य जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। भाजपा केरल और पंजाब में पैर जमाने के प्रयास में है। यही कारण है कि कुरियन और रवनीत बिट्टू को चुनाव हारने के बाद भी सरकार का हिस्सा बनाया गया है। भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार कर मंत्रिमंडल से बाहर हैं। वहीं हिमाचल से जीत कर आए युवा नेता अनुराग ठाकुर समेत पिछली सरकार के 37 मंत्री इस बार मंत्री पद से वंचित हैं। बिहार के चर्चित युवा चेहरे चिराग पासवान मोदी की टीम का हिस्सा बने हैं। उनको पांच सीटें मिली थीं। पांचों सीटें जीत कर उन्होंने मोदी का भरोसा जीता है।

सहयोगी दलों के 12 चेहरों को मंत्री बनाया गया है। चयन में दलीय कोटा का ध्यान तो रखना ही गया है...अनुभव, वरिष्ठता का खास ध्यान रखा गया है। मध्यप्रदेश से पांच मंत्रियों में दो बड़े चेहरे शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

पहले किसानोंकी सुधि

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने रविवारको लगातार तीसरी बार पद और गोपनीयताका शपथ ग्रहणके उपरान्त सोमवारको अपना कार्यभार सम्भाल लिया। उन्होंने सबसे पहले किसानोंकी सुधि ली और उन्हें बड़ी सौगात दी है। किसान सम्माननिधिकी १७वीं किस्त मदसे बीस हजार करोड़ रुपये जारी करनेका आदेश किसानोंके हितमें स्वागतयोग्य है। इससे देशके नौ करोड़ ३० लाखसे अधिक किसान लाभान्वित होंगे। प्रधान मंत्री मोदीने फाइलपर हस्ताक्षर करनेके बाद कहा कि हम किसानोंके कल्याणके लिए अधिकसे अधिक काम करना चाहते हैं। हमारी सरकार पहलेसे काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इसके पूर्व फरवरी माहमें प्रधान मंत्रीने किसान सम्माननिधिके तहत देशके करोड़ों किसानोंको १६वीं किस्त जारी की थी। इस योजनाके तहत किसानोंको प्रति वर्ष छह हजार रुपयेकी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। दो-दो हजार रुपयेकी तीन किस्तोंमें सहायता राशि सीधे किसानोंके बैंक खातोंमें भेज दी जाती है। इस योजनाके तहत चार महीनेमें एक बार धनराशि भेजी जाती है। निश्चित रूपसे किसान सम्माननिधिसे मिलनेवाली राशि किसानोंके लिए राहतकारी है लेकिन किसानोंकी अन्य समस्याएं भी हैं, जिनके लिए भी कार्य होने चाहिए। सबसे प्रमुख विषय किसानोंको उनकी फसलोंका उचित और लाभकारी मूल्य से सम्बन्धित है। किसानोंको जबतक लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तबतक उनकी आर्थिक स्थितिमें सुधार नहीं होनेवाला है। किसान कर्ज लेकर खेती करता है लेकिन उसे उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। वह कर्जकी अदायगी भी नहीं कर पाता है। हर वर्ष किसान आत्महत्या करनेको विवश हो जाते हैं। यह कृषिप्रधान देश भारतके लिए अत्यन्त ही दुर्भाग्यकी बात है। किसानोंके हितमें केन्द्र सरकार सतत प्रयास करती रहती है। कल्याणकारी योजनाएं भी बनायी गयी हैं और उनका क्रियान्वयन भी होता है लेकिन किसानोंकी मूलभूत समस्याओंके समाधानकी दिशामें विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता है। उम्मीद है प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीकी वर्तमान सरकार इस दिशामें अवश्य महत्वपूर्ण कदम उठायेगी। तीसरे कार्यकालका पहला दिन किसानोंके हितके कार्योंसे शुरू हुआ है, यह देशके करोड़ों किसानोंके लिए शुभ संकेत है। प्रधान मंत्री मोदीने लोकसभा चुनावोंके दौरान किसानोंसे जो वादे किये हैं, वे भी पूरे किये जायंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है। किसानोंकी समृद्धिसे ही देश समृद्ध होगा। उन्हें समृद्ध बनानेका दायित्व भी सरकारपर है।

जम्मूमें आतंकी हमला

जम्मूमें आतंकियोंका एक बार फिर सिर उठाना गम्भीर चिन्ताकी बात है। सरकारकी लाख कोशिशोंके बाद भी आतंकी गतिविधियां पूरी तरह रुक नहीं पायी है। जीरो टालरेंसकी सफलतापर प्रश्न खड़ा करनेवाली ऐसी गतिविधियां जहां केन्द्र सरकारके लिए सबक है वहीं बड़ी चुनौती भी है। जम्मू-कश्मीरमें इस समय केन्द्रकी सरकार है, ऐसेमें श्रद्धालुओंसे भरी बसको निशाना बनाया जाना हैरान करनेवाला है। जम्मू सम्भागके रियासी जिलेके शिवखोड़ी धामके दर्शन कर लौट रही तीर्थयात्रियोंसे भरी बसपर रविवारको आतंकियोंने घात लगाकर जिस तरह हमला किया उसने अतीतकी आतंकी घटनाओंकी याद ताजा कर दी। आतंकियोंने पहले बस चालकपर और फिर तीर्थयात्रियोंपर अंधाधुन्ध गोलीबारी की, जिससे बस अनियंत्रित होकर खाईंमें जा गिरी। इस घटनामें नौ लोगोंकी मौत और ३३ अन्यका घायल होना अत्यन्त दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रद्धालुओंमें अधिकतर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्लीके रहने वाले हैं। इस घटनाको पूरी तरह सोची-समझी साजिशके तहत अंजाम दिया गया है, क्योंकि उस समय नरेन्द्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्रीकी शपथ लेने जा रहे थे। अब देखना है कि केन्द्र सरकार इसे किस रूपमें लेती है और कैसे इससे निबटती है। इस मर्माहत कर देनेवाली घटनासे सुरक्षा एजेंसियों और निगरानी तंत्रकी खामियां भी उजागर हुई हैं। हैरान करनेवाली बात यह है कि रियासी जिलेमें सक्रिय आतंकियोंको सीमापारसे लगातार हमला करनेके फरमान जारी हो रहे थे और इसके इनपुट भी एजेंसियोंको मिल रहे थे। निकट भविष्यमें जम्मू-कश्मीरमें विधानसभा चुनाव होनेवाले हैं और सीमापार आतंकी संघटन इसके पूर्व ही माहौल बिगाड़नेकी साजिश रच रहे हैं जिसपर अंकुश लगानेके लिए बड़ीसे बड़ी कारवाईकी जरूरत है।

लोक संवाद

आर्थिक मुद्दोंको महत्व

महोदय,-लोकसभा चुनावके नतीजे उन लोगोंके लिए एक झटकेके रूपमें सामने आये हैं, जिन्होंने एग्जिट पोलपर विश्वास कर लिया था। एक मुख्य व्याख्या यह है कि इण्डी गठबंधनने सामाजिक न्याय और जाति जनगणनापर जोर दिया और अधिक चतुर गठबंधन बनाये रखा। जातिके संदर्भमें उम्मीदवारोंके लिए स्पष्ट विकल्प भी गठबंधनने बनाये। साहसी राज्योंमें स्थानीय कारकोंने भी भूमिका निभायी होगी। अगली सरकार बननेपर उसे मतदाताओंके स्पष्ट संदेशको पहचानना होगा। आर्थिक मुद्दोंका महत्वए बेरोजगारी और लगातार कम मजदूरी, स्व-रोजगारसे अपर्याप्त आजीविका और आवश्यक वस्तुओंकी बढ़ती कीमतोंके प्रमुख संकटोंको चुनावोंके दौरान नजरअंदाज कर दिया गया। ये मुद्दे देशके अधिकांश लोगोंके जीवनको प्रभावित कर रहे हैं। यह वह जगह है जहां इंडिया् गठबंधन, खासकर कांग्रेस द्वारा किये गये वायदे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे हिंदीपट्टीके कुछ हिस्सोंमें। विपक्षी पार्टियोंने सामाजिक न्यायके साथ-साथ आजीविका और रोजगारके मुद्दोंपर ध्यान केंद्रित किया। उनके वायदे निःसंदेह अधिकांश मतदाताओंके बीच प्रतिध्वनित हुए। युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकोंके लिए न्यायके साथ-साथ सामाजिक न्यायके माध्यमसे सम्मानपर ध्यान, जिसे उदाहरणके लिए कांग्रेसके घोषणा-पत्रमें उजागर किया गया था, आवश्यक रूपसे आर्थिक नीतिमें एक बड़े बदलावका संकेत देता है। वास्तवमें जो आवश्यक है वह मूलभूत परिवर्तनसे कम नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओंके वितरणको देश या सर्वोच्च नेतासे उपहारके रूपमें देखनेके बजाय मानवाधिकारों, विशेष रूपसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारोंके ढांचेपर वापस जाना है। इसके लिए तत्काल दो बातोंकी आवश्यकता है। पहला काम श्रमिकोंके अधिकारका विस्तार करके (बेहतर वित्त पोषित और अधिक सुलभ मनरेगाके साथ-साथ शहरी रोजगार गारंटी योजनाकी शुरुआतके माध्यमसे) सभीके लिए बुनियादी सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करना है। भोजनका अधिकार, जो अब भी अपर्याप्त है और कमसे कम सौ मिलियन भारतीयोंको इससे वंचित किया गया है। दूसरा है लाखों युवाओंकी निराश आकांक्षाओंको पूरा करनेके लिए नौकरियां पैदा करना है। यह प्राथमिक आर्थिक लक्ष्य बनना चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक रोजगारके विस्तारकी आवश्यकता है। सबसे पहले, रिक्तियोंको भरनेकी आवश्यकता है और योजनाके तहत श्रमिकों सहित सभी सार्वजनिक कर्मचारियोंको नियमित करनेकी आवश्यकता है। सूक्ष्मए लघु और मध्यम उद्यमोंकी जरूरतें पिछले दशककी नीतिगत गलतियोंसे प्रभावित हुई हैं। मोदीके नये कल्याणवादके बारेमें बहुत कुछ कहा जा चुका है लेकिन इसे अधिक सटीक रूपसे कल्याणवादके आसपास नयी ब्रांडिंगके रूपमें वर्णित किया गया है। केन्द्र और राज्यकी सफल सरकारें कल्याणकारी योजनाओंके प्रावधानकी ओर उन्मुख रही हैं, जो देशके अधिकांश हिस्सोंमें निरंतर गरीबी और खराब मानव विकास संकेतकोंको देखते हुए आवश्यक हैं। मोदी सरकारने अपने हस्तक्षेपोंको नये रूपमें विज्ञापित किया जबकि ये पुरानी योजनाओंका विस्तार है। इस चुनावके परिणामस्वरूप एक महत्वपूर्ण बदलाव आनेकी संभावना है। वह पिछले दशकमें स्पष्ट अलोकतांत्रिक केंद्रीकरणसे दूर, संघवादका पुनरुद्धार है। अधिकांश राज्य सरकारें सार्वजनिक सेवा वितरणके लिए जिम्मेदार हैं जो लोगों द्वारा चुनी जाती हैं। उनके लिए केन्द्रके हस्तक्षेप, नियंत्रण और पक्षपातके बिना इन्हें प्रदान करनेमें सक्षम होना महत्वपूर्ण है। **-जयति घोष, वाया ईमेल।**

वायुमण्डलीय अस्थिरताका खतरा

हवाई यात्रियोंके लिए थोड़ी-बहुत टर्बुलेंस एक आम अनुभव है। लेकिन हालिया स्तरकी गंभीर घटनाएं दुर्लभ हैं, जब वे घटती हैं तो घातक हो सकती हैं। टर्बुलेंस हवाके अनियमित प्रवाहके कारण होती है, जिससे यात्रियों और चालक दलको अचानक साइडमें और ऊपरकी तरफ तगड़े झटके लगते हैं।

❐ मुकुल व्यास

हालमें आकाशमें दो विमानोंको टर्बुलेंस (वायुमंडलीय अस्थिरता) का सामना करना पड़ा। लंदनसे सिंगापुर जानेवाली सिंगापुर एयरलाइंसकी फ्लाइटमें तीव्र टर्बुलेंससे एक व्यक्तिकी दिलका दौरा पड़नेसे मृत्यु हो गयी और कई अन्य बुरी तरह घायल हो गये। इस घटनाके कुछ दिन बाद ही दोहासे डबलिन जा रहे कतर एयरवेजके विमानमें टर्बुलेंस आनेसे १२ लोग घायल हो गये। सिंगापुर एयरलाइंसके विमानमें आयी भीषण टर्बुलेंसकी शुरुआती जांचसे पता चला है कि विमान ४.६ सेकंडमें लगभग ५४ मीटर नीचे गिर गया था। सिंगापुरके ट्रांसपोर्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोके प्रारंभिक निष्कर्षोंमें गुरुत्वाकर्षण बलमें तेजीसे परिवर्तन और ऊंचाईमें गिरावट पायी गयी। यह दूरी इटलीके पीसाकी झुकी हुई मीनारकी ऊंचाईके लगभग बराबर है। इस घटनामें संभवतः वे लोग घायल हुए जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। हवाई यात्रियोंके लिए थोड़ी बहुत टर्बुलेंस एक आम अनुभव है। लेकिन हालिया स्तरकी गम्भीर घटनाएं दुर्लभ हैं, जब वे घटती हैं तो घातक हो सकती हैं। टर्बुलेंस हवाके अनियमित प्रवाहके कारण होती है, जिससे यात्रियों और चालक दलको अचानक साइडमें और ऊपरकी तरफ तगड़े झटके लगते हैं। एयर टर्बुलेंसकी घटना कहीं भी हो सकती है, लेकिन कुछ मार्गोंपर यह दूसरोंकी तुलनामें कहीं अधिक आम है। जलवायु परिवर्तनसे एयर टर्बुलेंसकी संभावना बढ़ने और इसके और अधिक तीव्र होनेकी आशंका है। वास्तवमें कुछ शोधसे संकेत मिलता है कि पिछले कुछ दशकोंमें टर्बुलेंसकी स्थिति पहलेसे बदतर हो गयी है। लगभग हर उड़ान किसी न किसी रूपमें एयर टर्बुलेंसका अनुभव करती है। यदि कोई विमान दूसरे विमानके पीछे उड़ान भर रहा है या उतर रहा है तो पहले विमानके इंजन और पंखोंके सिरों द्वारा उत्पन्न हवा पीछेवालेके लिए टर्बुलेंसका कारण बन सकती है। हवाई अड्डेके पासके क्षेत्रसे गुजरनेवाली तेज हवाओंके कारण एयर टर्बुलेंस हो सकती है। अधिक ऊंचाईपर विमान यदि किसी अन्य विमानके करीब उड़ रहा हो या तूफानकी चपेटमें आया हो तो भी टर्बुलेंसकी घटना घट सकती है। एक अन्य प्रकारकी एयर टर्बुलेंस जो अधिक ऊंचाईपर होती है, उसका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। इसे क्लियर एयर टर्बुलेंस कहते हैं। जैसा कि नामसे स्पष्ट है, यह अदृश्य होती है। यह तूफान या बादलों जैसे किसी भी दृश्य संकेतसे जुड़ी नहीं होती। नियमित टर्बुलेंसके विपरीत यह अचानक आती है और इससे बचना मुश्किल होता है। यह अकसर गर्म हवाके ठंडी हवाकी तरफ बढ़नेके कारण होता है। जलवायु परिवर्तनके कारण इसके बदतर होनेकी आशंका है। सबसे बुनियादी स्तरपर एयर टर्बुलेंस दो या दोसे अधिक पवन संबंधित घटनाओंके टकरानेका परिणाम है। ऐसा अकसर पर्वत श्रृंखलाओंके पास होता है, क्योंकि भू-भागपर बहनेवाली हवा ऊपरकी ओर तेज हो जाती है। टर्बुलेंसकी घटनाएं अकसर जेट स्ट्रीमके किनारोंपर भी होती हैं। जेट स्ट्रीम दरअसल दुनियाभरमें ऊंचाईपर चक्कर लगानेवाली तेज हवाओंकी पतली पट्टियां हैं। गति बढ़ानेके लिए विमान अकसर जेट स्ट्रीममें यात्रा करते हैं लेकिन जेट स्ट्रीममें प्रवेश करते या छोड़ते समय कुछ टर्बुलेंस हो सकती है।

अन्य प्रकारकी एयर टर्बुलेंस, जो अधिक ऊंचाईपर होती है, पूर्वानुमान कठिन होता है। इसे क्लियर एयर टर्बुलेंस कहते हैं। यह अदृश्य होती है। यह तूफान या बादलों जैसे किसी भी दृश्य संकेतसे जुड़ी नहीं होती। नियमित टर्बुलेंसके विपरीत यह अचानक आती है और इससे बचना मुश्किल होता है। यह अकसर गर्म हवाके ठंडी हवाकी तरफ बढ़नेसे होता है। जलवायु परिवर्तनसे इसके बदतर होनेकी आशंका है। सबसे बुनियादी स्तरपर एयर टर्बुलेंस दोसे अधिक पवन संबंधित घटनाओंके टकरानेका परिणाम है। ऐसा अकसर पर्वत श्रृंखलाओंके पास होता है, क्योंकि भू-भागपर बहनेवाली हवा ऊपरकी ओर तेज हो जाती है।

अमेरिकामें हर साल लगभग ६५,००० विमान मध्यम टर्बुलेंस और लगभग ५,५०० गम्भीर टर्बुलेंसका सामना करते हैं। हालांकि यह संख्या बढ़नेवाली है। ब्रिटेनमें यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंगमें वायुमंडलीय विज्ञानके प्रोफेसर पॉल विलियम्सका मानना है कि जलवायु परिवर्तन टर्बुलेंसको बदल रहा है। विलियम्सने कहा, हमने कुछ कम्प्यूटर सिमुलेशन चलाये और पाया कि आने वाले दशकोंमें गम्भीर टर्बुलेंस दोगुनी या तिगुनी हो सकती है। सम्पूर्ण विश्वमें टर्बुलेंस पैटर्नका मानचित्रण करना सम्भव है। वैकल्पिक हवाई अड्डों या आपात स्थितियोंके लिए अग्रिम योजना बनानेके लिए एयरलाइंस इन मानचित्रोंका उपयोग करती हैं। मौसमकी स्थितिके साथ टर्बुलेंस बदलती है। कुछ क्षेत्रों और मार्गोंपर दूसरोंकी तुलनामें इसका खतरा अधिक होता है। टर्बुलेंसवाले अधिकांश मार्ग पहाड़ोंके करीबसे गुजरते हैं। पिछले साल प्रकाशित एक अध्ययनमें १९७९ और २०२० के बीच क्लियर टर्बुलेंसमें बड़ी वृद्धिका प्रमाण मिला। कुछ स्थानोंपर गम्भीर टर्बुलेंसमें ५५ प्रतिशततककी वृद्धि हुई। वर्ष २०१७ में एक अलग अध्ययनमें जलवायु मॉडलिंगका उपयोग करके यह अनुमान लगाया गया कि कुछ जलवायु परिवर्तन परिदृश्योंके तहत, २०५० तक क्लीयर एयर टर्बुलेंसमें चार गुना वृद्धि आम हो सकती है। टर्बुलेंसका पता लगानेकी तकनीक अब भी अनुसंधान और विकासके चरणमें है। इसलिए पायलट अपने उड़ान पथसे ठीक पहले उच्च स्तरकी नमीवाले मौसमसे बचनेकी कोशिश करते हैं। इसके लिए वे सर्वोत्तम योजना निर्धारित करनेके लिए मौसम राडारसे प्राप्त ज्ञानका उपयोग करते हैं। जब उन्हें अत्यंत तीव्र टर्बुलेंसका सामना करना पड़ता है तो वे तुरंत सीट बेल्ट बांधनेके संकेत चालू कर देते हैं और विमानको धीमा करनेके लिए इंजनका जोर कम कर देते हैं। भू-आधारित मौसम विज्ञान केन्द्र उपग्रहोंकी सहायतासे मौसमके मिजाजको विकसित होते हुए देख सकते हैं।

वे वास्तविक समयमें उड़ान कर्मियोंको यह जानकारी दे सकते हैं कि उनकी उड़ानके दौरान मौसम कैसा रहेगा। यदि अपेक्षित उड़ान मार्गपर तूफान विकसित होता है तो इसमें अपेक्षित टर्बुलेंसके क्षेत्र भी शामिल हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया और अधिक टर्बुलेंसवाले समयकी तरफ बढ़ रही है। एयरलाइंस विमानों और यात्रियोंपर इसके प्रभावको कम करनेके लिए हरसंभव प्रयास करेंगी। लेकिन आम हवाई यात्रीके लिए खास संदेश यह है कि वे सीट बेल्ट बांधनेके निर्देशकी अनदेखी न करें।

झुलसाती हवाओंकी चपेटमें विश्व

पृथ्वीका औसत तापमान बढ़ता ही जा रहा है। दुनियाभरमें भीषण गर्मीका प्रकोप जारी है। कहीं बहुत ज्यादा गर्मीके चलते जंगलोंमें आग लग रही है तो कहीं लोगोंको पानीकी कमीसे जूझना पड़ रहा है।

❐ शशांक द्विवेदी

भारतके भी कई राज्योंमें गर्मी और उमससे लोग बेहाल हैं। अपने ठंडे मौसमके लिए पहचाने जानेवाले यूरोप और अमेरिका भी एतिहासिक गर्मीका सामना कर रहे हैं। इसी बीच संयुक्त राष्ट्रने एक डरानेवाली चेतावनी जारी की है। यूएनके मुताबिक जलवायु परिवर्तनके कारण अकेले दक्षिण एशियामें तीन-चौथाई बच्चे खतरनाक गर्मीकी चपेटमें हैं, जिनकी संख्या करीब ४६ करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफके मुताबिक मौजूदा समयमें दुनियामें सबसे ज्यादा तापमान दक्षिण एशियामें है। जलवायु परिवर्तनके भयंकर असरके कारण इस क्षेत्रके तापमानमें असामान्य रूपसे वृद्धि हो रही है। इस बढ़ते हुए तापमानका सबसे ज्यादा असर बच्चोंपर पड़ रहा है। एक अनुमानके मुताबिक दक्षिण एशियामें १८ सालसे कम उम्रके ७६ फीसदी बच्चे भीषण तापमानवाले इलाकोंमें रहते हैं। इनकी तादाद करीब ४६ करोड़ है। यूनिसेफके मुताबिक यदि वैश्विक स्तरपर बात की जाय तो हर तीनमेंसे एक बच्चा भीषण गर्मीसे प्रभावित है। क्योंकि बच्चोंमें जलवायु परिवर्तनके साथ अपने शरीरके तापमानको ढालनेकी क्षमता नहीं होती है। विशेषज्ञोंके अनुसार जलवायु परिवर्तन इस हीटवेवको मुख्य वजह है। वहीं ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (जीएचजी), जो कोयले, गैस और तेल जैसे जीवाश्म ईंधनको जलानेसे आता है, वह हीटवेवको अधिक गर्म और खतरनाक बना रहा है। वैश्विक तापमान उबालपर है। आंकड़ोंसे साफ है कि दक्षिण एशियामें कराड़ों बच्चोंका जीवन हीटवेव और बहुत ज्यादा तापमानके कारण जोखिममें पड़ गया है। यूएनकी ओरसे जारी चेतावनीके मुताबिक भारत समेत अफगानिस्तान, बंगलादेश, मालदीव और पाकिस्तानमें जलवायु परिवर्तनके असरके कारण बच्चे ही सबसे ज्यादा जोखिममें हैं। अनुमान है कि दक्षिण एशियाके इन देशोंमें हर साल कमसे कम ८३ दिन ३५ डिग्री सेल्सियससे ज्यादा तापमान रहता है। विशेषज्ञोंके मुताबिक बच्चे अपने शरीरको इतने ज्यादा तापमानके मुताबिक ढालनेमें सक्षम नहीं होते हैं।

यूएनके अंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनकी अप्रैलमें आयी रिपोर्टके मुताबिक दुनियाभरमें हर साल काम काजके दौरान करीब १९,००० लोग गर्मीके चलते मारे जा रहे हैं। आसान भाषामें समझें तो एक ऐसा बिंदु आता है जब शरीर खुदको ठंडा नहीं कर पाता है। असलमें पानीकी कमीसे बॉडी डिहाइड्रेशनका शिकार हो जाती है। जब शरीरमें पानीकी कमी होती है तो पानीके साथ कई जरूरी मिनरल और विटामिनकी कमी भी हो जाती है। इस वजहसे बॉडीके कई ऑर्गन जैसे किडनी, लंग्स और हार्ट डैमेज हो सकते हैं और उस वजहसे लोगोंकी मौत हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंगकी वजहसे तीसरा ध्रुव कहे जानेंवाले हिमालयके ग्लेशियर दस गुना तेजीसे पिघल रहे हैं। तीसरा ध्रुव नामसे जाना जानेवाला हिमालय अंटार्कटिका और आर्कटिकके बाद ग्लेतशियर बर्फका तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है। वैज्ञानिकोंके अनुसार ४०० से ७०० साल पहलेके मुकाबले पिछले कुछ दशकोंमें हिमालयके ग्लेशियर दस गुना तेजीसे पिघले हैं। यह गतिविधि साल २००० के बाद ज्यादा बढ़ी है। साइन्स जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्समें प्रकाशित हुए एक शोधके अनुसार इससे एशियामें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदीके किनारे रहनेवाले करोड़ों भारतीयोंपर पानीका संकट आ सकता है। ब्रिटेनकी लीड्स यूनिवर्सिटीके शोधकर्ताओंके अनुसार आज हिमालयसे बर्फके पिघलनेकी गति लिटल आइस एजके वक्तसे औसतन दस गुना ज्यादा है। लिटल आइस एजका काल १६वींसे १९वीं सदीके बीचका था। इस दौरान बड़े पहाड़ी ग्लेशियरका विस्तार हुआ था। वैज्ञानिकोंकी मानें तो हिमालयके ग्लेशियर दूसरे ग्लेशियरके मुकाबले ज्यादा तेजीसे पिघल रहे हैं। हर साल गर्मीके रिकॉर्ड टूट रहे हैं। कथित विकासकी अंधी दौड़में शामिल दुनिया क्या खौलती गर्मियोंसे दुनियाको बचा पायेगी। वैज्ञानिकोंके मुताबिक पिछले साल उत्तरी गोलार्धमें इतनी गर्मी पड़ी कि करीब दो हजार सालका रिकॉर्ड टूट गया। २०२३ को धरतीपर अबतक सबसे गर्म वर्ष कहा गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेष भी इसे वैश्विक उबालका दौर कह चुके हैं। २०२४ में भी भीषण गर्मी अबतक एशियाके कई देशोंको झुलसा चुकी है।

भारतमें भी भीषण गर्मीका कहर जारी है। देशके कई इलाके हीटवेवकी चपेटमें है। इस बीच मौसम विभागने देशमें हीटवेवको लेकर चेतावनी जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत समेत मैदानी इलाकोंमें भीषण लूकी स्थिति जारी रहनेकी संभावना है। पारम्परिक जीवाश्म ईंधनके बहुत ज्यादा इस्तेमालके कारण ग्लोबल वार्मिंगने हीटवेवको ज्यादा गर्म और ज्यादा लम्बा बना दिया है। इसके अलावा तूफान और बाढ़ जैसी दूसरी मौसमकी चरम स्थितियोंको भी तेज कर दिया है। कुल मिलाकर दुनिया हानिकारक गैसोंके उत्सर्जनके कारण भयंकर समस्याओंका सामना कर रही है। इस दशकमें पूरी दुनियाको प्रदूषणको बेहद कम करना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आनेवाले समयमें हालात ज्यादा खराब हो जायंगे। भीषण गर्मी और हीट वेव, धरतीके तापमानमें असंतुलन और जलवायु परिवर्तनकी वजहसे हो रहा है, जिसका दायरा अब वैश्विक हो गया है। जमीनी सचाई यह है कि बड़े पैमानेपर ग्लेशियर्सका पिघलना और दुनियाभरमें हीटवेव बहुत बड़े वैश्विक खतरेंकी आहट है, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। कथित विकासकी बेहोशीसे दुनियाको जागना पड़ेगा।

आत्मबोध

उपासना

❐ सिद्धगुरु प्रमोदजी

भारतवर्षमें एक हजार सालकी लम्बी गुलामीके समय महिलाओंपर हुए अत्याचारके कारण महिलाओंको पर्देमें रखनेकी प्रथा अस्तित्वमें आयी, लेकिन उसका दुष्परिणाम हुआ कि 'सभ्य' कहे जानेवाले समाजमें महिलाओंकी स्वतंत्रता और उनके अधिकारोंपर अंकुश लगाये वे आर्थिक रूपसे परतंत्र हो गयीं, पीढ़ी-दर-पीढ़ी महिलाएं और ज्यादा दब्बू होती चली गयीं और अंततः वे लगभग हर मामलेमें पुरुषोंपर निर्भर हो गयीं। ऐसा सिर्फ 'सभ्य समाज' में हुआ, क्योंकि जंगलों और गुफाओंमें रहनेवाली, 'असभ्य' मानी जानेवाली जनजातिकी महिलाएं आज भी सभ्य समाजकी महिलाओंकी अपेक्षा कहीं अधिक स्वतंत्र हैं। पिछली आधी शताब्दीसे सभ्य कहे जानेवाले समाजमें महिला अधिकारोंकी बात चली है, महिलाएं घरसे बाहर निकली हैं और उन्होंने हर क्षेत्रमें पुरुषोंसे ज्यादा बढ़िया काम किया है और अपनी स्वतंत्रता हासिल करनेमें सफलता प्राप्त की है। लेकिन अब भी महिलाओंका एक बहुत बड़ा वर्ग इस स्वाभाविक अधिकारसे वंचित है। आर्थिक और तकनीकी प्रगतिके साथ ही डेटिंग, बलात्कार, शादीके बादके अवैध रिश्ते और तलाककी घटनाओंकी बाढ़-सी आ गयी है। दोनों पक्ष इसके लिए बराबरके जिम्मेदार हैं। वासनाका यह खेल व्यभिचारका कारण न बने, इसके लिए 'सहज संन्यास' की परम्परामें 'दिव्य समागम' का प्रावधान है और यह सिर्फ शादीशुदा जोड़ों, विधुर पुरुषों या विधवा महिलाओंके लिए ही मान्य है। 'दिव्य समागम' एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवित या मृत जीवनसाथीसे सहवासका आनन्द ले सकता है। 'दिव्य समागम' की खासियत यह है कि यह कोई शारीरिक क्रिया न होनेके बावजूद वैसा ही संतुष्टि प्रदान करता है। यह व्यक्तिको चरित्र भ्रष्ट होनेसे बचाता है और यदि इसे सामाजिक स्वीकृति मिल जाय तो यह शारीरिक शोषणके सामाजिक अपराधोंकी रोकथामका एक बड़ा साधन हो सकता है। अति कहीं भी अच्छी नहीं होती। परिवार, समाजमें रहते हुए, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियोंका निर्वहन करते हुए संयमित जीवनशैली अपनाकर व्यक्ति आध्यात्मिकताकी सीढ़ियां चढ़ सकता है और अंततः जीवनसे सीखनेकी जिस आवश्यकताके कारण उसने जन्म लिया था, उसे पूरा करते हुए जन्म-मरणके चक्करसे मुक्त होकर परमात्माके साथ एकाकार हो सकता है। यह कहना तो आसान है ही, करना भी बहुत कठिन नहीं है। धीरे-धीरे एक-एक कदम उठाते हुए, एक-एक बाधा पार करते हुए, हम जीवनका वह लक्ष्य पा सकते हैं। इस प्रकार हम उपासनाके आनन्दमें लीन होना सीख लेते हैं।

जासूसी करनेवालोंको हो फांसीकी सजा

❐ आर.के. सिन्हा

लोकसभा चुनावोंके नतीजोंके कोलाहलमें बीते दिनों पाकिस्तानके लिए जासूसी करनेवाले एक देशके दुश्मनको दी गयी उम्रकैदकी सजाकी खबर लगभग दब-सी गयी। ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेडके पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवालको पाकिस्तानके लिए जासूसी करनेके आरोप साबित होनेपर आजीवन कारावासकी सजा नागपुर जिला न्यायालयने सुनायी। अग्रवालको पाकिस्तानकी खुफिया एजेंसी आईएसआईकी ओरसे जासूसी गतिविधियोंके लिए आधिकारिक गोपनीयता अधिनियमके तहत दोषी ठहराया गया था। आजीवन कारावासके साथ-साथ उन्हें १४ सालके कठोर कारावास और ३००० रुपयेका जुर्माना भी लगाया गया। देशके गद्दारोंको इसी तरहकी सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि कोई मातृभूमिके साथ गद्दारी करनेके बारेमें सोचे भी नहीं। आपको याद होगा कि छह साल पहले २०१८ में इस मामलेने पूरे देशमें हलचल मचा दी थी। क्योंकि यह ब्रह्मोस एयरोस्पेससे जुड़ा जासूसीका पहला मामला था। अग्रवाल दो फेसबुक अकाउंट नेहा शर्मा और पूजा रंजनके जरिये संदिग्ध पाकिस्तानी खुफिया एजेंटोंके संपर्कमें था। इस्लामाबादसे चलाये जा रहे इन अकाउंट्सके बारेमें माना जाता है कि इन्हें पाकिस्तानके खुफिया एजेंट चला रहे थे। ब्रह्मोस मिसाइलकी जानकारी लीक करनेके आरोपमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र एटीएस और मिलिट्री इंटेलिजेंसने अग्रवालको गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसियोंने दावा किया कि उसके कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणोंकी जांच की गयी और पाया गया कि संवेदनशील डेटा ट्रांसफर किया गया था। यह कौन नहीं जानता कि हमारे यहां सेनाकी जासूसी करनेवाले जयचंद और मीर जाफर भी जगह-जगह मौजूद हैं। इनमें सेनाके अन्दर ही छिपे कुछ गद्दारों, सरकारी अफसरोंसे लेकर तथाकथित पत्रकार आदि भी बहुरूपिये शामिल हैं, जो दिखते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ये आरटीआईके माध्यमसे धीरे-धीरे सूचनाएं निकालनेकी जुगाड़में लगे रहते हैं। इन्हें अपने आकाओंसे मोटा पैसा जो मिलता है। इसलिए ये अपनी मातृभूमिका भी सौदा करनेसे पीछे नहीं हटते। इनका जमीर मर चुका है। दरअसल सूचनाके अधिकार (आरटीआई) की आड़में भारतीय सेनाकी तैयारियोंको लेकर कुछ देश विरोधी ताकतें सूचनाएं निकालनेकी फिराकमें रहते हैं। यह ही तत्व सेनासे संबंधित जानकारियां सूचनाके अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगते हैं। यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है, क्योंकि इधर देखनेमें आ रहा है कि कुछ तत्व सेनाकी अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण जानकारियोंको हासिल करनेमें भी अनावश्यक दिलचस्पी लेने लगे हैं। केन्द्रीय कैबिनेट सचिवकी अध्यक्षतामें हुई एक बैठक २८ अप्रैल, २०२२ को हुई थी, जिसमें इस बातपर गम्भीर चिन्ता जतायी गयी थी कि आरटीआईके नामपर सेनाकी अहम जानकारियां मांगी जा रही हैं। यह बैठक सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणेके रिटायर होनेसे दो दिन पहले ही हुई थी। देशके नागरिकोंको आरटीआई कानूनके तहत सूचना पानेके अधिकारोंकी सीमाएं भी हैं। सूचना अधिकारके द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकोंको, अपने कार्यको और शासन प्रणालीको सार्वजनिक करता है। लोकतंत्रमें देशकी जनता अपनी चुनी हुए व्यक्तिको शासन करनेका अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठाके साथ अपने दायित्वोंका पालन करेगी। लेकिन आम जनताको यह अधिकार तो कत्तई नहीं दिया जा सकता कि वह देशकी सुरक्षा और शत्रुका मुकाबलाके लिए की जा रही तैयारियोंकी ही जानकारियां मांगने लगे। पाकिस्तान और चीनकी तरफसे लगातार यह कोशिश बनी रहती है कि उन्हें हमारी रक्षा तैयारियोंकी जानकारी हासिल होती रहे। इसलिए यह दोनों देश हमारे नागरिकोंको तरह-तरहके लालच देकर सूचनाएं लेते रहते हैं। अब माधुरी गुप्तकी कहानी जान लें। वह भारतीय विदेश सेवाकी ग्रुप बी श्रेणीकी अधिकारी थी। अपनी २७ वर्षोंकी लम्बी सेवामें माधुरीने इराक, लाइबेरिया, मलेशिया, क्रोएशिया और पाकिस्तानमें नौकरी की। उर्दूपर अच्छी पकड़ और सूफियाना मिजाजवाली माधुरी साहित्यिक गतिविधियोंमें भी सक्रिय रहती थी। खुले ख्यालोंवाली माधुरी धूम्रपान, शराब-सेवन, गुटका खाने और पुरुष-मित्रोंसे सम्बन्ध बनानेके लिए खास तौरपर जानी जाती थी। कुछ साल पहले इस्लामाबाद स्थित भारतके उच्चायोगमें द्वितीय सचिवके रूपमें पोस्टिंगके दौरान माधुरीको उर्दूपर अच्छी पकड़ होनेके कारण पाकिस्तानी मीडियाको मॉनिटर करनेका काम सौंपा गया था। पाकिस्तानमें पोस्टिंगके बमुश्किल छह महीने बीतते-बीतते माधुरी जमशेद, जिसका कोड नाम जिम था, के द्वारा फंसा ली गयी। भारत सरकारके अधिकारियोंको जब आभास हुआ कि माधुरी शत्रुके जासूसी षड्यंत्रमें फंस गयी है तो पुष्टिके लिए उसके माध्यमसे एक गलत सूचना जान-बूझकर भेजी गयी। परिणामस्वरूप खुफिया सूचनाओंको लीक करनेका माधुरीके कारनामोंका पक्का यकीन हो गया। भूटानमें आयोजित होनेवाले सार्क समिटकी तैयारियोंके बहाने माधुरी गुप्तको भारत वापस बुलाया गया। २२ अप्रैल २०१० को वह वह ज्यों ही दिल्लीके हवाई अड्डेपर उतरी तो खुफिया एजेंसीके लोगोंने उसे अपनी पकड़में ले लिया। पूछताछसे पता लगा कि वह आईएसआईके दो जासूसों, मुन्नवर रजा राना और जमशेद उर्फ जिमीसे सांठ-गांठ करके उन्हें खुफिया सूचनाएं सप्लाई करती थी। इन आरोपोंके आधारपर २० जुलाई २०१० को माधुरीको गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक हिरासतमें रखा गया। १८ मई २०१८ को दिल्लीके अतिरिक्त सेशंस जज सिद्धार्थ शर्माने जासूसीके लिए माधुरीको तीन वर्षोंकी सजा सुनायी। कुछ साल पहले ही चीनके लिए जासूसी करनेके आरोपमें राजधानीके एक कथित वरिष्ठ पत्रकार राजीव शर्माको पकड़ लिया गया था। राजीव शर्माके बारेमें यह पता चला था कि वह आरटीआईसे जानकारियां निकालकर चीनको सप्लाई करता था। उसे आफिशियल सीक्रेट एक्ट (ओएसएस) के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसने सेनासे जुड़े कई राष्ट्रीय सुरक्षाकी दृष्टिसे संवेदनशील सूचनाओंवाले दस्तावेज चीनको दिये थे। चीनको संवेदनशील सूचनाएं उपलब्ध करानेकी एवजमें उसे मोटी रकम मिलती थी। इधर आरटीआईके तहत आवेदकोंकी बाढ़-सी आ गयी है। बहुतसे लोग अनाप-शनाप सवाल भी पूछते रहते हैं। इसलिए यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अधिकारका गलत इस्तेमाल न हो। इस बाबत बहुत सजग रहना होगा। एक बात और कि जो देशके साथ गद्दारी करे उसे सीधे मौतकी सजा देनेपर भी विचार किया जाना चाहिए। जरा सोचिये कि अग्रवालको इस देशने आईआईटी जैसे श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानमें पढ़नेका मौका दिया। उसने आईआईटीसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। इसके बाद वह ब्रह्मोस एयरोस्पेसमें इंजीनियरके तौरपर काम करने लगा। उसकी विशेषज्ञताकी वजहसे उसे बहुत कम समयमें ब्रह्मोस एयरोस्पेसमें जरूरी पदोंपर पदोन्नत किया गया और मिसाइल परियोजनाओंपर काम करनेवाली टीमका एक जरूरी सदस्य बनाया गया। वही शख्स देशका दुश्मन बन गया। उसके जैसोंको तो फांसी होनी ही चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दिल्ली में जल संकट

समस्या गंभीर

दिल्ली में जल संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। राजधानी में जल संकट हरियाणा और हिमाचल प्रदेश द्वारा खासकर गर्मी के महीनों में दिल्ली को अतिरिक्त जल सप्लाई से इनकार करने के कारण गहरा गया है। इनका कहना है कि वे समझौते के अनुसार जल-सप्लाई कर रहे हैं। यह मुद्दा खासकर जटिल है क्योंकि दिल्ली की जल सप्लाई का बड़ा हिस्सा निकटवर्ती राज्यों से आता है। जल संकट से एनसीआर के लाखों लोग तथा अनेक उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। यमुना दिल्ली को अधिकांश पानी देती है और पश्चिमी यमुना नहर के माध्यम से हरियाणा इसका मुख्य सप्लायर है। अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश सहायक नदियों के माध्यम से इसमें अपना योगदान देता है। राज्यों के बीच वर्तमान जल-साझा समझौतों के महत्व पर सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया है और इनकी पुष्टि की है। इस संबंध में लगभग एक सप्ताह पहले उसका नवीनतम निर्देश आया है। इसमें यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा दिल्ली को पूर्व-सहमति के आधार पर पानी खासकर गर्मी के महीनों में उपलब्ध कराएं जब इसकी मांग बढ़ जाती है। पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त 137 क्यूज़ेक पानी छोड़ने की अनुमति देते हुए हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह हथिनीकुंड बैराज के माध्यम से वजीराबाद होकर दिल्ली को यह प्रवाह छोड़े ताकि पेयजल का संकट कम किया जा सके। इस बीच दिल्ली भाजपा ने जल संकट की स्थिति पर विचार करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उम्मीद है कि इससे इस मुद्दे पर फौरन

ध्यान जाएगा जो इस बात की गारंटी होगा कि विधायक और नौकरशाह तत्काल ज्यादा तेजी से समस्या का समाधान खोजेंगे।

2023 में दिल्ली में लगभग 35 मिलियन लोग रहते थे, लेकिन हर साल खासकर गर्मी में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सप्लाई घटने के कारण गंभीर जल-संकट पैदा होता है। राजधानी के जल प्रदाता 'दिल्ली जल बोर्ड' को निश्चित सप्लाई स्तर बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। इसक कारण अक्सर पानी की कमी हो जाती है और उसे 'राशनिंग' करनी पड़ती है। अमीर और कम आय वर्ग के परिवार दिन में केवल कुछ घंटे पानी सप्लाई के कारण गंभीर असुविधा का सामना कर रहे हैं। इस कारण नागरिकों को महंगे, अस्वास्थ्यकर और अनिश्चित निजी जल टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जल समस्या के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खतरा और गहरा हो गया है। पानी की कम उपलब्धता के कारण जल-जनित रोगों की संभावना बढ़ जाती है जिससे स्वच्छता मानक प्रभावित होते हैं। ऐसे में खराब स्वच्छता के कारण कालरा, दस्तरोग व टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। दिल्ली की जल संकट समस्या का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है ताकि एक मानक कार्रवाई प्रक्रिया बनाई जा सके। आवश्यक है कि राज्य विधिक समझौतों का पालन करते हुए एक दूसरे के साथ ज्यादा सहयोग करें। जल सप्लाई ढांचे, जैसे शोधन व्यवस्थाओं तथा भंडारों के लिए आवश्यक निवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके साथ ही पानी की बचत करने वाले व्यवहारों को बढ़ावा देते हुए पानी की रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि उपलब्ध जल संसाधनों पर मांग में कमी आए। भूमिगत जल संभरण को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालीन पहलें की जानी चाहिए जिनमें वर्षा जल संचयन तथा निकटवर्ती जल भंडारों को पुनर्जीवित करना शामिल हैं।

लोकसभा चुनाव परिणाम का असर

अपने सहयोगियों के साथ कांग्रेस का विपक्ष में असर बढ़ा है। मोदी ने बदलती स्थिति के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रीय क्षत्रपों से समर्थन प्राप्त कर लिया है।

कुमार चेलप्पन
(लेखक, द पायनियर के विशेष संवाददाता हैं)

लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अब परिणाम स्पष्ट हो गए हैं तथा लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया है। हालांकि, इससे एक प्रकार से देश में अनिश्चितता और अनिर्णय भी एक सीमा तक पैदा हुआ है। किसी पार्टी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में लगभग 300 सदस्य है जो बहुमत के आंकड़े से 27 अधिक है। लेकिन विपक्ष की मुख्य शक्ति कांग्रेस सांसदों का आंकड़ा सैकड़े तक भी नहीं पहुंच सका है, भले ही सहयोगियों के साथ पार्टी की स्थिति काफी बेहतर हुई है। राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' की रिपोर्टिंग करते हुए 'द पायनियर' ने खबर दी थी कि यह राष्ट्रीय राजनीति में गेम चेंजर का काम कर सकती है। ऐसे में सवाल यह था कि क्या राहुल गांधी यात्रा से पैदा जोश लंबे समय तक बनाए रखने में सफल होंगे या नहीं।

उस समय भी राहुल को ऐसी नेताओं की टीम की अनुपस्थिति का अनुभव हो रहा था जो उनकी उम्मीदों के अनुसार काम कर सके। हो सकता है कि अगली बार भाग्य उनका साथ दे। परिणामों की घोषणा वाले दिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नरेन्द्र मोदी थोड़ा तनाव में दिखे थे। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार उनके स्वर में पहले की तरह आत्मविश्वास नहीं था और वे कार्यकर्ताओं को पूरी तरह प्रेरित करने में सफल नहीं हुए। यह प्रधानमंत्री के रूप में उनके एक दशक लंबे कार्यकाल की एक विरल घटना कही जा सकती है। मोदी ने 2014 में लोकसभा चुनाव जीत कर दिल्ली में शानदार प्रवेश किया था। उनके नेतृत्व में भाजपा को अपने दम पर 282 सीटें मिली थीं, जबकि गठबंधन की संख्या 336 पहुंच गई थी। इसके बाद 2019 में लोगों ने जैसे प्लेट में रख कर भारत नरेन्द्र मोदी को सौंप दिया था जबकि नई दिल्ली मीडिया ने उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया था। उस समय भाजपा को अपने दम पर 303 सीटें मिली थीं, जबकि राजग को 353 सीटें मिली थीं। इसने नरेन्द्र मोदी को एक प्रकार से बादशाह बना दिया था।

लेकिन 2024 ने एकदम अलग परिदृश्य प्रस्तुत किया है। करिश्माई, दृढ़, समझौता न करने वाले शक्तिशाली मोदी आज दो क्षेत्रीय क्षत्रपों-जदयू के नीतीश कुमार तथा तेदेपा के चंद्रबाबू नायडू की सहायता पर निर्भर हैं जिनकी स्वयं राष्ट्रीय महत्वाकांक्षायें हैं। राजग की पहली बैठक के पहले ही नीतीश कुमार और नायडू ने अपनी मांगें सामने रख दी थीं जिनमें जातीय जनगणना तथा अग्निवीर योजना रद्द करना शामिल है। यह भी समान रूप से महत्वपूर्ण है कि ये दोनों नेता समान नागरिक संहिता से सहमत नहीं हैं जो मोदी और भाजपा का 'ड्रीम प्रोजेक्ट' है। कहा जाता है कि नीतीश और नायडू ने कैबिनेट में ज्यादा सीटें मांगी थीं, पर मोदी सरकार के शपथ ग्रहण ने इन आशंकाओं को खारिज कर दिया है। मंत्रालयों का आबंटन होने पर स्पष्ट होगा कि इन दोनों सहयोगी दलों को कौन से विभाग दिए गए हैं। 2014 की लोकसभा चुनाव प्रचार तस्वीरों में चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश के अभियान में मोदी के पीछे चलते देखा गया थ। लेकिन दो-तीन साल में नायडू राजग से अलग हो गए क्योंकि प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने से इनकार कर दिया था। नायडू कांग्रेस के साथ चले गए थे और मीडिया के कुछ हिस्सों ने दावा किया था कि वे देश के सर्वोच्च पद के दावेदार हैं। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव ने नायडू की उम्मीदों को मिट्टी में मिला दिया। वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी ने विधानसभा में भारी विजय प्राप्त की थी। रेड्डी ने तेदेपा को पूरी तरह समाप्त करने का आक्रामक अभियान चलाया तथा नायडू और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाए। नायडू को इन आरोपों में गिरफ्तार कर जगन मोहन रेड्डी सरकार ने महीनों जेल में रखा गया।

ऐसे में नायडू को 2024 के विधानसभा चुनाव में समर्थन की जरूरत पड़ी और वे पूरी तरह भाजपा और मोदी के साथ आ गए। नायडू को अपनी उम्मीद से बहुत अधिक मिला और वे आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि उनकी नजरें प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं। ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करना कठिन होगा जिसन अपने ससुर तथा तेदेपा संस्थापक एन. टी. रामाराव की विरासत पर कब्जा कर लिया था। नीतीश कुमार पर भी 'आया राम गया राम' की परिघटना लागू होती है। ऐसे में आशंका है कि नीतीश कुमार राजग में कब तक बने रहेंगे। हालांकि, उनको अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में राजग का मुख्यमंत्री चेहरा बताया जा रहा है। नीतीश और नायडू की विचारधारा के बारे में दुविधा की स्थिति बनी हुई है क्योंकि अतीत में उन्होंने 'सांप्रदायिक' भाजपा से पंथनिरपेक्षता को बचाने के बड़े-बड़े वादे किए थे। इन कारणों से भाजपा थोड़ी दुविधा में है। जगन मोहन रेड्डी के अच्छे कामकाज के बावजूद चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश विधानसभा में प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। नायडू ने तत्कालीन प्रधानमंत्री देवगौड़ा को 1997 में पद से हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और केवल दस महीने तक प्रधानमंत्री पद पर रहने की पीड़ा आज तक देवगौड़ा को सताती रहती है।

यदि 2024 की वर्तमान स्थितियों पर गौर करें तो स्पष्ट होगा कि भाजपा ही काफी सीमा तक ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की जिम्मेदार है। लोगों को याद होगा कि महाराष्ट्र में तत्कालीन विपक्षी नेता देवेंद्र फडनवीस को 2019 में केवल रांकापा नेता अजीत पवार के समर्थन के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, लेकिन केवल चार दिन के बाद ही उनको यह पद छोड़ना पड़ा था। पहले फडनवीस और भाजपा ने अजीत पवार को 'भ्रष्टाचार की मूर्ति' बताया था, लेकिन उनके साथ गठबंधन करने में उसे कोई हिचक नहीं हुई। इसके बाद अजीत पवार अपने 'परिवार' में वापस चले गए, पर अंततः देवेंद्र फडनवीस उनको अपने पाले में वापस लाने में सफल हुए और उप-मुख्यमंत्री बना दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस प्रकार का अवसरवादी गठबंधन करने के बजाय फडनवीस को अगले विधानसभा चुनाव तथा महाविकास अघाड़ी में बिखराव तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। कहा जाता है कि 2024 में भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा का वह बयान भी घातक सिद्ध हुआ जिसमें कहा गया था कि भाजपा का आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा था कि 'हमारा ध्वज संभवतः स्वयं भगवान शंकर ने बनाया था। इस झंडे में भगवा रंग भगवान का है। हमने अपने राज्य के लिए यह झंडा चुना है। यह झंडा मानवता का प्रतिनिधित्व करता है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसका समुचित प्रतिनिधित्व करें।' इस प्रकार नड्डा एक प्रकार से भाजपा पर बोझ बन गए थे और उन्होंन भाजपा और संघ के बीच संबंधों को गहरी चोट पहुंचाई थी। नड्डा को दक्षिण भारत के दो प्रमुख नेताओं के. कामराज और एस. निजलिंगप्पा के बारे में पढ़ना और उनके इतिहास से सबक लेना चाहिए। ये दोनों नेता कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे।

हालांकि, ऐसा लगता है कि वर्तमान चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को देखते हुए नड्डा को उनकी सेवाओं के बदले मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। लेकिन इस प्रकार उनको पार्टी अध्यक्ष पद से विदा भी कर दिया गया है। भाजपा अध्यक्ष के रूप में नड्डा ऐसे पद पर थे जिस पर पहले अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी रह चुके थे। भाजपा को अध्यक्ष पद के लिए नेतृत्वकारी गुणों वाले व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। 2024 के चुनाव ने भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। हालांकि वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन-राजग के रूप में सरकार बनाने में सफल हुई है। 2024 में लोकसभा चुनाव परिणाम राहुल गांधी के लिए भी सबक हैं। उनको विंबलडन चैंपियनशिप में बोर्ग और मैक्नरो के बीच संघर्ष को याद करना चाहिए जिसमें पहले 1980 में बोर्ग ने मैक्नरो को हरा दिया था, पर आखिरकार 1981 में मैक्नरो पुनः विजेता बने थे। ऐसा लगता है कि टेनिस और राजनीति में कुछ समानतायें हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस को अब अगले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए।

व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक

"मूलतः मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसे दूसरों के साथ बातचीत करने और उनसे जुड़ने की आवश्यकता होती है। यह बदले में उनके दृष्टिकोण और व्यवहार पैटर्न को आकार देता है।"

रवि वलूरी
(लेखिक, रेल विभाग से संबद्ध हैं)

महाभारत उपमहाद्वीप में लिखे गए सबसे महान महाकाव्यों में से एक है, शायद दुनिया में भी। ऐसा माना जाता है कि इसे ऋषि वेद व्यास ने भगवान गणेश के साथ मिलकर लिखा था। यह गाथा स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों में मनुष्यों के विविध दृष्टिकोण और विषम विशेषताओं को दर्शाती है। मानवीय दृष्टिकोण और दृष्टिकोण सरल काले, सफेद और भूरे रंग के बजाय स्पेक्ट्रम के सभी रंगों में उभरते हैं। भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण ने कौरव वंशज दुर्योधन के अहंकार, अहंकार और क्रोध को शांत करने और पानी की जांच करने का फैसला किया। सामाजिक प्रभाव, अतिरंजित भावनाएं और पर्यावरणीय कारक मानव मन पर प्रभाव डालते हैं। परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत व्यवहार पैटर्न जटिल और अक्सर प्रकृति में प्रतिकूल हो जाते हैं। मन कोबवे और निरर्थक विचारों से भर जाता है और स्वयं और दूसरों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण कठोर हो जाता है।

दुर्योधन के मन में अपने चचेरे भाइयों के प्रति पूर्वाग्रह था और इस रवैये को उसके षडयंत्रकारी चाचा शकुनि, भाई दुशासन और अंतरंग मित्र तथा प्रसिद्ध धनुर्धर कर्ण ने बढ़ावा दिया। इतिहास ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहारों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। जर्मनी में नाजियों द्वारा असहाय यहूदी आबादी के खिलाफ किया गया नरसंहार इस बात का एक अनूठा और चरम उदाहरण है कि कैसे पूर्वाग्रह लोगों और मानवता के वर्गों के बीच घृणा, भेदभाव और सामूहिक विनाश की ओर ले जाता है। युगों पहले एक सम्मानित ज़ेन मास्टर ने कई भिक्षुओं और नौसिखियों को ध्यान के जोरदार सत्रों के लिए इकट्ठा किया था। इनमें से एक सत्र के दौरान एक शिष्य को उसके सहयोगियों ने चोरी करते हुए पकड़ लिया। दोषी को ज़ेन मास्टर के

सामने पेश किया गया और उपस्थित सभी लोगों ने मांग की कि उसे एक अनुकरणीय दंड के रूप में ज्ञान के मंदिर से निकाल दिया जाए। ज़ेन मास्टर ने भिक्षुओं की विनती को नज़रअंदाज़ कर दिया। एक बार फिर, शिष्य चोरी करते हुए पकड़ा गया। इससे भिक्षुओं की सभा क्रोधित हो गई और उन्होंने मांग की कि अपराधी को उसके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए ताकि मठ के सभी निवासियों पर इसका लाभकारी प्रभाव पड़े। ज़ेन मास्टर ने गहन विचार के बाद परेशान छात्र को माफ़ कर दिया, जिससे अन्य लोगों में निराशा फैल गई। उनका मानना था कि छात्र में नैतिक स्पष्टता की कमी थी जबकि अन्य ध्यान के माध्यम से विकसित हुए थे। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मास्टर ने कहा। प्रभावित होकर, छात्र ने बदलने की कसम खाई, एक बेहतर इंसान बनने के लिए अपने चोरी के तरीकों को त्याग दिया।

मास्टर द्वारा प्रदर्शित विचार और करुणा इस बदलाव के लिए एकमात्र जिम्मेदार थे। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य का झुकाव और झुकाव कुछ प्रमुख कारकों जैसे कि विभिन्न उत्तेजनाओं द्वारा उत्तेजना, विशेषता, दिन-प्रतिदिन के कार्यों में बनाए रखा गया संतुलन जैसे कुछ प्रमुख कारकों द्वारा अचल रूप से जुड़ा हुआ है। इसी तरह, ज़ेन शिष्य मास्टर द्वारा दिखाए गए कोमलता और परोपकार से अभिभूत था और वह चोरी के कार्य से बचकर एक बेहतर इंसान बन गया।

मूलतः मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उसे दूसरों के साथ बातचीत करने और उनसे जुड़ने की आवश्यकता होती है। यह बदले में उनके दृष्टिकोण और व्यवहार पैटर्न को आकार देता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण निरंतर सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं। ज़ेनोफोबिया और स्नेह विभिन्न घटनाओं और मानव मन पर उनके प्रभाव का परिणाम हैं। प्रभाव निर्माण एक व्यवस्थित तरीके से होता है और इसे सभ्य या अशिष्ट व्यवहार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी व्यवसायी, हेरोल्ड एस जेनेन ने प्रसिद्ध रूप से कहा था,नेतृत्व का अभ्यास शब्दों में नहीं बल्कि दृष्टिकोण और कार्रवाई में किया जाता है।

आप की बात

फिर बनी मोदी सरकार

सरकार के मुखिया के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। आशा है कि गठबंधन सरकार होने के बावजूद मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा। खुद बीजेपी के पास सर्वाधिक 240 सीटें हैं। उसने 10 अन्य निर्दलीय सांसदों को अपने साथ कर लिया है ताकि इंडिया गठबंधन द्वारा कोई दाव-पेंच नहीं चलाएं जा सके। टीडीपी व जेडीयू के पास सरकार में शामिल होकर अपने लिए मंत्रालय हासिल करने और राज्य में सरकार चलाने के लिए बीजेपी का सहयोग पाने के लिए उनका एनडीए के साथ बने रहना जरूरी है। कार्यभार संभालते ही मोदी ने कृषकों के लिए 17वीं किस्त जारी कर दी और पहले दिन से ही अपने काम में समर्पण भाव से जुट गए हैं। नरेन्द्र मोदी जी की तीसरी जीत ने विश्व भर में भारतीय प्रजातंत्र का गौरव बढ़ाया है। मोदी के शपथ ग्रहण में भारत-मित्र बांग्लादेश की शेख हसीना के साथ ही मालदीव के राष्ट्रपति मुहम्मद मुइज्जू की उपस्थिति संकेत देती है कि पड़ोसी देश मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार से बेहतर संबंध बनाए रखने तथा उनको और मजबूत करने के इच्छुक हैं।

–**सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

रचनात्मक विपक्ष जरूरी

सरकार के कामकाज को बेहतर बनाने, उसके द्वारा उठाये कदमों को सही राह पर चलाने और देश के उत्थान में बेहतर काम करने को प्रेरित करने के लिए रचनात्मक विपक्ष की जरूरत है। विपक्ष को बेवजह की तुच्छ आलोचना में संसद का समय खराब नहीं करना चाहिए। पिछले 10 वर्ष में विपक्ष ने सरकार की अनावश्यक व अति-आलोचना में संसद का समय तो गंवाया ही, साथ ही जनता के कामों को बेहतर करने में भी रुकावटें पैदा की। अब उसे पिछले रवैये में सुधार करना चाहिए ताकि सरकार देश की उन्नति में उठाये गए क़दमों को सुचारु रुप से लागू कर सके।। सरकार को भी चाहिए कि वो विपक्ष की देशहित में कही गई बातों को सुने और अपने कामों को और अधिक जन-हितैषी बनाने में उनसे सहयोग ले। सत्ता और विपक्ष के बीच बहस ऐसी होनी चाहिए कि जनता भी दांतो तले अंगुली दबाने में पीछे न रहे। ऐसा होने पर ही लोकतान्त्रिक परम्परा भी निभेगी और राष्ट्र निर्माण में दोनों पक्षों का बेहतर योगदान भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राजग के नव-निर्वाचित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार बहुमत से बनती है, पर उसे सर्वानुमति बनाने का प्रयास करना चाहिए।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

यूरोप की चिन्ता

यूरोप में मुसोलिनी एवं हिटलर की मौत के बाद लगा था कि धुर दक्षिणपंथ एवं उग्र राष्ट्रवाद से पीछा छूट गया। हाल ही में इसी विचारधारा को परास्त करने की 80 वीं वर्षगांठ मनाई गई। लेकिन यूरोपियन संसद चुनाव के नतीजों ने मध्यमार्गी एवं समाजवादियों को चिंतित कर दिया है। इस चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टियों ने बड़ी बढ़त हासिल की है तथा जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज़, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन व ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है। मरीन ले पेन की नेशनल रैली ने मैक्रोन के मध्यमार्गी पुनर्जागरण को करारी शिकस्त दी है। इसके बाद मैक्रॉन मौजूदा संसद को भंग कर इस महीने के अंत में संसदीय चुनावों की घोषणा की है। हालांकि, इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी की दक्षिणपंथी पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली ने संसद में अपनी सीटें दोगुनी से भी अधिक कर ली हैं। ऑस्ट्रिया की दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी ने उम्मीद जताई है कि वह अपनी सफलता इस वर्ष के अंत में संसदीय चुनावों में भी जारी रखेगी। यूरोप को धुर-दक्षिणपंथ के उभार की चिन्ता सता रही है। इसके कारणों की विस्तृत, तटस्थ एवं वस्तुनिष्ठ समीक्षा जरूरी है क्योंकि यह प्रवृत्ति दुनिया के अन्य हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

आतंकी हमला

जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कायराना हमला कर फिर अपने मंसूबे स्पष्ट कर दिए। वेष्णो देवी जा रही बस के ड्राइवर पर गोलियां दागना और इसके परिणामस्वरूप बस यात्रियों की मौत दुःखद घटना है। बस के खाई में गिरने से श्रद्धालुओं की मौत हुई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राजग की विजय के बाद ऐसी घटना भारत सरकार को चुनौती देने वाली है। लेकिन भारत को यह चुनौती आतंकियों और उनके आकाओं को महंगी साबित होगी। लगातार तीसरी बार बनी मोदी सरकार पाक के आतंकियों का फन तो कुचलेगी ही, पाकिस्तानी आतंकी फैक्टरी को भी ध्वस्त करेगी। ऐसे समय जब जम्मू कश्मीर की जनता ने दशकों बाद भारी संख्या में मतदान कर देश की मुख्यधारा में शामिल होने की घोषणा कर दी है तथा जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, यह हमला आतंकियों और उनके आकाओं की निराशा भी प्रकट करता है। यह आतंकी हमला नवगठित सरकार के समक्ष सीमापार के आतंकियों या देश में उनके समर्थकों की ओर से बड़ी चुनौती है। इसका मुंहतोड़ जवाब तत्काल देना जरूरी है।

– **योगेश जोशी,** बड़वाह

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। मंगलवार, 11 जून 2024

क्या बदलेंगे समीकरण

केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुआई में लगातार तीसरी बार NDA सरकार तो बन गई, लेकिन रविवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही असंतोष के स्वर भी फूट पड़े। अजित पवार की अगुआई वाली NCP ने राज्यमंत्री पद की पेशकश स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

कोई विवाद नहीं | हालांकि इसे लेकर विवाद की आशंका कम से कम फिलहाल नहीं है। NCP का कहना है कि उसकी ओर से मंत्रिपरिषद की सदस्यता के लिए नामित नेता प्रफुल्ल पटेल अतीत में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसलिए राज्यमंत्री का पद उनके लिए उपयुक्त नहीं है। BJP ने इस दलील को स्वीकारते हुए NCP को कुछ दिन इंतजार करने को कहा है, जिसके लिए पार्टी तैयार है।

कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव

कुछ महीनों में चुनाव | यानी कहा जा सकता है कि इस सत्तारूढ़ गठबंधन में ऊपर-ऊपर सब ठीक है। इसके बावजूद अगर राज्य में राजनीतिक तूफान के आसार बताए जा रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ महीने के अंदर राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों ने जहां विपक्षी महाविकास आघाड़ी का उत्साह बढ़ा दिया है, वहीं सत्तारूढ़ महायुति में इसे लेकर चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं।

पहले क्या हुआ | पिछला विधानसभा चुनाव BJP और शिवसेना के गठबंधन ने कांग्रेस और NCP गठबंधन के खिलाफ लड़ा था। चुनाव नतीजे आने पर शिवसेना ने कांग्रेस और NCP के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके कुछ समय बाद एकनाथ शिंदे की अगुआई में शिवसेना का एक धड़ा BJP से जा मिला और दोनों की सरकार बन गई। फिर अजित पवार की अगुआई में NCP का भी एक हिस्सा उस सत्तारूढ़ गठबंधन से जा मिला।

किसकी पार्टी, कौन नेता | स्वाभाविक ही इसके बाद असली NCP और असली शिवसेना का सवाल उठ खड़ा हुआ। इसका आखिरी फैसला फैसला चुनाव में ही होना था। हाल के लोकसभा चुनावों को आधार मानें तो जनता का फैसला उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP के पक्ष में आया माना जाएगा। शिवसेना (UBT) को 9 और NCP (शरदचंद्र पवार) को 8 सीटें मिलीं, जबकि शिंदे की सेना को 7 तो अजित पवार की NCP को महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा।

सियामी समीकरणों पर ध्यान | विधानसभा चुनाव में वोटिंग लोकसभा की तर्ज पर हो यह जरूरी नहीं होता। ऐसे में सबका ध्यान विधानसभा चुनाव के समीकरण साधने पर लगा हुआ है। क्या इसकी वजह से राज्य में एक बार फिर कोई बड़ी उथलपुथल देखने को मिलेगी? इस बारे में अभी कोई नतीजा निकालना जल्दबाजी होगा।

धूप-छांव

बाद वाले VP-अटल

प्रणव प्रियदर्शी

नागमणि एक ऐसे सांप की कल्पना है, जिसके पास मणि होती है। उसके तेज से वह दपदपाता रहता है। मिथक के मुताबिक, वह रात को मणि एक जगह निकालकर रखता है और उसकी रोशनी में इधर-उधर भोजन तलाशता है। अगर उसकी वह अनमोल मणि कोई ले ले तो मालामाल हो जाता है, लेकिन सांप अंधा होकर इधर-उधर भटकते हुए मर जाता है। यह मिथक हमें भारतीय चिंतन के एक विशेष पहलू से परिचित कराता है, जिसके मुताबिक व्यक्ति और उसका व्यक्तित्व दो अलग चीजें हैं।

महाभारत का कर्ण पहले ऐसे किरदार के रूप में हिंदुस्तानी जनमानस में दर्ज होता है, जो बताता है कि आपके व्यक्तित्व के गुणों के जरिए ही उसकी काट भी हो सकती है। देवराज इंद्र ने महाभारत युद्ध से पहले एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे उसका जन्मजात कवच-कुंडल मांग लिया था। अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध कर्ण ने शरीर से छीलकर कवच-कुंडल उन्हें दे भी दिया। थोड़े अलग, मगर ज्यादा स्पष्ट रूप में आती है अश्वत्थामा की कहानी, जिसे भगवान जिंदगी तो बख्श देते हैं लेकिन उसका तेज हर लेते हैं।

मिथक भले इतिहास न हों, किसी न किसी तरह जीवन की सचाई से जुड़े होते हैं। वरना वे इतने लंबे समय तक समाज के जनमानस का जीवंत हिस्सा नहीं बने रह सकते थे। ऐसे में अगर वास्तविक दुनिया में ऐसी शख्सियत तलाशें तो जाहिर है कथा को नाटकीय बनाने वाले तत्व तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे कई व्यक्तित्व मिलते हैं जिनके जीवन का एक खास हिस्सा ज्यादा चमकदार नजर आता है और एक बिंदु के बाद उनके जीवन से वह चमक गायब दिखती है। आधुनिक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्रित्व खत्म होने के बाद का जीवन भी कुछ ऐसा ही नजर आता है, हालांकि वह उस दौरान एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी ऐसी ही एक मिसाल हैं, जिनका पीएम बनने से पहले और पीएम रहने तक का राजनीतिक जीवन उसके बाद के जीवन से बिल्कुल अलग रहा। जीवित नेताओं की बात करें तो लालकृष्ण आडवाणी के जीवन और नेतृत्व को भी इस रूप में देखा जा सकता है 2014 के पहले और उसके बाद की अवधि में बांटकर। इन जानी-मानी और चर्चित हस्तियों से अलग अपने आसपास नजर डालें तो भी ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं जो बताते हैं कि दौलत, शोहरत, सफलता तो जाने दीजिए हमारा व्यक्तित्व भी पूरी तरह हमारा नहीं है। इसकी कुछ चीजें बनी रहती हैं और कुछ बीच में ही साथ छोड़ जाती हैं।

बोल वचन

चौंधिया गया भकचोन्हर

राहुल पाण्डेय

अवधी और भोजपुरी के बारे में कहते हैं कि दोनों एक ही मां की दो संतानें हैं। दोनों ही भाषाओं के बहुत से शब्द एक-दूसरे के यहां पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है भकचोन्हर। यह शब्द बहुत सारे लोगों ने 2021 में तब सुना होगा, जब लालू प्रसाद यादव ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के लिए इसका प्रयोग किया था।

AI Image

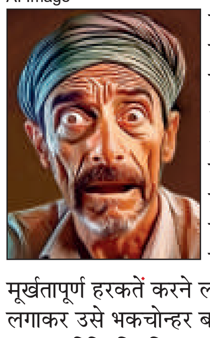

उनका यह शब्द बोलना था कि बहुत से लोग बुरा मान गए। उनका मानना था कि यह अपशब्द है। लेकिन भकचोन्हर कोई अपशब्द नहीं है। हम जानते हैं कि जब आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है तो कुछ देर के लिए वे चौंधिया जाती हैं। इसी चौंधियाने से बना है चोन्हर। यानी ऐसा शख्स, जिस पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा है कि उसे दिखना बंद हो गया है। जब इसी घबराहट में वह मूर्खतापूर्ण हरकतें करने लगता है तो लोक चौंधियाने के आगे भक लगाकर उसे भकचोन्हर बना देता है। मतलब ऐसा मूर्ख, जिसे देश, काल, परिस्थिति, विषय आदि का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन लगातार अल्ल-बल्ल किए जा रहा है। कोई कह सकता है कि मूर्ख को सिर्फ महामूर्ख कहकर ही काम चलाया जा सकता है। काम तो चलाया जा सकता है, लेकिन लोकभाषा में कामचलाऊ काम नहीं होता। लोक हमेशा शब्दों पर ऐसे वजन रख देता है कि सालों-साल उसे कोई हिला भी न पाए। लोक जानता है कि मूर्ख तो बदलेगा नहीं, लेकिन किसी चीज से प्रभावित होकर बनने वाले भकचोन्हर से उसे बदलने की आशा होती है। इसलिए वह भकचोन्हर बोलता है, इस आस में कि एक दिन उसे सब कुछ साफ-साफ दिखने लगे।

चुनाव में विपक्षी दलों की सीटें बढ़ने से हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर गहरा हुआ दुनिया का विश्वास

वैश्विक मंच पर कैसी होगी मोदी की छवि

सैबल दासगुप्ता

विपक्ष जितनी भी खुशियां मना ले, लेकिन हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी जीत ने उनकी ग्लोबल इमेज को और निखारा है। अब वह एक गठबंधन सरकार के नेता के रूप में अपनी बात रखेंगे, जिसमें कई राजनीतिक दल हैं। इससे भारत की भू-राजनीतिक स्थिति मजबूत ही होगी।

लोकतंत्र की जीत | इस आम चुनाव ने विपक्षी दलों को वापसी का मौका दिया, जिसे पश्चिम और पड़ोसी देशों में भारतीय लोकतंत्र की जीत के रूप में देखा जा रहा है। देश की लोकतांत्रिक साख एक महत्वपूर्ण कारण है कि मोदी सरकार पिछली सरकारों के गुटनिरपेक्ष दर्शन से व्यावहारिक multi-aligned policy में आसानी से बदलाव करने में सक्षम रही है।

पहले वाली टीम | देश की विदेश नीति में बड़े बदलाव की गुंजाइश नहीं दिखती। जो चार शख्सियतें इसे प्रभावित करती हैं, वे बदली नहीं हैं। वे लोग हैं - पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।

सुधार की दरकार | विदेश नीति में कुछ सुधार हो सकते हैं। विश्व मंच पर मोदी की मौजूदगी के बावजूद उनकी सरकार को आम तौर पर हिंदू राइट विंग और बहुसंख्यकों की सरकार के तौर पर देखा जाता रहा है। पश्चिम का मीडिया इसी तरह से मोदी सरकार की व्याख्या करता है। इसकी वजह से खाड़ी देशों के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक करीबी के बाद भी समय-समय पर मुस्लिम वर्ल्ड के साथ भारत के रिश्ते पर असर पड़ा है।

नई सरकार में क्या बदलेगा
- BJP को अपनाना पड़ेगा संतुलित रुख
- घटक दलों से बदलेगी पुरानी छवि
- विदेश नीति में हो सकते हैं सुधार

भारत विरोधी अभियान | हाल ही में मालदीव में 'इंडिया आउट' अभियान चला। इसकी वजह से कई दूसरी चीजों के साथ चीन की तरफ झुकाव रखने वाले मोहम्मद मुइज्जू को भी जीत मिल गई। रोचक बात यह है कि मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जो विदेशी मेहमान आए, उनमें मुइज्जू भी थे।

पड़ोसियों की चिंता | इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश में कुछ विपक्षी राजनीतिक धड़ों ने भी 'इंडिया आउट' अभियान चलाने का प्रयास किया। हालांकि उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। मालदीव और बांग्लादेश, दोनों ही मुस्लिम बहुल देश हैं। उनके यहां एक तबका भारत में दक्षिणपंथी सरकार से चिंतित है।

छवि में बदलाव | मोदी सरकार में TDP और JDU जैसे राजनीतिक दल शामिल हैं। ऐसे में इस सरकार की दक्षिणपंथी छवि को बदलना चाहिए। इन दलों को धर्मनिरपेक्ष और अल्पसंख्यक हितैषी माना जाता है। TDP ने साफ कर दिया है कि वह OBC सूची के तहत मुसलमानों को 4% आरक्षण देने की नीति जारी रखेगी। यह BJP के रुख के विपरीत है, जो मुसलमानों के लिए 'हिंदू' OBC कोटा के तहत आरक्षण खत्म करने के पक्ष में है। BJP नेताओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देश के मुस्लिमों के खिलाफ बोलना मौजूदा राजनीतिक हालात में सही नहीं होगा।

इमेज पर काम | मोदी सरकार ने पहले ही अपनी इमेज बदलनी शुरू कर दी है। 7 जून को पहली बार NDA के सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार 'सर्व पंथ समभाव' पर यकीन करती है। यह भी कहा कि किस तरह कूटनीतिक स्तर पर दोस्ताना और मिलनसार सरकार की छवि कई सारे दोस्त बनाने में मदद करेगी, खासतौर पर तेल उत्पादक अरब वर्ल्ड में। साथ ही, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लगातार चलने वाले अभियान को कमजोर करेगी।

पेइचिंग का भड़कना | मोदी ने शपथ ग्रहण से पहले ही बदलाव के प्रयास को भांपना शुरू कर दिया था, जब उन्होंने ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के साथ पहली बार मेसेज के जरिये बात की। चीन ने पिछले महीने हुए चुनाव में लाई की जीत को मान्यता नहीं दी है। वह ताइवान पर हक जताता है। ऐसे में मोदी और लाई की बातचीत उसे भड़काने के लिए काफी थी। उसने भारत को 'वन चाइना पॉलिसी' की याद दिलाते हुए कहा कि वह ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता।

ताइवान कार्ड | मोदी सरकार से उम्मीद है कि वह ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनियों से अपने यहां निवेश करने के लिए कहेगी। हालांकि यह तय है कि चीन ऐसी किसी भी कोशिश का पुरजोर विरोध करेगा। बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत भी चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए ताइवान कार्ड का इस्तेमाल करेगा। जब भी कोई देश सीधे ताइवान के साथ सीधे रिश्ते बनाता है, तो चीन नर्वस हो जाता है।

चीन का लालच | पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों - नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सेशेल्स, मॉरीशस और मालदीव के प्रमुख मौजूद रहे। इन देशों को चीन आकर्षक ऑफर देकर अपने पाले में लाने की कोशिश करता रहा है। नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में उसने कुछ सफलता भी पाई है। लेकिन, वह भारत के लिए समस्या खड़ी करने में इन मुल्कों का इस्तेमाल करने में सफल नहीं हो सका है।

PoK का क्या होगा | एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या नई सरकार BJP की इच्छा पर आगे बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाक अधिकृत कश्मीर के मुद्दे को फिर से उठाएगी। अमित शाह लगातार कहते रहे हैं कि PoK हमारा है और हम इसे वापस लेंगे। लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि इसकी वापसी के लिए उठाया जाने वाला कदम डिप्लोमैटिक होगा या फिर मिलिट्री एक्शन। नई NDA सरकार पुरानी BJP सरकार की तरह दिखेगी जिसमें सही चेक और बैलेंस होंगे। विश्व मंच पर भारत के लिए यह अच्छी खबर है।

बीमार भाई मस्त, तीमारदार हो गया पस्त

नमिता जोशी

Ai Image

भेजा फ्राई

लास्ट मंथ की बात है। गर्मी इत्ती पड़ रयेली थी कि बाथरूम से नहा के आने के बाद अपुन का टावल भी अपुन के माफिक कन्फ्यूज्ड था कि तू नहाने के बाद वाला पानी शरीर से पोछ रयेला है या इत्ती देर में फिर पसीने से गीला हो गयेला है। अपुन अपनी बॉडी के फव्वारे के बारे में सोच रयेला था कि उदर से मुन्ना भाई ने एंट्री मारा। एकदम रापचिक एक्सरसाइज करने के बाद फुल पसीने से तर बतर। अपुन ने बोला, 'क्या मुन्ना भाई, मस्त वर्कआउट करके आएले हो जिम से। अपुन को भी जॉइन करा दो।' मुन्नाभाई बोले, 'कौन सा जिम, कइसा जिम? अपुन तो डायरेक्ट खोली से आ रयेला है। पसीने से अक्खा बेड गीला हो गया, जिम जाने तक तो पसीना बॉडी में बचेगा भी नहीं।' इत्ता बोल के मुन्नाभाई चक्कर खाके धड़ाम डाउन टु अर्थ। बेहोश? पेजर और कचरा को बुला के अपुन मुन्ना भाई को फटाफट हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर ने बोला मुन्नाभाई को एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेंगा। बोले तो डिहाइड्रेशन हो गयेला है।

हॉस्पिटल आ के ये तो रिलीफ हो गया अपुन कू कि मुन्ना भाई सेफ जगह पे आ गयेला है। पन अपुन कू क्या मालूम था कि मुन्ना भाई तो सेफ है, अपुन डेंजर ज़ोन में आ गयेला है। हॉस्पिटल का पेपर वर्क खल्लास करके पॉकेट से मोबाइल निकाला तो देखा मोबाइल की बैटरी खल्लास। फटाफट किसी से चार्जर मांग के मोबाइल चार्ज किया तो देखा अक्खा नालासोपारा की पब्लिक के मिस्ड कॉल अपुन के मोबाइल में। वॉट्सऐप खोला तो मोबाइल हैंग। अक्खा धारावी के भाई लोग के मेसेज। सबका एकइच सवाल - क्या हुआ भाई को? कौन से हॉस्पिटल में है? अभी कइसा है? अपुन सबको एक एक करके रिप्लाई देना चालू किया। कितने लोग का कॉल आया, कॉल पे बताया, मेसेज में समझाया पन मुन्नाभाई अक्खा मुंबई में कितना वर्ल्ड फेमस है ये बात अपुन कू भी उसी दिन मालूम चला। और रात होते होते उदर मुन्ना भाई के अंदर एनर्जी का संचार और इधर अपुन के मोबाइल की बैटरी के माफिक अपुन की बैटरी का बंटाधार। फोन पे अक्खा मुंबई को एकइच बात बोलते बोलते अपुन का गला फटे ढोल के माफिक बजने लगा। पप्पू पेजर अपुन कू देख के बोला, सर्किट भाई तुम भी मुन्ना भाई के बेड के बगल में अपना एक बेड लगवा लो।

अपुन कू लगा चलो अब सबको बता दिया है तो सब समझ जाएंगे, पन अगले दिन अक्खा भाई लोग हॉस्पिटल पहुंच के अपुन कू सरप्राइज़ देने लगे। हेलो, सर्किट? तुम किदर है, अपुन इदर आएला है तुमको मिलने का है, भाई को देखने का है। अक्खा दिन और एनर्जी सब लोग कू ये समझाने में पसीने के माफिक बह गई कि अभी ट्रीटमेंट चल रयेला है, अभी मिलने नहीं दे रयेले, भाई कू ये हुआ था, वो हुआ था, डिस्चार्ज कब करेंगे वगैरह वगैरह। एक जोक पे एक इच बार हंसी आती है, दो या तीन बार सुनके खुन्नस आने लगता है, तो सोचो अपुन का कित्ता भेजा फ्राई हुआ होएंगा, एक इच बात का हजार बार रिपीट टेलिकास्ट करके। इत्ती बार तो सूर्यवंशम सोनी चैनल पे रिपीट नहीं हुई, सीआइडी सीरियल रिपीट नहीं हुआ और तारक मेहता का उल्टा चश्मा रिपीट नहीं हुआ जितनी बार अपुन ने सबको एक इच टाइप के सवाल का एकइच टाइप वाला जवाब दिया होएंगा। वइसे तो भाई बीमार था तो अपुन के भेजे में अइसे गलत विचार आने नहीं चाहिए थे, पन अपुन ने खुराफात कर डाली। डिस्चार्ज वाले दिन अपुन ने सबसे पहला काम ये किया कि मुन्ना भाई को उनका मोबाइल फोन हाथ में दे दिया। और अक्खा मुंबई के शुभचिंतक लोग कू मेसेज कर दिया कि भाई ठीक हैं, डॉक्टर ने उनको मोबाइल यूज़ करने के वास्ते दे दियेला है तो आप शुरू हो जाओ। मुन्ना भाई कब से आपके फोन का इच इंतजार कर रयेले हैं।

मुंबइया स्टाइल में मुन्ना और सर्किट का ये भेजा फ्राई आपको कैसा लगा? हमें अपनी राय लिखकर भेजिए इस मेल आईडी पर nbtreader@timesgroup.com और सब्जेक्ट में लिखें-'भेजा फ्राई'

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

जीवन में संतुलन से मान-अपमान बेअसर लगते हैं

श्री श्री आनंदमूर्ति

मन में तरह-तरह की कुंठाएं (complex) रहती हैं। धन, बल, प्रतिष्ठा की कुंठा superiority complex है। कुछ लोग अपने आपको दूसरे की तुलना में हीन समझते हैं। यह inferiority complex है। गरीब अमीर बनने के प्रयास में रहते हैं। जो अमीर हैं वे और ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं। कम पढ़े-लिखे लोग सोचते हैं विद्वान के सामने कैसे जाऊं। किसी में डर बैठा रहता है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा। किसी बीमार की रिपोर्ट आनी है तो वह डरा रहता है, यानी fear complex उसे सताता रहता है। किसी को हारने का डर सताता है। इन तमाम कुंठाओं के बीच संतुलन स्थापित करने के प्रयास पर जोर दिया जाता है। इसे ही समता भाव कहा गया है।

हमें जो कुछ मिला है, वह परमपुरुष की बदौलत। इसलिए हमें परमपुरुष पर उचित-अनुचित का फैसला छोड़ देना चाहिए। किसी को मन में घमंड नहीं रखना चाहिए। घमंड रखना ही है तो यह घमंड होना चाहिए कि मैं परमपुरुष की संतान हूं। इस संसार में जितनी भी संपदाएं हैं, उनका कारण परमपुरुष हैं और मैं उस ईश्वर का बेटा या बेटी हूं। फिर किसी भी तरह की कुंठा नहीं रहेगी। मन फल लदे वृक्ष की तरह झुका रहेगा। और वह दूसरों को आश्रय और फल बांटने के लिए तत्पर रहेगा। क्योंकि जब तक हम सांसारिक दुनिया में नहीं उलझते हैं, तब तक एक ही पिता की संतान अपने भाइयों या बहनों के प्रति जल्दी भेदभाव नहीं रखना चाहते।

लेकिन ऊंच-नीच की बात पर हम लड़ते-झगड़ते रहते हैं। मान लिया जाए, एक ही पिता के पांच बच्चे हैं तो वे जाति और धर्म को लेकर आपस में लड़ेंगे? नहीं न। तो सचाई यह है कि जो परमपुरुष को मानते हैं, वे भेदभाव नहीं मानते। जब भेदभाव मानने जैसी कोई बात होगी ही नहीं तो कुंठाएं कहां से आएंगी। मनुष्य में एक और कुंठा रहती है- मैं पापी हूं, मैंने यह पाप किया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। परमपिता सब देख रहे हैं। वह मुझे मेरे पाप की सजा देंगे। ऐसी कुंठा हम क्यों पालें, जब हम परमपिता की संतान हैं। पाप-पुण्य तो इस जगत की चीज है।

एक उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा है। वह साफ वस्त्र पहने हुए है। गले में सोने का हार है। वह देखने में अच्छा लग रहा है। पिता उसे गोद में उठा लेंगे। प्यार करेंगे। और एक बच्चा सड़क पर चलते-चलते नाली में गिर जाता है। हाथ-पैर में कीचड़ लग जाते हैं। उस बच्चे को कीचड़ में लिपटा देखकर कोई दूसरा घृणा कर सकता है। पर क्या उसका पिता घृणा करेगा? बिलकुल नहीं। वह झट उठाएगा, पोंछेगा और रोते हुए अपने बच्चे को चुप कराएगा। इसी तरह से पाप और पुण्य दुनिया के लिए है। परमपिता के लिए नहीं।

इसलिए मन में कभी किसी तरह की कुंठा नहीं रखनी चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि परमपुरुष के सामने कैसे खड़ा होऊंगा। बार-बार यह सोचकर शर्माना नहीं चाहिए। शर्म या लाज तो एक पाश है। एक बंधन है। इस बंधन से लड़ाई का मतलब है, परमपुरुष के समीप जाना।

प्रस्तुति : दिव्यचेतनानंद अवधूत

अपनी ही पिच पर कैसे पिछड़ी BJP

नरेन्द्र नाथ

2024 का आम चुनाव चौंकाने वाला रहा। नरेंद्र मोदी की अगुआई में NDA लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में जरूर सफल रहा, लेकिन इस चुनाव ने कई मिथ तोड़े और उसके साथ ही कुछ रिवर्स ट्रेंड भी दिखाए। सबसे अहम ट्रेंड था ऑल्टरनेटिव मीडिया और सोशल मीडिया पर विपक्षी स्पेस का मजबूत होकर उभरना। समानांतर नैरेटिव में विपक्ष इस बार बीस पड़ा। इसके साथ ही दिलचस्प बात यह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुआई में BJP के उभरने के पीछे जो प्लैटफॉर्म सबसे सशक्त मीडियम रहा, 2024 में वहीं से उनके लिए सबसे ज्यादा प्रतिरोध उभरा।

Ai Image

इस चुनाव में विपक्ष पूरी तरह सोशल मीडिया पर निर्भर रहा। खासकर I.N.D.I.A. के घटक दलों ने अपनी बात पहुंचाने, लोगों से जुड़ने के लिए इस मीडियम का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने खासतौर पर सार्वजनिक मंचों से मुख्यधारा की मीडिया के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। राहुल गांधी ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। विपक्ष और उनके समर्थकों ने पूरी ताकत सोशल मीडिया पर लगाई, खासकर यूट्यूब पर। इसमें social media influencers का भी साथ मिला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी का BJP के खिलाफ बनाया गया विडियो पूरे देश में वायरल हुआ, करोड़ों व्यू मिले। विपक्ष ने भी इस विडियो का इस्तेमाल किया। ऐसे विडियो से इस बात को और बल मिला कि BJP 400 सीटें जीतने के बाद संविधान बदल सकती है।

विशुद्ध राजनीति

कसौटी

सोशल मीडिया पर विपक्ष को बढ़त

आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले एक साल के दौरान सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर विपक्ष लगातार मजबूत हुआ। हालांकि चुनाव से ठीक पहले BJP और खुद नरेंद्र मोदी को इसका एहसास हो गया था। इलेक्शन के पहले मोदी ने social media influencers से मुलाकात भी की थी। लेकिन, विपक्ष ने शुरू में ही जो बढ़त बना ली थी, उसे उसका फायदा मिला। संविधान बदलने का मुद्दा हो, युवाओं को रोजगार का मसला या कोई और बात, विपक्ष ने सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल किया।

वोटिंग पैटर्न पर आए ट्रेंड जाहिर करते हैं कि चुनाव पर सोशल मीडिया का कितना बड़ा असर पड़ा। 18 से 30 साल के युवाओं ने 2014 और 2019 की तुलना में इस बार विपक्ष को अधिक वोट दिया। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी के विडियो 300% अधिक देखे गए। कांग्रेस का घोषणापत्र एक करोड़ बार डाउनलोड हुआ। यूट्यूब पर BJP के खिलाफ कंटेंट की व्यूअरशिप अधिक रही।

ऑल्टरनेटिव मीडिया और सोशल मीडिया ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ठीक वैसी ही भूमिका निभाई, जैसा कि UPA-2 के दौर में हुआ था। दरअसल, इसकी शुरुआत किसान आंदोलन के समय ही हो गई थी। तब किसानों ने सोशल मीडिया का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया और पूरे साल आंदोलन चला। आखिरकार किसान अपनी मांग मनवाने में सफल रहे। हालांकि इस बार जब विपक्ष सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बढ़ा रहा था, तब BJP ने इसे यह कहकर खारिज कर दिया कि वह जमीन पर अधिक ताकतवर हो चुकी है। लेकिन, उसका आकलन कहीं न कहीं गलत साबित हुआ, खासकर पहली बार वोट डालने वालों के बारे में। ऐसे मतदाताओं के बीच पिछले कुछ बरसों में ब्रैंड राहुल भी मजबूत हुआ है।

पिछले अनुभव का सबक

10 साल पहले, 2014 में लोगों ने पहली बार ऐसा चुनाव देखा था जिसका एक रणक्षेत्र सोशल मीडिया भी बना। नरेंद्र मोदी वहां सुपरस्टार बनकर सामने आए। पूरे चुनाव के दौरान सोशल मीडिया ने न सिर्फ खबरें ब्रेक कीं, बल्कि ओपिनियन मेकिंग में भी दखल दिया। तब लोकसभा की 163 सीटें शहरी या विकसित होते क्षेत्रों में आती थीं। जानकारों के अनुसार, इन जगहों पर सोशल मीडिया ने चुनाव प्रचार और लोगों के मत को प्रभावित करने में प्रभावी भूमिका निभाई। 2014 में सीमित इंटरनेट विस्तार के बावजूद सोशल मीडिया ने चुनाव पर गहरा असर डाला था। तब विपक्ष इस प्लैटफॉर्म से पूरी तरह अनजान-सा था। लेकिन, उस समय के अनुभव से सबक लेकर उसने धीरे-धीरे यहां भी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी।

एक दशक पहले सोशल मीडिया ने पहली बार भारत में कैंपेन और नैरेटिव को आगे ले जाने के सशक्त हथियार के रूप में उपयोग होने की संभावना की पुष्टि की थी। इससे पहले अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन हो या दिल्ली गैंग रेप के बाद शुरू हुआ आंदोलन, इनकी रूपरेखा सोशल मीडिया पर रची गई। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने तभी इसमें छिपी संभावना को समझ लिया था। आज भी वह सोशल मीडिया पर सबसे मजबूत हैं। लेकिन, कहीं न कहीं विपक्ष और social media influencers के सामूहिक हमले का काउंटर सत्ता पक्ष नहीं कर सका। जिस मैदान पर BJP और नरेंद्र मोदी कभी अजेय माने जाते थे, इस चुनाव में उसी मैदान पर वे पूरी तरह बैकफुट पर दिखे।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ टर्म पूरा करेगी सरकार

10 जून का संपादकीय 'विकास पर रहे फोकस' पढ़ा। NDA सरकार के मुखिया के तौर पर रविवार को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरा कार्यकाल हासिल करने वाले प्रधानमंत्री बन गए। लोग कह रहे हैं, गठबंधन सरकार होने के बावजूद मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल बेरोकटोक पूरा हो जाएगा। खुद BJP के पास सबसे ज्यादा 240 सीटें हैं। फिर उन्होंने 10 अन्य निर्दलीय सांसदों को अपने साथ कर लिया है। कार्यभार संभालते ही मोदी ने किसानों के लिए 17वीं किस्त जारी कर दी।

सुभाष बुडावन वाला, ईमेल से

■ मुद्दे की बात हो

यह पत्र 14 मई को 'भेजा फ्राई' कॉलम में प्रकाशित लेख 'एक रापचिक गारंटी अपुन की तरफ से भी' से संबंधित है। लेखिका ने मजाकिया अंदाज में यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे सर्किट जैसे लोग चुनावी मुद्दों को हल्के में लेते हैं और जनता की असली समस्याओं पर ध्यान नहीं देते। लेख में यह भी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि चुनावी वादों और राजनीति में कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हो सकती हैं।

सुरेंद्र रावत, ईमेल से

■ कहां हुई चूक

इस साल 24 लाख से अधिक बच्चों ने NEET की परीक्षा दी है और इनमें से 13.16% छात्रों को सफलता मिली है। इस साल कुल 67 कैंडिडेट्स ने ऑल इंडिया रैंक-वन हासिल किया। इन सभी कैंडिडेट्स को 720 में से 720 अंक मिले। लेकिन परिणाम आने के बाद से कई सवाल उठने लगे। हैरानी की बात है कि बार-बार परीक्षाओं में घालमेल की बातें आने के बावजूद ऐसी नौबत दोबारा क्यों आती है? क्या परीक्षाओं की व्यवस्था में ही कहीं बड़ा झोल है।

केतकी झा, ईमेल से

nbteditpage@gmail.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

बुमराह और हार्दिक की करिश्माई गेंदबाजी, पाक के जबड़े से छीनी जीत
- एक खबर
- इस हार के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बुरे सपने तो नहीं आएंगे!

कार्तिक सिंह

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • मंगलवार • 11 जून • 2024
www.rashtriyasahara.com

मंत्रिमंडल और गठबंधन दल

नरेन्द्र मोदी ने रविवार को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले। तीसरी बार भी मोदी सरकार में उत्तर प्रदेश और बिहार का दबदबा दिखता है। हालांकि तकनीकी वजहों से इस सरकार को मोदी सरकार नहीं कह सकते हैं क्योंकि भाजपा को अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ है। बहरहाल, मंत्रिमंडल में इस बार 30 के करीब नए चेहरे शामिल किए गए हैं जबकि कई पुराने मंत्री इस बार बाहर कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 11 मंत्री तो बिहार से 8 मंत्री बनाए गए हैं। थोड़ा चकित करने वाली बात उत्तर प्रदेश को लेकर है क्योंकि पार्टी इस राज्य में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी, इसके बावजूद मंत्रिमंडल में उसकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। हां, बिहार के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि यहां 8 मंत्री इसलिए

बनाया गया क्योंकि अगले वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। यानी कि राज्यों के चुनाव, जातिगत समीकरण और साझेदार दलों की जीत-हार का पैमाना; पूरे मंत्रिमंडल के गठन का आधार रहा है। केरल से भाजपा का पहली बार कोई सदस्य जीत कर लोक सभा पहुंचा है। लिहाजा इस जीत को प्रभावी मानकर पार्टी नेतृत्व ने वहां से जीतकर आए सुरेश गोपी को जगह दी है। दरअसल, पार्टी का विस्तार इस बार दक्षिण में बढ़ा है। यही वजह है कि उसे दर्शाने का कोई मौका पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है। हालांकि दिल्ली की सभी सातों सीटों पर विजय हासिल करने के बावजूद आलाकमान ने यहां से महज एक सदस्य को मंत्री पद दिया है। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल में साथी दलों का प्रभाव परिलक्षित होता है। अपने कई पुराने चेहरों की छुट्टी कर नए सदस्यों को मंत्री पद पर बिठाना और गठबंधन दलों के सदस्यों को तरजीह देना इसी ओर इशारा करती है। वैसे, सामाजिक समीकरण का मंत्रिमंडल में विशेष ध्यान रखा गया है। नए मंत्रियों में ओबीसी समुदाय के सबसे ज्यादा 27 मंत्री जबकि सवर्ण समुदाय से 25 मंत्री बनाए गए हैं। एससी, एसटी से जहां 14 लोगों को जगह दी गई है वहीं पांच अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं। इस रणनीति को इसलिए तरजीह मिली क्योंकि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी ने सामाजिक समीकरणों का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। अगले कुछेक महीने में तीन राज्यों-हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होंगे। उसी समय यह साफ-साफ पता चलेगा कि इनकी रणनीति सफल हुई है या नहीं।

कायम है दहशतगर्दी

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का वीभत्स रूप रविवार को देखने को मिला। यहां के रियासी जिले में शिवखोड़ी गुफा तीर्थस्थल से कटरा आ रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। गोली लगने से बस चालक नियंत्रण खो बैठा, जिससे बस खाई में गिर गई। इसमें दो बच्चों व तीन महिलाओं समेत दस यात्रियों की मौत हो गई तथा 33 घायल हैं। हमला करने वाले आतंकवादी पहाड़ी इलाकों में छिपे बताए जा रहे हैं। जो बीते महीने राजौरी व पुंछ में कई हमले कर चुके हैं। यह वारदात वाकई चिंताजनक है। घायलों के अनुसार, गोली दागने वाले दो-तीन थे। माना जा रहा है ये पाकिस्तानी आतंकी हो सकते हैं। यह हमला जान-बूझकर ऐसे समय किया गया, जब मोदी कैबिनेट शपथ लेने की तैयारी कर रही थी, जिसमें कई देशों के प्रमुख शिरकत कर रहे थे। इलाके को फौरन सुरक्षा घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया

गया। आम चुनाव के बाद यह माहौल बिगाड़ने और शांति के प्रयासों पर गहरा झटका माना जा रहा है। बौखलाये आतंकियों ने 25 -30 राउंड गोलियां चलायीं। हालांकि सभी यात्रियों की पहचान स्पष्ट नहीं पाई। इनमें कुछ उप्र, राजस्थान व दिल्ली के निवासी हैं। कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मददद से खाई में गिरे यात्रियों को निकाला जा सका। तीन दशकों में ऐसा हमला दूसरी बार किया गया है। 2017 में अमरनाथ यात्रा के दारान अनंतनाग में भी तीर्थयात्रियों से भरी बस पर ऐसा ही हमला हुआ था। बीते महीने भी पर्यटकों से भरी बस पर पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था। लगातार होने वाले ये हमले पर्यटकों को भयभीत करने के लिहाज से किये जा रहे हैं। ताकि जम्मू-कश्मीर में स्थानीय रोजगार तथा कारोबार में रुकावट पैदा की सके। बड़ी संख्या में नौजवानों में पढने और रोजगार करने का जोश इस दहशत के कारण थम सकता है। बौखलाये आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षाबलों के प्रयासों का नतीजा है कि राज्य में तेजी से पर्यटन बढ़ रहा है। लोग वर्तमान हालात से फिलहाल खुश हैं। सुरक्षा बलों के अनुसार इसमें लश्कर-ए-तैयबा का हाथ हो सकता है। राजौरी इलाके में आतंकी अबू हमजा के सक्रिय होने का अंदेशा भी व्यक्त किया जा रहा है। जरूरी है इन्हें दबोच कर राज्य में शांति प्रयासों में तेजी लाने में देरी न की जाए। ऐसी घटना पर लापरवाही कतई ठीक नहीं है।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

काम पर चलें, खटाखट

चुनाव निपट लिये जी, चुनावी डिबेट भी निपट जाएगी।

महीने भर से ज्यादा चली चाऊं चाऊं चक चक। खटाखट, सफाचट, फटाफट, धकाधक, मंगलसूत्र, मुगल, औरंगजेब सब आ लिये चुनावी चक्कलस में। खटाखट जैसा शब्द पालिटिकल शब्द हो गया। पॉलिटिक्स कुछ भी कर सकती है। वैसे क्या बचा है अब जो पॉलिटिकल नहीं है। आप कहिये किसी से गरमी बहुत है, तो क्या पता सामनेवाला बंदा नाराज हो जाए और कह उठे कि क्या यह गरमी सिर्फ मोदी ने करवाई है, पहले तो गरमी होती ही नहीं थी। पहले तो दिल्ली हमेशा शिमला होता था। सिंपल सी बात भी चुनावी गर्मी में पॉलिटिकल हो जाती है। आप किसी से कहिए कि अब दिन बहुत बड़े हो गए हैं, तो सामने से जवाब आ सकता है कि मोदीजी के नेतृत्व में सब कुछ बड़ा हो रहा है। सपने बड़े हो रहे हैं, परिणाम बड़े हो रहे है और दिन भी बड़े हो रहे हैं।

कुछ भी कहना खतरनाक हो गया है इन दिनों। समझ कर बोलने का वक्त था पर अब चुनाव निकल लिया है, किसी की नाव पार लगेगी, किसी की डूबेगी।

बहुतों के मुंह छिपाने के दिन आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हर हाल में इस पार्टी को उतनी सीटें मिल रही हैं। उन्होने कहा था कि उस पार्ट को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी। बात झूठी साबित हो जाएगी, तो शर्म आएगी। नहीं नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों को शर्म नहीं आती। इनका पब्लिक की मेमोरी पर अपार विश्वास होता है। जनता कुछ याद न रखती। जनता भी क्या क्या याद रखे। प्याज आलू के भाव याद रखने में दिमाग का सारा मेमोरी स्पेस खत्म हो जाता है। कौन क्या कह गया, यह याद रखना संभव ना होता।

फिर याद रख भी ले पब्लिक, तो भी क्या हो जाएगा। जो नेता कुछ महीने पहले कह रहा था कि यह वाली पार्टी तो देश को तबाह कर देगी, यह चुनाव हार जाएगी। कुछ वक्त बाद वही नेता इसी पार्टी में आ गया, जिसे वह तबाहकारी बता रहा था। पब्लिक क्यों याद रखे, जब कहने वाला नेता ही याद ना रख रहा। टेंट, जुलूस आन रेंट, कुर्ता, पेंट, इन सबके कारोबार खूब चले। आम आदमी ने बहुत टाइम वेस्ट किया, चुनावी चर्चा में। बहुत टाइम खर्चा किया, चुनावी चर्चा में।

नाकामी की वजह खोजें

अयोध्या में भाजपा

विनीत नारायण

पांच सौ वर्ष बाद प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। हम सनातनियों के लिए यह गर्व की बात है। अयोध्या में हुए विकास के लिए भाजपा सरकार को जितना भी श्रेय दिया जाए कम है। अयोध्या में हुए इस जीर्णोद्धार के चलते आज विश्व भर के हिन्दुओं का सर गर्व से ऊंचा उठा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते दस वर्षों के अपने कार्यकाल में हिन्दू संस्कृति के संरक्षण के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। अयोध्या का विकास भी उसी शृंखला का हिस्सा है। आज जो भी अयोध्या में दर्शन करके आता है वह श्री राम के भव्य मंदिर व उसके आसपास हुए विकास को देख गर्व करता है। इस सब के बावजूद 2024 के चुनावों में अयोध्या में भाजपा को मिली हार से पूरी दुनिया के हिन्दू अचंभे में हैं।

यूं तो अयोध्या में हुए विकास को लेकर हर किसी के पास सिवाय प्रशंसा के कुछ नहीं है परंतु चुनाव परिणामों के बाद से सोशल मीडिया में भाजपा को मिली हार के कई कारण सामने आए हैं। इन्हीं में से एक अयोध्या निवासी संत सियाप्यारेशरण दास का एक संदेश काफी चर्चा में है। इन्होंने अयोध्या में भाजपा की हार के असली कारण बताए। वे लिखते हैं, 'भक्त और भगवान का युगों युगों से अनन्य भावपूर्ण प्रेम, स्नेह, वात्सल्य भाव रस से भीगा नाता रहा है। भगवान अपने ऊपर सब आरोप, लांछन तो क्या लात तक सह लेते हैं, लेकिन वो अपने भक्त की परेशानी, दुख-तकलीफ नहीं सहन करते। उदाहरणस्वरूप जब रावण ने युद्ध में विभीषण को देखा तो उस पर बाण चलाया जिसे भगवान श्री राम ने अपनी छाती पर सह कर अपने भक्त विभीषण की रक्षा की।

इसी प्रकार ध्यानस्थ भगवान श्री विष्णु जी से किसी बात पर क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने उनके सीने पर लात मारी तो उन्होंने स्वयं इसके लिए क्षमा मांगी। इस प्रसंग पर प्रसिद्ध चोपाई है; क्षमा बड़ेन को चाहिए छोटन को उत्पात। विष्णु का क्या घट गया जब भृगु ने मारी लात।। भक्त और भगवान के अनन्य नाते से संबंधित अनेक उदाहरण हैं। हम इन दो उदाहरणों के परिप्रेक्ष्य में ही बीजेपी की अयोध्या में करारी हार का विश्लेषण करते हैं। मैं अयोध्या जी में पिछले लगभग 10 वर्षों से वहां की कुछ सेवाओं में लगा हूं। इस कारण अयोध्या जी में घटित होने वाले अधिकांश अच्छे-बुरे अनुभवों से भली-भांति परिचित होने के नाते कुछ लिख रहा हूं।'

प्रथम कारण: प्रभु श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर बनने के प्रारंभ में कहा गया कि मंदिर लगभग 1000 करोड़ रुपयों में बनेगा, फिर एक वर्ष बाद कहा कि मंदिर 1400 करोड़ में बनेगा, फिर एक वर्ष बाद तीसरी बार कहा कि मंदिर 1800 करोड़ में पूर्ण होगा, जनता ने मान भी लिया। सोचिए, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हिसाब के इतने कच्चे हैं कि तीन-तीन बार मंदिर की कुल लागत बढ़ा-बढ़ा

कर बताएंगे जबकि इस प्रकार के सभी आकलन प्रथम बार में ही सही होने चाहिए थे।

दूसरा कारण: भगवान के प्रति अनन्य भक्ति भावना से ओत-प्रोत हजारों भक्त कितने किमी. चल कर आते हैं लेकिन मंदिर ट्रस्ट या अयोध्या प्रशासन द्वारा सुविधाओं के अभाव में वो इधर-उधर भटकते हैं। स्वच्छ पेयजल के कुछ फ्रिज अभी गर्मी बढ़ने पर लगाए गए हैं, लेकिन चंदे के 10,000 करोड़ के ब्याज रूपी 1800 करोड़ रुपए में बन रहे मंदिर के बाकी पैसे की एफडी कराई जा रही है। परंतु राम का पैसा राम के भक्तों पर खर्च नहीं हो रहा जबकि अयोध्या जी में लोक मान्यता है कि अयोध्या जी में कोई भूखा नहीं सोता। उसे अन्नपूर्णारूपा माता 'श्रीसीता जी' भोजन कराती हैं। क्या माता श्रीसीता जी के नाम से ट्रस्ट 20-30 जगह भंडारे नहीं चला सकता?

तीसरा कारण: माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री काल के पिछले 7 सालों से अयोध्या जी की गली-गली कई बार तोडी-फोड़ी गई हैं जिस कारण गलियों में जाम और लाल बत्ती लगी सायरन बजाती वीआईपी गाड़ियों के कारण मुख्य मार्ग का रूट परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण चहुं ओर अफरातफरी के माहौल ने अयोध्या की शांति भंग कर दी है। जिधर देखो बड़े-बूढ़े, बीमार-लाचार भटकते भक्ति में सराबोर भक्त धक्के खाते हैं। लेकिन उनकी पीड़ा कौन सुने?

चौथा कारण: अयोध्या जी के नया घाट से फैजाबाद के सहादतगंज तक 14 किमी. लंबे बाजार के छोटे-छोटे दुकानदार अयोध्या जी के क्षेत्रीय निवासी इसी लोकसभा क्षेत्र के हैं। इनकी अधिकांश दुकानें 70-80 साल से पगड़ी (धरोहर राशि) के कारण कम किराए पर हैं। इस मार्ग के चौड़ीकरण में उनके हितों की बजाय मकान मालिकों के हितों का खयाल रखा गया। दुकानदारों के पुनर्वास में बहुत अनियमितता बरती गईं जिस कारण उनके आंदोलन व प्रदर्शन बार-बार दबा दिए गए।

पांचवा कारण: अनेक वीआईपी की तरह मुंबई तक से सिनेमा तारिकाओं को भी जन्मभूमि मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा का न्योता भेजा गया लेकिन अयोध्या जी के चारों ओर के जिलों में मौजूद अनेक ऐसे कारसेवकों को न्योता तक नहीं भेजा गया जिन्होंने जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में लाठी और गोली खाई थीं। संत सियाप्यारेशरण दास जी कहते हैं, 'अयोध्या जी में बीजेपी की हार के वैसे तो अनेक कारण हैं। कितने गिनाऊं, यहां के ठाकुर सांसद लल्लू सिंह अपनी ठकुराई की ठसक में काम के नाम पर जनता को पिछले दस साल से झूठे आश्वासन देते रहे। उन्होंने जनता की नब्ज उसके बीच जाकर कभी नहीं जानी। संविधान बदलने के बयान ने यहां के 35 प्रतिशत दलित वोटरों का सपा की ओर ध्रुवीकरण किया। असल समस्या अयोध्या जी की गलियों के जाम रूपी झाम ने यहां के मूल निवासियों को बेहाल किया। प्रचार से कभी कोई सरकार नहीं बनी।

अयोध्या में बेतरतीब काम से अफसर, नेता, मंत्रियों ने चांदी नहीं सोना और हीरे लूटे हैं। अयोध्या एयरपोर्ट के वास्ते किसानों से पहले सस्ती जमीने अफसर व नेताओं ने खरीद कर फिर उसका सर्किल रेट बढ़ाकर खूब चांदी काटी, लेकिन जब पत्ता-पत्ता भगवान श्री राम हिलाते हैं, तब इनकी हार भी मेरे खयाल से स्वयं भगवान श्रीराम ने देकर इनको चेतावनी दी है। बीजेपी को सत्ता मद ले बैठा। गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीरामचरितमानस में लिखते हैं- निहं कोउ अस जनमा जग माहीं। प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं।।' अब यह चुनौती तो बीजेपी के सामने है कि वो हिन्दू धर्म क्षेत्रों में इस चुनाव में मिली अपनी विफलता के कारण खोजे।

अयोध्या में बेतरतीब काम से अफसर, नेता, मंत्रियों ने चांदी नहीं सोना और हीरे लूटे हैं। अयोध्या एयरपोर्ट के वास्ते किसानों से पहले सस्ती जमीने अफसर व नेताओं ने खरीद कर फिर उसका सर्किल रेट बढ़ाकर खूब चांदी काटी, लेकिन जब पत्ता-पत्ता भगवान श्री राम हिलाते हैं, तब इनकी हार भी मेरे खयाल से स्वयं भगवान श्रीराम ने देकर इनको चेतावनी दी है। बीजेपी को सत्ता मद ले बैठा

भारतीयों में परवान चढ़ रहा सैर-सपाटे का शौक

- पर्यटन प्रेमी भारतीयों के लिए दुबई, बैंकाक और सिंगापुर शीर्ष तीन सबसे अधिक खोजे गए गंतव्य बने हुए हैं, जबकि लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारतीयों ने सबसे अधिक लंदन, टोरंटो और न्यूयार्क में रुचि दिखाई
- 'मेक माई ट्रिप इंडिया ट्रैवल ट्रेंड्स' रिपोर्ट के मुताबिक, हांगकांग, अल्माटी (कजाकिस्तान), पारो (भूटान), बाकू (अजरबैजान) डानांग (वियतनाम), त्बिलिसी (जॉर्जिया) जैसे गंतव्यों के बारे में भी लोगों ने खासी दिलचस्पी ली

(आईएएनएस)

नई मोदी सरकार के उद्घाटन समारोह में पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों या शासनाध्यक्षों को आमंत्रित किया गया था। पाकिस्तान को निमंत्रण न दिए जाने पर तो सभी ने ध्यान दिया, लेकिन चीन और प्रतिबंधों से प्रभावित म्यांमार को बाहर नहीं किया गया है, जबकि भारत का पड़ोसी देश होकर भी चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है।

ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक
@Chellaney

मजदूरी में पिसता बचपन

बाल श्रम दिवस | अरुण कु. कैहरबा

खुशहाली और अच्छे दिनों की चर्चा के बीच पेट पालने के लिए बच्चों को मजदूरी करते देखना और अधिक परेशान करने वाला है। जिन नन्हें हाथों में कॉपी, पेंसिल व किताब होनी चाहिएं थी, उन हाथों को कड़ा काम करते हुए हम जहां-तहां देख रहे हैं। खेतों में व घरों में काम करते बच्चों को बिना कुछ कहे देखने के आदी हो चुके हम यदि अपनी दृष्टि का विस्तार करें तो माचिस-बीड़ी बनाना, पटाखे बनाना, कालीन बुनना, वेल्डिंग करना, ताले बनाना, पीतल उद्योग, कांच उद्योग, हीरा उद्योग, पत्थर-खदानों, सीमेंट उद्योग व दवा उद्योग में बेहद कठिन व स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्थितियों में बच्चे कम कर रहे हैं। इनके अलावा भी वे कूड़ा बीनना व गंदे नालों से पॉलीथिन व प्लास्टिक इकट्ठा करते हुए दिखाई देते हैं।

जिन मासूम बच्चों को स्कूल में खेलते हुए पढ़ना चाहिए था वे लाचारी में अपने हाथ फैलाए भीख मांग रहे हैं। इन बच्चों को शारीरिक, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही हैं। बीड़ी के अधजल टुकड़े की भांति इन बच्चों को हम अनजाने नरक में फेंक कर अच्छे दिनों की बातें करने में लगे हुए हैं। आंकड़ों की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार पूरी दुनिया में 16 करोड़ बच्चे बाल मजदूर हैं। इनमें से सात करोड़, 90 लाख बच्चे उन जोखिम भरे कामों में लगे हैं, जिनमें उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

भारत में यह संख्या एक करोड़ से अधिक बताई जाती है। अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम संगठन के अनुसार भारत में कुल बाल श्रमिकों में से 19 प्रतिशत के लगभग घरेलू नौकर हैं। ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र में तथा कृषि क्षेत्र से लगभग 80 प्रतिशत जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में एक लक्ष्य बाल मजदूरी को समाप्त करना भी है। यह लक्ष्य 2025 तक पूरा किया जाना है। हालांकि भारत ने भी सतत विकास लक्ष्यों को माना है, इस दिशा में कई कानूनी प्रावधान भी किए हैं, लेकिन लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत चींटी की चाल से चल रहा है। प्रभावशाली स्थाई संसदीय कमेटी ने दिसम्बर, 2023 में जारी एक रिपोर्ट- 'बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीतिः एक समीक्षा' में भारत द्वारा लक्ष्य पूरा किया जाना 'व्यावहारिक रूप से असंभव' बताया है। कमेटी ने बाल मजदूरी को समाप्त करने की बाधाओं को पहचानते हुए महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए

हैं। गरीबी और लाचारी को दूर किए बिना बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को समाप्त करना संभव नहीं है। विकास की योजनाओं में गरीबी दूर करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लाचारी में बच्चों के अभिभावक भी बहुत थोड़े पैसों में उनको ऐसे ठेकेदारों के हाथ बेच देते हैं जो अपनी व्यवस्था के अनुसार उन्हें काम पर लगा देते है।

कई बार उनसे थोड़ा खाने को देकर मनमाना काम कराया जाता है। 18 घंटे या उससे भी अधिक काम करना, आधे पेट भोजन और मनमाफिक काम न होने पर पिटाई से वे नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। फैक्टरी के खतरनाक वातावरण व धूल-धुआं बच्चों की सांसों में घुल रहा है। मुनाफे की होड़ में लगे पूंजीपतियों की फैक्टरियों व कार्यस्थलों पर काम करते हुए दुर्घटनाएं होना आम बात है, जिसमें बच्चों की आंखों में शरीर के अन्य अंग गंवाने पड़ रहे हैं। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। इन बच्चों के विकास पर ही देश की तरक्की निर्भर करती है यदि देश की आबादी में शुमार करोड़ों बच्चे बाल श्रम की भट्टी में झोंक दिए जाएंगे तो भला कैसे हम उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं?

आजादी के 77 सालों के इतिहास में राजनेताओं ने वोट हासिल करने के लिए न सिर्फ वादे किए बल्कि लच्छेदार भाषणों से लोगों का पेट भरने की कोशिश करते रहे। काम किया तो कॉर्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बाल श्रम रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया हो। भारतीय संविधान ने बाल मजदूरी को प्रतिबंधित किया है। संविधान की धारा 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्टरी या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता और ना ही किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त किया जा सकता है। फैक्टरी कानून 1948 के द्वारा भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कम पर लगाना निषिद्ध किया गया है। इसके बाद बाल श्रम निषेध कानून 1986 बनाया गया, जिसमें 2016 में संशोधन किया गया।

बाल मजदूरी की बात करें तो आम समाज ने भी बाल अधिकारों के हनन के दृश्य उदासीनता भरी निगाहों से देखने के अलावा कुछ नहीं किया। बाल मजदूरी की त्रासदी से देश में दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए जहां सरकारी स्तर पर ठोस उपाय किए जाने चाहिएं, वहीं सामाजिक पहलकदमियां भी की जानी चाहिए। 2024 में बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जो विषय निर्धारित किया गया है-आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें: बाल श्रम समाप्त करें! देश व दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए इस संदेश को अमल में लाना होगा।

ज्ञान बहुत सस्ता है | ओशो

मैं वही कहूंगा जो मैं जानता हूं; वही कहूंगा जो आप भी जान सकते हैं, लेकिन जानने से मेरा अर्थ है, जीना। जाना बिना जीए भी जा सकता है। तब ज्ञान होता है एक बोझ। उससे कोई डूब तो सकता है, उबरता नहीं।

जानना जीवंत भी हो सकता है। तब जो हम जानते है, वह हमें करता है निर्भार, हलका, कि हम उड़ सकें आकाश में। जीवन ही जब जानना बन जाता है, तभी पंख लगते हैं, तभी जंजीरें टूटती हैं, और तभी द्वार खुलते हैं अनंत के। लेकिन जानना कठिन है, ज्ञान इकट्ठा कर लेना बहुत आसान। और इसलिए मन आसान को चुन लेता है और कठिन से बचता है, लेकिन जो कठिन से बचता है वह धर्म से भी वंचित रह जाएगा। कठिन ही नहीं, जो असंभव से भी बचना चाहता है, वह कभी भी धर्म के पास नहीं पहुंच पाएगा। धर्म तो है ही उनके लिए, जो असंभव में उतरने की तैयारी रखते हैं। धर्म है जुआरियों के लिए, दुकानदारों के लिए नहीं। धर्म कोई सौदा नहीं है। धर्म कोई समझौता भी नहीं है। धर्म तो है दांव। जुआरी लगाता है धन को दांव पर, धार्मिक लगा देता है स्वयं को। वही परम धन है। और जो अपने को ही दांव पर लगाने को तैयार नहीं, वह जीवन के गुह्य रहस्यों को कभी भी जान नहीं पाएगा। सस्ते नहीं मिलते हैं वे रहस्य, ज्ञान तो बहुत सस्ता मिल जाता है। ज्ञान तो मिल जाता है किताब में, शास्त्र में, शिक्षा में, शिक्षक के पास। ज्ञान तो मिल जाता है करीब-करीब मुफ्त, कुछ चुकाना नहीं पड़ता। धर्म में तो बहुत कुछ चुकाना पड़ता है। बहुत कुछ कहना ठीक नहीं, सभी कुछ दांव पर लगा दे कोई, तो ही उस जीवन के द्वार खुलते हैं। इस जीवन को जो दांव पर लगा दे उसके लिए ही उस जीवन के द्वार खुलते हैं। इस जीवन को दांव पर लगा देना ही उस जीवन के द्वार की कुंजी है, लेकिन ज्ञान बहुत सस्ता है। इसलिए मन सस्ते रास्ते को चुन लेता है; सुगम को। सीख लेते हैं हम बातें, शब्द, सिद्धात, और सोचते हैं जान लिया। अज्ञान बेहतर है ऐसे ज्ञान से। अज्ञानी को कम से कम इतना तो पता है कि मुझे पता नहीं है। इतना सत्य तो कम से कम उसके पास है। जिन्हें हम ज्ञानी कहते हैं, उनसे ज्यादा असत्य आदमी खोजने मुश्किल हैं। उन्हें यह भी पता नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। सुना हुआ, याद किया हुआ, कंठस्थ हो गया धोखा देता है। ऐसा लगता है, मैंने भी जान लिया। मैं आपसे वही कहूंगा जो मैं जानता हूं। क्योंकि उसके कहने का ही कुछ मूल्य है।

रीडर्स मेल

आतंकियों पर सख्ती जरूरी

फिर एक बार जम्मू-कश्मीर आंतकी हमले से थर्रा उठा। तीर्थयात्रियों के जत्थे से भरी एक बस पर आतंकियों ने लगातार गोलियां बरसाई। चालक के घायल होने से बस खाई में गिर गई, इससे बैठे सभी यात्रियों का जीवन संकट में आ गया। कई लोगों की मृत्यु और घायल होने की सूचना से हृदय विचलित हो उठा। आमजन धारा 370 हटने के बाद निश्चिंत होकर उत्तर भारत की यात्रा करने की योजनाएं बनाता है। तभी कोई आतंकी हमले के समाचार सुनने को मिलते हैं। और प्रधानमंत्री के शपथ समारोह के दिन यह घटना होना, सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है। इन घटनाओं का तुरंत और ठोस प्रतिउत्तर देना बहुत आवश्यक है। आतंक फैलाकर आतंकी देश में भय का माहौल बनाना चाहते हैं। आतंकी गतिविधियों की जड़ों को काटन बेहद जरूरी है ताकि भारत का प्रत्येक नागरिक, भारत के किसी भी भाग में स्वतंत्र और निर्भय होकर जा सकें। जनमानस में विश्वास का माहौल पैदा होना चाहिए।

इंदु मणि, जयपुर

पुरस्कारों की बंदरबांट

पिछले दशकों में पुरस्कारों की बंदरबांट कथित साहित्यकारों, कलाकारों और अपने लोगों को प्रस्तुत करने के लिए विशेष साहित्यकार, पुरोधा कलाकार, साहित्य ऋषि जैसी कई श्रेणियां बनी है। इसके तहत विभिन्न अकादमियां एक दूसरे के अध्यक्षों को पुरस्कृत कर रही है और निर्णायकों को भी सम्मान दिलवा रही है। इन पुरस्कारों में पारदर्शिता का अभाव है। राज्य अकादमी पुरस्कारों की वार्षिक गतिविधियां संदिग्ध है। जो कार्य एक वर्ष में पूर्ण होने चाहिए उनको करने में वर्ष लग रहे हैं। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया स्पष्ट और समयानुसार नहीं है। साहित्य किसी भी देश और समाज का दर्पण होता है। इस दर्पण को साफ-सुथरा रखने का काम करती है वहां की साहित्य अकादमियां, लेकिन सोचिए क्या होगा? जब देश या राज्य का आईना सही से काम न कर रहा हो तो वहां की सरकार पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। जी हां, ऐसा ही कुछ हो रहा है देश के राज्यों की साहित्य अकादमियों में। किसी भी राज्य की साहित्य अकादमी के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जिस संस्था के अध्यक्ष हों वही संस्था सही से काम न करें तो बाकी संस्थाओं की स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं।

डॉ. सत्यवान सौरभ, ई मेल

गठबंधन सरकार जरूरी

गठबंधन सरकार बनाने की बाध्यता आम तौर पर राजनीतिक दलों के लिए गठबंधन सरकार बनाने की आवश्यकता को संदर्भित करती है, जब कोई भी एक पार्टी बहुमत हासिल नहीं करती है। स्पष्ट बहुमत के अभाव में, शासन गठबंधन पर निर्भर करता है, जो लोगों और राष्ट्र के लिए अधिक स्थिर और लाभकारी सरकार बना सकता है। कोई भी एक पार्टी अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के गिरने का डर सहयोग को बढ़ावा देता है। इसलिए, गठबंधन सरकार प्रभावी शासन, राजनीतिक स्थिरता और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती हैं, जब कोई भी एक पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं करती है। देखना होगा, इस बार क्या होता है?

मोहम्मद तौकीर रहमानी, मुंबई
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 298
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **जिया कादरी** द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । **समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र*** ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, **फैक्स** - 23352370, **दूरभाष - नोएडा प्रेस** 0120-2444755, 2444756 **फैक्स** - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

कायराना हमला

जम्मू-कश्मीर में रियासी जिले में तीर्थयात्रियों पर आतंकियों का हमला बेहद निंदनीय और कायराना है. तीर्थयात्री जिस बस में सवार थे, उस पर आतंकियों ने गोलियां चलायी, जिससे घायल चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी. इस वारदात में दस जानें गयी हैं और तीस से अधिक लोग घायल हैं. यह इलाका राजौरी से करीब है, इसलिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी गयी है. पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षाकर्मियों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर बहुत हद तक नियंत्रण कर लिया है. पाकिस्तान के संरक्षण एवं समर्थन से चल रहे विभिन्न गिरोह अब स्थानीय युवाओं बरगलाकर आतंक की आग में झोंकने में असफल हो रहे हैं. ऐसी स्थिति में बचे-खुचे आतंकी निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में हैं. राज्य में छुपे हुए सरगना हों या सीमा पार बैठे हुए उनके आका हों, वे अमन-चैन की वापसी से बौखलाये हुए हैं. हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में दुनिया ने देखा कि बड़ी संख्या में मतदाताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की. मत प्रतिशत के लिहाज से यह चुनाव अभूतपूर्व रहा है. इससे साफ है कि आम लोग अब आतंकवाद और अलगाववाद के उस स्याह साये से बाहर निकलना चाहते हैं, जिसमें जम्मू-कश्मीर तीन दशक तक घुटता रहा है. कुछ समय से यह भी देखा जा रहा है कि घाटी की तुलना में जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में आतंकी गतिविधियों में कुछ तेजी आयी है. हाल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल के प्रमुख नवाज शरीफ ने स्वीकार किया है कि करगिल में घुसपैठ पाकिस्तान की गलती थी और वह भारत के साथ एक धोखा थी. उन्होंने उसके लिए पाकिस्तानी सेना को कसूरवार ठहराया है. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पहले स्वीकार किया है कि पाकिस्तान में आतंकी गिरोहों का जमावड़ा है. नवाज शरीफ के बयान से ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक लेते हुए भारत के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहता है. पर हालिया घटना यही इंगित करती है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी का भेद बना हुआ है. पाकिस्तान की मौजूदा सरकार को इमरान खान की पार्टी को छोड़कर लगभग सभी दलों का समर्थन प्राप्त है. सेना के साथ भी उसके अच्छे संबंध हैं. अगर सरकार और सेना सचमुच भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के इच्छुक हैं, तो उन्हें अपनी सड़कों पर खुलेआम घूम रहे आतंकियों और चरमपंथियों को काबू करना होगा. भारत ने हमेशा कहा है कि जब तक आतंक को पाकिस्तान की शह मिलती रहेगी, किसी तरह की बातचीत संभव नहीं है. हमें सतर्क और सक्रिय रहने के साथ-साथ पाकिस्तान पर दबाव बनाने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए.

बचे-खुचे आतंकी निर्दोष नागरिकों को निशाना बना कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में हैं.

राष्ट्रीय राजनीति में नायडू की वापसी

किंशुक नाग
वरिष्ठ पत्रकार-लेखक
editor@thebillionpress.org

चंद्रबाबू नायडू ने अपने सबसे ताकतवर अवतार में फिर वापसी की है. उनके हाथ में मोदी सरकार के अस्तित्व की चाबी है. राज्य में लोकसभा की 25 सीटों में से उन्होंने 16 जीती हैं तथा 175 सीटों की विधानसभा में भी 135 पर विजय पायी है. इस शानदार जीत और एनडीए सरकार के उनके समर्थन के बाद देशभर में यह चर्चा है कि वे बदले में क्या चाहते हैं और आगे वे क्या करेंगे.

बीते चार दशक में भाग्य उन्हें सत्ता में आते-जाते देखता रहा है. कभी वे प्रधानमंत्री पद के बेहद करीब पहुंचे, तो कभी आंध्र प्रदेश की राजनीति के हाशिये पर चले गये. चंद्रबाबू नायडू ने अपने सबसे ताकतवर अवतार में फिर वापसी की है. उनके हाथ में मोदी सरकार के अस्तित्व की चाबी है. राज्य में लोकसभा की 25 सीटों में से उन्होंने 16 जीती हैं तथा 175 सीटों की विधानसभा में भी 135 पर विजय पायी है. इस शानदार जीत और एनडीए सरकार के उनके समर्थन के बाद देशभर में यह चर्चा है कि वे बदले में क्या चाहते हैं और आगे वे क्या करेंगे. देवगौड़ा, गुजराल और वाजपेयी सरकारों के गठन एवं समर्थन में उनकी अहम भूमिका से साबित हो चुका है कि गठबंधन सरकारें बनाने में वे माहिर हैं. नायडू दोनों तरफ- भाजपा और उसके विरोधी- रह चुके हैं. राज्य पर पकड़ रखते हुए उन्होंने असंभव गठबंधनों को सच बनाया है. वे आंध्र प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं. उनके बारे में ठीक से जानने के लिए हमें उनके शुरुआती दिनों को देखना होगा.

युवा विधायक के रूप में अस्सी के दशक के शुरू में नायडू हैदराबाद में विधायकों के लिए बने हॉस्टल में रहा करते थे. उनके कमरे में साथ में वाईएस राजशेखर रेड्डी रहते थे, जो नायडू की तरह बाद में मुख्यमंत्री बने. उनके कमरे में फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा की तस्वीर लगी होती थी. तब नायडू और रेड्डी दोस्त हुआ करते थे, बाद में राजनीतिक विरोधी हो गये. इस चुनाव में नायडू ने जगन मोहन रेड्डी (दिवंगत राजशेखर रेड्डी के पुत्र) को हराया है. दिलचस्प है कि जब वे दोनों विधायक आवास में साथ रहते थे, नायडू भी कांग्रेसी होते थे. बाद में वे तेलुगू देशम पार्टी में शामिल हो गये, जिसकी स्थापना तेलुगू फिल्म स्टार एनटी रामाराव ने की थी, जो तब आंध्र की राजनीति में हलचल मचाने की कोशिश में थे. रामाराव अपने अनोखे अंदाज से लोगों को समझाया कि प्रदेश के साथ कांग्रेस का व्यवहार सामंती है और उनकी पार्टी इस राज का विकल्प है. उसी समय रामाराव अपनी बेटी भुवनेश्वरी के लिए योग्य वर की तलाश में थे और उन्होंने चंद्रबाबू को देखा, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे, पर तेजतर्रार दिखते थे. साल 1981 में जब यह शादी तय हुई, तब नायडू कांग्रेस सरकार में मंत्री थे. दो साल बाद जब रामाराव मुख्यमंत्री बने, तब नायडू कांग्रेस छोड़कर तेलुगू देशम के साथ आ गये. उस साल वे चुनाव हार भी गये थे. नायडू 1975 से ही कांग्रेस में थे और संजय गांधी खेमे से जुड़े माने जाते थे.

तेलुगू देशम में अपने पहले दशक में नायडू संगठन के काम में लगे रहे और उनके पास कोई मंत्री पद नहीं था. लेकिन पार्टी में उनका बहुत प्रभाव था और इसे लोग मानते भी थे. साल 1990 में तेलुगू देशम सत्ता से बाहर हो गयी और कांग्रेस की सरकार बनी. लगभग उसी समय विधुर रामाराव ने फिर शादी की. उनकी नयी पत्नी अपेक्षाकृत बहुत युवा थीं और उन्होंने तुरंत ही पार्टी पर अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया. यह बात रामाराव की संतानों, विशेषकर उनके दामाद नायडू को रास नहीं आयी. साल 1995 में नायडू ने एक होटल में विधायकों को जुटाकर रामाराव का तख्तापलट करने का प्रयास शुरू कर दिया. चूंकि अधिकतर विधायकों ने उनका साथ दिया, सो रामाराव अपदस्थ हो गये. जल्दी ही चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी और सरकार की कमान अपने हाथों में ले ली. नये मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने केंद्र में भाजपा का साथ दिया और जब एनडीए की सरकार बनी, तो वे अटल बिहारी वाजपेयी के पसंदीदा बन गये. वे अक्सर नायडू से सलाह-मशवरा किया करते थे. जब नायडू सरकार में आये थे, तब हैदराबाद एक पिछड़ा शहर हुआ करता था. विकास की उनकी अपनी समझ थी. पड़ोसी शहर बैंगलुरु से प्रेरणा लेते हुए नायडू ने हैदराबाद में उच्च तकनीकी उद्योगों और सॉफ्टवेयर कौशलों को बढ़ावा देना शुरू किया. उन्होंने साइबराबाद की स्थापना की और अपनी गंभीरता दिखाने के लिए वे सिएटल गये, जहां माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स से मिलने के लिए उनके दफ्तर में घंटे भर इंतजार किया. जल्दी ही माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में एक विकास केंद्र खोल दिया. उसके बाद कई कंपनियों ने ऐसा किया और हैदराबाद को एक हाई-टेक सिटी के रूप में देखा जाने लगा. इससे रियल इस्टेट बहुत बढ़ा और कई संस्थान स्थापित हुए. शहर पूरी तरह बदल गया.

फिर भी 2004 में नायडू की पार्टी हार गयी. वाजपेयी सरकार भी पराजित हुई. कहा जाता है कि वाजपेयी ने नायडू की सलाह पर ही समय से पहले चुनाव कराया था. नायडू 2002 के गुजरात दंगों और उसके असर को लेकर आशंकित थे. तेलंगाना आंदोलन जोर पकड़ रहा था, जिसके कारण राज्य का विभाजन हुआ और तेलंगाना राज्य बना. नायडू अब ऐसे आंध्र प्रदेश में थे, जिसके पास हैदराबाद नहीं था. उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर अमरावती नामक नयी राजधानी बनाने का निर्णय लिया. यह नाम एक प्राचीन शहर से लिया गया था, जो अब अस्तित्व में नहीं था. पर यह राजधानी खेतों में बननी थी. नायडू के पास एक व्यापक योजना थी. पहले कार्यकाल में उन्होंने अमेरिका और यूरोप से निवेश जुटाया. दूसरे कार्यकाल में उनकी इच्छा थी कि जापान, सिंगापुर आदि देशों से निवेश लाया जाए. प्राचीन अमरावती शहर एक बौद्ध केंद्र हुआ करता था. इसलिए उन्हें आशा थी कि राजधानी के ऐसे नाम के आधार पर पूर्व के बौद्ध देशों से निवेश मिल जायेगा. लेकिन 2009 के विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हारकर सत्ता से बाहर हो गयी. उससे पहले ही वे भाजपा के साथ अपने पुराने गठबंधन से अलग हो चुके थे. वे केंद्र सरकार से आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जा चाहते थे, जिससे उन्हें अधिक धन हासिल हो सके. लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था. साल 2014 में वे जीते, पर 2019 में जगन रेड्डी जीत गये और केंद्र में फिर भाजपा की जीत हुई. जगन रेड्डी राजधानी को विशाखापट्टनम, जो एक बंदरगाह शहर है, ले जाना चाहते थे, पर इसमें बड़ी मुश्किलें थीं. उन्होंने राज्य में जिलों की संख्या बढ़ा दी और कई लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा की. इससे राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा. इस बार के चुनाव में एक बार फिर आंध्र प्रदेश ने व्यावहारिक विकास के प्रतीक नायडू को अपना नेतृत्व सौंपा है, जिनके पास राज्य के विकास और दिल्ली में अपनी खास जगह बनाने का लंबा अनुभव है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

किसान, जलवायु परिवर्तन और संभावित संकट

केसी त्यागी
पूर्व संसद सदस्य
kctyagimprs@gmail.com

बिशन नेहवाल
संस्थापक, 1 बिलियन ट्री

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई एक वैश्विक प्रयास है, जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों के सहयोग की आवश्यकता है. योगदानकर्ता और संभावित शमनकर्ता दोनों के रूप में किसानों की बहुमुखी भूमिका को पहचानना आवश्यक है.

दिल्ली व आसपास प्रदूषण और तापमान के बढ़ते स्तर से हाहाकार मचा हुआ है. इससे बीमारियों में काफी वृद्धि हुई है. प्रदूषित वायु के लिए संभ्रांत लोग पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा पराली जलाने को एकतरफा दोषी ठहरा देते हैं. राज्य सरकारों के बीच भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. सिर्फ दिल्ली में नहीं, बल्कि बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है. मध्य प्रदेश की स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है, लेकिन इसका मुख्य कारण इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में बड़ी संख्या में वाहन नहीं होना है. कारण कोई भी रहे, पर जलवायु परिवर्तन भावी पीढ़ी के लिए गंभीर चुनौती बन गयी है. इसके खिलाफ वैश्विक लड़ाई में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक महत्वपूर्ण योगदान कर्ता के रूप में कृषि पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है. यह समझना आवश्यक है कि उत्सर्जन के लिए किसानों को दोषी ठहराना अदूरदर्शी दृष्टिकोण है. ध्यान उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने और कृषि एवं पर्यावरण दोनों को लाभ पहुंचाने वाले स्थायी समाधान खोजने पर होना चाहिए. प्रदूषण के बारे में बात करते हुए आर्थिक विकास के बारे में भी बात होनी चाहिए. वर्तमान आर्थिक विकास भारी प्रदूषण पैदा कर रहा है. अगस्त 2018 में राज्यसभा में पेश संसदीय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, वाहनों का धुआं, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री उत्सर्जन, कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं और सड़कों पर जमी धूल की वजह से प्रदूषण बढ़ता है. विडंबना देखिये, जब पराली जलती है, तो उसका धुंआ दिल्ली तक पहुंच जाता है, पर जब किसान की फसल जलती है, तो उसका धुंआ तहसील स्तर तक भी नहीं पहुंच पाता.

कृषि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का एक स्रोत है, पर कृषि उत्सर्जन की जटिलताओं को पहचानना भी आवश्यक है. किसान समाज की रीढ़ हैं, जो हमें भोजन उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार हैं. वे भूमि संरक्षक भी हैं. कई किसान अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कम जुताई, फसल चक्र और सटीक कृषि जैसी टिकाऊ प्रथाओं को अपना रहे हैं. वे समझते हैं कि दीर्घकालिक कृषि स्थिरता के लिए एक स्वस्थ वातावरण आवश्यक है. भारत में कृषि मात्र जीविकोपार्जन का साधन नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है. यह एक ऐसी विधा है, जिसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के पोषण के लिये व्यवस्था की गयी है. लेकिन आज यह विधा बड़े बुरे दौर से गुजर रही है. किसान अप्रत्याशित मौसम, बढ़ती लागत, बदलती बाजार मांगों और पैदावार बढ़ाने के लगातार दबाव से जूझते हैं. अधिकतर किसान पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वे बस बढ़ती आबादी को खाना खिलाते हुए जीविकोपार्जन की कोशिश कर रहे हैं. जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका के लिए किसानों को दोषी ठहराने के बजाय टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए प्रोत्साहित करना अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण है. इसके लिए वित्तीय पुरस्कार से लेकर प्रशिक्षण व कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी तक पहुंच तक जैसे विभिन्न प्रयास हो सकते हैं.

पूरी दुनिया में किसानों को अक्सर अपनी सरकारों से सब्सिडी और प्रोत्साहन मिलता है. इनका उद्देश्य आम तौर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों को संरक्षण देना और कृषि स्थिरता को बढ़ावा देना है. आलोचकों का तर्क है कि कुछ सब्सिडी अनजाने में उन प्रथाओं को प्रोत्साहित करती हैं, जो उच्च उत्सर्जन को जन्म देती हैं, जैसे सिंथेटिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग. यह समझना आवश्यक है कि ये सब्सिडी मुख्य रूप से आर्थिक और खाद्य सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से हैं. किसान अक्सर सीमित मार्जिन के भीतर काम करते हैं और बाजार के उतार-चढ़ाव का सामना करते हैं, इसलिए सब्सिडी उनकी आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. अब सरकारें टिकाऊ कृषि पद्धतियों के महत्व को पहचानते हुए उन्हें प्रोत्साहित कर रही हैं. प्रौद्योगिकी भी कृषि उत्सर्जन को कम करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है. अधिक टिकाऊ कृषि प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और विकास में सरकारी निवेश आवश्यक है. सरकारों को नियमों और प्रोत्साहनों के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और वित्तीय रूप से समर्थन देना जारी रखना चाहिए. कृषि पद्धतियों को आकार देने में उपभोक्ता भी भूमिका निभाते हैं. पर्यावरण के प्रति जागरूक खेतों से उत्पाद चुनकर वे उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम किसानों को समझाने में मदद कर सकते हैं.

जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई एक वैश्विक प्रयास है, जिसमें समाज के सभी क्षेत्रों के सहयोग की आवश्यकता है. योगदानकर्ता और संभावित शमनकर्ता दोनों के रूप में किसानों की बहुमुखी भूमिका को पहचानना आवश्यक है. किसानों पर उंगली उठाने के बजाय हमें पर्यावरण और कृषि दोनों जरूरतों को पूरा करने वाले समाधान खोजने के लिए काम करना चाहिए. सरकारों, समाजों और कृषि उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों में परिवर्तन के लिए आवश्यक समर्थन, प्रोत्साहन और शिक्षा प्रदान करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है. **(ये लेखकद्वय के निजी विचार हैं.)**

देश दुनिया

दक्षिण कोरिया में प्रवासी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार

दक्षिण कोरिया की एक प्रवासी कामगार योजना के तहत फिलीपींस के अलावा नेपाल, वियतनाम, मंगोलिया, लाओस, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड से भी कामगारों की भर्ती की जाती है. काम पाने वालों में अधिकतर किसान और मछुआरे हैं. ये सभी अधिक वेतन दिये जाने के वादे पर पांच से आठ महीने के लिए दक्षिण कोरिया आते हैं. कामगारों की मानें, तो महीनों काम करने के बाद भी उन्हें खाली हाथ घर लौटना पड़ा. वास्तव में काम दिलवाने के बहाने बिचौलियों ने उनसे बहुत ज्यादा फीस ली, कइयों से तो काम दिलाने के बदले जमीन और खेत भी बंधक रखवा लिये, उनके पासपोर्ट और बाकी जरूरी कागजात जब्त कर लिये गये और जी तोड़ काम करवाया गया तथा वादे के मुताबिक वेतन भी नहीं दिया गया. ज्वाइंट कमेटी ऑफ माइग्रेंट्स इन कोरिया, प्रवासी श्रमिकों के काम करने की स्थितियों में सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था है. इसके एक अधिकारी, को जिकबो का कहना है कि ऐसी स्थितियां बताती हैं कि मौसमी कामगार मानव तस्करी और जबरन काम करवाये जाने के खतरों का सामना कर रहे हैं. को जिकबो ने दक्षिण कोरिया की प्रवासी कामगार योजना को आधुनिक गुलामी का एक रूप बताया. कहा कि यह मौजूदा समय में मानव तस्करी जैसा है. ब्रोकर, मौसमी कामगारों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार कर रहे हैं. दक्षिण कोरिया ने 2022 में यह योजना शुरू की थी. इसके तहत अब तक 3,500 से ज्यादा फिलीपींस के लोगों की भर्ती की जा चुकी है. इन श्रमिकों को यह कहकर रिझाया गया था कि वे अपने गांव-शहर में जितना कमाते हैं, उससे पांच गुना तक अधिक कमाई कर पायेंगे. दक्षिण कोरिया में बूढ़ी होती आबादी और सिकुड़ती जनसंख्या के कारण काम करने वालों की कमी है. कामगारों की मुख्य शिकायतें हैं वेलफेयर से जुड़े नियमों का उल्लंघन, बिचौलियों की ऊंची फीस, काम करने की बेहद मुश्किल स्थितियां, कम भुगतान और किसी भी तरह की सुनवाई न होना.

Deutsche Welle

जयंती विशेष

रामप्रसाद 'बिस्मिल' : 'ऐ मातृभूमि! तेरी जय हो, सदा विजय हो!'

कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार
kp_faizabad@yahoo.com

ग्यारह जून, 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में पैदा हुए सरफरोश क्रांतिकारी और कलमकार रामप्रसाद 'बिस्मिल' की 19 दिसम्बर, 1927 को गोरखपुर जेल में हुई शहादत से एक बड़ा ही भावुक वाकया जुड़ा हुआ है. शहादत से पहले वीरमाता मूलमती उनसे मिलने पहुंचीं, तो उनकी डबडबाई आंखें देखकर भी कमजोर नहीं पड़ीं. अपने कलेजे पर पत्थर रख उलाहना देती हुई बोलीं, 'अरे, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है और अंग्रेज सरकार उसके नाम से थर-थर कांपती है. मुझे पता नहीं था कि वह मौत से इतना डरता है!' उन्होंने फिर उनसे पूछा, 'रो-रोकर ही सूली चढ़ना था, तो तूने इस राह पर कदम ही क्यों रखा?' 'बिस्मिल' ने बिना पल गंवाये अपनी आंखें पोंछ डालीं और कहा, 'गलत मत समझ मां, मेरी आंखें मौत के खौफ से नहीं, यह सोचकर डबडबा आयी थीं कि अब उन्हें तेरे जैसी बहादुर मां को देखना मयस्सर नहीं होगा.' कुछ ही दिनों पहले उन्होंने इस मां को पत्र में लिखा था, 'केवल एक ही इच्छा थी मेरी कि तुम्हारे चरणों की सेवाकर अपना जीवन सफल करूं. किंतु यह इच्छा पूरी होती नजर नहीं आती. शायद तुम्हें जल्दी ही मेरी फांसी की सूचना मिले. मां, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य रख लोगी कि तुम्हारा पुत्र भारतमाता की सेवा की भेंट चढ़ गया. उसने तुम्हारी कोख को कलंकित नहीं किया.'

ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन ऐक्शन में क्रांतिकारियों ने अपने आंदोलन के लिए धन जुटाने हेतु उनकी अगुआई में लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन से ले जाया जा रहा सरकारी खजाना लूट लिया था. साल 1918 के 'मैनपुरी कांड' में भी बिस्मिल की कुछ कम भूमिका नहीं थी. वहां प्रसिद्ध कांतिकारी गेंदालाल दीक्षित द्वारा गठित 'मातृवेदी' के घुड़सवारों व हथियारों से लैस दस्ते के साथ बिस्मिल ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष चलाया था. इसके बाद उन्हें दो वर्षों के लिए भूमिगत होना पड़ा था. लेकिन गोरी अदालत द्वारा उक्त कांड में पकड़े गये क्रांतिकारियों को कठोर सजायें सुना दी गयीं, तो भगोड़ा करार दिये गये बिस्मिल ने चंद्रशेखर 'आजाद' के नेतृत्व वाले 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों का नया दौर आरंभ किया. दुर्भाग्य से काकोरी ट्रेन ऐक्शन के बाद वे पकड़ लिये गये और लखनऊ सेंट्रल जेल में रखे गये. फिर अशफाकउल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रौशन सिंह के साथ उन्हें मौत की सजा सुना दी गयी.

रामप्रसाद बिस्मिल
(जून 11, 1897 – दिसंबर 19, 1927)

गोरों को लगता था कि इस सजा के बाद देश में भय का ऐसा वातावरण बनेगा कि क्रांतिकारी आंदोलन अपनी मौत मर जायेगा. लेकिन बिस्मिल ने अपनी एक रचना में उसकी इस धारणा का भरपूर मजाक उड़ाते हुए पूछा- 'कभी ओ बेखबर तहरीके-आजादी भी रुकती है/ बढ़ा करती है उसकी तेजी-ए-रफ्तार फांसी से.' फिर चेतावनी दी- 'यहां तक सरफरोशाने-वतन बढ जायेंगे कातिल/ कि लटकाने पड़ेंगे नित तुझे दो-चार फांसी से.' उनकी शहादत के सवा तीन साल बाद 23 मार्च, 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में राजगुरू व सुखदेव के साथ शहीद-ए-आजम भगत सिंह ने भी ऐसा ही विश्वास जताया था- 'मेरी शहादत के बाद देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जायेगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवादियों या उनकी तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रह जायेगी.' शहादत से पहले मैजस्ट्रिट ने बिस्मिल से उनकी अंतिम इच्छा पूछी, उन्होंने कहा था, 'मैं ब्रिटिश राज का सर्वनाश चाहता हूं.' अपनी सजा को तो वे पहले से ही ठेंगे पर रखे हुए थे- 'बला से हमको लटकाए अगर सरकार फांसी से/ लटकते आए अक्सर पैकरे-ईसार फांसी से. लबे-दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी/ तमन्ना थी कि करता मैं लिपटकर प्यार फांसी से.' देशवासियों के लिए उनका आह्वान था- 'कौम पर कुरबान होना सीख लो ऐ हिन्दियो/ जिंदगी का राजे-मुज्मिर खंजरे-कातिल में है.' क्रांतिकारियों के सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम के गंभीर अध्येता सुधीर विद्यार्थी बताते हैं कि बिस्मिल का क्रांति और कलम से लगभग एक जैसा रिश्ता था. वे संवेदनशील कवि/शायर, लेखक ओर अनुवादक भी थे. साल 1915 में वे ब्रिटिश साम्राज्य के समूल विनाश की प्रतिज्ञा कर क्रांतिकारी बने, तो इसके लिए जरूरी हथियार उन्होंने अपनी पुस्तकों की बिक्री से मिले धन से ही खरीदे थे. लेखन या कवि कर्म के लिए बिस्मिल के अलावा उनके दो और उपनाम थे- राम और अज्ञात. तीस साल के जीवनकाल में उनकी कुल 11 पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं, जो सब जब्त कर ली गयी थीं.

अपनी शहादत से दो दिन पहले तक वे जेल के अधिकारियों की नजर बचाकर अपनी आत्मकथा लिखते और किस्तों में बाहर भिजवाते रहे थे. उन्होंने लिखा था कि मैं प्राण त्यागते समय निराश नहीं हूं, न ही यह सोचता हूं कि हम लोगों के बलिदान व्यर्थ गये. उनकी कामना थीः 'ऐ मातृभूमि! तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा, सुख-शांति-कांतिमय हो दिल फिदा करते हैं कुरबान जिगर करते हैं/ पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं".

आपके पत्र

इस बार देश को मिला मजबूत विपक्ष

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग की सरकार बनी. इस बार के चुनाव ने देश की सत्ता की वैकल्पिक धुरी का रास्ता खोल दिया. इस बार देश को मजबूत विपक्ष मिला है. लोकतंत्र की मजबती के लिए विपक्ष का सशक्त होना अनिवार्य है. इसका लाभ आम जनता को मिलेगा और सत्ता निरकुंश नहीं होगी. साथ समय-समय पर जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विपक्ष मजबूती से आवाज उठायेगा. आम लोगों को उम्मीद है कि उनकी समस्याओं को सरकार के सामने विपक्ष निष्पक्षता के साथ उठायेगा. साथ ही उनकी बातों को उठायेगा.

अभिनव कुमार, बेगूसराय

स्मार्ट फोन ने बदली जीवनशैली

स्मार्ट फोन ने जीवनशैली बदल दी है. ऐसा हो गया कि अब कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के नहीं रह सकता है. हर कोई को मोबाइल की दुनिया में व्यस्त देखा जा रहा है. अधिकतर काम मोबाइल की मदद से ही हो रहा है. घर-दफ्तर की व्यस्तता से लेकर यात्रा तक की सहजता तक संवाद की कड़ियां टूट गयी हैं. इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि मोबाइल से कई प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं. कोरोना काल में इसका भरपूर लाभ मिला. घर बैठे स्टूडेंट्स मोबाइल पर ही ऑललाइन पढ़ाई कर रहे थे.

गोपाल सोनी, इमेल से

पपोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ मेल करें : patna @prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

फिर आतंकी हमला

जम्मू के कटरा में शिव खोरी गुफा मंदिर से माता वैष्णो देवी मंदिर तक तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकियों की गोलीबारी और उसके बाद हुई दुर्घटना जितनी दुखद है, उतनी ही चिंताजनक भी। दुखद इसलिए कि आमतौर पर तीर्थयात्रियों को निशाना नहीं बनाया जाता है और चिंता इसलिए कि जम्मू में वैष्णो देवी मार्ग को भी अगर निशाना बनाया जा रहा है, तो यह एक बड़ी चुनौती है। दुर्घटना बहुत भयानक थी। एक बच्चे सहित कम से कम नौ तीर्थयात्री मौत की नींद सो गए। 30 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। क्या यह हमला करने का आतंकियों का नया तरीका है? क्या उन्होंने जान-बूझकर बस चालक पर गोलियां बरसाईं, ताकि बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरे? वैसे, सुरक्षा बलों को शक है कि आतंकियों का इरादा बस रोककर गोलियां बरसाने का था? रियासी की यह घटना अनेक सवाल खड़े करती है। इसके पीछे किसी गहरी साजिश का संकेत मिलता है और इस नई आतंकी साजिश के तमाम धागे खोलना सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की प्राथमिकता होनी चाहिए।

जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मृतकों के परिजन व पीड़ित लोगों के लिए उचित ही मुआवजे की घोषणा की है और राहत के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। संवेदनाओं का तांता लगा हुआ है और आतंकियों की कायरता की निंदा की जा रही है। यह बात गौर करने की है कि यह हमला उसी दिन हुआ, जिस दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए शपथ ग्रहण था। जाहिर है, यह आतंकी हमला सरकार को सीधी चुनौती है। इसका माकूल जवाब हमारी सुरक्षा एजेंसियों को देना चाहिए। सुरक्षा बलों ने बहुत मेहनत से वैष्णो देवी मार्ग को निष्कंटक बनाए रखा था, अब फिर उग आए कांटे उखाड़ने का वक्त आ गया है। कश्मीर और जम्मू के संवेदनशील रास्तों पर हर जगह पहरे बिठाना व्यावहारिक नहीं, पर ऐसे हमलों की हिमाकत को सड़क पर उतरने से पहले ही ठिकाने लगाना बेहतर है। क्या आतंकी हमले के बारे में कोई पूर्व सूचना थी? अगर पूर्व सूचना नहीं थी, तो यह और भी गंभीर बात है। क्या महत्वपूर्ण रास्तों पर पुलिस गश्त में कमी आई है? इस आतंकी हमले ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या कोई नया आतंकी गिरोह सक्रिय हुआ है? वैष्णो देवी के पूरे मार्ग पर यह स्थानीय लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे देवी दर्शन के लिए आने वाले तमाम मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करें। पुलिस ने ग्राम सुरक्षा गार्ड्स को सचेत भी किया है, पर अब पहले की तुलना में ज्यादा मुस्तैदी का वक्त आ गया है।

वैष्णो देवी के रास्ते में हुआ यह आतंकवादी हमला सरकार को सीधी चुनौती है। इसका माकूल जवाब हमारी सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर देना चाहिए।

ध्यान देने की बात है कि वैष्णो देवी तीर्थ के दर्शन के लिए एक दिन में औसतन 25 हजार लोग जाते हैं। देश भर से ही नहीं, बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आते हैं। बेशक, इधर के महीनों में जब जम्मू-कश्मीर में माहौल सुधरा है, तब पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। वैष्णो देवी तीर्थ की वजह से हजारों करोड़ रुपये का व्यवसाय होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा स्थानीय लोगों की जेब में जाता है। देशद्रोही आतंकी यह साजिश कर सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को पहले की तरह मजबूर बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था को कमजोर करें। अब सरकार को युद्ध स्तर पर आश्वस्त करना चाहिए कि सैलानियों, श्रद्धालुओं का आना न कम हो और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाए। यही जवाब दशहतगर्दों को नेस्तनाबूद करेगा।

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले
11 जून, 1949

स्पष्ट चिंतन की आवश्यकता

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भी जब हम यह पाते हैं कि स्वतंत्रता की चाह के साथ की गई हमारी कल्पनाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो हमारे बीच एक बेचैनी पैदा हो रही है। कभी हम सोचने लगते हैं, हमारी स्वतंत्रता अयथार्थ तो नहीं है? किन्हीं कारणों से हमारे साथ न रहे लोग इस स्थिति का लाभ उठा ऐसा प्रचार करने में चूक भी नहीं रहे हैं। यही नहीं, जब आवश्यकता स्वतंत्रता को स्थिर करने में संलग्न होने की है, हमारे ऐसे 'मित्र' उलटा ही काम कर रहे हैं। वे सहयोग द्वारा शक्ति बढ़ाने के बजाय आलोचना, भ्रम-प्रसार और विरोध का मार्ग ग्रहण कर रहे हैं। आश्चर्य और दुःख की सीमा नहीं रहती, जब हम देखते हैं कि कुछ महानुभाव तो स्वदेश में ही नहीं विदेशों तक में जाकर देशवासियों के विरुद्ध प्रचार करने में नहीं झिझक रहे। क्या इसका अर्थ यह लगाया जाये कि देश में सफलता की आशा न देख वे विदेशों की नैतिक अथवा भौतिक सहायता देशवासियों के विरुद्ध प्राप्त करना चाहते हैं?

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नाम पर अपने नेतृत्व का महल खड़ा करने वाले श्री शरतचन्द्र बोस को जब हम विदेशों में जाकर भारतीय नेतृत्व को बदनाम करते देखते हैं तो हमें हैरानी नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने भाई के कारण ही वह स्थायी रूप से भारतीय नेतृत्व में अग्रस्थान नहीं रख सकते और जब उससे वंचित होना पड़ता है तो उनके महत्वाकांक्षी मन के लिए खिजलाहट होना स्वाभाविक है। किन्तु खिजलाहट होने पर भी क्या किसी व्यक्ति को अपना संतुलन खो देना चाहिए? नैतिकता और देशभक्ति की दृष्टि से हम उनके उस प्रचार को बहुत घातक समझते हैं, जो वह विदेशों में भारत के संबंध में कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के शासन को बदनाम करना ही उन्होंने अपना काम बना रक्खा मालूम पड़ता है और ऐसे हल्के इलजाम लगाये जा रहे हैं कि कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से गठबन्धन कर लिया है तथा कांग्रेस के हाथ में शासन आने से ही पक्षपात और भ्रष्टाचार बढ़ गया है। वर्तमान स्थिति की विषमताओं को अनुभव करते हुए भी क्या यह सचाई नहीं है कि ऐसे आरोपों में सद्बुद्धि कम और बदनाम करने की प्रवृत्ति अधिक है? देश ने राष्ट्रमण्डल के साथ रहना मंजूर किया है, इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से गठबन्धन कहना स्थिति को गलत रूप से रखना नहीं तो और क्या है?

नीट जैसी परीक्षा पर उठे नए प्रश्न

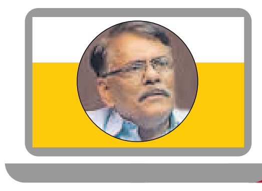

राय की राय
यहां स्कैन करें

विभूति नारायण राय | पूर्व आईपीएस अधिकारी

आखिर ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि बिना पूर्व सूचना के दस दिन पहले ही अचानक मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए? कमियों की पूरी जांच होनी चाहिए।

जब दिन भर पूरा देश अठारहवीं लोकसभा के चुनावी नतीजों में डूब-उतराकर सोने की तैयारी कर ही रहा था, तब 4 जून, 2024 की रात डॉक्टरी की पढ़ाई करने का सपना देखने वाले लाखों छात्रों के लिए किसी दुःस्वप्न की तरह उतरी। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षाओं में से एक नीट या नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) की 5 मई को परीक्षा देने के बाद ये छात्र बड़ी बेसब्री से 14 जून का इंतजार कर रहे थे, जब उनकी मेहनत का परिणाम आने वाला था।

परीक्षा लेने वाली संस्था नेशनल टेस्ट एजेंसी (एनटीए) ने सूचना बुलेटिन में यही तारीख घोषित कर रखी थी। इस परीक्षा की एक खासियत यह है कि परीक्षा समाप्त होने के चंद घंटों में ही छात्रों को अपने प्रदर्शन का आभास हो जाता है। एनटीए ली गई परीक्षा के सही उत्तर ऑनलाइन प्रसारित कर देती है और परीक्षार्थी को कमोबेश अपनी मेरिट का अंदाज लग जाता है। परीक्षा परिणाम से इस मेरिट और उसके आधार पर मिलने वाले मेडिकल कॉलेज की पुष्टि हो सकती है। 4 जून की रात अचानक बच्चों व उनके अभिभावकों के सेलफोन की घंटियां बजने लगीं और किसी विस्फोट की तरह यह सूचना साझा की जाने लगी कि एनटीए ने नीट का परीक्षाफल घोषित कर दिया है। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि एनटीए ने तो अपने बुलेटिन में 14 जून की तारीख घोषित कर रखी थी और हर साल परीक्षा के नतीजे घोषित करने के घंटों पूर्व सूचना प्रसारित की जाती है कि परिणाम आने वाले हैं। फिर इस बार ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि बिना किसी पूर्व सूचना के दस दिन पहले ही अचानक नतीजे घोषित कर दिए गए?

यह तो दूसरे दिन शाम तक स्पष्ट होना शुरू हुआ कि इस परीक्षा में बड़ा घपला हुआ है, जिसका पूरा आकलन करने में विशेषज्ञों की भी अक्ल चकरा जाएगी। क्या यह अनायास था कि परिणाम घोषित करने के लिए ऐसी तारीख चुनी गई, जब पूरे देश का मीडिया चुनावी नतीजों को समझने में व्यस्त था? यह तो भला हो सोशल मीडिया का, जिसने शुरुआती झटके से उबरते ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि हजारों मेधावी छात्रों के साथ घपलेबाजों ने खेल कर दिया गया है। बिना किसी तैयारी के आए अखबारनवीसों के सामने एक प्रेस कांफ्रेंस में एनटीए के महानिदेशक एक पत्रकार के इस प्रश्न पर लड़खड़ा गए कि परीक्षा के परिणाम तय तिथि से इतने पहले क्यों घोषित हो गए?

सारा विवाद सिर्फ सोलह सौ बच्चों से संबंधित है, लेकिन जानकारों के मुताबिक पचास हजार के लगभग अभ्यर्थियों की मेरिट पर इसका असर पड़ेगा। 720 अंकों की इस परीक्षा में पिछले वर्षों तक अधिकतम दो, तीन परीक्षार्थियों को ही पूर्णांक मिलते रहे हैं। इस वर्ष इतने अंक पाने वालों की संख्या 67 हो गई। प्रतिभा के इस विस्फोट का जो कारण एनटीए अधिकारियों ने बताया, उसमें इतने झोल हैं कि आसानी से किसी विशेषज्ञ के गले नहीं उतरेंगे। घपलों की शुरुआत फॉर्म भरने के साथ ही हो गई। फॉर्म भरने की निर्धारित तिथि 9 फरवरी से 9 मार्च थी। बहुत से बच्चों ने अंतिम दिनों में फॉर्म भरने की कोशिश की, पर नीट की वेबसाइट क्रैश हो जाने के कारण कई तरह की दिक्कतें आईं और अभिभावकों की मांग पर फॉर्म भरने की अंतिम तारीख एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई। बाद में बड़े रहस्यमय ढंग से फॉर्म भरने के लिए नीट की वेबसाइट दो दिनों (9 अप्रैल से 10 अप्रैल) के लिए फिर खोली गई। यह जांच का विषय होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में इन दो दिनों में फिर से फॉर्म भरे गए और नए शामिल अभ्यर्थियों में से कितने सफल हुए?

एनटीए द्वारा जारी नीट टॉपरों की मेरिट लिस्ट में आठ छात्रों के क्रमांक एक ही सीरीज (62 से 69) में होने पर भी संदेह व्यक्त किया गया है। इनमें से छह छात्रों ने रैंक 1 प्राप्त की है और ये सभी हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित एक ही परीक्षा केंद्र के हैं। इन आठ में से सात छात्रों के सरनेम लिस्ट में नहीं दिए गए हैं, जिससे संदेह और बढ़ गया है। इन छात्रों के नीट रोल नंबर, नाम, अंक और रैंक का स्नैपशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इन आठ में से छह छात्रों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि अन्य दो ने 719 और 718 अंक प्राप्त किए हैं। यह भी जांच का विषय हो सकता है कि इन छात्रों ने बाद में खोली गई वेबसाइट के जरिये तो प्रवेश नहीं लिया था?

एनटीए ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि हरियाणा के परीक्षा केंद्र पर छात्रों का समय बर्बाद हुआ था, जिसके चलते उन्हें मुआवजे के तौर पर 'ग्रेस मार्क्स' दिए गए थे। इन उदार अंकों का तिलिस्म भी बड़ा रहस्यमय है। शक इससे भी गहराया कि कई राज्यों में परीक्षार्थियों के समय का नुकसान हुआ था और 'ग्रेस मार्क' हरियाणा वाले केंद्र पर ही क्यों दिया गया? फिर फॉर्म भरते समय जारी सूचना पुस्तिका में ग्रेस मार्क का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? यह तो खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने जैसा है।

यह भी उल्लेखनीय है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में परीक्षा शुरू होने के पहले ही पेपर आउट होने की अफवाहें गश्त करने लगी थीं और दोनों प्रांतों में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। कुछ लोगों ने एनटीए को मेल भेजकर आउट हुए परचे की जानकारी भी दी थी।

पिछले कुछ वर्षों से देश के नौनिहालों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के रूप में छल हो रहा है। शायद ही कोई प्रतियोगी परीक्षा ऐसी हुई हो, जिसकी शुचिता को लेकर छात्रों के मन में संदेह न उठा हो। हर बार आरोप लगते ही परीक्षा कराने वाली एजेंसी के अधिकारी सब कुछ ठीक-ठाक होने की दुहाई देने लगते हैं, बाद में अदालत या शासन के स्तर पर उनकी कलई खुलती है और परीक्षा पुनः करानी पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में धन और समय की बर्बादी तो होती ही है, हमारी नई पीढ़ी के मन में देश की संस्थाओं और कानून कायदों से विश्वास भी खत्म होता जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए जरूरत है कि नीट की इस परीक्षा की पूरी जांच कराई जाए और एनटीए के दोषी अधिकारियों को ऐसा दंड दिया जाए, जो भविष्य के लिए सबक बने।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

माली और मालिक की बढ़ती दूरियों के चुनावी मायने

यहां स्कैन करें

मनु जोसेफ | पत्रकार और उपन्यासकार

कुछ दिनों पहले अपनी कॉलोनी में मुझे झगड़े का शोर सुनाई पड़ा। यह बहसबाजी मेरे जैसे मकान में रहने वाले एक शख्स और उसके माली में हो रही थी। वह आदमी अलग से कुछ काम करवाना चाहता था, जिसके एवज में माली कुछ रुपये और मांग रहा था। मालिक प्रवासियों के 'लालच' व 'कामचोरी' की कथित मानसिकता पर बिफरा हुआ था। उसने कहा, 'संभल जाओ। देखा नहीं, केजरीवाल के साथ क्या हुआ है? बहुत चालाकी दिखा रहे थे, अपनी हद नहीं जानते थे।' दरअसल, कुछ घंटे पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।

यह झगड़ा मुझे कुछ असामान्य लग रहा था, क्योंकि संभाव्यता के नियमों के मुताबिक, दोनों के भाजपा वोटर होने की संभावना अधिक थी। यह पूरा घटनाक्रम इस तथ्य का खुलासा भी कर रहा था कि आखिर क्यों इस बार भाजपा को 60 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ है? दरअसल, एक समय था, जब वह मालिक और उसके खिदमतगार, दोनों समान चीजें किया करते थे, मसलन, कांग्रेस पार्टी को वोट देना और एक ही हिंदी फिल्म देखना। फिर ऐसा वक्त आया, जब उनके बच्चे भी समान स्कूलों में पढ़ने लगे। इसके बाद भारत बदला और अलग-अलग वर्ग के लोगों की राहें अलग-अलग हो गईं। मगर जैसे ही भाजपा सत्ता में आई, तमाम वर्गों के लोग फिर समान पार्टी और विचारधारा के लिए वोट करने लगे, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक स्थायी नहीं रहने वाली थी। असल में, राजनेताओं और कुछ रसूखदार लाभार्थियों के अलावा भाजपा का वोटर कौन है? पत्रकारिता, सिनेमा, कारोबार आदि क्षेत्रों का अमूमन उच्च मध्यम वर्ग। कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो उतने नामचीन नहीं, पर उसके हिमायती हैं। वे शहरी उच्च वर्गों से हैं, जो अपने यहां घरेलू सहायक, ड्राइवर, माली आदि रखते हैं। वे भाजपा के शुभंकर जैसे हैं, पर दुर्भाग्य से ये किसी भी पार्टी के सबसे खराब ध्वजवाहक माने जा सकते हैं।

राजनीतिक पर्यवेक्षक कह रहे हैं कि 'अहंकार' ने 'भाजपा' को नुकसान पहुंचाया है। मगर मैं इससे सहमत नहीं। वास्तव में, पिछले कुछ महीनों से भाजपा नेता अपनी घबराहट ही जाहिर कर रहे थे। असल में, जो लोग आत्ममुग्ध और मगरूर थे, वे उनके सहायक थे, ठीक उस शख्स जैसा, जो माली से झगड़ रहा था। लाखों आम मतदाताओं ने, जिन्होंने कभी भाजपा को वोट दिया था, इन्हीं लोगों का दंभ देखा। लोग आमतौर पर उन इंसानों के विचार पसंद नहीं करते, जिनसे वे नफरत करते हैं। यहां यह मत समझिए कि उनको ज्ञान पसंद नहीं, बल्कि वे इसलिए उसे नहीं मानते, क्योंकि ज्ञान बांटने वाला शख्स उन्हें पसंद नहीं। यह भी एक परिघटना है, जिसने भारत में दक्षिणपंथियों का साथ दिया था। मगर जब उच्च वर्ग के रूप में भाजपा को अपना ध्वजवाहक मिला, तब उसके मतदाता-आधार पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा।

जब उच्च वर्ग के रूप में भाजपा को अपना ध्वजवाहक मिला, तब पार्टी के एक मतदाता वर्ग पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा।

समीक्षकों की नजर में महंगाई ने लोकसभा के नतीजों को सबसे अधिक प्रभावित किया, फिर बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी कारगर साबित हुए, लेकिन यह कल्पना करना कठिन है कि भाजपा के मतदाता यह सोचेंगे कि कोई दूसरी पार्टी उनको संपन्न बनाएगी। दरअसल, भारत के लाखों लोगों की नजर में भाजपा 'साहबों' और 'दबंगों' की पार्टी बन गई है। इसीलिए, जब भाजपा ने दागी नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इसे उच्च वर्ग की दबंगई के रूप में देखा गया।

मैं पिछली भाजपा सरकार का इस मामले में मुरीद हूं कि उसे अपने दम पर बहुमत हासिल था। मुझे लगता था कि कोई है, जिसका देश पर नियंत्रण है, यहां तक कि इसके भविष्य पर भी। फिर, पहले किसी राजनेता का जेल जाना भी दुर्लभ था। शायद इसका कारण राजनीतिक शिष्टाचार था, क्योंकि राजनेता जानते थे कि एक दिन वे भी सत्ता में नहीं रहेंगे और सत्तारूढ़ दल ऐसा ही शिष्टाचार दिखाएंगे। मगर वह समय आया, जब लगा, भाजपा को सत्ता गंवाने का डर नहीं है। कई विरोधी नेता जेल भेजे गए। लिहाजा यह स्पष्ट है कि कमजोर होती भाजपा को अब अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कहीं अधिक बैठकें करनी पड़ सकती हैं, अन्य विचारों के प्रति अधिक सहिष्णु नजरिया अपनाना पड़ सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

स्वतंत्र रूप से सोचें

क्या मानव मन विश्वास से मुक्त होने में सक्षम है? इस सवाल का जवाब यही है कि आप तभी इससे मुक्त हो सकते हैं, जब आप विश्वास करने के लिए मजबूर करने वाले कारणों की अंदरूनी सच्चाई को समझ लेते हैं; जब आप न केवल चेतन, बल्कि अचेतन प्रेरकों को भी समझ जाते हैं, जो आपको विश्वास करने के लिए बाध्य करते हैं। आखिरकार हम कोई सतही लोग नहीं हैं, जो बस चेतन स्तर पर कार्य करते हैं। जब आपका चेतन मन शांति से सोच, सुन और देख रहा होता है, तब अचेतन मन कहीं अधिक सक्रिय, सतर्क व ग्रहणशील होता है; अतः उसके पास जवाब हो सकता है।

विश्वास करने के लिए बाध्य किया गया, अधीन किया गया, डराया गया या दबाया गया मन क्या कभी स्वतंत्रतापूर्वक सोच-समझ सकता है? क्या वह आपके व दूसरे के बीच अलगाव की प्रक्रिया को खत्म कर सकता है? कृपया यह न कहें कि विश्वास लोगों को निकट लाता है। वह ऐसा नहीं करता। किसी भी धर्म-संप्रदाय ने ऐसा कभी नहीं किया है। स्वयं अपने देश में, अपने आप पर गौर कीजिए। आप सब विश्वास करने वाले हैं। लेकिन क्या आप सब एक साथ हैं? क्या आप में एकता है? आप जानते हैं कि आप एक नहीं हैं। आप अनेक छोटे-छोटे दलों, छोटी-छोटी जातियों में बंटे हुए हैं और आप असंख्य विभाजनों को जानते हैं। पूर्व हो या पश्चिम, समूचे विश्व में इसकी प्रक्रिया एक जैसी ही है। ईसाई ईसाई को मारता है, मुस्लिम मुस्लिम को मारता है, हिंदू हिंदू को मारता है। छोटी-छोटी बातों के लिए एक-दूसरे की हत्या करता है, लोगों को राहत शिविरों में धकेल देता है। अतः विश्वास लोगों को एक नहीं करता। यह बात बिल्कुल साफ है।

यदि यह स्पष्ट है, यदि यह सत्य है और आप इसे देख पाते हैं, तो इसके बारे में कुछ करना होगा। मगर दिक्कत यह है कि हममें से ज्यादातर इस बात को देखते ही नहीं, क्योंकि हम आंतरिक असुरक्षा का, अपने भीतर मौजूद अकेलेपन का सामना ही नहीं कर पाते। हमें कोई न कोई सहारा चाहिए राज्य, जाति, राष्ट्रीयता, महात्मा, उद्धारक या कुछ और। और जब हम इस सबकी भ्रामकता को देख लेते हैं, तो एक पल के लिए ही सही, हमारा मन इस बात की सच्चाई को देख पाता है, हालांकि जब यह उसकी क्षमता से परे हो जाता है, तब वह पूर्वावस्था में लौट आता है।

विश्वास करने के लिए बाध्य किया गया, अधीन किया गया मन क्या कभी स्वतंत्रतापूर्वक सोच-समझ सकता है? क्या वह आपके व दूसरे में अलगाव की प्रक्रिया को खत्म कर सकता है?

अतः हमारा प्रश्न है : क्या मन का लोप हो सकता है? यही समस्या है। जैसा कि हम जानते हैं, मन के पीछे विश्वास है, लालसा है, सुरक्षित होने की कामना है, ज्ञान है, शक्ति का संचय है। इसकी समस्त शक्ति और श्रेष्ठता के बावजूद अगर आप स्वतंत्र रूप से न सोच पाएं, तो विश्व में शांति नहीं हो सकती।

जे कृष्णमूर्ति

डॉ एस वाई कुरैशी | पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

मैंने हमेशा कहा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि यहां के हिंदू धर्मनिरपेक्ष हैं। भारत का मूल लोकाचार धर्मनिरपेक्ष है। ताजा चुनावों ने इसे निर्णायक रूप से साबित कर दिया है।

अनुलोम-विलोम
सांसद से दुर्व्यवहार

सुरक्षाकर्मियों का यह रवैया स्वीकार्य नहीं

मैं भी किसान हूं, लेकिन किसी भी हिंसा या गैर-विधिक कार्य का समर्थन नहीं करता। जवानों को भावनात्मक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून के मुताबिक अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अगर किसी के गलत बयान से भावना को ठेस पहुंची है या किसी ने कोई अपराध किया है, तो ठेस पहुंचाने वाले या कथित अपराध करने वाले के विरुद्ध कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। सजा या दंड देने का काम न्यायालय का है, हम स्वयं किसी प्रकार का दंड या सजा नहीं दे सकते। अगर ऐसा करते हैं, तो कानून की नजर में हम स्वयं दंड के भागी हैं। फिर यह भी समझिए कि सुरक्षा बलों में तमाम धर्मों, जातियों, विचारधाराओं के लोग होते हैं, मगर उनके लिए वर्दी पहनने का एकमात्र पैमाना होता है, उनका भारतीय होना। ऐसे में, यदि कोई जवान किसी विपरीत विचार वाले लोग पर हमला करता है, तो इससे पूरे समाज में सुरक्षा बलों के प्रति अविश्वास पैदा होगा। सुरक्षाकर्मियों की पहुंच नेताओं के शरीर तक होती है, तो क्या जब कोई दक्षिणपंथी सुरक्षाकर्मी किसी विपरीत विचारधारा के नेता पर हमला करेगा, तब भी उसका यह कहकर बचाव किया जाएगा कि वह कर्मी उस नेता के बयान से नाराज था? बयानों के संदर्भ में नाराजगी का कोई अंत नहीं, इसलिए इस कृत्य को सही नहीं ठहराया जा सकता। इसी तरह के विपरीत विचारों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बलि ली है, लिहाजा सुरक्षा बलों के लिए तय मानदंडों से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

परमेश्वर पिलानिया, टिप्पणीकार,

कई तरीके हैं विरोध के

अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना के विरोध में की जा रही टीका-टिप्पणियों से ऊपर उठने की जरूरत है। हिंसा इतनी हो या उतनी, उसके बीज का आकार एक ही तरह का होता है, जिसके बड़े होने में कोई वक्त नहीं लगता। सीआईएसएफ की सुरक्षाकर्मी एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ने के लिए तैनात नहीं की गई थीं, बल्कि उनका कर्तव्य थप्पड़ जड़ने वालों को रोकना था। उस महिला सुरक्षाकर्मी के पास विरोध दर्ज करने के कई अन्य लोकतांत्रिक रास्ते थे, लेकिन उसने उन रास्तों पर गौर न करके हिंसा का सहारा लिया। ऐसी हिंसा का समर्थन करने वाले स्वयं के भीतर भी एक हिंसात्मक प्रवृत्ति का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि, यह घटना इतनी भी बड़ी नहीं कि उस महिला की तुलना इंदिरा या राजीव गांधी के हत्यारों से की जाए। असामान्य घटना जरूर है, मगर तुलना योग्य नहीं। इस नैरेटिव को छोड़ना ही उचित होगा।

राकेश भट्ट, टिप्पणीकार

नेताओं के बोल भी संयमित होने चाहिए

सीआईएसएफ की महिला जवान ने नई-नई सांसद बनी एक अभिनेत्री को एयरपोर्ट पर थप्पड़ जड़ दिया, जो निंदनीय कृत्य है। वह जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं और उनके साथ ऐसा सुलूक नहीं होना चाहिए था। मगर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं। सवाल है, आखिर महिला सुरक्षाकर्मी ने ऐसा क्यों किया? दरअसल, नेताओं या सेलिब्रिटी को संभलकर बोलना चाहिए। उनकी टिप्पणी ऐसी होनी चाहिए कि किसी के स्वाभिमान को ठेस न लगे। नेताओं को यह समझना चाहिए कि कोई अगर उनका विरोध करता है या सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है, तो वह संविधान से हासिल अधिकारों के तहत ही करता है। बकौल मुंशी प्रेमचंद, 'लोग कहते हैं, आंदोलन, प्रदर्शन, जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं।' अभिनेत्री सांसद ने किसान आंदोलन के दौरान फिजूल टिप्पणी की थी। ऐसी टिप्पणी से स्वाभाविक ही उस महिला सुरक्षाकर्मी के स्वाभिमान को ठेस लगी और उसने प्रतिक्रिया में तमाचा मार दिया। इस घटना का सबक यही है कि नेताओं को सोच-समझकर बोलना चाहिए। हर किसी को गद्दार, देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी आदि बता देना मुनासिब नहीं। वास्तव में, यह थप्पड़ ऐसी मानसिकता के ही खिलाफ है।

हेमा हरि उपाध्याय, टिप्पणीकार

मां का अपमान बर्दाश्त नहीं

सांसद कंगना को थप्पड़ मारने वाली सुरक्षाकर्मी का वीडियो वायरल है, जिसमें वह कह रही है, जब कंगना ने गलत बयान दिया था, मेरी मां वहां (आंदोलन स्थल) पर बैठी थी। कंगना ने कहा था कि आंदोलन में शामिल महिलाएं 100-100 रुपये लेकर धरने में बैठी हैं। उस वक्त किसान तीन काले कानूनों को लौटाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर आंदोलित थे, लेकिन उन पर तमाम गंदे कमेंट किए थे। तब किसानों की आवाज को किसी ने ध्वनि नहीं दी। मनदीप पूनिया जैसे पत्रकार को जेल की यात्रा करनी पड़ी। ये हालात कमोबेश हर आंदोलन के साथ हुए हैं। हर आंदोलन को हेकड़ी, हिकारत और क्रूरता से कुचला गया। आंदोलनकारियों और उनके समर्थन में बोलने वालों को मां-बहन की गालियां मिलीं। आम इंसान की चमड़ी नेताओं व ट्रोल्स की तरह मोटी नहीं होती। एक-एक गाली उसे दिल पर लगती है। उसकी गांठ स्थिर रह जाती है। अब इसका 'पे बैक टाइम' है। लोग पंजा खोलकर इंतजार कर रहे हैं। बेशक, हिंसा और कर्तव्यहीनता से मेरी असहमति है, लेकिन स्वाभिमान और हिम्मत को मेरा सलाम है।

मनीष, टिप्पणीकार

दैनिक जागरण
गलती करने में नहीं, अपितु उसे दोहराने से समस्या बढ़ती है

आतंकियों का दुस्साहस

जम्मू संभाग के रियासी जिले में एक धार्मिक स्थल से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस को आतंकियों ने जिस तरह निशाना बनाया, उससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने इस हमले के लिए खास तौर पर वह दिन चुना, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने जा रहे थे। इस हमले का उद्देश्य केवल निर्दोष-निहत्थे हिंदू श्रद्धालुओं पर कायरतापूर्वक हमला करना ही नहीं, बल्कि कहीं न कहीं मोदी सरकार को चुनौती देने का भी था, लेकिन यदि आतंकी अथवा उनके आका यह सोच रहे हैं कि इस तरह के हमलों से वे मोदी सरकार को झुकाने में समर्थ हो जाएंगे तो यह उनकी भूल ही है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। उलटे इस हमले के बाद तो मोदी सरकार आतंकियों के दुस्साहस का दमन करने के लिए और प्रतिबद्ध ही होगी। उसे ऐसा होना भी चाहिए। उसे केवल आतंकियों के समूल नाश का ही अभियान नहीं चलाना चाहिए, बल्कि उन्हें सहयोग-समर्थन देने वाले तत्वों को भी निशाने पर लेना चाहिए-भले ही वे सीमा के अंदर हों अथवा सीमा पार यानी पाकिस्तान में।

रियासी में आतंकी हमले ने एक बार फिर यह रेखांकित किया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। हैरानी नहीं कि वह इससे बौखलाया हो कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान में भाग लेकर राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने की अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से प्रकट की। पाकिस्तान और उसकी शह पाने वाले आतंकी संगठन इससे भी बौखलाए हो सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने, विभाजनकारी अनुच्छेद-370 को समाप्त करने और पाकिस्तान को कोई भाव न देने वाली मोदी सरकार फिर से सत्ता में आ गई। साफ है कि मोदी सरकार को जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकियों और उनके समर्थकों के साथ सीमा पार से उन्हें सहयोग देने वालों पर भी अपनी नजरें टेढ़ी करनी होंगी। इस क्रम में उसे यह भी देखना होगा कि आखिर क्या कारण है कि कश्मीर के साथ-साथ जम्मू संभाग में भी आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं? आतंकी अब पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को भी निशाना बना रहे हैं। जम्मू के विभिन्न इलाकों में आतंकी एक लंबे समय से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जब उनकी गतिविधियों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता का परिचय देना चाहिए था, तब यह देखा ही जाना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहीं खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों से कोई चूक तो नहीं हुई? अब जब लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि आतंकियों और उन्हें पनाह देने वाले तत्वों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की जाए। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों और उनसे सहानुभूति रखने वालों को सिर उठाने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए।

बालू संकट जारी

झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के क्षेत्रों में बालू संकट का निदान सरकार मानसून की शुरुआत तक नहीं कर पाई और अभी भी आम लोगों को सरकारी व्यवस्था से बालू मिलने का मार्ग प्रशस्त नहीं हुआ है। दूसरी ओर, इस संकट के कारण झारखंड में बिहार से बड़े पैमाने पर बालू का कारोबार शुरू हो गया है और निर्माण उद्योग से जुड़े लोग बढ़ी हुई कीमतों पर बालू खरीदने और बिहार से बालू मंगाने के लिए मजबूर हैं जबकि झारखंड में बालू का स्टाक जस का तस पड़ा रह गया है। कई घाटों पर बालू उत्खनन की व्यवस्था तक नहीं की गई और यह बालू अवैध कारोबारी जैसे-तैसे स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को मैनेज कर उठा रहे हैं और बढ़ी हुई कीमतों पर बेच रहे हैं। सरकार द्वारा बालू घाटों का टेंडर नहीं होने से भी अवैध कारोबार को बल मिल रहा है। 10 जून से अगले 15 अक्टूबर तक एनजीटी की ओर से बालू खनन पर रोक रहता है और यही कारण है कि पूरे में राज्य में बालू संकट बरकरार रहने की संभावना बनी हुई। झारखंड में लगभग चार-पांच वर्षों से बालू संकट चल रहा है और राज्य सरकार इसका निदान निकालने में विफल रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद चम्पाई सोरेन ने इस समस्या के निदान की बात की थी, लेकिन प्रक्रियागत खामियों के कारण बालू मिलने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। बालू घाटों से उत्खनन को लेकर निर्धारित राज्यस्तरीय एजेंसियां और फिर जिलों में बनी समितियों का गठन नहीं होने से समस्या बढ़ती जा रही थी। हालांकि पिछले दिनों सिया का गठन कर लिया गया और अन्य तमाम कमेटियां भी बन चुकी हैं।

> सरकार द्वारा बालू घाटों का टेंडर नहीं होने से भी अवैध कारोबार को बल मिल रहा है। सरकार इसका निदान निकालने में विफल रही है

निरंतरता का संदेश देती नई सरकार

राहुल वर्मा

गठबंधन सरकारों के फैसलों में कुछ विलंब जरूर हो जाता है, लेकिन जब वे होते हैं तो व्यापक सहमति के साथ

जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेन्द्र मोदी ने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। हालांकि पिछली दो बार अपनी पार्टी के पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने के बाद तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार गठबंधन के भरोसे है। इसका असर राजनीतिक परिदृश्य पर भी दिखने लगा है। रविवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण में यह बदलाव दिखा। यह प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद है, जिसमें 72 मंत्री बनाए गए हैं। जबकि इससे पहले 2019 में 56 और 2014 में 48 मंत्रियों ने पहले दिन शपथ ली थी। वर्ष 2014 के आम चुनाव में तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख नारों में से एक नारा यही था कि 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन।' उस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए एक स्वरूप वाले कई मंत्रालयों को एक साथ जोड़ दिया गया। हालांकि नई सरकार में न केवल अपने दल के नेताओं, बल्कि सहयोगियों को साधने के लिए भी उन्हें अधिक मंत्री बनाने पड़े।

चूंकि केंद्र की सरकार में विभिन्न जातीय एवं सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखना पड़ता है और बड़े राज्यों के भिन्न-भिन्न अंचलों को भी प्रतिनिधित्व देने की चुनौती से भी दो-चार होना पड़ता है इसलिए मंत्रिपरिषद का आकार बढ़ जाना बहुत स्वाभाविक है। आरंभ में अनुमान लगाया जा रहा था कि नई सरकार पर गठबंधन के साथियों का बहुत दबाव देखने को मिलेगा, वैसा कुछ उसकी संरचना में अभी तक नजर नहीं आया। यह सही है कि पिछली राजग सरकारों की तुलना में सहयोगी दलों की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन एक सीमित दायरे में। छिटपुट शिकायतें सुनने को जरूर मिलीं, लेकिन याद रहे कि गठबंधन की सरकारें किसी बरात जैसी होती हैं, जहां किसी की कुछ न कुछ शिकायत बनी रहती है, लेकिन बरात अपनी गति से आगे बढ़ती है। जिस प्रकार मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, उससे यही लगता है कि शासन के स्तर पर कोई बड़ा बदलाव आने के बजाय निरंतरता बने रहने के आसार ही अधिक हैं।

पिछले एक सप्ताह में भारतीय राजनीति के रंग बहुत बदल गए हैं। चार जून को एक प्रकार के अनपेक्षित परिणाम सामने आए, क्योंकि व्यापक रूप से यही माना जा रहा था कि भाजपा बहुत सहजता से अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेगी और सहयोगियों की सीटें उसकी शक्ति बढ़ाने का काम करेंगी। जो परिणाम आए उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठा कि मोदी को गठबंधन सरकार का कोई अनुभव नहीं तो वह कैसे ऐसी सरकार चलाएंगे। उनकी छवि सख्त फैसले लेने वाले निर्णायक नेता की है, जो गठबंधन की सरकारों में कठिन हो जाते हैं। गठबंधन सरकार के संचालन को लेकर मोदी की क्षमताओं पर सवाल उठाने वाले शायद यह नहीं जानते कि वाजपेयी सरकार के दौरान मोदी भाजपा के संगठन महासचिव थे और गठबंधन की बारीकियों से भलीभांति परिचित रहे। साथ ही राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने की मोदी की क्षमताओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब भी कई लोगों ने सवाल उठाया था कि वह विदेश नीति जैसे संवेदनशील विषय को कैसे संभालेंगे। ऐसे संदेहवादियों की धारणा को मोदी ने बखूबी खारिज किया। उन्होंने विदेश नीति को नए तेवर दिए। उसे व्यावहारिक, गतिशील बनाकर सक्रियता प्रदान की। कई वैश्विक नेताओं के साथ व्यक्तिगत मेलजोल बढ़ाया।

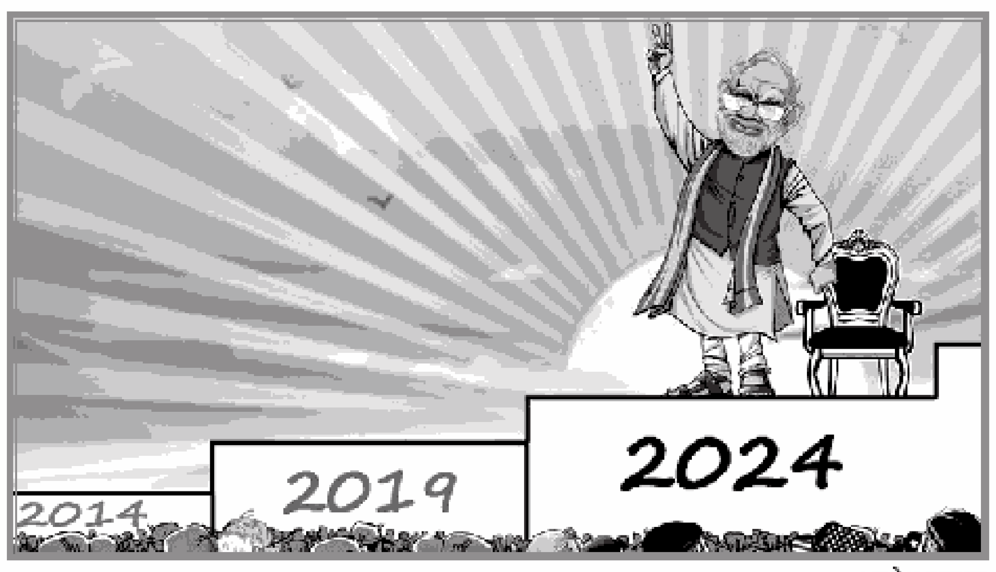

अवधेश राजपूत

एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि अब भाजपा के मूल एजेंडे का क्या होगा? इसका उत्तर तलाशें तो पाएंगे कि राम मंदिर और अनुच्छेद-370 जैसे उसके मूल वैचारिक मुद्दे पहले ही सुलझ चुके हैं। तीन तलाक और नागरिकता कानून के मोर्चे पर भी भाजपा प्रभावी पहल कर चुकी है। अब समान नागरिक संहिता का एक बड़ा मुद्दा बचा है, जिसे लेकर किसी गतिरोध के उत्पन्न होने की आशंका नहीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कभी कोई खाका पेश ही नहीं किया। उसके शासन वाले राज्य ही इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। गठबंधन सरकार में नीतिगत निर्णयों को लेकर भी बहुत नकारात्मक धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। ऐसी सरकारों में फैसलों में कुछ विलंब जरूर हो जाता है, लेकिन जब निर्णय होते हैं तो व्यापक सहमति के साथ। नरसिंह राव की अल्पमत सरकार ने ही ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी तो वाजपेयी की गठबंधन सरकारों में सुधारों का व्यापक सिलसिला जारी रहा।

भाजपा की सीटों की संख्या में आई कमी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की दशा-दिशा को जरूर प्रभावित करेगी। इससे भाजपा की आंतरिक राजनीति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। संघ और भाजपा के बीच समन्वय नए सिरे से तय हो सकता है। साथ ही सहयोगी दलों के साथ समीकरणों को भी सुलझाए रखना होगा। इस प्रकार देखें तो नई व्यवस्था में सत्ता और शक्ति का संतुलन बना रहेगा, जिसकी दिशा काफी हद तक आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से तय होगी। यदि भाजपा का चुनावी प्रदर्शन बेहतर होता है तो प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव पूर्व की भांति बना रहेगा और वह सहयोगी दलों सहित सभी पक्षों को साधने में सफल रहेंगे। अब देखना यही होगा कि मोदी इस जनादेश को एक तात्कालिक झटका मानकर उन वर्गों तक पहुंचने का प्रयास कैसे करते हैं, जिनके चलते उन्हें अपनी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए। यह भी देखना होगा कि विपक्ष खुद को मिली संजीवनी की खुमारी में ही खोया रहता है या फिर खुद को नए सिरे से मजबूत करने के लिए अपने प्रयासों को गति देता है।

यह जनादेश भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और परिपक्वता का एक सशक्त प्रमाण भी सिद्ध हुआ है। जनता ने दिखाया कि कोई भी खुद को अविजित न समझे और वह समय आने पर किसी को भी आईना दिखा सकती है। ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर विपक्षी खेमे के आरोप भी निराधार सिद्ध हुए हैं। हालांकि समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण की छाप राजनीतिक दलों के व्यवहार में भी झलकना एक चिंतित करने वाले पहलू के रूप में उभर रहा है। जब दुनिया भर से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश मिले और वैश्विक नेता उनके शपथ ग्रहण समारोह में आए तो विपक्षी दलों का व्यापक रूप से समारोह का बहिष्कार अखरने वाला रहा।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो और राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

आर्थिक मोर्चे पर बेहतरी की उम्मीद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई राजग सरकार बन गई। गठबंधन के नेताओं ने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विकसित भारत के लिए सरकार को हरसंभव योगदान देने की बात कही है। इससे देश के आर्थिक विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ने के साथ दुनिया में इसकी आर्थिक अहमियत बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। नई सरकार को विरासत में मजबूत अर्थव्यवस्था मिली है। विगत 10 वर्षों से भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्थिर, मजबूत और प्रभावी सरकार के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में सफल रहा है। हाल में दुनिया की प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने मजबूत आर्थिकी, तेज आर्थिक सुधार और राजकोषीय मजबूती के मद्देनजर भारत की रेटिंग को स्थिर यानी स्टेबल से बदलकर पाजिटिव कर दिया है। उसका कहना है कि पिछले तीन साल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत वास्तविक वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत सालाना रही है और अगले तीन साल सात प्रतिशत के करीब रहेगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दुनिया के प्रसिद्ध निवेश बैंक गोल्डमैन साक्स ने भी अपनी नई रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने इसके 6.8 प्रतिशत, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने सात प्रतिशत तथा विश्व बैंक ने 7.5 प्रतिशत रहने के अनुमान व्यक्त किए हैं। भारत में बीते वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.7 प्रतिशत बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपये हो गया। जीएसटी संग्रह 11.7 प्रतिशत बढ़कर 20.18 लाख करोड़ रुपये हो गया। कर संग्रह के ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज उछाल और व्यक्तियों तथा कारपोरेट सेक्टर की आमदनी में वृद्धि को दर्शाते हैं। कुछ और भी ऐसे कारण हैं, जो भारत की अहमियत बढ़ा रहे हैं। इस समय जनसांख्यिकीय लाभांश भारत के पक्ष में है। भारत में दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में छलांग लगाकर आगे बढ़ रहा है। भारत के पास बेहतर स्टार्टअप व्यवस्था और पूंजी बाजार है। दुनिया में साफ्टवेयर के क्षेत्र में भी भारत पहले स्थान पर है। बेहतर इन्फ्रास्ट्राक्चर से लाजिस्टिक लागत घटाकर भारत उद्योग कारोबार के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत अपने 80 करोड़ से अधिक गरीब वर्ग के लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कर रहा है, जिससे उनकी कार्यक्षमता एवं उत्पादकता बढ़ी है। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के कारण भारत को अपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने में सफलता मिली है।

डा. जयंतीलाल भंडारी

> बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पांच लाख करोड़ डालर के पार पहुंचना बड़ी बात है

वैश्विक निवेशकों का भारत पर बढ़ता भरोसा। प्रेट्र

मजबूत आर्थिक विकास से रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में महंगाई भी कई विकसित और विकासशील देशों की तुलना में अपेक्षाकृत नियंत्रण की स्थिति में है। इस समय वैश्विक व्यापार की स्थिति ठीक नहीं है। बावजूद इसके पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से वस्तु एवं सेवाओं का कुल निर्यात रिकार्ड 776.68 अरब डालर रहा। भारत के कच्चे तेल के आयात बिल में 16 प्रतिशत की गिरावट आने के साथ व्यापार घाटे में भी कमी आई। इस समय दुनिया में कृषि निर्यात में भारत का स्थान सातवां है। भारत से करीब 50 हजार डालर से अधिक मूल्य का कृषि निर्यात होता है।

रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को रिकार्ड लाभांश दिए जाने और वैश्विक आर्थिक संगठनों एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत की ऊंची विकास दर के अनुमान का लाभ भारतीय शेयर बाजार को भी मिल रहा है। बांबे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पांच लाख करोड़ डालर के पार पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। भारत इस मुकाम तक पहुंचने वाला दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश बन गया है। कोरोना काल के बाद भारतीय घरेलू खुदरा निवेशकों की रुचि शेयर बाजार में बढ़ी है। पिछले 10 साल में डीमैट अकाउंट 2.3 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ हो गए हैं और म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या एक करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ हो गई है। 2014 में सेंसेक्स 25,000 पर था, वह आज 76,000 अंक से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गया है। वैश्विक निवेशकों का भरोसा भी भारत के शेयर बाजार पर बढ़ा है। यह विदेशी कंपनियों और निवेशकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है कि वे भारत से हुई कमाई को फिर भारत में ही निवेश करें। इससे भारत में कारोबारी माहौल में सुधार होगा। यह सुधार उन घरेलू निवेशकों को भी बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, जो अभी किनारे बैठकर निवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह देश की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के साथ आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को बेहतर करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल से देश को एक बार फिर मजबूत गठबंधन सरकार मिली है। उम्मीद है कि वह एक ऐसी प्रभावी सरकार चलाएंगे, जो देश को चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में और सक्षम बनाएगी। इस सरकार से यह भी आशा है कि वह वैश्विक मंचों पर भारत को उभारते हुए गरीब कल्याण एवं सामाजिक न्याय के ऊंचे प्रतिमानों से आम आदमी की मुस्कुराहट बढ़ाएगी। आठ-नौ प्रतिशत सालाना विकास दर प्राप्त करने के लिए बड़े आर्थिक और कृषि एवं श्रम सुधारों को आगे बढ़ाएगी। अधिक पूंजीगत व्यय कर बुनियादी परियोजनाओं का विकास करेगी। राजकोषीय आदर्श और सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विकास के मूल्यों को अपनाएगी। देश में विकास का जज्बा पैदा करते हुए भारत को 2027 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी।

(लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्य आचरण

मनुष्य को पूजा-पाठ, यज्ञ-अनुष्ठान जीवन को नियमित, व्यवस्थित तथा संयमित करने के लिए करना चाहिए, न कि किसी चमत्कार के लिए। कई लोग यह कहते सुने जाते हैं कि बहुत दिनों से धार्मिक कार्य कर रहे हैं, ताकि भगवान प्रकट हो जाएं और उनसे अपनी समस्या बताकर उसके समाधान का वरदान प्राप्त किया जाए। जबकि ऐसा कुछ नहीं होने पर निराशा होती है और भगवान की सत्ता एवं मान्यता पर अविश्वास होने लगता है।

जप-तप से नकारात्मकता दूर होती है, आत्मबल मजबूत होता है। सच कहा जाए तो आत्मबल ही भगवान है। आत्मबल सत्य-आचरण से ही संभव है। जबकि गलत कामों से भय उत्पन्न होता है। भय व्यक्ति को इतना कमजोर बना देता है कि वह हमेशा संशय तथा उलझन में रहता है। इस स्थिति में दिमाग डांवाडोल हालत में रहता है। फिर कोई काम सुचारु रूप से नहीं हो पाता है। यहां तक कि पूजा-पाठ भी बेमन से होता है। जीवनचर्या बाधित होती है। जिस प्रकार से बादलों से घिरे सूरज से प्रकाश नहीं मिलता, उसी प्रकार दुर्गुणों से घिरे मन से ऊर्जावान विचार नहीं जन्म लेते। जब संकल्प ही कमजोर होगा तब कार्य उसी प्रकार कमजोर होगा जैसे नींव कमजोर होने पर भवन मजबूत नहीं बन सकता। भगवान की पूजा करते समय उन सद्गुणों को अपनाने पर जोर देना चाहिए, जो मनुष्य से देवता बनाने की राह पर ले जाएं।

गहराई से देखें तो दैवीय कृपा निरंतर बरस रही है। उसे महसूस एवं आत्मसात करने की जरूरत है। मनुष्य को जीवन तथा हालात को कोसने के बजाय भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर हमेशा हंसते-मुस्कुराते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि रोते हालत में काम बनने के बजाय और बिगड़ जाएगा। दयनीय स्थिति में लोग साथ देना तो दूर मजाक ही उड़ाते हैं। 'वीर भोग्या वसुंधरा' का आशय ही है कि प्रतिकूलताओं को झेलने में जो दक्ष है, धरती पर उसे हर प्रकार की उपलब्धि हासिल होकर रहती है।

सलिल पांडेय

चुनाव आयोग की सफलता

डा. महेश परिमल

> चुनाव आयोग को दूध का दूध और पानी का पानी करना अच्छी तरह से आता है

देश में लोकसभा चुनाव हो गए। अभी स्थिति यह है कि "न हम हारे न तुम जीते"। इन सबसे हटकर इस बार सबसे अधिक आलोचना चुनाव आयोग की हुई। विपक्ष का आरोप था कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल का पक्ष ले रहा है। इस पर आयोग ने भी जवाब में कहा था कि आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, उसे साबित करो। इस पर आरोप लगाने वाले खामोश हो गए। एक्जिट पोल के आते ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आयोग पर आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 कलेक्टरों को डांट लगाई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बार भी कहा-केवल आरोप न लगाएं, उसे साबित भी करें। जयराम रमेश किसी भी तरह से इसे साबित करने में विफल रहे।

जिस देश में 41 दल हों, वहां चुनाव आयोग की भूमिका खेल के "अंपायर" की तरह नहीं हो सकती। उसे सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करना होता है। हर दल स्वयं को दूध का धुला मानता है, इसका वह प्रदर्शन भी करना चाहता है। सभी दल आरोप लगाने में आगे होते हैं, पर जब बात उनके पक्ष में होती है, तब वे चुप हो जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की मशक्कत को समझने की कोई कोशिश नहीं करता। भीषण गर्मी के बीच चुनावकर्मी सुदूर क्षेत्रों तक ईवीएम लेकर जाते हैं। वहां शांतिपूर्ण चुनाव करवाते हैं, पर आयोग को बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाती। कांग्रेस ने तो इस बार इसमें एड़ी-चोटी का जोर भी लगा दिया। आश्चर्य इस बात का है कि जब आयोग यह कहता है कि कोई भी आकर ईवीएम की जांच कर सकता है, तब कोई सामने नहीं आता। जब विपक्ष हारने लगता है, तब वह एवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर देता है। इस बार एक्जिट पोल की आते ही ईवीएम पर लांछन लगाने का काम शुरू भी हो गया, पर बाद में जीत के आंकड़ों ने इसे ठंडा कर दिया। कांग्रेस के आरोप चमत्कारिक रूप से अदृश्य हो गए।

हमारे देश के चुनाव आयोग की प्रशंसा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन भारत में उसकी आलोचना करना एक फैशन बन गया है। सभी देश चाहते हैं कि उनके यहां भी ऐसे चुनाव हों, जिस पर कोई अंगुली न उठा सके। इसके लिए कई देश भारतीय चुनाव व्यवस्था के संबंध में जानने को उत्सुक हैं। अपने यहां चुनाव होने के पहले वे हमारे चुनाव आयोग से सलाह लेने लगे हैं। आयोग के स्टाफ को विदेश भी बुलाया जा रहा है। इसके बाद भी हमारा चुनाव आयोग सदैव आलोचना का शिकार होता रहा है। उसके काम की कद्र करना देश के नेताओं एवं दलों को सीखना होगा। यही एक ऐसा आयोग है, जिसे दूध का दूध और पानी का पानी करना अच्छी तरह से आता है। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली का हमें सम्मान करना चाहिए। इतने बड़े देश में सुचारु रूप से निर्विघ्न चुनाव करवाने के लिए बधाई देनी चाहिए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

अयोध्या ने फिर चौंकाया

'कसमसाती अयोध्या की बेचैनी' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में आचार्य मिथिलेशनंदिनीशरण ने कहा है कि यदि श्रीराम को अपना राजा मानने वाली अयोध्या की आध्यात्मिकता छिनेगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। मेरा मानना है कि अयोध्या (फैजाबाद लोकसभा सीट) में भाजपा को मिली हार के लिए किसी को बेचैन होने की जरूरत नहीं है। न ही इस पर किसी को राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह। सारे देश में इस बात की चर्चा कम है कि भाजपा को अबकी बार प्रचंड बहुमत क्यों नहीं मिला, लेकिन लगभग हर जुबान पर एक ही बात है कि अयोध्या में भाजपा को हार क्यों मिली? यह इसलिए प्रश्न है, क्योंकि मोदी सरकार के राज में ही लंबे अर्से बाद भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन जरूरी नहीं होता कि मतदाता धार्मिक भावनाओं में बहकर ही अपने कीमती मत का प्रयोग करते हों। यह ठीक है कि अपनी धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल मतदाता रखते होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि भाजपा को अयोध्या में जो हार मिली है उसकी वजह वहां के मतदाताओं की राम मंदिर निर्माण से जुड़ी नाराजगी हो। हो सकता है कि केंद्र या राज्य सरकार के किसी काम के प्रति वहां के मतदाताओं में कोई नाराजगी हो या फिर भाजपा के प्रत्याशी को लेकर उनमें कोई नाराजगी हो। एक चीज और। भगवान श्रीराम सिर्फ भाजपा के ही नहीं, हम सबके हैं, इसलिए भी भाजपा की अयोध्या में हार का संबंध श्रीराम मंदिर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। किसी को भी कोई ऐसी टिप्पणी या बात नहीं करनी चाहिए, जो अयोध्या के मतदाताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

भारी पड़ी अफवाह

'अपनी गलतियों से भी मात खाई भाजपा ने' शीर्षक से लिखे आलेख में संजय गुप्त ने क्रमबद्ध तरीके से भाजपा की गलतियां गिनाई हैं, जो गौर करने लायक है। मोदी नाम के सहारे भाजपा नेताओं में शिथिलता आ गई। विपक्ष खार खाए बैठा ही था। लगातार दुष्प्रचार में लगा था। लेकिन उसका यथोचित जवाब नहीं दिया गया। नतीजा हुआ संविधान और आरक्षण पर चोट की अफवाह ने मोदी की नेकनीयती और कार्य को बदनामी में बदल दिए। दलित और पिछड़े मतदाता भारी तादाद में छिटक गए। इसका भान प्रदेश नेतृत्व को नहीं हुआ या कुछ उपाय नहीं किए गए। प्रत्याशी चयन में कार्यकर्ताओं की घोर उपेक्षा हुई। दल बदलू को भारी संख्या में टिकट दिए गए। भाजपा औरों से अलग है, की छवि जाती रही। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और विकसित भारत के लक्ष्य से गरीब को क्या लाभ होगा? इसे समझाने में भाजपा नेतृत्व नाकाम रहा। उम्मीदवारों के चयन में जातीय समीकरण का ध्यान ना रखना, सबसे बड़ी भूल थी। विपक्ष जातीय गणना और आरक्षण का राग अलाप रहा था। जब कोई राष्ट्रीय मुद्दा केंद्र में नहीं रहता है। तब जातीय समीकरण का ध्यान रखना जरूरी है।

मुकेश कुमार मनन, पटना

परीक्षार्थियों के साथ न हो धोखा

इस बार की अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा अर्थात नीट में गड़बड़ी की आकांक्षा जताई जा रही है। अगर इसमें धांधली है तो यह मेहनतकश परीक्षार्थियों के साथ धोखा है, और गलत तरीके से अगर कोई डाक्टर बन भी जाता है तो क्या वह मरीजों की जान के लिए खतरा नहीं बनेगा? जब किसी की मेहनत पर पानी फिरता है, तब उसका कितना दर्द होता है, उसका अंदाजा वही लगा सकता है, जिसने जिंदगी में कभी मेहनत की होती है। कभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर, कभी उनमें धांधली, कभी शिक्षा बोर्ड के प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं। क्या प्रश्नपत्रों को लीक करने वालों को कानून का जरा भी डर नहीं है? या फिर परीक्षाओं का संचालन या इन परीक्षाओं का आयोजन करने वाला प्रशासन लापरवाह है? या फिर प्रशासन के कुछ भ्रष्ट लोगों की मिलीभगत से मेहनतकश युवावर्ग के भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा? इसकी जांच होनी चाहिए।

raju09023693142@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

संपादकीय जागरण

(10) मंगलवार, 11 जून, 2024 : ज्येष्ठ शुक्ल – 5 वि. 2081

गलती करने में नहीं, अपितु उसे दोहराने से समस्या बढ़ती है

आतंकियों का दुस्साहस

जम्मू संभाग के रियासी जिले में एक धार्मिक स्थल से लौट रही श्रद्धालुओं से भरी बस को आतंकियों ने जिस तरह निशाना बनाया, उससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने इस हमले के लिए खास तौर पर वह दिन चुना, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ लेने जा रहे थे। इस हमले का उद्देश्य केवल निर्दोष-निहत्थे हिंदू श्रद्धालुओं पर कायरतापूर्वक हमला करना ही नहीं, बल्कि कहीं न कहीं मोदी सरकार को चुनौती देने का भी था, लेकिन यदि आतंकी अथवा उनके आका यह सोच रहे हैं कि इस तरह के हमलों से वे मोदी सरकार को झुकाने में समर्थ हो जाएंगे तो यह उनकी भूल ही है। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। उलटे इस हमले के बाद तो मोदी सरकार आतंकियों के दुस्साहस का दमन करने के लिए और प्रतिबद्ध ही होगी। उसे ऐसा होना भी चाहिए। उसे केवल आतंकियों के समूल नाश का ही अभियान नहीं चलाना चाहिए, बल्कि उन्हें सहयोग-समर्थन देने वाले तत्वों को भी निशाने पर लेना चाहिए-भले ही वे सीमा के अंदर हों अथवा सीमा पार यानी पाकिस्तान में। रियासी में आतंकी हमले ने एक बार फिर यह रेखांकित किया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। हैरानी नहीं कि वह इससे बौखलाया हो कि हाल में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान में भाग लेकर राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने की अपनी इच्छा स्पष्ट रूप से प्रकट की। पाकिस्तान और उसकी शह पाने वाले आतंकी संगठन इससे भी बौखलाए हो सकते हैं कि जम्मू-कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने, विभाजनकारी अनुच्छेद-370 को समाप्त करने और पाकिस्तान को कोई भाव न देने वाली मोदी सरकार फिर से सत्ता में आ गई। साफ है कि मोदी सरकार को जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकियों और उनके समर्थकों के साथ सीमा पार से उन्हें सहयोग देने वालों पर भी अपनी नजरें टेढ़ी करनी होंगी। इस क्रम में उसे यह भी देखना होगा कि आखिर क्या कारण है कि कश्मीर के साथ-साथ जम्मू संभाग में भी आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं? आतंकी अब पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को भी निशाना बना रहे हैं। जम्मू के विभिन्न इलाकों में आतंकी एक लंबे समय से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जब उनकी गतिविधियों को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता का परिचय देना चाहिए था, तब यह देखा ही जाना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? कहीं खुफिया एवं सुरक्षा एजेंसियों से कोई चूक तो नहीं हुई? अब जब लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि आतंकियों और उन्हें पनाह देने वाले तत्वों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की जाए। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों और उनसे सहानुभूति रखने वालों को सिर उठाने का कोई मौका नहीं दिया जाना चाहिए।

कड़ी से कड़ी सजा मिले

राज्य में बालू के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। किंतु, समय-समय पर होने वाली घटनाओं से ऐसा लगता है कि धंधेबाजों को कानून का कोई डर नहीं रह गया है। ऐसी ही एक घटना बीते रविवार की सुबह हुई। औरंगाबाद जिले में सोन नदी से अवैध बालू लेकर आ रहे ट्रैक्टर को खनन विभाग के सिपाही ने रोकने की कोशिश की तो चालक ने उन्हें कुचल कर मार डाला। पुलिस ने ट्रैक्टर के चालक तथा मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा नहीं है कि इन घटनाओं में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। अभियान चलाकर कार्रवाई भी की जाती है, किंतु इन धंधेबाजों के हौसले पस्त नहीं हो रहे। इसके अलावा भी पुलिस पर वारंटी को पकड़ने के दौरान या शराब के अड्डों पर छापेमारी के दौरान हमले की घटनाओं में खासी वृद्धि हुई है। इन घटनाओं के आरोपितों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। दरअसल, कानूनी दांव-पेच के कारण कुछ दिनों के बाद आरोपित छूट जाते हैं या फिर पीड़ित पुलिसकर्मी द्वारा थक-हार कर मुकदमे की पैरवी छोड़ देने के कारण वे बरी हो जाते हैं। इससे दूसरे ऐसे माफिया या धंधेबाज मनबढ़ हो जाते हैं। विभागीय समन्वय का नहीं होना भी आरोपितों के छूट जाने का कारण बनता है। जरूरी है कि इन मुकदमों की पैरवी सरकार द्वारा गंभीरता से की जाए तथा संबंधित विभागों का दायित्व बनता है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी आवश्यक कागजात या संसाधन समय पर उपलब्ध कराए जाएं। पुलिसकर्मियों पर हमलों के मामलों की माहवार मानीटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द आरोपितों को सजा मिल सके।

> पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाएं चिंताजनक हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में हर स्तर पर गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को और सक्षम एवं जवाबदेह बनाया जाना आवश्यक हो गया है?

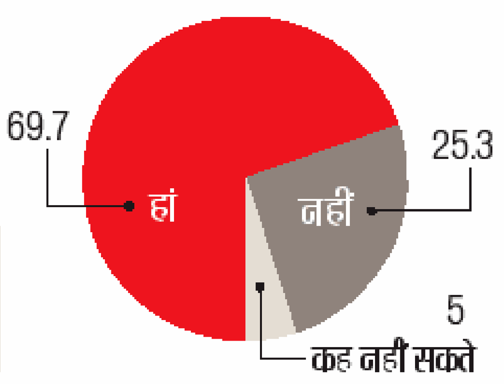

आज का सवाल

क्या रियासी में हुआ आतंकी हमला जम्मू संभाग में आतंकी तत्वों के बेलगाम होने का संकेत है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

निरंतरता का संदेश देती नई सरकार

राहुल वर्मा

गठबंधन सरकारों के फैसलों में कुछ विलंब जरूर हो जाता है, लेकिन जब वे होते हैं तो व्यापक सहमति के साथ

जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर नरेन्द्र मोदी ने भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। हालांकि पिछली दो बार अपनी पार्टी के पूर्ण बहुमत से सरकार चलाने के बाद तीसरे कार्यकाल में उनकी सरकार गठबंधन के भरोसे है। इसका असर राजनीतिक परिदृश्य पर भी दिखने लगा है। रविवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण में यह बदलाव दिखा। यह प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद है, जिसमें 72 मंत्री बनाए गए हैं। जबकि इससे पहले 2019 में 56 और 2014 में 48 मंत्रियों ने पहले दिन शपथ ली थी। वर्ष 2014 के आम चुनाव में तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख नारों में से एक नारा यही था कि 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन।' उस संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए एक स्वरूप वाले कई मंत्रालयों को एक साथ जोड़ दिया गया। हालांकि नई सरकार में न केवल अपने दल के नेताओं, बल्कि सहयोगियों को साधने के लिए भी उन्हें अधिक मंत्री बनाने पड़े।

चूंकि केंद्र की सरकार में विभिन्न जातीय एवं सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखना पड़ता है और बड़े राज्यों के भिन्न-भिन्न अंचलों को भी प्रतिनिधित्व देने की चुनौती से भी दो-चार होना पड़ता है इसलिए मंत्रिपरिषद का आकार बढ़ जाना बहुत स्वाभाविक है। आरंभ में अनुमान लगाया जा रहा था कि नई सरकार पर गठबंधन के साथियों का बहुत दबाव देखने को मिलेगा, वैसा कुछ उसकी संरचना में अभी तक नजर नहीं आया। यह सही है कि पिछली राजग सरकारों की तुलना में सहयोगी दलों की संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन एक सीमित दायरे में। छिटपुट शिकायतें सुनने को जरूर मिलीं, लेकिन याद रहे कि गठबंधन की सरकारें किसी बरात जैसी होती हैं, जहां किसी की कुछ न कुछ शिकायत बनी रहती है, लेकिन बरात अपनी गति से आगे बढ़ती है। जिस प्रकार मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, उससे यही लगता है कि शासन के स्तर पर कोई बड़ा बदलाव आने के बजाय निरंतरता बने रहने के आसार ही अधिक हैं।

पिछले एक सप्ताह में भारतीय राजनीति के रंग बहुत बदल गए हैं। चार जून को एक प्रकार के अनपेक्षित परिणाम सामने आए, क्योंकि व्यापक रूप से यही माना जा रहा था कि भाजपा बहुत सहजता से अपने दम पर बहुमत हासिल कर लेगी और सहयोगियों की सीटें उसकी शक्ति बढ़ाने का काम करेंगी। जो परिणाम आए उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठा कि मोदी को गठबंधन सरकार का कोई अनुभव नहीं तो वह कैसे ऐसी सरकार चलाएंगे। उनकी छवि सख्त फैसले लेने वाले निर्णायक नेता की है, जो गठबंधन की सरकारों में कठिन हो जाते हैं। गठबंधन सरकार के संचालन को लेकर मोदी की क्षमताओं पर सवाल उठाने वाले शायद यह नहीं जानते कि वाजपेयी सरकार के दौरान मोदी भाजपा के संगठन महासचिव थे और गठबंधन की बारीकियों से भलीभांति परिचित रहे। साथ ही राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने की मोदी की क्षमताओं पर संदेह नहीं करना चाहिए। जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब भी कई लोगों ने सवाल उठाया था कि वह विदेश नीति जैसे संवेदनशील विषय को कैसे संभालेंगे। ऐसे संदेहवादियों की धारणा को मोदी ने बखूबी खारिज किया। उन्होंने विदेश नीति को नए तेवर दिए। उसे व्यावहारिक, गतिशील बनाकर सक्रियता प्रदान की। कई वैश्विक नेताओं के साथ व्यक्तिगत मेलजोल बढ़ाया।

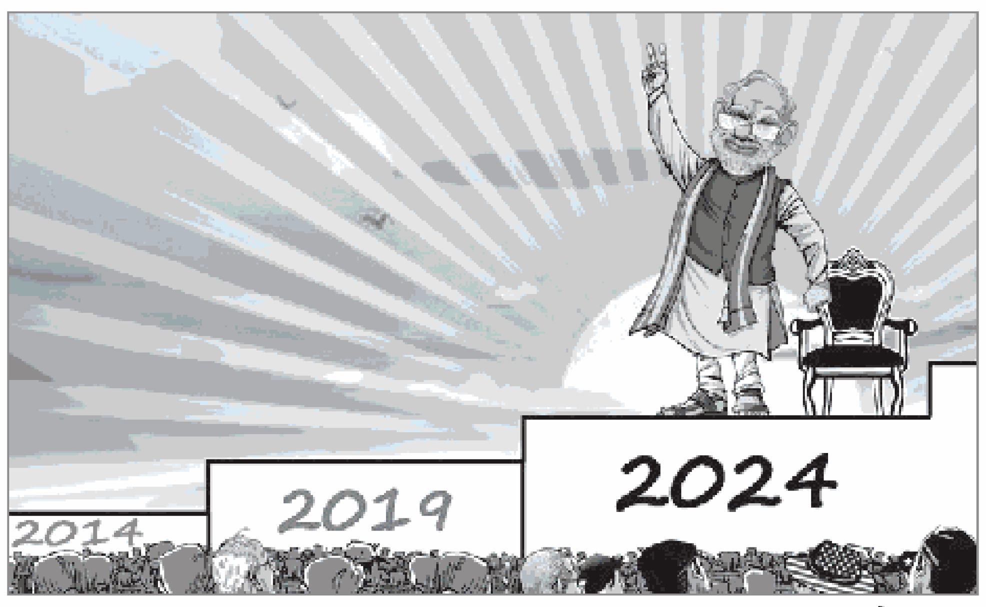

अवधेश राजपूत

एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि अब भाजपा के मूल एजेंडे का क्या होगा? इसका उत्तर तलाशें तो पाएंगे कि राम मंदिर और अनुच्छेद-370 जैसे उसके मूल वैचारिक मुद्दे पहले ही सुलझ चुके हैं। तीन तलाक और नागरिकता कानून के मोर्चे पर भी भाजपा प्रभावी पहल कर चुकी है। अब समान नागरिक संहिता का एक बड़ा मुद्दा बचा है, जिसे लेकर किसी गतिरोध के उत्पन्न होने की आशंका नहीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कभी कोई खाका पेश ही नहीं किया। उसके शासन वाले राज्य ही इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। गठबंधन सरकार में नीतिगत निर्णयों को लेकर भी बहुत नकारात्मक धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। ऐसी सरकारों में फैसलों में कुछ विलंब जरूर हो जाता है, लेकिन जब निर्णय होते हैं तो व्यापक सहमति के साथ। नरसिंह राव की अल्पमत सरकार ने ही ऐतिहासिक आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी तो वाजपेयी की गठबंधन सरकारों में सुधारों का व्यापक सिलसिला जारी रहा।

भाजपा की सीटों की संख्या में आई कमी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की दशा-दिशा को जरूर प्रभावित करेगी। इससे भाजपा की आंतरिक राजनीति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। संघ और भाजपा के बीच समन्वय नए सिरे से तय हो सकता है। साथ ही सहयोगी दलों के साथ समीकरणों को भी सुलझाए रखना होगा। इस प्रकार देखें तो नई व्यवस्था में सत्ता और शक्ति का संतुलन बना रहेगा, जिसकी दिशा काफी हद तक आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रदर्शन से तय होगी। यदि भाजपा का चुनावी प्रदर्शन बेहतर होता है तो प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव पूर्व की भांति बना रहेगा और वह सहयोगी दलों सहित सभी पक्षों को साधने में सफल रहेंगे। अब देखना यही होगा कि मोदी इस जनादेश को एक तात्कालिक झटका मानकर उन वर्गों तक पहुंचने का प्रयास कैसे करते हैं, जिनके चलते उन्हें अपनी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं हुए। यह भी देखना होगा कि विपक्ष खुद को मिली संजीवनी की खुमारी में ही खोया रहता है या फिर खुद को नए सिरे से मजबूत करने के लिए अपने प्रयासों को गति देता है।

यह जनादेश भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और परिपक्वता का एक सशक्त प्रमाण भी सिद्ध हुआ है। जनता ने दिखाया कि कोई भी खुद को अविजित न समझे और वह समय आने पर किसी को भी आईना दिखा सकती है। ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर विपक्षी खेमे के आरोप भी निराधार सिद्ध हुए हैं। हालांकि समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण की छाप राजनीतिक दलों के व्यवहार में भी झलकना एक चिंतित करने वाले पहलू के रूप में उभर रहा है। जब दुनिया भर से प्रधानमंत्री मोदी को बधाई संदेश मिले और वैश्विक नेता उनके शपथ ग्रहण समारोह में आए तो विपक्षी दलों का व्यापक रूप से समारोह का बहिष्कार अखरने वाला रहा।

(लेखक सेंटर फार पालिसी रिसर्च में फेलो और राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

आर्थिक मोर्चे पर बेहतरी की उम्मीद

डा. जयंतीलाल भंडारी

> बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पांच लाख करोड़ डालर के पार पहुंचना बड़ी बात है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई राजग सरकार बन गई। गठबंधन के नेताओं ने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और विकसित भारत के लिए सरकार को हरसंभव योगदान देने की बात कही है। इससे देश के आर्थिक विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ने के साथ दुनिया में इसकी आर्थिक अहमियत बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। नई सरकार को विरासत में मजबूत अर्थव्यवस्था मिली है। विगत 10 वर्षों से भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में स्थिर, मजबूत और प्रभावी सरकार के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में सफल रहा है। हाल में दुनिया की प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने मजबूत आर्थिकी, तेज आर्थिक सुधार और राजकोषीय मजबूती के मद्देनजर भारत की रेटिंग को स्थिर यानी स्टेबल से बदलकर पाजिटिव कर दिया है। उसका कहना है कि पिछले तीन साल में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत वास्तविक वृद्धि दर 8.1 प्रतिशत सालाना रही है और अगले तीन साल सात प्रतिशत के करीब रहेगी।

दुनिया के प्रसिद्ध निवेश बैंक गोल्डमैन साक्स ने भी अपनी नई रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.7 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने इसके 6.8 प्रतिशत, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने सात प्रतिशत तथा विश्व बैंक ने 7.5 प्रतिशत रहने के अनुमान व्यक्त किए हैं। भारत में बीते वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.7 प्रतिशत बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपये हो गया। जीएसटी संग्रह 11.7 प्रतिशत बढ़कर 20.18 लाख करोड़ रुपये हो गया। कर संग्रह के ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज उछाल और व्यक्तियों तथा कारपोरेट सेक्टर की आमदनी में वृद्धि को दर्शाते हैं। कुछ और भी ऐसे कारण हैं, जो भारत की अहमियत बढ़ा रहे हैं। इस समय जनसांख्यिकीय लाभांश भारत के पक्ष में है। भारत में दुनिया की सबसे अधिक युवा आबादी है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में छलांग लगाकर आगे बढ़ रहा है। भारत के पास बेहतर स्टार्टअप व्यवस्था और पूंजी बाजार है। दुनिया में साफ्टवेयर के क्षेत्र में भी भारत पहले स्थान पर है। बेहतर इन्फ्रास्ट्राक्चर से लाजिस्टिक लागत घटाकर भारत उद्योग कारोबार के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत अपने 80 करोड़ से अधिक गरीब वर्ग के लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कर रहा है, जिससे उनकी कार्यक्षमता एवं उत्पादकता बढ़ी है। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के कारण भारत को अपने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने में सफलता मिली है।

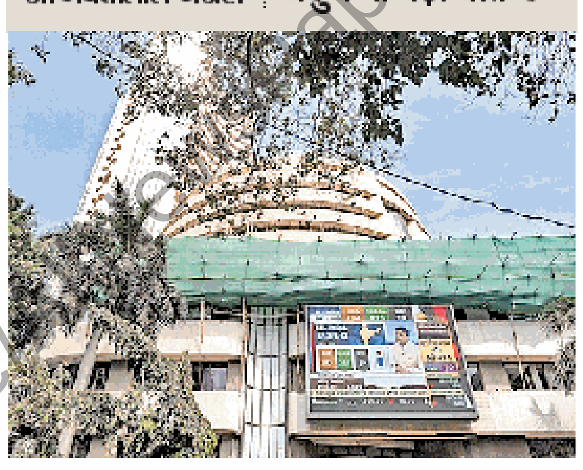

वैश्विक निवेशकों का भारत पर बढ़ता भरोसा ● प्रेट्र

मजबूत आर्थिक विकास से रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में महंगाई भी कई विकसित और विकासशील देशों की तुलना में अपेक्षाकृत नियंत्रण की स्थिति में है। इस समय वैश्विक व्यापार की स्थिति ठीक नहीं है। बावजूद इसके पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारत से वस्तु एवं सेवाओं का कुल निर्यात रिकार्ड 776.68 अरब डालर रहा। भारत के कच्चे तेल के आयात बिल में 16 प्रतिशत की गिरावट आने के साथ व्यापार घाटे में भी कमी आई। इस समय दुनिया में कृषि निर्यात में भारत का स्थान सातवां है। भारत से करीब 50 हजार डालर से अधिक मूल्य का कृषि निर्यात होता है।

रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को रिकार्ड लाभांश दिए जाने और वैश्विक आर्थिक संगठनों एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत की ऊंची विकास दर के अनुमान का लाभ भारतीय शेयर बाजार को भी मिल रहा है। बांबे स्टाक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण पांच लाख करोड़ डालर के पार पहुंचना कोई छोटी बात नहीं है। भारत इस मुकाम तक पहुंचने वाला दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश बन गया है। कोरोना काल के बाद भारतीय घरेलू खुदरा निवेशकों की रुचि शेयर बाजार में बढ़ी है। पिछले 10 साल में डीमैट अकाउंट 2.3 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ हो गए हैं और म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या एक करोड़ से बढ़कर 4.5 करोड़ हो गई है। 2014 में सेंसेक्स 25,000 पर था, वह आज 76,000 अंक से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गया है। वैश्विक निवेशकों का भरोसा भी भारत के शेयर बाजार पर बढ़ा है। यह विदेशी कंपनियों और निवेशकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है कि वे भारत से हुई कमाई को फिर भारत में ही निवेश करें। इससे भारत में कारोबारी माहौल में सुधार होगा। यह सुधार उन घरेलू निवेशकों को भी बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा, जो अभी किनारे बैठकर निवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह देश की उत्पादक क्षमता बढ़ाने के साथ आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं को बेहतर करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल से देश को एक बार फिर मजबूत गठबंधन सरकार मिली है। उम्मीद है कि वह एक ऐसी प्रभावी सरकार चलाएंगे, जो देश को चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में और सक्षम बनाएगी। इस सरकार से यह भी आशा है कि वह वैश्विक मंचों पर भारत को उभारते हुए गरीब कल्याण एवं सामाजिक न्याय के ऊंचे प्रतिमानों से आम आदमी की मुस्कुराहट बढ़ाएगी। आठ-नौ प्रतिशत सालाना विकास दर प्राप्त करने के लिए बड़े आर्थिक और कृषि एवं श्रम सुधारों को आगे बढ़ाएगी। अधिक पूंजीगत व्यय कर बुनियादी परियोजनाओं का विकास करेगी। राजकोषीय आदर्श और सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय विकास के मूल्यों को अपनाएगी। देश में विकास का जज्बा पैदा करते हुए भारत को 2027 में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तथा वर्ष 2047 तक विकसित देश बनाने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी।

(लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्य आचरण

मनुष्य को पूजा-पाठ, यज्ञ-अनुष्ठान जीवन को नियमित, व्यवस्थित तथा संयमित करने के लिए करना चाहिए, न कि किसी चमत्कार के लिए। कई लोग यह कहते सुने जाते हैं कि बहुत दिनों से धार्मिक कार्य कर रहे हैं, ताकि भगवान प्रकट हो जाएं और उनसे अपनी समस्या बताकर उसके समाधान का वरदान प्राप्त किया जाए। जबकि ऐसा कुछ नहीं होने पर निराशा होती है और भगवान की सत्ता एवं मान्यता पर अविश्वास होने लगता है।

जप-तप से नकारात्मकता दूर होती है, आत्मबल मजबूत होता है। सच कहा जाए तो आत्मबल ही भगवान है। आत्मबल सत्य-आचरण से ही संभव है। जबकि गलत कामों से भय उत्पन्न होता है। भय व्यक्ति को इतना कमजोर बना देता है कि वह हमेशा संशय तथा उलझन में रहता है। इस स्थिति में दिमाग डांवाडोल हालत में रहता है। फिर कोई काम सुचारु रूप से नहीं हो पाता है। यहां तक कि पूजा-पाठ भी बेमन से होता है। जीवनचर्या बाधित होती है। जिस प्रकार से बादलों से घिरे सूरज से प्रकाश नहीं मिलता, उसी प्रकार दुर्गुणों से घिरे मन से ऊर्जावान विचार नहीं जन्म लेते। जब संकल्प ही कमजोर होगा तब कार्य उसी प्रकार कमजोर होगा जैसे नींव कमजोर होने पर भवन मजबूत नहीं बन सकता। भगवान की पूजा करते समय उन सद्गुणों को अपनाने पर जोर देना चाहिए, जो मनुष्य से देवता बनाने की राह पर ले जाएं।

गहराई से देखें तो दैवीय कृपा निरंतर बरस रही है। उसे महसूस एवं आत्मसात करने की जरूरत है। मनुष्य को जीवन तथा हालात को कोसने के बजाय भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर हमेशा हंसते-मुस्कुराते हुए समय व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि रोते हालत में काम बनने के बजाय और बिगड़ जाएगा। दयनीय स्थिति में लोग साथ देना तो दूर मजाक ही उड़ाते हैं। 'वीर भोग्या वसुंधरा' का आशय ही है कि प्रतिकूलताओं को झेलने में जो दक्ष है, धरती पर उसे हर प्रकार की उपलब्धि हासिल होकर रहती है।

सलिल पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

अयोध्या ने फिर चौंकाया

'कसमसाती अयोध्या की बेचैनी' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में आचार्य मिथिलेशनंदिनीशरण ने कहा है कि यदि श्रीराम को अपना राजा मानने वाली अयोध्या की आध्यात्मिकता छिनेगी तो उसकी प्रतिक्रिया होगी। मेरा मानना है कि अयोध्या (फैजाबाद लोकसभा सीट) में भाजपा को मिली हार के लिए किसी को बेचैन होने की जरूरत नहीं है। न ही इस पर किसी को राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि धर्म अपनी जगह है और राजनीति अपनी जगह। सारे देश में इस बात की चर्चा कम है कि भाजपा को अबकी बार प्रचंड बहुमत क्यों नहीं मिला, लेकिन लगभग हर जुबान पर एक ही बात है कि अयोध्या में भाजपा को हार क्यों मिली? यह इसलिए प्रश्न है, क्योंकि मोदी सरकार के राज में ही लंबे अर्से बाद भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन जरूरी नहीं होता कि मतदाता धार्मिक भावनाओं में बहकर ही अपने कीमती मत का प्रयोग करते हों। यह ठीक है कि अपनी धार्मिक भावनाओं का भी ख्याल मतदाता रखते होंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि भाजपा को अयोध्या में जो हार मिली है उसकी वजह वहां के मतदाताओं की राम मंदिर निर्माण से जुड़ी नाराजगी हो। हो सकता है कि केंद्र या राज्य सरकार के किसी काम के प्रति वहां के मतदाताओं में कोई नाराजगी हो या फिर भाजपा के प्रत्याशी को लेकर उनमें कोई नाराजगी हो। एक चीज और। भगवान श्रीराम सिर्फ भाजपा के ही नहीं, हम सबके हैं, इसलिए भी भाजपा की अयोध्या में हार का संबंध श्रीराम मंदिर से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। किसी को भी कोई ऐसी टिप्पणी या बात नहीं करनी चाहिए, जो अयोध्या के मतदाताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

अयोध्या अपराजेय

'कसमसाती अयोध्या की बैचेनी' शीर्षक आलेख में आचार्य मिथिलेशनंदिनी शरण ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उचित लिखा है कि अयोध्या को कोई हरा नहीं सकता है, यह अपराजेय है। अयोध्या पर विजय प्राप्त करना कोरी कल्पना है। चुनाव से पूर्व और अब देश में जिस संसदीय क्षेत्र का लोगों ने सर्वाधिक नाम लिया और चर्चाएं कीं, वह फैजाबाद (अयोध्या) संसदीय क्षेत्र है। अयोध्या ने अपने विजय का बिगुल उस दिन फूंक दिया, जिस दिन प्रभु श्रीराम के मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। श्रीराम मंदिर का निर्माण करा भाजपा ने जितनी खुशियां देश के लोगों को दीं, शायद ही देश के इतिहास में ऐसा अवसर कभी आया हो। चुनाव में पांच वर्ष के लिए यह संसदीय सीट विपक्ष के खाते में जाने पर भाजपा की खिंचाई हो रही है, जो उचित नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है। इसे धार्मिक मामलों से जोड़ना अव्यवहारिक है। इस संसदीय क्षेत्र का कायाकल्प जिस गति से हुआ और हो रहा है, ऐसा कभी किसी ने पूर्व में देखा नहीं होगा। अयोध्या सबकी है। यहां न जात है और न पात है। जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि अयोध्या में भाजपा जानबूझ कर हारी है। श्रीराम ने माता शबरी के बेर खाए थे। केवट को गले लगाया था। इस भाजपा ने अनुसूचित जाति के बुजुर्ग प्रत्याशी को जीतने दिया।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

32 वर्षों से पेंशन में संशोधन नहीं

गत 32 वर्षों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पेंशनर्स अपनी पेंशन में संशोधन नहीं होने के कारण परेशान हैं। 2002 से पूर्व सेवानिवृत्त सीजीएम की मूल पेंशन, इस समय के सेवानिवृत्त क्लर्क से भी कम है। यह असमानता तब है, जबकि इसके लिए राशि की व्यवस्था सरकार या बैंक को नही करनी होती है। बैंक कर्मी की सेवा के दौरान ही उसके लिए स्थगित भुगतान द्वारा फंड का निर्माण होता रहता है। पेंशन रेगुलेशन एक्ट 1995 के सेक्शन 35(1) में मूल पेंशन में संशोधन होते रहने की बात का उल्लेख है। इसके सेक्शन 56 में यह भी व्यवस्था है कि अन्य केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही उनके वेतन में वृद्धि होने पर पेंशन भी तदनुसार संशोधित होती रहेगी। 29 अक्टूबर 1993 को हुए एक समझौते के खंड 06 एवं 12 के अनुसार रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंकों की पेंशन स्कीम में एकरूपता रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में एक जुलाई 2015 को व्यवस्था दी है कि पेंशन की राशि संबंधित पद के वर्तमान वेतन से आधी से कम नहीं होनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक कर्मचारियों के कार्य के प्रति समर्पण की भावना का सम्मान करते हुए आइबीए के चेयरमैन एवं स्टेट बैंक के चेयरमैन को नवंबर 2020 में निर्देश दिया था कि बैंकों में भी 'वन रैंक वन पेंशन' तुरंत लागू करें। वित्त मंत्री की इस सदेच्छा का सम्मान भी अभी तक नहीं किया गया है। इस तरह सभी प्रविधानों व वित्त मंत्री के निर्देश की स्पष्ट रूप से अवहेलना की जा रही है।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादेवी मंदिर मार्ग, चौक, पटना

पोस्ट

जम्मू-कश्मीर में हिंदू तीर्थयात्रियों पर पाकिस्तानी आतंकियों के विचलित करने वाले हमले का पूरी दुनिया संज्ञान ले। आर्थिक बदहाली का शिकार होने के बावजूद पाकिस्तान भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध से बाज नहीं आ रहा है। आतंकियों की बेहद शर्मनाक हरकत।

शेहला रशीद@Shehla_Rashid

लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। इसके बावजूद अगर सदन में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी लेने जा रहे राहुल गांधी नरेन्द्र मोदी को नई सरकार गठन पर एक बधाई तक नहीं देते तो कौन सी लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन कर रहे हैं? क्या मन में कड़वाहट रखकर राजनीतिक रंजिश पाल कर लोकतंत्र मजबूत होगा?

रोमाना ईसार खान@romanaisarkhan

मोदी सरकार के शपथ ग्रहण में शाह रुख खान की मौजूदगी पर सवाल उठाने वाले लोगों को क्यों लगता है कि उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि वे भारत के मुस्लिमों को बताएं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वे एक भारतीय नागरिक के अपने प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में शामिल होने की कैसे आलोचना कर सकते हैं। यह न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात, बल्कि विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देता है।

सना हाशमी@sanahashmi1

जनपथ

'इंडी' गठबंधन सदृश खेला पाकिस्तान,
पा न सका वह लक्ष्य जो मिला उसे आसान।
मिला उसे आसान ढ्हा खुद आधे रस्ते,
बैटर को निपटाय इंडिया के वह सस्ते।
करके लाख प्रयास हुई ना ऊंची झंडी,
दोनों खाए मात पाक अरु अपना 'इंडी'!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक – आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 60

जब दो देशों के बीच कूटनीति खत्म हो जाती है, तो युद्ध की शुरुआत होती है। -एडोल्फ हिटलर

जब देश की राजधानी में नई सरकार शपथ लेने जा रही हो, ठीक तभी जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर गोलियां बरसाना आतंकियों के दुस्साहस को ही दर्शाता है। जम्मू-कश्मीर में आतंकी जिस तरह से नए रास्ते खोज रहे हैं, उसे देखते हुए सतर्कता और रणनीतियों पर पुनर्विचार बेहद जरूरी है।

दुस्साहस

जम्मू के रियासी में रविवार की शाम को आतंकियों ने जिस तरह श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया, वह दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, ऐसे वक्त में जब देश की राजधानी में नई सरकार शपथ ले रही हो, ठीक उससे पहले इस वारदात को अंजाम देना, आतंकियों के दुस्साहस को भी दर्शाता है। दरअसल, श्रद्धालुओं से भरी बस शिवखोड़ी से कटरा लौट रही थी, तभी घात लगाकर बैठे आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दीं, जिससे बस संतुलन खोकर खाई में गिर गई और करीब दस लोगों की मौत भी हो गई। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन दशकों में यह दूसरी बार था, जब आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला किया। इससे पहले, जुलाई, 2017 में अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की थी, जिसमें सात तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी।

दरअसल, राजोरी, पुंछ और रियासी जिले 1990 के दशक के अंत से 2000 के दशक की शुरुआत तक आतंकवाद का केंद्र जरूर रहे, लेकिन उसके बाद से यहां शांति स्थापित हुई। वर्ष 2021 से राजोरी और पुंछ में आतंकी वारदात फिर से शुरू हुई हैं, लेकिन रियासी अब तक आतंकवाद से अपेक्षया अछूता ही रहा था। ताजा हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से संचालित लश्कर-ए तैयबा के एक आतंकी गुट टीआरएफ ने ली है, जो जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से दर्जनों आतंकी हमलों में शामिल रहा है। टीआरएफ इस क्षेत्र में किस तरह सक्रिय है, उसका पता जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक रिपोर्ट से भी होता है, जिसके अनुसार, कश्मीर में 2022 में आतंकी गुटों के साथ सुरक्षा बलों की 90 मुठभेड़ों में 172 आतंकी मारे गए, जिसमें करीब 108 टीआरएफ से जुड़े थे। चिंता की बात है कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा पार आतंकवाद का पैटर्न जिस तरह बदलता दिख रहा है, उसके अनुरूप जवाबी रणनीति अब तक नहीं बन सकी है। पहले आतंकी घाटी पर हमला करते थे, अब वे जम्मू के पुंछ, राजोरी और

रियासी को निशाना बना रहे हैं। दरअसल, घाटी में आतंकियों की कमर टूट चुकी है, इसलिए वे कश्मीर के दुर्गम इलाकों के बजाय कम ऊंचाई वाले पीर पंजाल के दक्षिणी इलाके चुन रहे हैं, जहां से वारदात को अंजाम देकर घने जंगलों में भागने में सहूलियत होती है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर में जो बदलाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी यहां रिकॉर्ड मतदान हुआ, उससे उपजी हताशा ही इन आतंकी हमलों के रूप में दिख रही है। 29 जून से चूंकि अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। जम्मू-कश्मीर में आतंकी जिस तरह से नए रास्ते खोज रहे हैं, उसे देखते हुए सतर्कता और रणनीतियों पर पुनर्विचार बेहद जरूरी है।

चीन को उसी की भाषा में

अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के चीनी कदम का जवाब देने के लिए भारत ने 'जैसे को तैसा' अभियान चलाया है। भारतीय सेना का सूचना युद्ध प्रभाग इसका नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने तिब्बत के 30 स्थानों की एक सूची को अंतिम रूप भी दे दिया है।

भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने के चीनी कदम का जवाब देने के लिए 'जैसे को तैसा' अभियान चलाया है, यानी भारत भी तिब्बत के 30 स्थानों के नाम बदलेगा। चीन द्वारा भारतीय क्षेत्रों के नाम बदलने को लेकर नई दिल्ली को संदेह है कि बीजिंग ने पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य अरुणाचल प्रदेश पर अपनी मजबूत दावेदारी दिखाने के लिए ऐसा किया है।

भारतीय सेना का सूचना युद्ध प्रभाग इस अभियान का नेतृत्व कर रहा है, जिसे कोलकाता स्थित ब्रिटिशकालीन एशियाटिक सोसाइटी जैसे प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों का समर्थन प्राप्त है। सेना ने अपने लोगो के साथ प्रसारित विस्तृत ट्वीट में अरुणाचल प्रदेश के सात स्थानों के नाम बदलने को चुनौती दी है और चीन द्वारा जिन 30 स्थानों के नाम बदले गए, उनके विरोध का प्रयास कर रही है। अब उन्होंने तिब्बत के 30 स्थानों की एक सूची को भी अंतिम रूप दे दिया है, तथा ऐतिहासिक अभिलेखों से भारतीय भाषाओं में उनके प्राचीन नामों को पुनः प्राप्त किया है। इन पंक्तियों के लेखक के पास यह सूची उपलब्ध है, जो मीडिया के जरिये सार्वजनिक की जाएगी। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और विवादित सीमा के अन्य हिस्सों पर चीनी दावों के खिलाफ एक मजबूत जवाबी आख्यान प्रस्तुत करने के वैश्विक अभियान का हिस्सा है।

सुबीर भौमिक
(वरिष्ठ पत्रकार)
साथ में प्रत्यूष मुखर्जी

अब चूंकि केंद्र में नई सरकार का गठन हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इसलिए चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के स्थानों का नाम बदलने का इस्तेमाल अरुणाचल प्रदेश पर चीनी दावे को खत्म करने के लिए बदले के तौर पर किया जाएगा। सैन्य अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि नए नाम व्यापक ऐतिहासिक शोध के आधार पर रखे जाएंगे।

पूर्व खुफिया ब्यूरो के अधिकारी बेनु घोष, जिन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्षों काम किया है और जिन्हें पर्वतारोहण में भी दिलचस्पी है,

कहते हैं, 'जब भी ऐसा होगा, यह भारत द्वारा तिब्बत के प्रश्न को फिर से उठाने की तरह होगा। जब से बीजिंग ने तिब्बत पर जबरन कब्जा किया है, तब से भारत ने इसे चीनी हिस्सा माना है, लेकिन अब मोदी सरकार चीनी मानचित्रण और नामकरण संबंधी आक्रामकता को कम करने के लिए अपना रुख बदलने को तैयार है।'

भारतीय सेना ने हाल के हफ्तों में इन विवादित सीमावर्ती क्षेत्रों में मीडिया के कई दौरे आयोजित करवाए हैं तथा मीडिया को उन स्थानीय लोगों से बात करने का मौका दिया है, जो चीनी दावों का कड़ा विरोध करते हुए कहते हैं कि वे हमेशा से भारत का हिस्सा थे। नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर इस अभियान से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि भारत का 'अंतिम लक्ष्य क्षेत्रीय और वैश्विक मीडिया के माध्यम से विवादित सीमा पर भारत के जवाबी आख्यान को आगे बढ़ाना है, जो ठोस ऐतिहासिक शोध और स्थानीय निवासियों के जनमत पर आधारित है। गौरतलब है कि इसी वर्ष कुछ समय पूर्व अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने के लिए चीन ने इस राज्य में एलएसी के पास के 30 स्थानों का नाम बदल दिया। हांगकांग स्थित एक दैनिक के अनुसार, प्रशासनिक प्रभागों की स्थापना और नामकरण के लिए जिम्मेदार चीनी असैन्य मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 'मानकीकृत' भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की है, जिसे बीजिंग जंगनान कहता है। यह चौथी बार है, जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थानों का एकतरफा नामकरण किया है। इससे पहले उसने ऐसा वर्ष 2017, 2021 और 2023 में किया था। चीन द्वारा नाम बदले गए स्थानों की सूची में 11 आवासीय क्षेत्र, 12 पर्वतीय, चार नदियां, एक झील, एक पहाड़ी दर्रा और एक भूखंड है। इन नामों में चीनी, तिब्बती और पिनयिन अक्षर हैं, जो मंदारिन चीनी का रोमन वर्णमाला संस्करण है। *साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट* ने मंत्रालय के बयान को उद्धृत किया है, जो कहता है कि 'भौगोलिक नामों के प्रबंधन पर राज्य परिषद (चीनी मंत्रिमंडल) के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, हमने संबंधित विभागों के साथ मिलकर चीन के जांगनान में कुछ भौगोलिक नामों को मानकीकृत किया है।' बीजिंग ने वर्ष 2017 में अरुणाचल प्रदेश के छह स्थानों के कथित मानकीकृत नामों की पहली सूची जारी की थी, फिर वर्ष 2021 में 15 स्थानों की दूसरी सूची जारी की और उसके बाद वर्ष 2023 में 11 स्थानों के नामों की एक और सूची जारी की। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीनी कदम को बार-बार खारिज करते हुए कहा है कि अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है और 'मनगढ़ंत' नाम रखने से यह वास्तविकता नहीं बदल जाती। वर्ष 2023 में तत्कालीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, 'हमने ऐसी रिपोर्टें देखी हैं। यह पहली बार नहीं है, जब चीन ने ऐसा प्रयास किया हो। हम इसे सिरे से खारिज करते हैं।' उन्होंने आगे कहा, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और रहेगा। मनगढ़ंत नाम रखने की कोशिशें इस सच्चाई को नहीं बदल पाएंगी।'

अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावों को पुष्ट करने के लिए चीनी बयानों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर भारत के समक्ष कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने से हुई, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फुट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 मार्च को अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बार-बार के दावे को 'हास्यास्पद' बताते हुए कहा कि यह सीमावर्ती राज्य 'भारत का स्वाभाविक हिस्सा' है। उन्होंने सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दक्षिण एशियाई अध्ययन संस्थान में व्याख्यान देने के बाद अरुणाचल मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, 'यह कोई नया मुद्दा नहीं है। चीन के ये दावे शुरू से ही हास्यास्पद रहे हैं और आज भी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में हम हमेशा से बहुत स्पष्ट और तार्किक रहे हैं। यह सीमा पर चल रही चर्चाओं का हिस्सा बनेगा।' कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना लिया है और जैसे को तैसा की रणनीति अपनाते हुए नाम बदलने के अभियान में शामिल हो गया है।

edit@amarujala.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

कार्लोस अल्कारेज

जरूरी नहीं है कि आप हर बार सफल या विफल रहें, लेकिन प्रयास छूटने नहीं चाहिए। मैं हमेशा एक अच्छा इन्सान और अच्छा खिलाड़ी बनने की कोशिश करता हूं।

सूरज हर सुबह नई उम्मीदों के साथ निकलता है

मैं हमेशा खुद पर विश्वास करता हूं और सभी से ऐसा ही करने के लिए भी कहता हूं। मुश्किलें आती हैं। कई बार तो लगता है कि अब सब कुछ हाथ से निकल गया। मन संशय से भर जाता है। लेकिन ऐसे कमजोर क्षणों से भी बाहर निकला जा सकता है। आप खुद पर फोकस करें। मुश्किल वक्त में भी सकारात्मक बने रहें। मैच के दौरान कई बार मुश्किल क्षण आते हैं, लेकिन मैं खुद पर केंद्रित होकर मुस्कराता रहता हूं, लोगों से हंसी-मजाक करता रहता हूं, ताकि दबाव मुझ पर हावी न हो सके और मैं खुद को संतुलित रख सकूं। आपके ऊपर जब दबाव होता है, तो उससे बाहर आने का रास्ता भी खुद ही ढूंढना पड़ता है। कई बार परिस्थितियों के अनुकूल ढलना पड़ता है। अनेक बार ऐसे पल आते हैं, जब मन और शरीर दोनों ही धैर्य खो बैठते हैं, तब कुछ समय के लिए शांतचित्त हो जाएं और आपके ऊपर जो दुख या कष्ट आया है, उसमें खुशी ढूंढें। कष्ट का भी एक अपना आनंद है, जब सफलता हाथ लगती है, तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मेरी खुद की कोई सीमा नहीं है और उसे निर्धारित भी नहीं करना चाहता हूं। मेरा मानना है कि आपको कोई चीज उपहार में नहीं मिलती और अंगुलियां चटकाने से भी दुनिया आपके कदमों में नहीं होगी। ठोस उपलब्धियां पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपने प्रतिद्वंद्वियों को बताना होता है कि आप क्या हैं। मेरा लक्ष्य और सपना दोनों स्पष्ट हैं कि मुझे दुनिया में नंबर एक बनना है। मुझे पता है कि मैं टेनिस खेलता हूं और उससे प्यार भी करता हूं। जब आप आने काम में आनंद नहीं ले रहे हैं, तो समझो आप हार गए हैं।

स्पेन के 21 वर्षीय कार्लोस अल्कारेज फ्रेंच ओपन का खिताब जीतकर टेनिस के तीनों कोर्ट (हार्ड, ग्रास और क्ले) पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। आइए जानें, वह जीवन के बारे में क्या सोचते हैं?

आपका लक्ष्य और सपना पवित्र होना चाहिए और सपने को पूरा करने के लिए प्रयास करते रहें। प्रतिदिन कठिन मेहनत करें। मुझे चिढ़ होती है, जब कोई मुझे स्पेशल कहता है, क्योंकि ऐसा कहकर वह मेरी मेहनत को अनदेखा कर रहा होता है। बड़ा लक्ष्य बनाएं और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। सफल या असफल होना अलग बात है। दोनों ही सूरतों में सुधार के लिए कोशिश करते रहें। आप जब कठिन परिश्रम करते हैं, तो उसका नतीजा अवश्य मिलता है। अच्छा बनने की कोशिश में आप जब कार्यक्षेत्र में जाते हैं, तो दिमाग में जीतने के बजाय अपना ध्यान सर्वश्रेष्ठ करने पर दें। जरूरी नहीं है कि आप हर बार सफल या विफल रहें, लेकिन प्रयास छूटने नहीं चाहिए। मैं हमेशा एक अच्छा इन्सान और अच्छा खिलाड़ी बनने की कोशिश करता हूं। हर दिन नया सूरज नई उम्मीदों के साथ निकलता है। (विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित)

थकने का समय नहीं

सूत्र

लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि थकने का समय नहीं है। मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए कई कष्टों से गुजरना पड़ा है। मुझे कोई फूलों की सेज नहीं मिली। कई बुरे दौर देखे हैं। मेरे आदर्श और सार्वकालिक महान खिलाड़ी राफेल नडाल से मैंने काफी कुछ सीखा है कि अच्छे वक्त में भी सौम्य कैसे बना रहा जा सकता है। दरअसल सबसे बेहतर को पाने के लिए आपको प्रयास भी सर्वश्रेष्ठ करने पड़ते हैं।

दूसरा पहलू

ओपन एआई के नए चैटबॉट का डेमो एक तरह से धोखा साबित हुआ। इसके नए चैटजीपीटी में कोई सुधार नहीं हुआ।

चैटजीपीटी : नाम बड़े और दर्शन छोटे

ओपन एआई ने अपने बेहद लोकप्रिय चैटजीपीटी चैटबॉट के नवीनतम संस्करण का अनावरण किया, तो इसमें एक नई आवाज थी, जिसमें मनुष्यों की तरह उतार-चढ़ाव एवं भावनाएं थीं। डेमो अनिवार्य रूप से एक प्रलोभन और धोखा साबित हुआ, क्योंकि नए चैटजीपीटी को इसकी अधिकांश नई सुविधाओं के बगैर जारी किया गया था। अभी नए चैटजीपीटी में जो कुछ पेश किया गया है, वह बॉट के विश्लेषण के लिए फोटो अपलोड करने की क्षमता है। बॉट वास्तविक समय में भाषा अनुवाद कर सकता है, पर चैटजीपीटी अपनी पुरानी, मशीन जैसी आवाज में जवाब देगा। फिर भी यह अग्रणी चैटबॉट है, जिसने टेक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। दो हफ्ते तक इस चैटबॉट को आजमाने के बाद मेरे मन में मिली-जुली भावनाएं थीं। भाषा का अनुवाद तो यह उत्कृष्ट करता है, लेकिन गणित एवं भौतिकी की समस्याओं को हल करने में इसे जूझना पड़ता है। कुल मिलाकर, मुझे पिछले संस्करण चैटजीपीटी-4 से इसमें कोई सार्थक सुधार नहीं लगा।

ब्रायन एक्स चेन

चैटबॉट को आजमाने के बाद मेरे मन में मिली-जुली भावनाएं थीं। भाषा का अनुवाद तो यह अच्छा करता है, पर गणित एवं भौतिकी की समस्याओं को हल करने में उलझ जाता है।

यह रणनीति, जिसमें एआई कंपनी नए-नए फीचर्स का वादा करती हैं, लेकिन आधे-अधूरे उत्पाद बनाकर पेश करती हैं, लोगों को भ्रमित एवं निराश करती है। ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी सैम अल्टमैन द्वारा वित्त पोषित स्टार्ट-अप ह्यूमैन का 700 डॉलर का पिन, जो एक बोलने वाला लैपल पिन है, की सार्वभौमिक रूप से आलोचना की गई, क्योंकि यह बहुत जल्दी गर्म हो जाता था। मेटा ने भी हाल में अपने एप में एक एआई चैटबॉट जोड़ा है, जो अधिकांश कार्यों में खराब प्रदर्शन करता है, जैसे कि हवाई जहाज के टिकट के लिए वेब सर्च करना।

ओपन एआई के मुख्य कार्यकारी सैम अल्टमैन द्वारा वित्त पोषित स्टार्ट-अप ह्यूमैन का 700 डॉलर का पिन, जो एक बोलने वाला लैपल पिन है, की सार्वभौमिक रूप से आलोचना की गई, क्योंकि यह जल्द ही गर्म हो जाता है।

कंपनियां पूरी तरह से तैयार होने से पहले ही एआई उत्पाद जारी कर रही हैं। अतीत में जब कंपनियां फोन जैसे नए तकनीकी उत्पाद जारी करती थीं, तो हमें जो दिखाया जाता था, वही मिलता था। एआई के साथ कंपनियां ऐसी तकनीकों का प्रदर्शन कर रही हैं, जो केवल सीमित, नियंत्रित परिस्थितियों में ही काम कर रही हैं। एक परिपक्व, विश्वसनीय उत्पाद आ भी सकता है-या नहीं भी। सीखने वाली बात यह है कि एक उपभोक्ता के रूप में हमें प्रचार का विरोध करना चाहिए और एआई के प्रति सजग दृष्टिकोण रखना चाहिए। हमें किसी भी कमजोर तकनीक पर तब तक ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, जब तक कि इसका सबूत न मिले कि उपकरण विज्ञापन के अनुसार काम करते हैं। चैटजीपीटी का नया संस्करण (जीपीटी-4 ओमनी) अब ओपन एआई वेबसाइट और एप पर मुफ्त में आजमाया जा सकता है।

©The New York Times 2024

आंकड़े

हथकरघा बाजार

दुनियाभर में भारतीय हथकरघा उत्पादों की काफी मांग है। अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय हथकरघा उत्पादों का निर्यात होता है।

राशि करोड़ डॉलर में है। स्रोत : HEPC

जनक ने कहा कि राजा होने के बाद भी मुझे राज्य का मोह नहीं। मान और अपमान पर ध्यान नहीं देता। सुलभा ने कहा-अभी आप पूरे ब्रह्मज्ञानी नहीं हैं।

सुलभा ने दिया जनक को ज्ञान

अंतर्यात्रा
संकलित

महाभारत के शांति पर्व में जनक और सुलभा के संवाद का जिक्र है। सुलभा परम विदुषी थीं। वह प्रधान नाम के राजर्षि के कुल में पैदा हुईं। उनके पूर्वजों ने कई बड़े यज्ञ संपन्न कराए। वह इतनी ज्ञानी थीं कि उनके योग्य कोई वर नहीं मिला और आजन्म ब्रह्मचारिणी रहीं।

महाराज जनक का ब्रह्मज्ञानियों में बड़ा ही नाम था। सुलभा ने सोचा कि देखना चाहिए कि जनक कितने ज्ञानी हैं। वह संन्यासिनी का वेश त्याग कर अपने योग के बल से सुंदर युवती का रूप धारण कर भिक्षा मांगने के बहाने महाराज जनक के दरबार में पहुंचीं। महाराज जनक ने उनका आदर किया और भोजन करवाया। इसी दौरान सुलभा ने ब्रह्म ज्ञान की बात शुरू कर दी। महाराज जनक ने कहा कि शासन करते हुए मुझे राज्य का मोह नहीं। अग्नि और चंदन को समान समझता हूं। मुझे मान-अपमान का ध्यान नहीं। इत्यादि कई बातें बताईं।

इसके बाद सुलभा ने कहा, महाराज आप जो कह रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन जिन लोगों को ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर वे मौन हो जाते हैं। सब कामों से उदासीन होकर एकदम शांत रहते हैं। आपको अब भी वादी-प्रतिवादी, जय-पराजय, स्वपक्ष-परपक्ष का ध्यान है। शास्त्रार्थ भी करते हैं। अतः कुछ कमी है। सुलभा की बात सुनकर महाराज जनक ने कहा कि जो भी त्रुटि है, उसे दूर करेंगे। जनक को ज्ञान देने के बाद सुलभा अपने आश्रम लौट गईं।

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 19 मई, 1977

मणिपुर में नए मंत्रिमंडल के गठन का मामला अधर में

मणिपुर में नये मंत्रिमण्डल के गठन का मामला अभी अधर में
जनता पार्टी हाई कमान निर्णय करेगी
नशाबंदी मात्र कानून से ही संभव नहीं : श्री मोरारजी

मणिपुर विधानसभा के 35 सदस्यों में से जिन 33 सदस्यों ने जनता विधायक दल का गठन किया था, उन्होंने जनता पार्टी में शामिल होने का पत्र सौंप दिया है। हालांकि अभी वहां सरकार का गठन अधर में है।

बढ़त को बरकरार रखने की चुनौती

लोकसभा चुनाव की सफलता अखिलेश के लिए अवसर लेकर आई है, तो चुनौतियां भी हैं, क्योंकि देश में फिर से गठबंधन का दौर लौट आया है।

अजय बोस — सियासत

देश के सबसे अधिक आबादी वाले और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी (सपा) ने अविश्वसनीय छलांग लगाई है। पिछली बार पांच सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार पांच गुना से ज्यादा 37 तक पहुंच गई है। यह इस पार्टी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सपा ने 2004 में अनुभवी नेता मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में 35 सीटें जीती थीं।

अपने पिता के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ना अखिलेश के लिए व्यक्तिगत बड़ी सफलता है, जिनकी अक्सर राजनीतिक सूझबूझ और संगठनात्मक कौशल की कमी के लिए आलोचना की जाती रही है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में लगभग खत्म हो चुकी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर अपना मतदान प्रतिशत 33.59 तक पहुंचा दिया और 2019 के चुनाव में 62 सीटें हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी (33

सीट) को दूसरे स्थान पर खिसका दिया। हालांकि अतीत में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन करने का समाजवादी पार्टी का अनुभव अच्छा नहीं रहा था, फिर भी अखिलेश ने राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन के साथ जाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया। अखिलेश शुरुआत में हिचकिचा रहे थे, लेकिन जमीन स्तर पर चर्चा करने के बाद उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का मन बनाया। अखिलेश का पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) मुद्दा, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर गया। जहां गैर-यादव पिछड़ी जातियां, दलित और मुस्लिम मतदाताओं का महत्वपूर्ण गठजोड़ बनता है।

यादव मतदाताओं की निष्ठा के प्रति आश्वस्त और यह जानते हुए कि मुसलमानों के पास समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन को वोट देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा, उन्होंने गैर-यादव पिछड़ी और दलित जातियों के लिए अपना रास्ता ही बदल लिया। यद्यपि यादवों और मुस्लिमों की पार्टी का ठप्पा लगा होने के बावजूद समाजवादी पार्टी ने सिर्फ चार मुस्लिम और पांच यादव प्रत्याशियों को टिकट दिया, जबकि अन्य पिछड़ी जातियों, जैसे कि निषाद और कुर्मियों के साथ-साथ दलितों को 27 टिकट दिए। महत्वपूर्ण तो यह है कि दलितों को न केवल आरक्षित सीटों पर, बल्कि फैजाबाद जैसी सामान्य श्रेणी की सीट पर टिकट दिया, जहां अयोध्या में राममंदिर है, वहां समाजवादी पार्टी के अनुभवी दलित नेता अवधेश प्रसाद ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की।

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीबी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल होने से अखिलेश को तगड़ा झटका लगा था, लेकिन वह इससे घबराए नहीं, इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। इस चुनाव में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का उत्थान हुआ है, तो यह मायावती और बहुजन समाज पार्टी का शायद अंतिम राजनीतिक पतन है, जिन्होंने डेढ़ दशक पहले भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का वादा किया था। बहनजी की पार्टी का वोट प्रतिशत एकल अंक (9.39 फीसदी) में आ गया है, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन से भी ज्यादा निराशाजनक है। 2014 में भी बसपा कोई सीट नहीं जीत सकी थी, लेकिन उसे 20 फीसदी वोट मिले थे।

बहनजी के लिए सबसे अधिक अपमानजनक तो नगीना लोकसभा क्षेत्र से उनके प्रतिद्वंद्वी दलित नेता और भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद की जीत रही। चंद्रशेखर ने आश्चर्यजनक रूप से डेढ़ लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी। हालांकि, अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती और बसपा द्वारा रिक्त किए गए राजनीतिक स्थान पर चंद्रशेखर आजाद कब्जा कर पाते हैं या नहीं। निश्चित रूप से राज्य की राजनीति में आजाद का भविष्य है, जबकि मायावती अब बीता हुआ कल हैं। जहां तक सपा की बात है, तो वह भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी बड़ी पार्टी बन गई है। यह सफलता अखिलेश के लिए अवसर लेकर आई है, तो चुनौतियां भी साथ में हैं, क्योंकि देश में फिर से गठबंधन के राजनीतिक युग की वापसी हुई है। उनके पिता राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की राजनीति से अधिकतम लाभ उठाने में माहिर थे। अब बेटे की बारी है।

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

देश की प्रगति के लिए साथ चलने का समय

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी सरकार का कामकाज शुरू हो गया है। पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले फैसले में किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर इसे आगे भी बनाए रखने के संकेत दिए। नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो गया है। इसके साथ ही कैबिनेट की पहली बैठक में तीन करोड़ नए आवास बनाने की घोषणा करके सभी को छत मुहैया कराने के अपने इरादों को भी साफ कर दिया है। मोदी ने पहली बार में ही 71 मंत्रियों को अपनी टीम में शामिल कर यह भी साफ कर दिया है कि सरकार की पहली प्राथमिकता अपने कामों को गति देना है।

मंत्रिमंडल गठन में हर बार की तरह राज्यों के साथ-साथ जातिगत समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इस बार के मंत्रिमंडल में पिछली बार वाले 37 चेहरे नहीं हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तरप्रदेश ने हालांकि भाजपा की उम्मीदों पर तुषारापात जरूर किया, लेकिन फिर भी यहां से 10 मंत्रियों को मौका मिला है। मंत्रिमंडल की औसत आयु 57 वर्ष है, यानी अनुभव के साथ ऊर्जा को भी पूरा स्थान दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषक हर मंत्रिमंडल का विश्लेषण अपने-अपने तरीके से करते हैं। इस बार भी यह विश्लेषण हो रहा है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत सात पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पर 71 सदस्यीय मंत्रिमंडल में सिर्फ सात ही महिलाओं का होना, नारी उत्थान के दावों पर प्रश्नचिह्न जरूर खड़े करता है। आजादी के बाद से देश ने अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेतृत्व में बनी अलग-अलग सरकारों को देखा है। बीते दस सालों में मोदी सरकार अनेक फैसलों से देश को चौंका चुकी है। चुनाव रैलियों में मोदी ने दस साल के काम को ट्रेलर बताते हुए साफ किया था कि 'असली पिक्चर' तो अभी शुरू होगी। देश को इंतजार रहेगा कि अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार क्या बड़े फैसले लेती है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे देश के सामने हमेशा की तरह इस बार भी खड़े हैं। देश को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना भी एक चुनौती है। 'सबका साथ-सबका विकास' के मुद्दे को भी गति देने की अपेक्षा अगले पांच सालों में रहेगी।

देश को आगे ले जाने के लिए राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना समय की सबसे बड़ी मांग है। सिर्फ सरकार ही नहीं, पूरे देश को एक साथ चलना होगा। लोकतंत्र में जितना महत्त्व सत्तापक्ष का है उतना ही प्रतिपक्ष का भी। दस साल बाद देश को मान्यता प्राप्त विपक्ष मिला है। देश की जनता उम्मीद करती है कि अब सभी साथ मिलकर काम करें।

नई मंत्रिपरिषद: सरकार की स्थिरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती और कसौटी है

गठबंधन की बिसात पर सधी हुई चाल

राज कुमार सिंह
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं
@patrika.com

शपथ ग्रहण में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर कोई खास नाराजगी सामने नहीं आई। हां, अजित पवार की एनसीपी अवश्य मंत्रिमंडल से बाहर रह गई।

लगातार तीन बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के पंडित जवाहर लाल नेहरू के रेकॉर्ड की बराबरी अपने आप में महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इस बार गठबंधन पर निर्भरता के चलते देश को स्थिर सरकार दे पाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती और कसौटी होगी। यह चुनौती ज्यादा मुश्किल इसलिए है कि इस बार गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे गठबंधन राजनीति में माहिर नेता भी शामिल हैं। इस लिहाज से नौ जून की शाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ लेने वाली मंत्रिपरिषद पर नजर डालें तो कहा जा सकता है कि मोदी गठबंधन की बिसात पर सधी चाल चल रहे हैं। शपथ ग्रहण में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहे और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर कोई खास नाराजगी सामने नहीं आई।

हां, अजित पवार की एनसीपी अवश्य मंत्रिमंडल से बाहर रह गई, पर इसके कारण आंतरिक और तार्किक, दोनों बताए जा रहे हैं। पहला, मंत्री बनने के लिए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे में खींचतान। दूसरा, अतीत में कैबिनेट मंत्री रह चुके प्रफुल्ल का स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री बनने से इनकार। मात्र एक लोकसभा सीट जीत पाई उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी सौदेबाजी की स्थिति में नहीं है। इसका इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव वाले महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके गुट के एक दर्जन से भी ज्यादा विधायकों के शरद पवार से संपर्क में होने की खबरें हैं। शिवसेना तोड़ कर मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे ज्यादा कमजोर आंके जा रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन अजित पवार की एनसीपी से अच्छा रहा, जिसका पुरस्कार भी उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री के रूप में मिला है। महाराष्ट्र से कुल छह मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें भाजपा की रक्षा खड़से भी शामिल हैं, जिनके श्वसुर एकनाथ खड़से फिलहाल शरद पवार की एनसीपी के एमएलसी हैं, पर जल्द अपनी पुरानी पार्टी भाजपा में लौटने वाले हैं। हरियाणा में भी इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हैं, जहां से एक कैबिनेट समेत कुल तीन मंत्री बनाए गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में हैं। वहां से एक राज्य मंत्री बनाया गया है। तीसरी बार सांसद बने भोजपुरी गायक मनोज तिवारी चूक गए, लेकिन पहली बार सांसद बने हर्ष मल्होत्रा की लॉटरी लग गई। मोदी सरकार में इस बार प्रधानमंत्री के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, पांच स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्यमंत्रियों समेत कुल 71 मंत्री शामिल हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल जैसे पुराने चेहरे तय माने जा रहे थे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सभी 29 लोकसभा सीटें जिताने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रूप में कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। जीतन राम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल और एचडी कुमारस्वामी भी क्रमशः बिहार, असम और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

जेपी नड्डा को मंत्री बना दिए जाने की वजह से भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तलाशना होगा। वैसे भी लोकसभा चुनाव के चलते बढ़ाया गया नड्डा का कार्यकाल इसी महीन समाप्त हो रहा है। नड्डा के मंत्री बनने के चलते ही शायद अनुराग सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। मात्र चार लोकसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश से एक से ज्यादा कैबिनेट मंत्री बनाए जाते तो अन्य बड़े राज्यों में असंतुलन पैदा हो जाता। यह देखना होगा कि भविष्य में अनुराग ठाकुर को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। एक और पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी भी इस बार सरकार में नहीं हैं। पुरुषोत्तम रूपाला जैसे कुछ पूर्व मंत्री चुनाव जीतने के बावजूद नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए, पर उनके कारण अलग हैं।

चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ कर आए लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू इस बार चुनाव हार जाने के बावजूद मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब की राजनीति में अपने सिख चेहरे के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है। बिट्टू आतंकवाद से संघर्ष में शहीद हुए पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र हैं। रणनीति के तहत ही केरल में भाजपा का खाता खोलने वाले अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी को मंत्री बनाया गया है।

आंकड़ों की बात करें तो चुनाव हार जाने समेत कई कारणों से पिछले मोदी मंत्रिमंडल के कुल 37 चेहरों को इस बार शामिल नहीं किया गया है, जबकि 33 नए चेहरों की एंट्री हुई है। नए चेहरों में सहयोगी दलों के चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल हैं। राज्यवार देखें तो बिहार के कुल आठ मंत्रियों में से चार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के नौ मंत्रियों में से अकेले राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात से कुल छह मंत्री बनाए गए हैं। राजस्थान से 4 मंत्री बनाए गए हैं।

फैक्ट फ्रंट

तीसरी बार प्रधानमंत्री बनीं मार्गरेट थैचर

ब्रिटेन की आयरन लेडी कही जाने वाली मार्गरेट थैचर ने साल 1979 से 1990 तक कंजरवेटिव पार्टी की सरकार का नेतृत्व किया था। वह लगातार तीन बार देश की प्रधानमंत्री रहीं। 11 जून 1987 में उन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। 1959 में पहली बार संसद की सदस्य बनने के बाद थैचर ने अपने राजनीतिक करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थैचर ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मामलों में साहसपूर्ण निर्णय लिए। इसी कारण उन्हें आयरन लेडी कहा जाता है। 8 अप्रेल 2013 को थैचर का निधन हो गया था।

चर्चा में: गठबंधन सरकारों को बनाने में माहिर राजनेता

देश की राजनीति के केंद्र में लौटे चंद्रबाबू नायडू

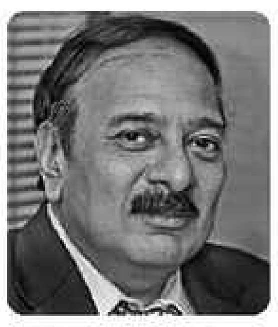

किंगशुक नाग
'बैटलग्राउंड तेलंगाना' समेत कई किताबों के लेखक
(द बिलियन प्रेस)
@patrika.com

नायडू ने जब पहली बार सत्ता संभाली, तब हैदराबाद की पहचान पिछड़े शहर के रूप में थी।

पिछले चार दशकों में चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक जीवन अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। इस दौरान वह सत्ता में भी रहे और सत्ता के बाहर भी - पीएम पद के करीब पहुंचने से लेकर आंध्र प्रदेश में हाशिए पर खिसकने तक। अब चंद्रबाबू नायडू अभी तक के अपने सबसे प्रभावशाली रूप में लौट आए हैं। वह मोदी 3.0 के कार्यकाल में प्रतिकूल या असामान्य परिस्थितियों में उनके अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा की 25 में से 16 और विधानसभा की 175 में से 135 सीटों पर जीत हासिल की है। इस शानदार जीत और एनडीए को उनके समर्थन की नई भूमिका ने उन्हें देश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है।

एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन सरकारों को आकार देने और समर्थन में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। गठबंधन सरकारें बनाने में मदद करने का उनका अच्छा रिकॉर्ड है। नायडू दोनों पक्षों के लिए अनुकूल साबित हुए हैं। वह भाजपा के साथ रहे हैं तो भाजपा के विरोधियों के साथ भी। वह अपने गृह राज्य पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हुए अनिश्चित गठबंधन के साथ भी रहे हैं और उन्होंने तीन बार राज्य पर शासन भी किया है। 1980 के दशक की शुरुआत में चंद्रबाबू नायडू हैदराबाद में विधायकों के लिए बनाए गए हॉस्टल के एक कमरे में एक अन्य विधायक के साथ रहते थे। उनके रूम-मेट थे वाइ.एस. राजशेखर रेड्डी, जो आगे चलकर नायडू की तरह ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। रेड्डी और नायडू उस वक्त मित्र थे, पर बाद में राजनीतिक अलगाव हो गया। इस चुनाव में नायडू की पार्टी ने जगन मोहन रेड्डी (दिवंगत राजशेखर रेड्डी के बेटे) की पार्टी को मात दी है। दिलचस्प तो यह है कि नायडू जब एमएलए हॉस्टल में रहते थे, तब वह एक उत्साही कांग्रेसी थे। 1981 में राज्य की कांग्रेस नीत गठबंधन सरकार में वह मंत्री थे। 1983 में एनटीआर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद, नायडू ने कांग्रेस छोड़ दी और टीडीपी से हाथ मिला लिया। इसी दौरान एनटीआर अपनी पुत्री भुवनेश्वरी के लिए उपयुक्त वर की तलाश में थे। उनका ध्यान चंद्रबाबू की ओर गया। नायडू 1975 से ग्रांड ओल्ड पार्टी के साथ थे और उन्हें संजय गांधी के अनुयायी के रूप में देखा जाता था। टीडीपी के साथ अपने पहले दशक में, नायडू पार्टी के संगठनात्मक कार्य से जुड़े रहे। वह मंत्री नहीं थे। हालांकि, पार्टी में उनकी बहुत चलती थी। फिर 1990 में, टीडीपी के हाथ से सत्ता फिसल गई और कांग्रेस विजयी रही। लगभग उसी समय विधुर एनटीआर ने अपने से उम्र में बहुत छोटी एक तेलुगु लेखिका से फिर शादी कर ली। 1995 में पार्टी पर एनटीआर की पकड़ कमजोर पड़ती गई और उनके दामाद नायडू ने टीडीपी और बहुत जल्द ही सरकार पर नियंत्रण कर लिया।

चंद्रबाबू ने नए मुख्यमंत्री के रूप में केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन किया। जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो वह पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के पसंदीदा बन गए। बताते हैं कि वाजपेयी अक्सर कई मुद्दों पर नायडू से सलाह लिया करते थे। नायडू ने जब सत्ता संभाली, तब हैदराबाद की पहचान पिछड़े शहर के रूप में थी जिसकी सड़कें धूल भरी थीं। नायडू का विकास का अपना विजन था। उनकी कोशिशों से माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में अपना डवलपमेंट सेंटर बनाया। धीरे-धीरे हैदराबाद हाइटेक सिटी बन गया। पर चुनाव में इसका लाभ नहीं मिला और 2004 में नायडू की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। दस साल बाद 2014 में नायडू फिर ऐसे आंध्र प्रदेश की सत्ता में लौटे जिसमें हैदराबाद नहीं था। उन्होंने अमरावती को नई राजधानी के रूप में तैयार करने का निश्चय किया। भाग्य का खेल, नायडू 2019 का चुनाव हार गए। अब 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ नायडू फिर वापस आ गए हैं। उनके पास अब वह काम है जिसमें उन्हें महारत हासिल है - राज्य का सतत, दीर्घकालिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास करना और दिल्ली में नए सत्तारूढ़ गठबंधन में अपनी मजबूत और विश्वसनीय स्थिति को बनाए रखना।

सिंगापुर: परिवहन सुविधाओं के बीच इनडोर झरने का अनोखा अनुभव है यह 'रेन वोर्टेक्स'

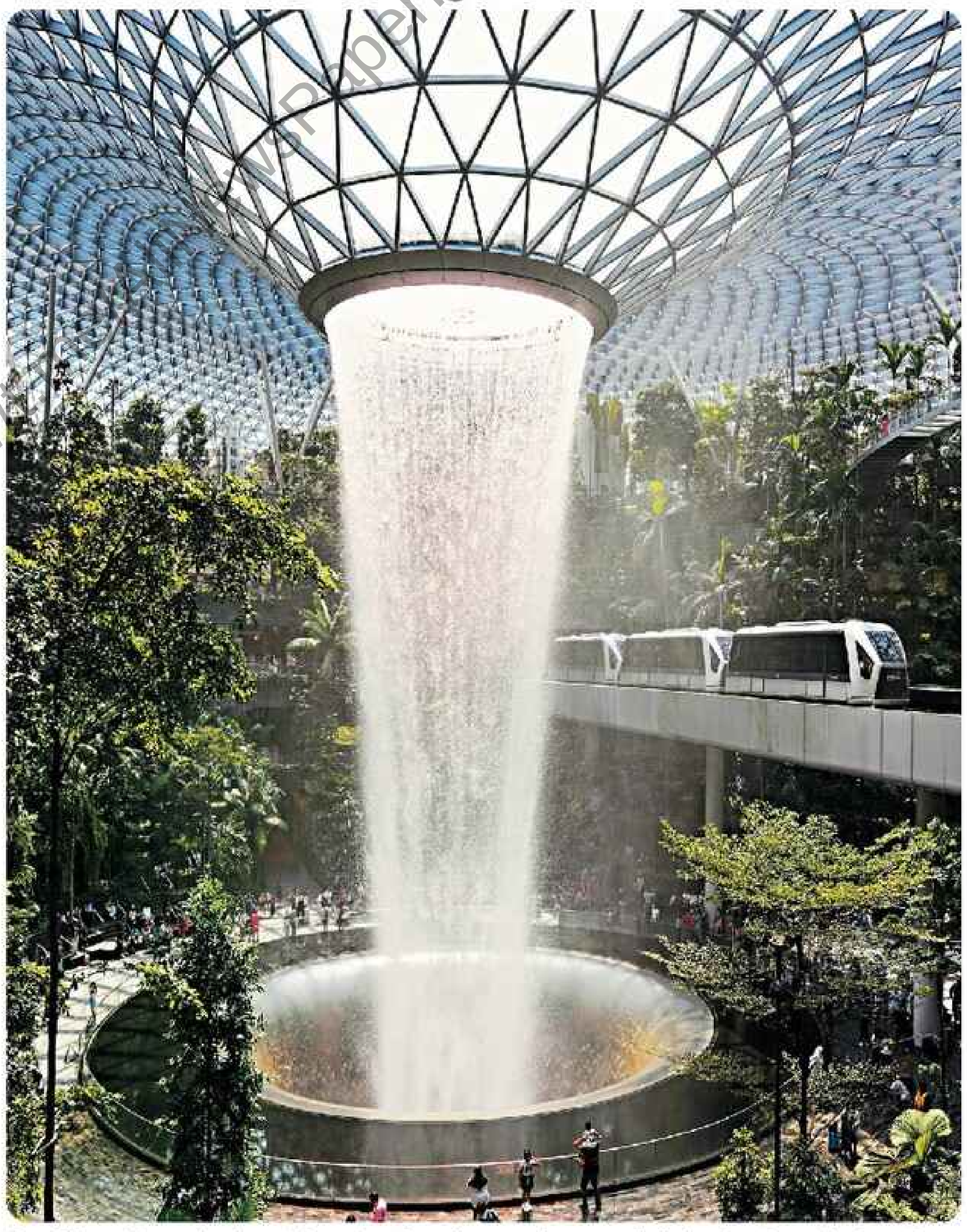

'रेन वोर्टेक्स' सिंगापुर के ज्वेल चांगी हवाई अड्डे पर स्थित एक ऐसा झरना है जिसे दुनिया के सबसे बड़े इनडोर झरने के रूप में जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। हवाई अड्डे परिसर से बाहर निकल आपको इसके लिए शिसेडो फॉरेस्ट वैली का रुख करना होगा। यह एक ऐसा हरा-भरा अभयारण्य है जो दुनिया के सबसे बेहतरीन परिवहन केंद्र में एक शांत जगह का अनुभव देता है। यहां आप पेड़ों को रोशन करती नाचती रोशनी, पृष्ठभूमि में बजने वाले सुखदायक संगीत और 'शिसेडो अल्टीम्यून' की खास खुशबू का भी अनुभव कर सकते हैं।

प्रसंगवश

कैसे पनप गए फर्जी ड्राइविंग स्कूल, जरूरी है जांच

इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि फर्जी ड्राइविंग स्कूलों के संचालन में मिलीभगत का खेल तो नहीं चल रहा

वाहन चालक पूरी तरह से प्रशिक्षित हो और वह यातायात नियमों से भलीभाति वाकिफ हो तो सड़क हादसों को एक हद तक रोका जा सकता है। इसीलिए वाहन चलाना सीखने के इच्छुक लोगों को रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूलों के जरिए कार प्रशिक्षण लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन यदि ऐसे ड्राइविंग स्कूलों में असली-नकली का भेद होता दिखे तो फिर दोष किसको दें? सचमुच उन्हें ही, जिनकी जिम्मेदारी ऐसे स्कूलों की निगरानी की होती है, फिर भी चांदी की खनक के आगे वे सब चुपचाप देखते रहते हैं। यह जानकारी चौंकाने वाली है कि अकेले राजधानी जयपुर में ही बड़ी संख्या में अवैध ड्राइविंग स्कूल चल रहे हैं। जयपुर में 30 ड्राइविंग स्कूल ही आरटीओ से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 300 चल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये फर्जी ड्राइविंग स्कूल धड़ल्ले से अपना प्रचार भी कर रहे हैं। लोगों से मनमानी फीस वसूलते हैं सो अलग। पूरी तरह वाहन चलाना सिखाने का काम तो शायद ही ये स्कूल कर पाते हों? चिंता इस बात की भी है कि मुंहमांगी रकम देने के बावजूद इन अप्रशिक्षित लोगों के भरोसे कोई कार चलाना भला कैसे सीख सकता है? हैरत की बात यह भी कि ये स्कूल वाहन चालक को प्रशिक्षण देने के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। नियमानुसार जिस वाहन से प्रशिक्षण दिया जाता है, उसका कमर्शियल पंजीयन आवश्यक होता है।

शिकायत मिलने के बाद अब आरटीओ हरकत में आया है और कुछ वाहन जब्त भी किए गए हैं। ये फर्जी ड्राइविंग स्कूल अचानक तो शहर में प्रकट हुए नहीं। राजधानी जयपुर की जब यह हालत है तो राज्य के दूसरे इलाकों की क्या स्थिति होगी, यह बात आसानी से समझी जा सकती है। ड्राइविंग स्कूलों को पंजीकृत करने के लिए आरटीओ के कुछ मानदंड हैं। प्रशिक्षित चालकों के अलावा वाहनों की फिटनेस पर भी ध्यान दिया जाता है। चेहरा देखकर फीस तय करने वाले फर्जी स्कूलों के वाहन की फिटनेस और कार चालक की योग्यता सवालों के घेरे में ही रहती है। ऐसे फर्जी स्कूलों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इस तरह के फर्जी ड्राइविंग स्कूलों के संचालन में मिलीभगत का खेल तो नहीं चल रहा। कार चलाना सीखने के इच्छुक लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे जांच-परख कर ही ड्राइविंग स्कूल का चयन करें, ताकि प्रशिक्षण के नाम पर उनके साथ किसी प्रकार का छल न हो। - ज्ञान चंद पाटनी

gyan.patni@epatrika.com

यह भी जानें कैशलेस क्लेम की पारदर्शी प्रक्रिया के साथ होगा मरीज के स्वास्थ्य रिकॉर्ड व डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल का डिजिटलीकरण

क्या है डिजिटल प्लेटफॉर्म 'नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज'?

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के साथ उन उपायों पर काम कर रहा है, जिनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक मरीजों की पहुंच को सुलभ कराना और आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च में कमी लाना है। आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च यानी चिकित्सा पर होने वाला व्यय जो स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा कवर नहीं होता है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और इरडा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म 'नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज' (एनएचसीएक्स) को लॉन्च करने जा रहे हैं। क्या यह प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में मरीजों की मदद करेगा? क्या इससे स्वास्थ्य देखभाल दावों के पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता आएगी?

एनएचसीएक्स: एक गेटवे

भारत डिजिटल मिशन के तहत विकसित किया जा रहा 'एनएचसीएक्स' सभी बीमा कंपनियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं व स्वास्थ्य बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के लिए एक गेटवे के तौर पर काम करेगा। इससे बीमा उद्योग में दक्षता, पारदर्शिता बढ़ने, पॉलिसीधारकों और रोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे पारदर्शिता के साथ स्वास्थ्य बीमा दावों की प्रक्रिया तेज होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि 'एनएचसीएक्स' इरडा के '2047 तक सभी के लिए बीमा' के लक्ष्य के अनुरूप है। इससे अस्पतालों व बीमा कंपनियों के बीच सुव्यवस्थित, कागज रहित और संविदात्मक दायित्व के तहत एक ढांचा तैयार होगा, जो स्वास्थ्य देखभाल लागत में दक्षता, पूर्वानुमान और पारदर्शिता में सुधार लाने वाला साबित होगा। अब तक एनएचसीएक्स से एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर और 12 बीमा कंपनियां जुड़ चुकी हैं।

29% है भारत की कुल सामान्य बीमा प्रीमियम आय में स्वास्थ्य बीमा की हिस्सेदारी। अभी भी बड़ी आबादी किसी भी बीमा या स्वास्थ्य बीमा योजना से वंचित है।

2023 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक परिपत्र के जरिए सभी बीमा कंपनियों को सलाह दी थी कि वे बीमा कवर चाहने वाले सभी लोगों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर लेना शुरू करें।

कैशलेस क्लेम

सभी कैशलेस बीमा दावों के निपटान के लिए समयसीमा तय की गई है। इरडा के मुताबिक सभी कैशलेस बीमा दावों के लिए अस्पताल से डिस्चार्ज प्रमाणपत्र प्राप्त करने के तीन घंटे के भीतर प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। आवश्यक प्रणालियां और प्रक्रियाएं लागू करने के लिए 31 जुलाई तक की समय सीमा तय की गई है।

अन्य प्रोत्साहन योजनाएं?

मरीज के स्वास्थ्य रिकॉर्ड व डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल का डिजिटलीकरण बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जनवरी 2023 में डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (डीएचआइएस) शुरू की थी, जिसमें अस्पतालों को एक्सचेंज के जरिए प्रति बीमा दावा लेन-देन पर 500 रुपए या दावा राशि का 10% (जो भी कम हो) का वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है।

एक्सचेंज की जरूरत क्यों

'भारत में स्वास्थ्य बीमा कवरेजः राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए अंतर्दृष्टि' नामक दस्तावेज स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और आउट-ऑफ पॉकेट के भारी-भरकम खर्चों को कम करने में स्वास्थ्य बीमा के महत्त्व को रेखांकित करता है। यह दस्तावेज बताता है कि निजी बीमा कंपनी की योजना हो या सरकारी, बीमित होने पर अस्पताल में भर्ती होना सहज हो जाता है। एनएचसीएक्स प्लेटफॉर्म बीमा कंपनियों, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सरकारी वित्तपोषित स्कीम, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, पॉलीक्लिनिक्स के बीच हेल्थ क्लेम डेटा, दस्तावेजों आदि के निर्बाध आदान-प्रदान को मानकीकृत और सक्षम करेगा। डिजिटलीकरण और योजना के केंद्रीकरण से दावा निपटान की लागत में काफी कमी आने का अनुमान है।

क्या हैं चुनौतियां

मुख्य चुनौती अस्पतालों व बीमा कंपनियों के बीच संबंधों में सुधार है। इसके लिए जरूरी हैं डिजिटलीकरण के प्रयास, आइटी प्रणाली का उन्नयन व कार्यबल प्रशिक्षण। फिट होने के बाद भी मरीज को अस्पताल से छुट्टी देने में देरी, गलतफहमी जैसे कुछ मुद्दे हैं जो बाधा पैदा करते हैं। डेटा में सेंधमारी जैसी चुनौतियों से लगातार कुशलतापूर्वक निपटा जा रहा है। उम्मीद है कि एक्सचेंज को पूरे पैमाने पर जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।

आपकी बात

जल स्रोतों तक पहुंचे वर्षा जल

भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए सरकार को जल स्रोतों तक बरसात का पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए।

-ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उदयपुरा, मप्र

आज का सवाल

केंद्र की नई सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए?' ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

rb.gy/lmce38

कल्पमेधा

सामान्य नेता लोगों को उस जगह ले जाते हैं, जहां वे जाना चाहते हैं। महान नेता वहां ले जाते हैं, जहां लोग जाना नहीं चाहते, फिर भी जाने की आशा रखते हैं।

– रोजलिन कार्टर

दहशत की बुनियाद

जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों पर अंकुश लगाना चुनौती बना हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने के बाद दहशतगर्दी में भारी कमी आई है और आतंकी संगठन कुछ इलाकों तक सिमट कर रह गए हैं। मगर लगातार कुछ-कुछ अंतराल पर जिस तरह आतंकी घात लगा कर हमले कर रहे हैं, उससे इस दावे पर यकीन करना मुश्किल लगता है। आतंकवादी लगातार अपनी रणनीति बदलते देखे जा रहे हैं। वे कभी सशस्त्र बलों को निशाना बनाते हैं, तो कभी बाहरियों, कश्मीरी पंडितों को लक्ष्य बनाया जाता है। अब वहां जा रहे सैलानियों पर हमले हो रहे हैं। पिछले महीने पहलगाम में सैलानियों पर हमला किया गया था। अब कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस को निशाना बनाया गया, जिसके चलते बस खाई में गिर गई। इसमें नौ लोगों की मौत हो गई और इकतालीस से अधिक लोग घायल हैं। पर्यटन कश्मीरी लोगों की आजीविका का बड़ा आधार है। इस तरह के हमलों से पर्यटन पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे हमले नब्बे के दशक में बढ़ गए थे, मगर लंबे समय से सैलानियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा था। अब ऐसा दिख रहा है तो इसकी वजहें भी साफ हैं।

पर्यटकों पर हमले के पीछे आतंकवादी संगठनों का मकसद घाटी में बाहर के लोगों की आवाजाही रोकना होता है। बाहरी मजदूरों और कश्मीरी पंडितों को लक्ष्य बना कर हमले करने के पीछे भी उनका मकसद यही है। मगर अब जिस तरह बड़ी संख्या में सैलानियों और श्रद्धालुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उससे जाहिर है कि आतंकी लोगों में भय पैदा करना चाहते हैं। मगर इसे लेकर स्थानीय लोगों में किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है, तो हैरानी की बात है, क्योंकि इससे उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। पिछले दस वर्षों में बेशक पत्थरबाजी और आंदोलन वगैरह की घटनाएं कम हुई हैं, आतंकी हमलों में मरने वालों की संख्या भी घटी है, मगर हकीकत यही है कि दहशतगर्दी किसी भी रूप में कम नहीं हुई है। दस वर्ष पहले और बाद के आंकड़ों की तुलना से साफ पता चलता है कि आतंकी हमले बढ़े हैं। इस दौरान बेशक बड़ी तादाद में आतंकवादी मारे गए हैं, मगर दहशतगर्दों की भर्ती में भी तेजी आई है। उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन बढ़ा है। इसलिए यह स्वाभाविक ही पूछा जा रहा है कि जब सीमा पर चौकसी बढ़ी है, तलाशी अभियान तेज हुए हैं, दहशतगर्दों की वित्तीय मदद पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, तो उन्हें भर्तियां करने और साजो-सामान जुटाने में कामयाबी कैसे मिल जा रही है।

पिछले दस वर्षों में जिस तरह सुरक्षाकर्मियों, सैलानियों, श्रद्धालुओं और बाहर से मजदूरी वगैरह करने गए लोगों को निशाना बना कर हत्याएं की गई हैं, उससे यह सवाल निरंतर गाढ़ा होता गया है कि आखिर यह सिलसिला कब रुकेगा। राष्ट्रीय जांच एजंसी की रपट के मुताबिक ऐसे हमलों में पाकिस्तान के प्रशिक्षत दहशतगर्दों का हाथ होता है, स्थानीय लोग उन्हें सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। अगर सीमा पर चौकसी सख्त की गई है, तो फिर सीमा पार से आतंकियों की घाटी में पैठ कैसे हो पा रही है। अगर खुफिया तंत्र पहले से चौकन्ना हुआ है, तो आतंकी कैसे सेना के काफिले पर हमला कर देते हैं और पहले ही उसकी भनक नहीं लग पाती। घाटी में आतंकवाद से निपटने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाने की जरूरत है।

संघ की शक्ति

यूरोपीय संघ के चुनाव में इस बार बड़ी उलट-फेर देखने को मिली है। दक्षिणपंथी रुझान वाले दलों को शानदार कामयाबी मिली है। इसे देखते हुए जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों के सत्ताधारी दलों की घबराहट बढ़ गई है। हार की आशंका से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो राष्ट्रीय संसद भंग कर मध्यावधि चुनाव की घोषणा कर दी है। सत्ताईस सदस्य देशों वाले यूरोपीय संघ में जर्मनी सबसे बड़ा देश है। वहां की 'अल्टरनेटिव फार जर्मनी' पार्टी मजबूत होकर उभरी है। हालांकि उसके कई शीर्ष उम्मीदवारों के नाम घोटालों में शामिल थे, मगर उसके बावजूद पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा। पार्टी ने 2019 में ग्यारह फीसद मत हासिल किए थे, जो इस बार बढ़ कर साढ़े सोलह फीसद हो गए। वहीं जर्मनी के सत्तारूढ़ गठबंधन में तीन दलों का संयुक्त मत मुश्किल से तीस फीसद से ऊपर रहा। इस तरह 'अल्टरनेटिव फार जर्मनी' ने देश के चांसलर ओलाफ शोल्ज की 'सोशल डेमोक्रेट्स' पार्टी को मात देने के लिए पर्याप्त सीटें जुटा ली हैं। जर्मनी में दक्षिणपंथ के इस उभार को कुछ लोग हिटलर के नाजी उभार के रूप में देख रहे हैं।

यूरोपीय संघ यूरोप के सत्ताईस देशों का संगठन है, जिसकी संसद के लिए करीब चालीस करोड़ लोग मतदान करते हैं। यही संसद यूरोपीय देशों की आर्थिक विकास, वाणिज्य-व्यापार, राजनयिक, आप्रवासन आदि से जुड़ी नीतियां तय करती है। इसलिए दुनिया के तमाम देशों की नजर इसके चुनाव पर रहती है। यूरोपीय संघ में दक्षिणपंथी रुझान वाले दलों का दबदबा बढ़ने से वाणिज्य-व्यापार, आप्रवासन आदि को लेकर कुछ देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दक्षिणपंथी रुझान वाली सरकारों में देखा गया है कि वे राष्ट्रवादी नीतियों पर अधिक जोर देती हैं। यूरोपीय संघ आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन की पार्टी 'क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स' ने चुनावों से पहले ही दक्षिणपंथी रुझान के उभार को भांप लिया था और प्रवासन और जलवायु के मुद्दे पर और अधिक दक्षिणपंथी रुख अपना लिया था, जिसके कारण यूरोपीय संसद में उनकी पार्टी अब तक की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। भारत के लिए भी इसे इसलिए चिंता का विषय माना जा सकता है कि उन देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रोजगार आदि के लिए जाते हैं।

तपती धरती सुलगते सवाल

पेड़-पौधों की कमी, अधिक शहरीकरण तथा कंक्रीट से अधिक निर्माण आदि विविध कारणों से शहर ज्यादा तप रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह शहरों में निरंतर बढ़ता जनसंख्या घनत्व भी है।

योगेश कुमार गोयल

देश के ज्यादातर हिस्सों में लोग भीषण गर्मी से बेहाल नजर आ रहे हैं। दिल्ली सहित कई इलाकों में तापमान इस बार 49 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया और देश के कुछ हिस्सों में 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया। आमतौर पर ठंडे रहने वाले शिमला, मनाली, धर्मशाला सहित लगभग तमाम पर्वतीय शहर भी तप रहे हैं। इनमें से कुछ पर्वतीय इलाकों में भी पारा 40 के पार पहुंच चुका है। वैसे तो हर वर्ष उत्तर पश्चिमी भारत, मध्य, पूर्व और उत्तर प्रायद्वीपीय भारत के मैदानी इलाकों में मार्च से जून के दौरान लू का दौर चलता है, लेकिन जैसे-जैसे पृथ्वी गर्म होती जा रही है, दिन और रात भी सामान्य से अधिक गर्म हो रहे हैं, जिससे मौतों तथा बीमारियों की आशंका भी बढ़ रही है।

पिछले पंद्रह वर्षों में 2009, 2010, 2016, 2017 और 2022 भारत में दर्ज पांच सबसे गर्म वर्ष रहे। आइएमडी के मुताबिक पंद्रह सबसे गर्म वर्षों में से ग्यारह वर्ष 2008 से 2022 के बीच ही दर्ज किए गए। प्रश्न है कि भारत में गर्म हवाओं को लेकर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? पिछले तीस वर्षों के तापमान तथा गर्म हवाओं का आकलन करते हुए आइआइटी खड़गपुर के एक अध्ययन में यह स्पष्ट किया गया था कि घटती हरियाली, शहरीकरण तथा कंक्रीट से निर्माण के कारण अब प्रतिवर्ष लू में वृद्धि हो रही है।

पेड़-पौधों की कमी, अधिक शहरीकरण तथा कंक्रीट से अधिक निर्माण आदि विविध कारणों से शहर ज्यादा तप रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह शहरों में निरंतर बढ़ता जनसंख्या घनत्व भी है। दरअसल, कामकाज और सुविधा संपन्न जिंदगी की चाह में ग्रामीण अंचलों से बड़ी संख्या में लोग शहरों की ओर रुख कर रहे हैं और फिर सदा के लिए वहीं बस जाते हैं। इससे शहरों में तमाम संसाधनों पर बोझ बढ़ रहा है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ने के कारण हरियाली नष्ट हो रही है। सुविधाओं के विस्तार के लिए पर्यावरण विरोधी विकास योजनाओं के नाम पर हरे-भरे प्राकृतिक क्षेत्रों को सीमेंट तथा कंक्रीट के तपते जंगलों में तब्दील किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ स्थानीय कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। दरअसल, अधिक हरे-भरे इलाकों में तापमान कम दर्ज किया जाता है, जबकि चारों ओर बसी कालोनियों तथा ऊंची-ऊंची इमारतों वाले इलाकों में तापमान ज्यादा दर्ज होता है। तकनीकी भाषा में इसे 'अर्बन हीट आईलैंड इफैक्ट' कहा जाता है।

विभिन्न शोधों के आधार पर वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि लू के लिए जलवायु संकट जिम्मेदार है और शहरीकरण तथा जनसंख्या घनत्व इसमें बड़ा योगदान देते हैं। आइआइटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के 1972 से 2014 के दिल्ली-एनसीआर में जमीन के बदल रहे उपयोग पर किए गए एक अध्ययन में भी सामने आ चुका है कि इस दौरान दिल्ली में धरातल के तापमान में 1.02 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई और तापमान में यह बदलाव अधिक शहरीकरण तथा क्षेत्र में जमीन के उपयोग में बदलाव के कारण ही हुआ। कापरनिक्स सेंटिनल-3, इनसैट 3डी तथा नासा के

एक उपग्रह द्वारा कुछ समय पहले पृथ्वी की सतह की ली गई तस्वीरों से यह चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ था कि धरती की सतह का तापमान (एलएसटी) 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो गया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजंसी के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों

> **अत्यधिक तापमान से जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य प्रणालियों की चिंता बढ़ जाती है, वहीं लू का श्रमिकों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे देश की समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रपट के अनुसार भारत ने 1995 में गर्मी के कारण काम के करीब 4.3 फीसद घंटे खो दिए और 2030 में काम के घंटों में 5.8 फीसद की कमी आने की संभावना है। 2030 तक 3.4 करोड़ लोगों की नौकरियों पर संकट होगा। 2030 में गर्मी के कारण कृषि तथा निर्माण क्षेत्रों में 9.04 फीसद काम के घंटे कम हो जाने की आशंका है।**

में एलएसटी 55 डिग्री के करीब है, जबकि अहमदाबाद के दक्षिण-पूर्व तथा दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में तो यह 65 डिग्री दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि धरती की सतह सूर्य की किरणों के ताप को अवशोषित कर उसे ऊष्मा के रूप में छोड़ती है, जिससे धरती की सतह तथा आसपास का तापमान बढ़ जाता है। इसी को एलएसटी (लैंड सरफेस टेंपरेचर) कहा जाता है, जबकि आमतौर पर मापा जाने वाला तापमान सतह से कुछ फुट की ऊंचाई का तापमान होता है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) की 'द स्टेट आफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2021' रपट में कहा गया था कि भूमध्यसागरीय तथा उत्तरी अमेरिकी क्षेत्रों में भी लू ने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं और बीते सात साल सबसे गर्म रहे हैं। रपट के मुताबिक विगत नौ दशकों में धरती से लेकर समुद्र तक इंसानी दखल बढ़ने से मौसम का मिजाज बिगड़ा है और मौसम, पृथ्वी, समुद्र तथा पर्यावरण को होने वाली क्षति ने सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। प्रचंड लू से बाढ़ तक के लिए मानव निर्मित ऐसी परिस्थितियां ही जिम्मेदार हैं। डब्लूएमओ की रपट के अनुसार 2020 में वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मौजूदगी 413.2 पीपीएम थी और उद्योगीकरण से पहले की तुलना में वर्ष 2021 में इसमें 149 फीसद की बढ़ोतरी हुई।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भारत में 1991 से 2018 के बीच लू लगने के कारण 24 हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि एक अन्य रपट के मुताबिक अत्यधिक गर्मी या लू से 2010 के बाद से अब तक साढ़े छह हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आइआइटी खड़गपुर के एक अध्ययन से यह स्पष्ट हो चुका है कि तापमान में वृद्धि तथा लू का मानव शरीर पर व्यापक असर पड़ रहा है। गर्म हवाओं से मस्तिष्क आघात, हृदयाघात, नसों में खून के थक्के जमने की आशंका, स्थायी विकलांगता का खतरा बढ़ जाता है और इससे मृत्यु दर में भी वृद्धि हो सकती है। राष्ट्रीय एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के मुख्य अन्वेषक का कहना है कि लू, बाढ़ के बाद दूसरी सबसे घातक आपदा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौतियां पेश कर रही है। लू से ऐसे लोगों की स्थिति और खराब होने की संभावना होती है, जो हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे की बीमारी आदि समस्याओं से पीड़ित हैं। इन घातक स्थितियों से बचने के लिए जलवायु संकट से निपटने के अन्य उपायों के अलावा प्राकृतिक जंगलों के संरक्षण तथा आवासीय इलाकों में हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देना होगा।

अत्यधिक तापमान से जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य प्रणालियों की चिंता बढ़ जाती है, वहीं लू का श्रमिकों की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे देश की समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रपट के अनुसार भारत ने 1995 में गर्मी के कारण काम के करीब 4.3 फीसद घंटे खो दिए और 2030 में काम के घंटों में 5.8 फीसद की कमी आने की संभावना है। 2030 तक 3.4 करोड़ लोगों की नौकरियों पर संकट होगा। 2030 में गर्मी के कारण कृषि तथा निर्माण क्षेत्रों में 9.04 फीसद काम के घंटे कम हो जाने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रपट के अनुसार भीषण गर्मी तथा लू के कारण 2030 तक दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को 4.2 ट्रिलियन डालर की क्षति का अनुमान है।

बेचैनी बढ़ाते विकल्प

दुनिया मेरे आगे

शिखर चंद जैन

आजकल अक्सर अनेक युवाओं को हम परेशान, हैरान और उलझन में देखते हैं। उनके चेहरे पर तनाव, झुंझलाहट और व्यग्रता का अंदाजा कोई भी समझदार व्यक्ति आसानी से लगा लेगा। हैरानी की बात है कि इन बेचैनियों में से ज्यादातर बहुत बचकाने कारणों से होती हैं। हालांकि ये युवा अपने करिअर के दबाव, वैवाहिक भविष्य या कुछ निजी समस्याओं से भी जूझते हैं। बहुत सारे कामकाजी युवक-युवतियां अक्सर खाने-पीने की चीजें घर पहुंचाने वाले एप पर पसंदीदा भोजन और रेस्तरां की खोज में लंबा समय बर्बाद करते और परेशान होते हैं। बहुत सोच-समझ कर मंगाने के बाद वे इस खाने की बुराई करते और असंतुष्ट होते दिखते हैं। कई बार तो वे इस बात का निर्णय लेने में काफी वक्त बर्बाद कर देते हैं कि 'ओटीटी' मंचों पर कौन-सी फिल्म देखी जाए। ऐसे कई युवाओं को लगता है कि काफी वक्त और ऊर्जा खर्च करने के बाद उन्होंने जो निर्णय लिया, वह बिल्कुल गलत था।

कुछ दिनों पहले एक युवक ने दफ्तर से जल्दी जाने की बात की, तो उसके वरिष्ठ अधिकारी ने उससे कारण पूछा। युवक ने बताया कि उसे अपनी मां को हृदयरोग विशेषज्ञ के पास ले जाना है। अधिकारी ने पूछा कि क्या उसने चिकित्सक के बारे में जानकारी ले ली है, तो युवक ने कहा कि उसने गूगल में देखा था, 'हर्ट स्पेशलिस्ट नियर मी' यानी मेरे आसपास हृदयरोग विशेषज्ञ, तो उन्हीं का नाम दिखा था। जवाब सुनकर उसका अधिकारी हैरान रह गया और उसे डांटते हुए कहा कि तुम एक हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जा रहे हो, बिना उसकी जानकारी हासिल किए, जहां एक गलत निर्णय तुम्हारी मां के लिए जीवन-मरण का सवाल खड़ा कर सकता है। जबकि डेढ़-दो सौ रुपए का खाना मंगाने के पीछे तुम इतनी मगजमारी करते, और छानबीन करते हो। क्या तुम्हें अपनी बेवकूफी का कुछ अंदाजा है? युवक शर्मिंदा हो गया।

> **बहुतायत के युग का जीवन पर प्रभाव' के विषय में अध्ययन करने वाले समाज वैज्ञानिक कहते हैं कि सुख और खुशहाली के लिए विकल्पों की बहुतायत बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरत से ज्यादा विकल्पों की उपलब्धता इंसानी दिमाग को शिथिल या निष्क्रिय कर सकती है, जिससे अंत में हम वह खरीद लेते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं।**

ये हालात सिर्फ युवाओं के नहीं, इसके शिकार कुछ हद तक अब प्रौढ़ भी होने लगे हैं। हम अपनी जिंदगी के महत्त्वपूर्ण और कठिन निर्णयों को मामूली समझने लगे हैं। शादी के लिए या फिर सहजीवन के लिए साथी चुनने में हम ज्यादा वक्त और ऊर्जा भले न लगाएं, पर मामूली निर्णय को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। फैशन की होड़ और बेकार की जोड़-तोड़ के जंजाल में हम ऐसे फंसे हैं कि अपनी मानसिक शांति खो बैठे हैं। क्या हमने सोचा है कि आखिर इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है, ज्यादा विकल्पों की मौजूदगी।

हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, जहां सब कुछ बहुतायत में उपलब्ध है। सुविधाएं अंतहीन हैं और बाजार ढेर सारे विकल्पों से भरे पड़े हैं। यही अधिकता हमारी मानसिक अशांति, चिंता, दुख, बेचैनी और अवसाद की सबसे बड़ी वजह है। असल में आज की तारीख में हमें सबसे ज्यादा परेशान वह चीज करती है, जिसे हम खरीद नहीं पाए। सभी जरूरी और गैरजरूरी सामान की खरीदारी के लिए हमारे सामने इतने विकल्प होते हैं कि हम भ्रमित और बेचैन हो जाते हैं कि आखिर इनमें से कौन-सा चुनें। हालत यह है कि जो टीवी हमने लिया, उससे अलग दूसरे के पास है तो भी हम दुखी हो जाते हैं।

करीब दो दशक पहले हर चीज के सीमित विकल्प होते थे। शादी में खाने की चीजें गिनती की होती थीं। फिल्में थोक भाव से नहीं आती थीं। सामाजिक स्तर पर दिखावा आज जैसा नहीं था। तब हम एक उपभोक्ता के रूप में इतने बेचैन, दुखी और भ्रमित नहीं रहते थे। कमरे में फर्नीचर के नाम पर एक गद्दा और अलमारी होती थी, जिसमें पूरा परिवार अपने कपड़े रखता था। लेकिन अब ज्यादातर चीजों को चुनने के लिए भी काफी माथापच्ची करनी पड़ती है।

'बहुतायत के युग का जीवन पर प्रभाव' के विषय में अध्ययन करने वाले समाज वैज्ञानिक कहते हैं कि सुख और खुशहाली के लिए विकल्पों की बहुतायत बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरत से ज्यादा विकल्पों की उपलब्धता इंसानी दिमाग को शिथिल या निष्क्रिय कर सकती है, जिससे अंत में हम वह खरीद लेते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं।

हमने देखा होगा कि जिन रेस्तरां में सब्जियों, रोटियों और अन्य चीजों के बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं, वहां निर्णय लेने में काफी देर लग जाती है और तब तक हमारी भूख मर जाती है। जबकि थाली या सीमित विकल्पों वाली जगह पर हम ज्यादा अच्छी तरह संतुष्ट होकर भोजन कर सकते हैं। कहीं जाने के लिए पहले एक-दो विकल्प होते थे, या तो टैक्सी ले लें या बस से चले जाएं, लेकिन अब हमारे पास एप पर कई टैक्सियों के विकल्प हैं। स्मार्टफोन के दर्जनों विकल्प है। खरीदारी के अनगिनत विकल्प हैं। किसी माल, मोहल्ले की दुकान, बड़े बाजार या फिर आनलाइन खरीदारी कर लें।

ज्यादा विकल्पों ने हमारा जीवन कुछ मामलों में आसान भले बनाया हो, मगर हकीकत यह है कि इन्होंने जीवन को पहले से ज्यादा जटिल और जहरीला बनाने के साथ-साथ हमारी शारीरिक-मानसिक क्षमता पर जंग लगाने का भी काम किया है। हमें चिढ़ होती है, जब भारी मशक्कत के बाद चुनी गई वस्तु हमें खत्म हो जाने के कारण नहीं मिल पाती, जबकि हमारे किसी मित्र को वह मिल जाती है। ऐसे में हम खुद को हारा हुआ और पिछड़ा मान कर बेचैन हो जाते हैं। हमारी सारी शारीरिक-मानसिक ऊर्जा इस बात में खर्च हो रही है कि हम दूसरे से बेहतर, होशियार और आगे कैसे नजर आएं। बजाय अपनी जरूरत पर आधारित बेहतरी के प्रयास के हम इन अर्थहीन मसलों में उलझे रहते हैं।

अनुचित समर्थन

महिला सुरक्षाकर्मी द्वारा कंगना रनौत पर हमले को सही ठहराने की कोशिश चिंताजनक है। राकेश टिकैत और बजरंग पुनिया जैसे लोग इस अभियान में शामिल होकर उस सुरक्षाकर्मी को नायिका की तरह पेश कर रहे हैं। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। एक सुरक्षाकर्मी को विभागीय अनुशासन का पालन करते हुए सभी को सुरक्षा प्रदान करना होता है। वह अपने पूर्वाग्रह के साथ अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता। देश पहले भी सुरक्षाकर्मियों के पूर्वाग्रह भरे व्यवहार का खमियाजा भुगत चुका है। कल्पना कीजिए कि सुरक्षाकर्मी अगर भावना आहत होने की मानसिकता और पूर्वाग्रह के साथ ड्यूटी पर अनुचित व्यवहार करेगा, तो वह कितना भयावह होगा। कंगना रनौत केवल एक नागरिक या अभिनेत्री नहीं, जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि भी हैं। उन पर हुए हमले को सही बताना अराजकता को ही निमंत्रण देना है। इस घटना से एक सबक यह भी मिलता है कि ऐसे स्थानों पर सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति उनके अतीत और संपर्कों की सघन जांच के बाद ही होनी चाहिए।

– विमलेश पगारिया, बदनावर, मप्र

दागी प्रतिनिधि

इस बार की लोकसभा में 543 माननीय सांसदों में से 251 यानी छियालीस फीसद के खिलाफ विभिन्न अदालतों में आपराधिक मामले चल रहे हैं। अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस संसद पर देश को चलाने, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कायदे-कानून बनाने की जिम्मेदारी हो, वहां छियालीस फीसद खुद आरोपी बैठे हों, तो इस देश का भविष्य क्या होगा। इसमें सभी दलों की न्यूनाधिक सहभागिता है। 2019 में ऐसे दागियों की संख्या 233 थी, जो अब बढ़ कर 251 तक जा पहुंची है। अगर अदालतें इस मसले पर स्वतः संज्ञान लें और कड़े नियम बना दें, तो शायद बात बने। इसी तरह पंजाब में पकड़े गए खालिस्तानी चरमपंथी अमृतपाल सिंह जेल से ही चुनाव लड़ कर जीत गया। कश्मीर में 'टेरर फंडिंग' के आरोप में जेल में बंद एक आतंकी भी जेल से ही चुनाव जीत गया। ऐसे तत्त्वों को राजनीति से दूर रखने के लिए कठोर कानूनों की जरूरत है।

– इंद्रसिंह धिगान, दिल्ली

दूषित भोजन

वैश्वीकरण के बाद के दशकों में हमारे खानपान, रहन-सहन में काफी बदलाव आया है। हमारे जीवन में 'फास्ट फूड' और 'जंक फूड' का दायरा काफी बढ़ा है। इससे हमारी जीवन शैली काफी हद तक प्रभावित हुई है और हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। एक रपट के अनुसार दूषित खाने से हर साल लाखों लोग बड़ी संख्या में बीमार होते हैं, जिनमें से कई लोगों को अपने जीवन से हाथ भी धोना पड़ता है। दूषित भोजन के कारण दो सौ से अधिक खतरनाक बीमारियों जैसे पीलिया, हैजा, उल्टी, फूड पाइजनिंग, डायरिया आदि का सामना करना पड़ता है। दूषित भोजन की समस्या विकासशील और गरीब देशों में अधिक है, जहां भोजन की समस्या देखने को मिलती है। दूषित अन्न ने हमारे शरीर और मन दोनों को बीमार करना शुरू कर दिया है। थोड़ी सजगता और जागरूकता से अपने आप को दूषित भोजन के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है।

– विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

कुदरत से दूर

देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग लू से परेशान हैं। एअर कंडीशनर की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। कभी एसी बड़े दफ्तरों और अमीर घरों की शान हुआ करता था। मगर अब तो ग्रामीण कस्बाई परिवेश में भी इसका चलन बढ़ रहा है। लोग प्राकृतिक हवा नहीं लेना चाहते, ठंडक के लिए एसी पर निर्भर होते जा रहे हैं। एसी की बिक्री में हो रही जबर्दस्त वृद्धि से लोगों को लगता है कि देश की तरक्की हो रही है। दूसरी ओर आंकड़े यह भी कहते हैं कि खेतिहर और मैदानी इलाकों से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। सड़क किनारे अब पेड़ बहुत कम दिखते हैं। विकास का पहिया तब गति पकड़ेगा जब पुराने पेड़ों को काटने के साथ-साथ नए-नए पेड़ों को भी लगाने की आवश्यकता महसूस की जाए। आने वाली पीढ़ी को हम क्या विरासत सौंप कर जाएंगे, यह वर्तमान पीढ़ी को ही सोचना होगा।

– मिथिलेश कुमार, भागलपुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन जरूरी

भारत में केंद्र सरकार के शपथग्रहण कार्यक्रम के दिन ही कश्मीर में आतंकी हमला निश्चित रूप से नापाक साजिश है। गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीर में हमले करने वाले आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात ही है, इसी के साथ सरकार कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान को तेज करेगी। भारत के इस खास दिन को कश्मीर में आतंकी हमला अनायास नहीं है, बल्कि सुनियोजित साजिश है। इस आतंकवादी हमले के पीछे पाक प्रायोजित आतंकवाद की नीति है। इसकी जांच होनी चाहिए। जम्मू-कश्मीर में अभी जिस प्रकार शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लोगों ने बढ़ - चढ़ कर हिस्सा लिया, यह बात आतंक के आकाओं को खली, इसलिए संभवतः उसने राजग सरकार के शपथग्रहण के दिन को अपने आतंकी हमले के लिए चुना। तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया। यह कायराना हरकत है। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में एक यात्री बस पर हमले के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने सोमवार को घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया है। इस हमले में नौ लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के तीर्थयात्रियों को ला रही बस पर रविवार शाम आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसके कारण वाहन गहरी खाई में गिर गया। बस शिव खोड़ी मंदिर से कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी और इसी दौरान पोनी इलाके के तेरयाथ गांव के पास आतंकी द्वारा हमला किया गया और 53 सीट वाली बस गोलीबारी के बाद गहरी खाई में गिर गई। हमले में शामिल आतंकवादियों के राजौरी और रियासी के ऊपरी इलाकों में छिपे होने की आशंका है। इस इलाके में घने जंगल और गहरी खाइयां हैं। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आतंकवादी हमला जम्मू क्षेत्र में अशांति फैलाने की नापाक साजिश का हिस्सा है। अब कश्मीर सरकार का दायित्व है कि हमले में लिप्त आतंकियों के खिलाफ एक्शन सुनिश्चित करे। भारत को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान को तेज करना होगा, सीमा पर मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने होंगे। पाक में मौजूद आतंकी अड्डों पर भी एक्शन लेना होगा। सेना को अपने ऑपरेशन क्लीन अभियान को तेज करना चाहिए। वर्ष 2018 में शुरू इस ऑपरेशन क्लीन से आतंकवाद पर काफी अंकुश लगा। हाल के वर्षों में जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद में बहुत कमी आई है, इसके बावजूद आतंकवाद जड़ से खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान की फौज व खुफिया इकाई आईएसआई घाटी में सीमा पर आतंकवाद को हवा देती रहती हैं, तमाम विफलताओं के बावजूद उन पर कोई असर नहीं हुआ है। वे भारत के खिलाफ नापाक हरकतों में लिप्त रहती हैं। पाक पीएम शाहबाज शरीफ ने जिस प्रकार पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने का संकल्प लिया है, अगर पाक सरकार निष्पक्ष भाव से पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ अभियान चलाए, आतंकियों का खत्मा करे, तो इससे पाकिस्तान की छवि ही सुधरेगी। भारत सहयोग भी करेगा, पर देखने वाली बात है कि क्या वह सिलेक्टिव रहेगी और क्या वह अपनी फौज व आईएसआई को आतंकवाद के खात्मे के लिए सहयोग देने के प्रति तैयार कर पाएगी। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत को कश्मीर से आतंकवाद के खात्मे के लिए आरपार की तैयारी के साथ बड़ी कार्रवाई करनी होगी।

राजग सरकार
आर.के. सिन्हा

भाजपा जानती है गठबंधन धर्म

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने रविवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपना कामकाज संभाल लिया है। यह पहली बार नहीं है जब भाजपा गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेगी। वास्तव में, भाजपा की पहली सरकार, जो 1996 में गठित हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक गठबंधन की सफल प्रयोग वाली सरकार थी। भले ही वह केवल 13 दिनों तक चली। अटल जी 1998 में एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः वापस आए थे। इसलिए यह कहना सरासर गलत होगा कि भाजपा को गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने का अनुभव नहीं है। भाजपा को 2014 में 283 और 2019 में 303 सीटें मिली थीं। लेकिन, पूर्ण बहुमत के बाद भी मोदी ने गठबंधन का धर्म निभाया। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 240 सीटें जीतीं - बहुमत से 32 कम। एनडीए में 14 पार्टियां शामिल हैं। उसमें भाजपा को 240 सीटों पर विजय मिली और शेष 53 सीटें हासिल कीं, उसकी सहयोगी दलों ने।

अगर हम गुजरे दौर के पन्नों को खंगाले तो पता चलेगा कि कि भारत में सबसे पहले 1977-1979 गठबंधन सरकार बनी थी। कांग्रेस के 1977 में चुनाव हारने के बाद जनता पार्टी की सरकार देश में बनी थी। 1977 के चुनाव प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल की स्थिति लागू करने के लगभग दो साल बाद हुए थे। श्रीमती गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी को जनता पार्टी नामक कई पार्टियों के एक गठबंधन द्वारा हराया गया था, जिसमें भाजपा की पूर्ववर्ती, भारतीय जनसंघ शामिल थी। जनता पार्टी को देश की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला था। उस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री थे। उस सरकार में बाबू जगजीवन राम, हेमवती नंदन बहुगुणा, जॉर्ज फर्नांडीज जैसे जननेता भी शामिल थे। जनता पार्टी की उस चुनाव में जीत के बाद मोरारजी देसाई प्रधान मंत्री बने। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार दो साल तक चली। उसके बाद वैचारिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी बिखर गई। मोरारजी देसाई सरकार में गृह मंत्री चरण सिंह को कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। संयोग देखिए कि अब चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी उस एनडीए सरकार का हिस्सा हैं जिसके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं। चरण सिंह 1979 में जनता पार्टी के बिखरे हुए समूहों के समर्थन और कांग्रेस पार्टी के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बने। लेकिन चरण सिंह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल केवल 23 दिनों तक चला क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। 1980 में फिर चुनाव हुआ। इस बार इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ गईं, जब कांग्रेस ने 353 सीटें जीतीं।

लोकसभा के 1989 के चुनाव परिणाम भारत के लिए एक नये दौर को लेकर आए। यह पहली बार था जब राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा 529 सीटों में से 197 जीतने के बाद किसी भी पार्टी या चुनाव पूर्व गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं किया था। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में भाजपा के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार 1990 में गिर गई जब भाजपा ने अपना समर्थन वापस ले लिया। 1989 से 2004 तक, छह आम चुनावों में एक भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। इनमें से कुछ गठबंधन विशेष रूप से अराजक रहेः 1989 और 1999 के बीच, आठ गठबंधन बनाए गए और कई जल्दी ही ढह गए। इस बीच, ये मानना होगा कि भारत के कुछ सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार भाजपा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकारों के समय ही आए। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 से 2004 तक एक सफल बहु-पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत में विदेशी निवेश बढ़ा, एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज हुआ, व्यापार बाधाओं को कम किया गया। उनके ही दौर में देश ने पोखरण का परमाणु परीक्षण किया, पाकिस्तान के साथ तनाव को कम किया व अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। कांग्रेस 1991 में 232 सीटों के साथ और 2004 और 2009 में केवल 145 और 206 सीटों के साथ एक सफल अल्पसंख्यक सरकार चलाने में सक्षम कोशिश की थी।

मोदी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे तपे हुए नेताओं के सहयोग से देश को एक मेहनती और ईमानदार गठबंधन सरकार देने में सफल रहेंगे। उन्हें अपनी पार्टी के अनेक अनुभवी नेताओं का समर्थन और सहयोग तो मिलेगा ही, पर अब इंडिया गठबंधन को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। उन्हें हर बात पर सरकार को कोसना छोड़ना होगा। लोकतंत्र में वाद, विवाद, संवाद लगातार जारी रहना चाहिए। इसके बिना लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिल कर देश को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में बढ़ना होगा।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

गठबंधन की पहली परीक्षा में पास

मोदी 3.0
राज कुमार सिंह

चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार गठबंधन राजनीति के माहिर के सौदेबाज माने जाते हैं। इस लिहाज से नौ जून की शाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ लेने वाली मंत्रिपरिषद पर नजर डालें तो कहा जा सकता है कि वह अपनी पहली परीक्षा में सफल रहे हैं। शपथ ग्रहण में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद थे और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी सामने नहीं आई। शिवसेना तोड़ कर मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे कहीं ज्यादा कमजोर आंके जा रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन अजित पवार की एनसीपी से अच्छा रहा, जिसका पुरस्कार भी उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री के रूप में मिला है।

आखिरकार नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू ने 1952,1957 और 1962 में लगातार तीन बार देश की सत्ता संभाली थी। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने नौ जून की शाम राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले कर पंडित नेहरू का लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बराबर कर लिया। 2014 और 2019 में अकेले दम बहुमत मिल जाने के बावजूद भाजपा ने सहयोगी दलों के साथ एनडीए सरकार बनाई थी, पर इस बार बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे छूट जाने के चलते गठबंधन सरकार मजबूरी बन गई। मजबूरी ज्यादा बड़ी सिर्फ इसलिए नहीं है कि इस बार भाजपा के पास अपना बहुमत नहीं है, बल्कि गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे सहयोगी भी हैं, जो गठबंधन राजनीति के माहिर के सौदेबाज माने जाते हैं। इस लिहाज से नौ जून की शाम प्रधानमंत्री मोदी के साथ शपथ लेनेवाली मंत्रिपरिषद पर नजर डालें तो कहा जा सकता है कि वह अपनी पहली परीक्षा में सफल रहे हैं। शपथ ग्रहण में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता मौजूद थे और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व को लेकर किसी तरह की कोई नाराजगी सामने नहीं आयी।

हां, एनसीपी के अजित पवार गुट के मोदी मंत्रिमंडल में शामिल न होने से अवश्य महाराष्ट्र की भावी राजनीति को ले कर कुछ कयास लगाये जा सकते हैं। मात्र एक लोकसभा सीट जीत पाए उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री पद का ऑफर दिया गया था, जिसे अतीत में कैबिनेट मंत्री रह चुके प्रफुल्ल ने अपना डिमोशन बताते हुए अस्वीकार कर दिया। एक लोकसभा सीट के बल पर अजित पवार सौदेबाजी कर पाने की स्थिति में नहीं। सो, मोदी सरकार में उनकी एनसीपी की कोई हिस्सेदारी नहीं, पर इस सबका इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव वाले महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके गुट के एक दर्जन से भी ज्यादा विधायकों के शरद पवार से संपर्क में होने की खबरें हैं। शिवसेना तोड़ कर मुख्यमंत्री बनने वाले एकनाथ शिंदे कहीं ज्यादा कमजोर आंके जा रहे थे, लेकिन कम से कम लोकसभा चुनावों में उनका प्रदर्शन अजित पवार की एनसीपी से अच्छा रहा, जिसका पुरस्कार भी उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री के रूप में मिला है। महाराष्ट्र से कुल छह मंत्री बनाये गए हैं, जिनमें भाजपा की रक्षा खड़से भी शामिल हैं, जिनके श्वसुर एकनाथ खड़से फिलहाल शरद पवार की एनसीपी के एमएलसी हैं, पर जल्द अपनी पुरानी पार्टी भाजपा में वापसी करने वाले हैं। हरियाणा में भी इसी साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हैं, जहां से एक कैबिनेट मंत्री समेत कुल तीन मंत्री बनाये गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में हैं। वहां से एक राज्यमंत्री बनाया गया है। तीसरी बार सांसद बने भोजपुरी गायक मनोज तिवारी चूक गये, लेकिन पहली बार सांसद बने हर्ष मल्होत्रा की लॉटरी खुल गयी।

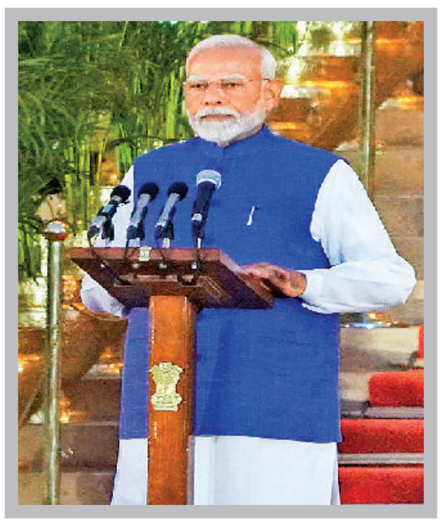

मोदी सरकार में इस बार प्रधानमंत्री के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, पांच स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 राज्यमंत्रियों समेत कुल 71 मंत्री शामिल हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल जैसे पुराने चेहरे तय माने जा रहे थे, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सभी 29 लोकसभा सीटें जिताने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रूप में कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए हैं। इस बार मोदी मंत्रिमंडल में पूर्व मुख्यमंत्रियों की संख्या पांच है। जीतन राम मांझी, सर्बानंद सोनोवाल और एचडी कुमारस्वामी भी क्रमशः बिहार, असम और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जेपी नड्डा को मंत्री बनाये जाने के चलते भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना होगा। वैसे भी लोकसभा चुनाव के चलते बढ़ाया गया नड्डा का कार्यकाल इसी महीने जून में समाप्त हो रहा है। नड्डा के मंत्री बनने के चलते ही शायद अनुराग सिंह ठाकुर का पत्ता इस बार कट गया है। मात्र चार लोकसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश से एक से ज्यादा कैबिनेट मंत्री बनाये जाते तो अन्य बड़े राज्यों में असंतुलन पैदा हो जाता। पिछली सरकार के सक्रिय मंत्रियों में शुमार अनुराग ठाकुर बड़बोले माने जाते हैं, पर आधुनिक राजनीति में वह तो नेता के पक्ष में जाता है। यह देखना होगा कि भविष्य में अनुराग ठाकुर को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। एक और बड़बोली मंत्री स्मृति ईरानी भी इस बार मोदी सरकार में नहीं हैं। पिछली बार राहुल गांधी को अमेठी से हरा कर चर्चा में आयीं स्मृति ईरानी इस बार कांग्रेस के एक अल्पज्ञात कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से हार गयीं। वैसे ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ कर आये लुधियाना के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू इस बार चुनाव हार जाने के बावजूद मोदी सरकार में राज्य मंत्री बनाये गये हैं। शायद भाजपा रवनीत सिंह बिट्टू को पंजाब की राजनीति में अपने सिख चेहरे के रूप में आगे बढ़ाना चाहती है। बिट्टू आतंकवाद से संघर्ष में शहीद हुए पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र हैं। इसी रणनीति के तहत केरल में भाजपा का खाता खोलने वाले अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी को भी मंत्री बनाया गया है।

वैसे आंकड़ों की बात करें तो चुनाव हार जाने समेत कई कारणों से पिछले मोदी मंत्रिमंडल के कुल 37 चेहरों को इस बार बाहर का रास्ता दिखाया गया है, जबकि 33 नये चेहरों की एंट्री हुई है। नये चेहरों में सहयोगी दलों के चिराग पासवान और जयंत चौधरी भी शामिल हैं। पिछली सरकार में चाचा पशुपति पारस को सत्ता सुख देने वाली भाजपा ने इस बार भतीजे चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी से गठबंधन किया था। लोक जनशक्ति बिहार में गठबंधन में मिली सभी पांच लोकसभा सीटें जीत गयी तो चिराग कैबिनेट मंत्री बना दिये गये, जबकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन में मिली दोनों लोकसभा सीटें जीतने पर जयंत के हिस्से स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री का पद ही आया। राज्यवार देखें तो बिहार के कुल आठ मंत्रियों में से चार कैबिनेट मंत्री बनाये गये हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के नौ मंत्रियों में से अकेले राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से ही सांसद हैं। प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात से भी कुल छह मंत्री बनाये गये हैं। इस बार मोदी मंत्रिमंडल के कुल 72 सदस्यों में से लगभग दस प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से 42 मंत्री बनाये गये हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

ज्ञान का अभिषेक

संकलित
दर्शन

अखिल ब्रह्मांड ईश्वर का स्वरूप है। श्रावण मास में बरस रही जलधारा ही ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रकृति इस धरा का अभिषेक कर रही है। प्रकृति के इसी कृत्य का अनुकरण हम मानव भी करते हैं। श्रावण मास में हम भी शिवलिंग पर जल चढ़ा कर अपने आपको ईश्वर के उसी कृत्य के साथ जोड़ लेते हैं। ईश्वर अथवा प्रकृति के गुणों को अपनाना सदाचार है। श्रावण मास हमें यह अवसर देता है। जल जीवन है और यह धरती को पुनर्जीवित करता है। वर्षा से प्रकृति पनपती है। तपती हुई धरती पर जब वर्षा होती है तो उसे शीतलता का आभास होता है। वनस्पतियां उगने लगती हैं। पेड़ों पर नए पत्ते लगने लगते हैं। जैसे श्रावण में लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, वैसे ही ज्ञान के श्रवण से मन को पीड़ा और बेचैनी से राहत मिलती है। श्रावण में लोग एकत्रित होकर ज्ञान-श्रवण करते हैं। दिव्य कथाएं सुनते हैं। ईश्वर का गुणगान करते हैं, जिससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है। जब मन पर ज्ञान का अभिषेक होता है, तो मन शांत और शीतल हो जाता है। श्रावण को सबसे पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि यह अनेक धार्मिक उत्सवों और पर्वों को अपने साथ लाता है। हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। शिव परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ऊर्जा हैं। शिव जीवन के मार्ग की बाधाओं को दूर करने वाले हैं। वह पुरातन को विनष्ट कर नूतन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव कल्याणकारी हैं। शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं।

मृत्यु टाले नहीं टलती

संकलित
प्रेरणा

भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठ कर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़ कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देख कर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यम देव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरूड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारो कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया, और खुद वापिस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजर से क्यों देखा था। यम देव बोलेः गरुड़ जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहां से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जलदी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहां नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती चाहे कितनी भी चतुराई की जाए।

अंतर्मन

आज की पाती

सरकार के साथ मजबूत विपक्ष भी समझे जिम्मेवारी

एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हो गए और यह इनका लगातार तीसरा कार्यकाल आरंभ हो रहा है। इसलिए यह नई सरकार नहीं, बल्कि पुरानी ही सरकार है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी में देश के हर वर्ग के अच्छे दिन लाने के प्रयास करेंगे, ऐसा कोई फैसला नहीं लेंगे जिससे किसी भी वर्ग को कोई नुकसान हो। लोकतंत्र में जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। सभी राजनीतिक दलों को जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए। इस बार के लोकसभा चुनाव में जिन राजनीतिक दलों को जीत हासिल हुई है, उन्हें बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के आमजन के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए। *- विमल जैन, भिलाई*

ट्रेंड

मोदी को बधाई

श्री नरेन्द्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। आपको सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं। हमारा देश आपके नेतृत्व में विकास की नयी ऊंचाइयों को छुएं।
-नवीन पटनायक, निवर्तमान मुख्यमंत्री, ओडिशा

अब रोजगार पर ध्यान दे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत राजग सरकार को अपने तीसरे कार्यकाल में देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटना चाहिए, खासकर असंगठित क्षेत्र और लघु एवं मध्यम उद्यमों में..।
-राजीव कुमार, नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन

जनगणना जल्द हो

केंद्र सरकार हर 10 साल में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आवश्यक देशव्यापी जनगणना करवाती है। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से जनगणना 2021 में होनी थी। लेकिन अब तक नहीं करवाया है। अब होनी चाहिए।
-जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव

पीएम को बधाई

आंध्र प्रदेश की जनता की ओर से मैं मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई देता हूं। यह राष्ट्र के लिए विकास, प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।
-एन चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी प्रमुख

करंट अफेयर

यूक्रेन शांति सम्मेलन में 90 देशों के भाग लेने की पुष्टि

दो साल से अधिक समय से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच यहां सप्ताहांत में स्विटजरलैंड की मेजबानी में आयोजित 'यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन' में करीब 90 देशों और संगठनों ने शामिल होने की पुष्टि की है, जबकि मॉस्को ने इसमें शरीक होने से इनकार कर दिया है। स्विटजरलैंड की राष्ट्रपति वियोला एमहर्ड ने सोमवार को संवाददाताओं को यह जानकारी दी। सम्मेलन में भाग लेने से रूस के इनकार करने के बावजूद इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें शामिल होने वाले देशों में से आधे से अधिक राष्ट्र यूरोप से हैं। एमहर्ड ने स्विटजरलैंड की राजधानी में कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले शुरू करने के करीब 28 महीने बाद शनिवार और रविवार को आयोजित शिखर सम्मेलन का लक्ष्य संभावित शांति का मार्ग प्रशस्त करना है। उन्होंने कहा, 'यह दुष्प्रचार नहीं है। यह स्विटजरलैंड द्वारा मुहैया की जा रही मानवीय सहायता के मुद्दे पर और वार्ता की पहले करने के बारे में है।' स्विस अधिकारियों ने बताया कि ब्राजील और चीन ने कहा है कि वह तब तक भाग नहीं लेंगे, जब तक कि रूस सहित दोनों पक्ष वार्ता की मेज पर नहीं आते। स्विटजरलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश ने बार-बार कहा है कि रूस के बिना शांति प्रक्रिया नहीं हो सकती।

ऑफ बीट

सूर्य से प्रभावित अंतरिक्ष क्षेत्र को कहते हैं हेलियोस्फीयर

सूर्य पृथ्वी को गर्म करता है, जिससे यह इनसानों और बाकी तमाम जीवों के लिए रहने योग्य बन जाती है। लेकिन यही सब कुछ नहीं है, और सूर्य अंतरिक्ष के बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। हेलियोस्फीयर, सूर्य से प्रभावित अंतरिक्ष का क्षेत्र, सूर्य से पृथ्वी की दूरी से सौ गुना अधिक बड़ा है। सूर्य एक तारा है जो लगातार प्लाज़्मा – अत्यधिक ऊर्जावान आयनित गैस – की एक स्थिर धारा उत्सर्जित करता है जिसे सौर पवन कहा जाता है। निरंतर सौर हवा के अलावा, सूर्य कभी-कभी प्लाज्मा के विस्फोट भी छोड़ता है, जिसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है, जो अरोरा में योगदान कर सकता है, और प्रकाश और ऊर्जा के विस्फोट, जिन्हें फ्लेयर कहा जाता है। सूर्य से निकलने वाला प्लाज्मा सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के साथ-साथ अंतरिक्ष में फैलता है। साथ में वे आसपास के स्थानीय अंतरतारकीय माध्यम के भीतर हेलियोस्फीयर बनाते हैं – प्लाज्मा, तटस्थ कण और धूल जो तारों और उनके संबंधित खगोलमंडल के बीच की जगह को भरते हैं। मेरे जैसे हेलियोफिजिसिस्ट हेलियोस्फीयर को और इस बात को समझना चाहते हैं और यह अंतरतारकीय माध्यम के साथ कैसे संपर्क करता है।

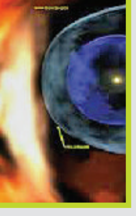

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid